

श्रीमान् गोखले के व्याख्यान ।

हिन्दी संस्करण ।

साद्री १॥
जिल्ददार १॥

{	प्रथम संस्करण	{	भारत सेवक-समिति,
	१९१७		प्रयाग ।

अभ्युदय प्रेस, प्रयाग, मे
सद्रीप्रसाद पाण्डेय द्वारा मुद्रित।

भारतवर्ष के लिए स्वराज्य ।

(दूसरा संस्करण ।)

—*—

लेखक--मान० श्रीमान् श्रीनिवास शास्त्री,

अध्यक्ष, भारत-सेवक-समिति ।

—*—

एक महीने के भीतर पहिला संस्करण चिक गया ।

पृष्ठ संख्या २५, दाम छ आना ।

विषय सूची ।

भारत का दावा—कुछ तुलनाय—योग्यता—स्कीम—
जापत्तिया—क्या अंगरेज लोग शक्ति को छोड़ना पसन्द करेंगे—
समाप्ति—परिशिष्ट ।

मान० डाक्टर तेज बहादुर सम्—यदि आपने इस पुस्तक को
अभी तक नहीं पढ़ा तो तुरन्त मंगाकर पढ़िये ।

“लीडर,” प्रयाग—पुस्तक अनेखी है । इसकी युक्तियों का
जवाब कोई एंग्लो इंडियन पत्र आज तक नहीं दे सका ।
विषय की विवेचना परम प्रशंसनीय है ।

“अभ्युदय,” प्रयाग—इसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह
थोटी है । इतनी उत्तम पुस्तक इतने कम दामों पर हमें
नहीं मालूम और कहाँ मिल सकती है । सभी समालोचकों
ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है ।

भारत सेवक-समिति,

प्रयाग ।

लखनऊ कांग्रेस में स्वराज्य ।

(दूसरा संस्करण)

पिछली कांग्रेस में स्वराज्य पर

श्रीमान् सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी,

मान० पं० मदनमोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसन्ट,
श्रीमान् बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती सरोजिनी नायडू,
श्रीमान् विपिनचन्द्र पाल, श्रीमान् मजहरल हक,
सर दिनशा पेन्डिट, मान० तेजबहादुर सप्रू,
आदि के व्याख्यान ।

"प्रज्ञाप", कानपुर—पुस्तक में लखनऊ की कांग्रेस में स्वराज्य के प्रस्ताव पर दिये गये बड़े बड़े विद्वानों और देश की उज्ज्वल मूर्तियों के व्याख्यानों का संग्रह है। पुस्तक स्वराज्य प्राप्ति की अवसर और अफाटव दलीलों और स्वराज्यवादियों के मुद्दालिफों को दिये गये बहुतेक उत्तरों से भरी पड़ी है। अन्त में माननीय मालवीय जी का वह सारगर्भित मर्मस्पर्शी व्याख्यान भी पुस्तक में जोड़ दिया गया है जो उन्होंने समापति की अन्यवाद देने हुए कांग्रेस के अन्तिम दिन दिया था। दाम, चार आना ।

भारत-सेवक-समिति,

प्रयाग ।

प्रयाग ।

विषय-सूची ।

विषय

पृष्ठ से पृष्ठ तक

भूमिका	७-८
गोपाल कृष्ण गोखले—चरित्र चित्रण	६-२५
हमारा आदर्श	१

प्रथम भाग--आर्थिक ।

१—भारतीय वज्र	७—३७
२—तमक का टैक्स	३८—६७
३—होम चार्जस या विलायती कर	६८—८१
४—भागतवर्ष के मृती माल पर महम	८२—६१
५—स्वदेशी आन्दोलन	६२—११७
६—सन् १९०८ का वज्र	११८—१२१
७—सरकारी व्यय की वृद्धि	१२२—१४७

द्वितीय भाग--राजनैतिक ।

१—लार्ड कर्जन का शासन	३—६
२—गजदरोही सभा सम्मन्त्री जाईन	१०—३१
३—य गाल और यगाली	३२—३६
४—सुधार के प्रस्ताव	४०—५७
५—भारतवासी और सरकारी नोकरिया	५६—६६
६—वर्तमान स्थिति के अनुकूल कार्यनीति	७३—८६

७—हिन्दू-मुसलमानों का मेल	८७—९६
८—हम लोगों की राजनीतिक स्थिति	९७—११०
९—भारतवर्ष के प्रति इंग्लैंड का कर्तव्य	१११—१२४
१०—भारतीय प्रश्न	१२५—१४२

तीसरा भाग--शिक्षा-सम्बन्धी ।

१—फर्ग्युसन कालेज में शिक्षा	३—८
२—अनन्य जातियों की उन्नति	९—१५
३—प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कानून का मसौदा	१६—२८
४—प्राथमिक शिक्षा १९१०—	२९—४८

चौथा भाग--फुटकर ।

१—श्रीमान दादाभाई नोरोजी	३—११
२—श्रीमान महादेव गोविन्द रानाडे	१२—४७
३—सर जी० एम० मेहता	४८—५१
४—विद्यार्थी और राजनीति	५२—६७

४२६

पुस्तक विद्यन्त में पृष्ठ नं० १७ से २२ सुलझे छप गया है पाठक महाशय उपर्युक्त सूची के अनुसार उधे ५२ से ६७ तक सुधार कर मड़ने की कृपा करें ।

भूमिका ।



भारत सेचक्र-समिति प्रयाग, श्रीमान गोपाल के व्याख्यानों के हिन्दी सस्करण के प्रकाशन से अपने को कृतकृत्य समझती है, और उसे आशा है कि श्रीमान गोपाल के व्याख्यान हिन्दी-साहित्य के राजनैतिक अंग की पूर्ति विशेष रूप से करेंगे। ये व्याख्यान कितने निर्भीक, गम्भीर, और महत्वपूर्ण हैं। इस पर कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं। वास्तव में वे भारतवर्ष की उच्चतम आकांक्षाओं और हमारी वर्तमान राजनैतिक स्थिति को अपूर्व रूप से चित्रित करने हैं। हमें आशा है कि पाठक इनका बार-बार ध्यानपूर्वक पाठ और मनन करेंगे।

अनुवाद के विषय में हम केवल इतना ही कहना है कि यह स्वतंत्र है। भाव पर न कि भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है। और हिन्दी साहित्य की वर्तमान अवस्था को देखते हुए हमारी सम्मति में इसी नियम का पालन अधिकतर उपयोगी है। दूसरे अनुवाद एक ही लेखनी का फल नहीं है। कई मित्रों ने श्रीमान गोपाल की स्मृति पर प्रेमाञ्जलि को अर्पित करने की इच्छा से प्रेरित होकर अनुवाद किया है। १९०२ और १९०६ की वज्रट वाली स्पीचों को गान्धी गोपाल नारायण सेन सिंह, बी० ए०, ने, राजविद्रोही मानन, बंगाल और बंगाली, सुधार के प्रस्ताव तथा विद्यार्थी और राजनीति को "सत्य शोधक" जी ने, और गांधी (गया) के बानू

अखौरी कृष्ण प्रकाश सिंह ने "अवनत जातियों का सुधार", "हम लोगों की राजनैतिक स्थिति" और "भारत के प्रति इटली का कर्त्तव्य" को, और बाबू केदारनाथ गुप्त ने "दादाभाई नौरोजी", "रानाडे," "सर फीरोजशाह मेहता" और फरगुसन कालेज से विदाई को अनुवादित किया। शेष व्याख्यानों के अधिकांश का अनुवाद एक अन्य सज्जन ने किया है। प्रफ़ देखने में प० भगवानदीन पाठक ने विशेष रूप से सहायता दी है। इस परम उदार सहायता के लिए समिति सब सज्जनों को हार्दिक धन्यवाद देती है। बिना इनकी सहायता के पुस्तक इतनी जल्दी कदापि न निकल सकती।

भारत सेवक समिति { वेङ्कटेश्वरनारायण तिवारी।
 प्रयाग, १० ६ १९१७



गोपालकृष्ण गोखले

गोपाल कृष्ण गोखले ।

[गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म मई, १८६६, में हुआ । अठारह वर्ष की उम्र में बी० ए० पास कर, वे १८८५ में दक्षिण शिक्षा समन्वयी समिति के आज़न्म सभासद हुए । सार्वजनिक सभा, पुणे, के मंत्री और उसके मुखपत्र के सार्वजनिक व्र मासिक पत्रिका के सम्पादक १८८६ से १८९६ तक रहे । १८९७ में वैल्यी कमीशन के सामने साक्षी देने के लिए वे इंग्लैंड गये । दो वर्ष तक घम्बई की प्रान्तिक व्यवस्थापक कौंसिल के सदस्य रहने के बाद, १९०१ में इम्पीरियल कौंसिल के मेम्बर चुने गये, और मृत्यु के समय तक इस कौंसिल में वे घम्बई के प्रतिनिधि रहे । १९०५ में कांग्रेस के काशी वाले अधिवेशन के सभापति हुए । १९०५, १९०६, १९०७, १९०८, १९१० और १९११ १४ में वे किसी न किसी राष्ट्रीय काम से इंग्लैंड गये और माले मिन्टो के रिफार्म्स के निर्णय में उन्हात बहुत भाग लिया । १९०५ में भारत सेवक समिति की मरुथा पता हुई । १९१२ से १९१५ तक वे पब्लिक सचिसेज कमीशन के मेम्बर थे । १९१२ में वे दक्षिण अफ्रिका गये और वहा के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की स्थिति के सुधारने में बहुत बड़ा भाग लिया, १६ फरवरी, १९१५ में उनकी जीर्न लीला का संवरण हुआ ।]

फरवरी १९, १९१५, को गोपाल कृष्ण गोखले के स्वर्गवास पर, प्रयाग के "लीडर" ने भाग्य के मर्म भेदी आघात से कातर होकर लिखा था कि इस तीस कोटि के भारत में गोखले का यम से चिन्तने के लिए हम और किन्हीं भारतवर्सी का विछोह सहर्ष सह लेते। यद्यपि यह कथन ताजे घाव का कारुणिक क्रन्दन था, परन्तु आज भी जब उनके संसार छोड़े दो वर्ष से अधिक हो गये हैं वह अक्षरशः सत्य है। उनकी असामयिक मृत्यु ने सारे देश को ऐसा रुलाया जैसा आज तक हम कभी न रोये थे, और उनकी मृत्यु ने वह चरितार्थ कर दिखाया जो उनका जीवन दावे के साथ उद्घोषित करता था कि हम भारतीय एक जाति हैं, और एक राष्ट्र हो सकते हैं। वह इस संसार से उठ गये, परन्तु हमारे देश के दुर्भाग्य से आज कोई सावित्री भारतवर्ष में नहीं है जो यम के पाश से उनके मृतक शरीर को छुड़ा लाती। अब हमारे लिए सिर्फ उनके जीवन का उज्ज्वल उदाहरण बानी है, और उनकी शिक्षा पूर्ण उपदेश इस समय पर भी उतने ही महत्व पूर्ण हैं जितने वे उस समय थे जब वे उनके मुख से स्वदेश प्रेम की ज्वाला से तपते हुए पहिले पहिले निकले थे। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा इसलिए जीवित रहेगा कि एक साधारण घराने का वात्सल्य भावगर्भ के लिए कैसे जी और मर सकता है। यह सत्य है कि वे हिन्दुस्तान को पराधीनता से स्वायत्त के उच्च शिखर तक न पहुँचा सके। लेकिन हमारे आँखों के सामने उनकी मृत्यु की, और यद्यपि उनकी उत्थान के उपाय स्थापित देखना न पड़ा था परन्तु मृत्यु के समय पर उनके यह विश्वास हो गया था कि निशीथ निशा शीघ्र ही स्वर्णमय प्रभात में विकसित हो जायगी।

जैसा वे प्रायः कहा करते थे, उनको और उनके सहयोगियों को पराजय ही के पथ पर चलना बड़ा था, उनके उत्तराधिकारियों का यह सौभाग्य होगा कि वे देश सेवा में विजय लाभ करें। आजन्म उन्होंने इसी आशा से काम किया कि उनके चले जाने के बाद देशभक्तों का मार्ग सुगम हो। गोखले अब हम लोगों के साथ नहीं हैं, परन्तु जब तक हिन्दुस्तान में निष्काम सेवा का आदर है और देशभक्ति का मान है, तब तक भारतवासी उनके नाम पर कृतज्ञता के सुरमित पुष्पों की अञ्जलि निरन्तर चढ़ाते रहेंगे।

प्रभाव का रहस्य ।

भारतवर्ष के ऊपर उनके इस अद्भुत और अद्वितीय प्रभाव का क्या रहस्य था ? जन्म से एक किन्तु व्यक्तिगत विशिष्टता, से हमारे पदों के राजा, हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास में कोई दूसरा भारतवासी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी मृत्यु से लोग घर्ष, जानि और मत के भेद के शोक में भूल कर ऐसे ही रोचें जैसा कोई अपने प्रिय के विद्रोह से कातर हो उठे। और न केवल यह दशा किसी एक ही प्रान्त की थी। जितना उन का आदर लोग घट्टाई में करते थे, उस से कुछ भी कम मात्रा उनका मयुक्त प्रान्त या मद्रास में न था। जनता उन में भारतीयता की मूर्ति को पूजती थी, और उनके जीवित में भारतीय इतिहास के उन प्रशसित अङ्कशों का सजीव संचार था, जिनके सामने भारतवासी सदा से सिर झुकाते चले आये हैं। उनमें मानसिक प्रौढ़ता, नैतिक उत्कृष्टता का पैसा ही सम्बन्ध था जैसा मालती में मन्दिर्य और सुरभि। पर यह ठीक है कि उनकी सौ मानसिक शक्तियाँ किसी देश और

काल में दुर्लभ हैं ; लेकिन उनसे अधिक प्रतिभाशाली मनुष्य हुए और होंगे, और वीरप्रसूता भारत भूमि के गर्भ से इस अग्रजत अवस्था में भी ऐसे मनीषी नरपुंगव पैदा होते जाते हैं जो इस घात में उनसे कहीं चढ़े बड़े हैं । गोपले—इस ऐतिहासिक नाम के पहले प्रशंसासूचक शब्द का प्रयोग नितान्त धृष्टता है—अपनी घाणी के जादू से वे कौंसिल और जनता दोनों ही पर विचित्र प्रभाव डालते थे, और क्या कांग्रेस में, और क्या कौंसिल में, लोग उनकी मधुर और गम्भीर शब्दावली ने मोहित होकर चित्रित हो जाते थे, लेकिन हिन्दुस्तान के बालनेवालों में उनकी गणना प्रथम न थी । इसमें सन्देह नहीं कि गोपले सरस्वती के बड़े भक्त थे और उनका पाण्डित्य उतना ही विस्तृत था जितनी उम्र में गम्भीरता थी । पाश्चात्य साहित्य का उन्हें उतना ही उत्तम ज्ञान था, जितनी भारतीय साहित्य की उन्हें प्रौढ़ अभिज्ञता थी । किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान में उनसे बढ़कर पण्डित हुए हैं । राजनैतिक क्षेत्र में भी वे अद्वितीय नहीं बहे जा सकते हैं । उन्होंने देश के बालने की शिक्षा में अपने जीवन के घटत बढ़े भाग को समर्पित कर दिया था, लेकिन यह जीवन फट गया है कि उससे उत्तर आचार्य भारत में नहीं । इसमें एक भी प्रयोग नहीं, एक चार्क भी कि वे भारत के एक व्यक्ति में होते, इन सब विशिष्टताओं का एक ही व्यक्ति । लोग उनके अतुल्य प्रभाव का अनुभव करते हैं । उनकी अपार शक्ति जो न सिर्फ सोती थी और न रुकती, और जिसकी शक्ति की शक्ति ने साथ मन्द हो गई कि विराट दिन पर दिन अधिक तेजमयी होती जाती थी, उनका निष्काम सेवा का घट और विशोरावस्था ही में देशहित के लिए

भीष्म के समान दरिद्रता का पाणिग्रहण, उनकी उच्चकोटि की मानसिक विशिष्टता, उनका निर्मल और अकलंकित जीवन, उनकी पारस्परिक व्यवहार में सत्यता, निश्छलता और स्वार्थ विस्मृति, उनकी विरोधियों के प्रति निष्पक्षता, और उदारता, अपने मित्रों में उनकी श्रद्धा और विश्वास, तथा उनकी भारतीयता जो न जन्म और न धर्म के घन्यता से परिमित थी, ये उस प्रेम और विश्वास के कारण थे, जो हिन्दू और मुसलमानों को उनकी आर विशेष रूप से खींचते थे। जिनका उनके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है उनका मालूम है कि भूलकर भी शुद्ध विचार और मकीण भाव उनके पास तक न फटकरने पाते थे। उनके प्रेरक भाव सदा उच्च और शुद्ध होते थे। घड़ी भर के लिए स्वार्थ के उत्तेजक उद्देश से वे कत्तय पथ से विचलित नहीं हुए। न एक पल भी अपने हित के लिए उन्होंने दिया, अपना मारा जीवन दश सेवा की पुनात घेदी पर अर्पण कर दिया था। ये भारत ही के लिए जीते थे, और भारत ही के लिए उन्होंने मृत्यु का असामयिक स्पर्श किया। जो भारतवर्ष के मित्र थे ही उनके भी मित्र थे और भारत का शत्रु, चाहे जितना बड़ा आदमी वह क्यों न हो, उनकी दृष्टि में कभी सम्मान का पात्र न था। जिनका माता से प्यार था वही उन्हें भी प्यारा था, और जो उनकी पूज्य भगवनी का आदर करना न जानता था उसके साथ उनका कुछ सम्बन्ध न था। भारत के लिए उन्होंने उनसे मित्रता की, जिनकी मित्रता से माता के उद्धार में सहायता की आशा थी। और वही उनका शत्रु था जो भारत की उन्नति का विरोधी था, और ऐसे व्यक्ति को शक्तिहीन करने के लिए वे निर्भीकता और उस कुशलता से, जो उनमें

हो थी, ये सदा कटिबद्ध थे। भारत और भारतवासियों के लिए वे जिये और मरे, भारतवासियों ने भी कृतज्ञता का अनमोल प्रेमोपहार जीवन में और उनके मृत्यु होने पर उनके ऊपर समर्पित किया। वे कुसमय में मरे किन्तु उनका नाम और उनके जीवन का उदाहरण हम यात का साक्षी है कि भारत जननी आज भी उसी प्रकार वीर प्रसूता बनी है। जैसी वह तब थी जब उसके सुपूतों की कीर्ति दुन्दुभि का उत्तेजक निनाद स्मार के गर्भ गुहों तक में प्रतिध्वनित होता था।

उनका स्वदेश-प्रेम ।

ऐसे महापुरुष के चरित्र का चित्रण योग्य से योग्य लेखनी के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। फिर, अभी हम सब उनके समय के इतने निष्ठ हैं कि निष्पक्ष आलोचना करना प्रायः असम्भव है। इन पत्रियों के लेखक में जहां इस कार्य के सम्पादन की और बहुत सी बाधाएँ की कमी हैं वहां उनसे सम्बन्ध समीप सम्बन्ध विशेष रूप से इस काम का ठीक ढंग से करने के लिए उसके मार्ग में बाधक है। किन्तु इस चित्रण का उद्देश्य उनके विचारों और नीति के अन्तिम परिणामों का विवेचन नहीं है। और उनके आदर्शों तथा प्रेरक अभिप्रायों को जानने के उन्हीं को विशेष अवसर मिल सकते हैं। जिन्हें उनके चरणों में बैठकर उपदेश पाने का सौभाग्य प्राप्त था। यदि विवेक द्वारा चरित्र को समझने का प्रयत्न किया जाय तो समीपवर्ती को इस और साधारण लेखक से अधिक सफलता हो सकती है।

गोपले से मिलने पर उनके गुणों में से जो सब से अधिक प्रभाव दर्शक के हृदय पर डालता था वह उनकी देशभक्ति

थी। देश का प्राचीन गौरव, उसकी वर्तमान शोचनीय दशा, उसके इतिहास की ज्वलन्त घटनाएँ और भाग्य के पलटे, भविष्य के लिए आशाएँ और आशंकाएँ, आपस की फूट और विदेशी शासन की—यद्यपि वे इंग्लैंड और भारत के सम्बन्ध को विधि की कृपामयी लीलाओं में गिनते थे—लज्जा और अपमान, सोते और जागते उनकी आँखों के सामने आचा करती थी। वे उन धीरे महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए थे, जिस के स्वाधीन राष्ट्र के पूर्ण अधिकार का नाश थोड़े ही वर्ष पूरा हुआ था। इसलिए पराधीनता की सुगहली जजीर उन्हें उन अन्य प्रान्तवालों से अधिक खलती थी, जो बहुत पहिले अपनी स्वाधीनता को खो चुके हैं। उनमें जातीय अभिमान कूट कूट कर भरा था। मृद्ग के पिचे हुए तारों की तरह, उनकी प्रकृति छोटी से छोटी घटना के अगुलि स्पर्श से प्रभावित होती थी। उनके स्वदेशानुराग की उगारों की लम्बे दिन प्रति दिन बढ़ती ही जाती थी, और उसकी पावन अग्नि में उन्होंने “अहम्” को सर्वथा जला दिया था। वे चाहते थे कि संसार की सभी जातियों में भारत का वही उच्च स्थान भविष्य में हो जो हमारा पहिले था। अपने देशवासियों की उच्च से उच्च आशाओं और आकांक्षाओं में उन्हें पूर्ण विश्वास था, और यद्यपि वे उनकी कमजोरियों को भली भाँति जानते थे और इसीलिए अपनी नाति के निर्धारण में वास्तविक स्थिति को सदा दृष्टिगोचर रखने थे परन्तु वे यह भी समझते थे कि संसार भारत के बिना दान रहेगा और मनुष्य जाति के इतिहास के भावी अध्यायों में जा घटनाएँ भारतीय राष्ट्रियता की कीर्ति लेखनी से लिख जायंगी, उन्हें कोई अन्य जाति लिखने में समर्थ न

होगी । उनके गुरु रानाडे का यह दृढ़ विश्वास था कि इस देश के निवासी सत्तार की जातियों में विशेष प्रकार से "बुढ़ा के बन्दे हैं" गोखले का भी यही दृढ़ विश्वास था । इस समय जब चारों ओर स्वराज्य की आकाशभेदी घाणों में सोती हुई जाति अपने ईश्वरीय भाग्य के महत्व के प्रति धीरे धीरे जाग रही है, हमारे बहुत से एलो इन्डियन मित्र गोखले का नाम लेकर रो रहे हैं, "हाय ! वे न हुए, नहीं तो ऐसे उड़्ड प्रस्ताव कांग्रेसवाले न उठाते ।" लेकिन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के शिक्षा-सचिव, मिस्टर हर्बर्ट फिशर को जो भारतीय पब्लिक कमिशन के एक मेम्बर थे, ऐसी भ्रान्ति कदापि न थी । गोखले की मृत्यु पर उन्होंने नेलडन के प्रसिद्ध सामाहिक "नेशन" में उनके विषय में प्रशंसात्मक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ने कहा है कि बहस के लिए गोखले यह मान लेते थे कि भारत में उन्नति की गति मन्द होनी चाहिए, और सुधार धीरे धीरे ही हो सकते हैं, परन्तु उनके हृदय में यह भाव सदा दृढ़ रहता था कि भारत अपने भाग्य के पूर्ण विकास के लिए इस समय पर भी पूरी तरह से तैयार है और वे इस आशा में रहते थे कि जापान के समान भारत में भी अचानक उद्योग फैल जाय । जो उनके पास रहते थे वे जानते हैं कि यदि किसी भी कारण से ब्रिटिश शासन भारत से उठ जाय तो उस अवस्था में गोखले को दृढ़ निश्चय और विश्वास था कि उनके देशवासी शासन के भार को लेंगे । वे कहते थे कि "हम लोगों ने एक प्रकार से अंगरेजी सल्तनत को मजूर कर लिया है । इस लिए जहां धर्म हमें उसका विरोध करने से रोकता है वहां उस शासन पर इसका अनिवार्य दायित्व है कि वह हमें साम्राज्य में अपरिमित और

स्वतंत्र उन्नति और विकास के समान अवसर है। किसी अन्य विदेशीय राष्ट्र भी पराधीनता की आशंका मात्र उनके अचिन्त्य और असाध्य थी। शत्रु नहीं मिल सकने, जिन के द्वारा उस भीषण क्रोध, और तिरस्कार का वर्णन किया जाय जो उनके चेहरे पर इस सङ्घर्ष में दिखाई देते थे। साम्राज्य में स्वाधीन भारत उनका आदर्श था।

जहाँ उनको अपने देश के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास था वहाँ ही परिस्थिति के महत्व को भी न भूलने थे। यदि उनके नेत्र आदर्श के स्वर्ण शिखर को रात दिन एकटक देखने रहते थे तो साथ ही वे आदर्श की सीमा और उस तक पहुँचने के परिमित साधनों को भी अच्छी तरह से जानते थे। यह समझते थे कि सच्ची उन्नति का नाम वृद्धि है, विघटन नहीं—राष्ट्र सजीव है, मृतक पदार्थ नहीं। स्थायी उन्नति क्रम क्रम से होती है। वे इतिहास के भर्षा को अच्छी तरह से अनुभव करते थे कि जैसे पालर पैदा होते ही बीघन का अधिकारी नहीं, वैसे ही जादू से अचानक जाति पूण राष्ट्रीय जीवन को नहीं प्राप्त कर सकती है। यदि भाग्यता का अद्भुत मंदिर संसार में सर्वार्थ सुन्दर बनेगा तो तभी जब उसकी नींव रेत पर नहीं किन्तु घटान पर रखी जाय। और इसके लिए कि नींव चिरस्थायी और मजबूत हो, यह आवश्यक है कि वह जड़ हो विस्तृत और मजबूत पत्थरों की बनाई जाय। इस व्यापक दृष्टि से—और यह उनकी देश भक्ति की एक विशेषता थी,—हिन्दुस्तान उनके लिए अगरेजी पढ़े लिखे लोगों का मुल्क न था। उनका भारत महलों में न था किन्तु साधारण शोषकों में। वे साधारण व्यक्ति की उन्नति से, इने गिने भाग्यशाली आदमियों की तरक्की से, जाति की उन्नति को नहीं जाचते थे।

यद्यपि उन्होंने फरगुसन कालेज के कमरे में अपने अठारह वर्ष बिताये परन्तु उनको जितनी फिक्र प्रारम्भिक शिक्षा का मुक्त और लाजिमी बनाने की थी उतनी किसी दूसरी बात की न थी। और इसके दाहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि आज लोकमत इस विषय के विश्वव्यापी महत्व और उसकी निरंतर आवश्यकता को अनुभव करने लगा है तो यह उन्नी के प्रचण्ड उद्योग का फल है। अछूत जातियों के सुधार पर भी वे इसी मात्र से जोर देते थे। स्त्री शिक्षा के लिए इसीलिए आवश्यक नहीं कि स्त्रियाँ उगलान, पढ़ सकें या मन्त्र से व्याख्यान दें, परन्तु इसलिए कि वे जाति के पथ में अग्रगण्य हों, वे जाति का सच्ची और सुयोग्य मानाएँ बनें, जिसमें भारी सन्तान राष्ट्र का सेना में योग्य स्थान ले सके। इसलिए यद्यपि जन्म और सम्कारों से वे हिन्दू थे और हिन्दूत्व की छाप उनके प्रत्येक गुण विशेष पर दिखाई देती थी, किन्तु सामाजिक क्षेत्र में और प्रश्न के विवेचन में वे भारतीय पहलू ही पर जोर देते थे। उनके लिए भारतीय जातीयता एक स्वप्न न थी, उनके जीवन में यह साफ़ और सजीव दिखाई देती थी। तिरले ही राजनैतिक नेता ऐसे आज दिन भारत में मिलेंगे, जो इस आदर्श में अपने जीवन का मूल सिद्धान्त मानकर लोकसेवा करते हैं। एक उड़ी सुन्दर उमा द्वारा वह वर्तमान स्थिति का वर्णन किया करते थे। वे कहते थे कि भारत को दशा एक त्रिकोण के समान है, जिसकी दो भुजाएँ मिलकर तीसरी भुजा से घड़ी होती हैं। भारत में उन्नी तरह तीन प्रधान शक्तियों का संघर्ष है। हिन्दू, मुसलमान और एंग्लो इण्डियन। इनमें से कोई दो मिलकर तीसरे को दबा सकते हैं। इसीलिए वे हिन्दू और मुसलमानों

में मेल की परमावश्यकता को अपने जीवन के उच्च आदर्शों में गिनते थे। एक बार श्रीमती सरोजनी नायडू से उनकी बातें हो रही थीं। हिन्दू मुसलमानों के मेल की भी बात छिड़ गई। श्रीमती सरोजनी ने कहा कि पांच साल के भीतर दोनों दल मिल जायेंगे। इस पर गोखले ने कहा कि यदि तुम्हारे ओर मेरे जीवन काल में भी ऐसा होना सम्भव हो तो देश उड़ भागी होगा। साल ही भर बाद लखनऊ में लीग का जलमा हुआ और श्रीमती नायडू भी उस में पधारी थी, इसी अधिवेशन में पहिलेपहल लीग ने भारत में स्वराज्य के आदेश को स्वीकृत किया था। इस सन्देश को लेकर जब श्रीमती सरोजनी पूने में उनसे मिली उस समय पर वे बीमारी ने बहुत कमजोर हो गये थे। परन्तु इस समाचार ने उनको इतना प्रफुल्ल और उत्सुक बना दिया था कि वे चुशी में व्यक्ति के केंद्रों को बिल्कुल भूल गये, और श्रीमती से बार बार यह पूछते थे कि क्या यह समाचार सत्य है और क्या मुसलमान फिर पलट न जायेंगे। उनके आश्वासन दिलाने पर लीग के सम्बन्ध में छोटी से छोटी बात को कई दफा उन्होंने उन से पूछा। उसी शाम को श्रीमती सरोजनी उन से फिर मिलने आई, और जब गोखले उनके साथ पुस्तकालय में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो श्रीमती नायडू ने उन से कहा कि आप इतने बीमार हैं, सीढ़ियों पर क्यों चढ़ रहे हैं। गोखले ने कहा, “आप ने आज मुझे जो समाचार सुनाया है, उसने मुझ में नई जाने डाल दी है और जीवन सग्राम में फिर से तठवार उठाने की शक्ति मुझ में आ गई।” ऐसे ही जब दक्षिण अफ्रिका में निष्क्रिय प्रतिरोध शुरू हो गया था और वहाँ की सरकार के उग्र आचरण से कमवीर गांधी के जेल

जाने की आशंका थी, गोखले को रातों दिन चैन नहीं पड़ता था। वे प्रवासी भारतवासियों के विदेश में अनादर के राष्ट्रीय अपमान को सह नहीं सकते थे। उन दिनों में गोखले दिल्ली में थे। एक रात को लगभग दो घंटे उनके कमरे में टहलने की आहट उनके एक प्रिय शिष्य को सुनाई पड़ी। उठकर शिष्य ने उनके कमरे में झांक कर देखा कि वे टहल रहे हैं। उस समय गोखले का स्वास्थ्य बहुत पराव था। बीमारी में इतनी व्यग्रता और प्रयास से हानि पर जोर देने और सोने के लिए आग्रह करने पर उन्होंने कहा, “दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी इतनी यातनाएँ भाग रहे हैं और गांधी जेल जाने को हैं। यह कैसे सम्भव है कि मैं शान्ति से बैठूँ।” पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गोखले को दिन-ब-दिन एंग्लो इंडियन गवाहियों के हिन्दुस्तानियों पर अयोग्यता के लक्षणों को सुनने से जो अपार क्रोध होता था उसका वर्णन कठिन है। और इनमें सन्देह नहीं कि उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। इतना अधिक दुःख उनको और किसी बात से न होता था। जितना भारत की निन्दा सुनने से। और कमीशन के दिनों में वे प्रायः कहा करते थे कि इस गवाहों के अपमानजनक प्रश्न सुनते सुनते मेरे दृढ़ मूँखता जाता है। एक रात उनके एक मित्र ने आग्रह उनसे स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने के लिए कहा। उत्तर में गोखले ने कहा कि मरना तो एक दिन है ही किन्तु भारत की दशा को देख कर चुप बैठना मेरे लिए असम्भव है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में श्वास है तब तक एक पल भी ऐसा न बीते जो माता की सेवा में न लगा सकूँ।” उनके लिए मृत्यु उस जीवन से कहीं अधिक

प्रिय थी, जिसका एक निमित्त मात्र भी भारत के चरणों में न समर्पित हो। श्रीमती सरोजिनी नायडू के शब्दों में, मातृभूमि उनकी स्वामिनी और माता, हृदय की पूज्य देवी और प्रिय नम पुत्री थी। उनके लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं था कि भारत का विभव बढ़े। उनके जीवन की एकरात्र यही लालसा थी कि अपना हृदय, तन, मन और धन उसी के लिए श्रीचरणों में धत्ता के साथ अर्पण करें। इसके सामने उनके दूसरे सामान या सुख, विभव या कीर्ति, अपमान या पराजय सब धुट्ट घे घट्ट भारत के सेवक थे, और ससार में इससे बढ़कर किसी भारतवासी के लिए अधिक क्या कहा जा सकता है।

उनका आत्मसमर्पण और त्याग।

उनकी देश में तल्लीनता साधारण आदमियों के स्वदेशा नुराग की तरह मजाक या छुट्टी के समय दिल बहलाने की बात न थी। वह यह जानते थे कि जैसे भाग्न के प्राचीन इतिहास में ईश्वर की खोज में ध्रुव ने और सत्यज्ञान की रक्षा में यम का पीछा करती हुई सावित्री ने ससार और जीवन को तिलाजलि दे दी, वैसे ही आधुनिक समय में ध्रुव का त्याग, सावित्री की ज्ञान प्रज्ञा तथा आत्मसमर्पण और लक्ष्मण की कार्यक्षमता देश-रक्ष के लिए आवश्यक हैं। तप और त्याग हमारे जातीय इतिहास में सबसे अधिक प्रशंसित हैं और प्राचीन भारत की गरिमा के निर्माण पूज्य ऋषि और मुनि प्रकृति से जीतने के लिए इनसे साधनों का आश्रय लेते थे। जो अब भारत के उत्थान का बड़ा उठाते हैं उनको भी "मैं" की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिये। गोखले ने

जाने की आशा का थी, गोखले को रातों दिन चैन नहीं पड़ता था। वे प्रवासी भारतवासियों के विदेश में अनादर के राष्ट्रीय अपमान को सह नहीं सकते थे। उन दिनों में गोखले दिल्ली में थे। एक रात को लगभग दो घंटे उनके कमरे में टहलने की आहट उनके एक प्रिय शिष्य को सुनाई पड़ी। उठकर शिष्य ने उनके कमरे में झांक कर देखा कि वे टहल रहे हैं। उस समय गोखले का स्वास्थ्य बहुत खराब था। बीमारी में इतनी व्यग्रता और प्रयास से हानि पर जोर देने और सोने के लिए आग्रह करने पर उन्होंने कहा, "दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी इतनी यातनाएँ भोग रहे हैं और गांधी जेल जाने को हैं। यह कैसे सम्भव है कि मैं शान्ति से बैठूँ।" पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने गोखले को दिन प्रतिदिन एंग्लो इंडियन गवाहियों के हिन्दुस्थानियों पर अयोग्यता के लाल्छनों को सुनने से जो अपार क्रोध होता था उसका वर्णन कठिन है। और इसमें सन्देह नहीं कि उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। इतना अधिक दुःख उनको और किसी बात से न होता था। जितना भारत की निन्दा सुनने से। और कमीशन के दिनों में वे प्रायः कहा करते थे कि इन गवाहों का अपमानजनक बयान सुनते सुनते मेरे खून सूखता जाता है। एक बार उनके एक मित्र ने साग्रह उनसे स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने के लिए कहा। उत्तर में गोखले ने कहा कि मरना तो एक दिन है ही किन्तु भारत की दशा को देख कर चुप बैठना मेरे लिए असम्भव है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में श्वास है तब तक एक पल भी ऐसा न बीते जो माता की सेवा में न लगा सकूँ।" उनके लिए मृत्यु उस जीवन से कहीं अधिक

प्रिय थी, जिसका एक निमित्त मात्र भी भारत के चरणों में न समर्पित हो। श्रीमती सरोजनी नायडू के शब्दों में, मातृभूमि उनकी स्वामिनी और माता, हृदय की पूज्य देवी और प्रियतम पृथ्वी थी। उनके लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं था कि भारत का विभव बढ़े। उनके जीवन की एकमात्र यही लालसा थी कि अपना हृदय, सत्त, मन और धन उसी के लिए श्रीचरणों में धरती के साथ अर्पण करें। इसके सामने उनके दूसरे सामान या सुख, विभव या कीर्ति, अपमान या पराजय सब धुड़ ये वह भारत के सेवक थे, और ससार में इससे बढ़कर किसी भारतप्राप्ति के लिए अधिक क्या कहा जा सकता है।

उनका आत्मसमर्पण और त्याग।

उनकी देश में तल्लीनता साधारण आदमियों के स्वदेशा नुराग की तरह मजाक या छुट्टी के समय दिठ पहलाने की बात न थी। वह यह जानते थे कि जैसे भारत के प्राचीन इतिहास में ईश्वर की आज्ञा में ध्रुव ने और सत्यवान की रक्षा में यम का पीठा करती हुई सावित्री ने संसार और जीवन को तिलाजलि दे दी, वैसे ही आधुनिक समय में ध्रुव का त्याग, सावित्री की लगन प्रह्लाद का आत्मसमर्पण और नक्षत्र की कार्यप्रमत्ता देश-रक्ष के लिए आवश्यक हैं। तप और त्याग हमारे आनीय इतिहास में सबसे अधिक प्रशंसित हैं और प्राचीन भारत की गरिमा के निर्माण पूज्य ऋषि और मुनि प्रकृति को जीतने के लिए इन्हीं साधनों का आश्रय लेते थे। जो अब भारत के उत्थान का बड़ा उठाते हैं उनको भी "मैं" की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिये। गोखले ने

त्याग और तप से इस पवित्र काम में आत्म समर्पण किया। अठारह वर्ष की उम्र में, जब आमारजित भविष्य उनको आदर से स्वार्थ साधन के पथ पर चलने को प्रोत्साहित कर रहा था, गोखले ने फरगुमा कालेज में नाममात्र के धेतन पर बीस वर्ष तक सेवा का कठिन घत धारण किया और उस समय मरणान्त तक वे उसी धर्म का अनुसरण करते चले गये। यदि वे चाहते तो विपुल धन के स्वामी होते। उनको कई रियासतों की दीवानी स्वीकार करने को दी गई। भारत-सचिव की कौंसिल में प्रथम भारतीय मेम्बर होने का गौरव उनको मिल सकता था। वाइसराय की कार्य कारिणी कौंसिल में वे आसानी से जा सकते थे परन्तु उनके सामने ये सब तुच्छ थी। इसी भाव से उन्होंने के० एम० आइ० ई० की उच्च पढ़ाई को भी विनम्रता के साथ अस्वीकार किया, यद्यपि इस देश के अनेक सज्जन इन सम्मानों को, पाने के लिए अपनी आत्मा को गैतान के हाथ बँधने तक को उत्सुक रहते हैं। वह गरीब ही पैदा हुए थे, और गरीब ही वे मरे-पर जो स्थान उनका आज भारतीय इतिहास है वह पर राजे महाराजों तक को प्राप्त है? फिर, ससार के सभी देशों में सार्वजनिक नेता अपने नाम के लिए जमीन आसमान के कुलाये एक करने को तैयार रहते हैं। और वे इस ही सिद्धि में सार्वजनिक कार्यों तक को तहस नहस कर देश के विद्रोही बन जाते हैं। गोखले में यह कानोसी कदापि न थी। १९१२ में जब उनका देश में स्थान बहुत ऊँचा था, गोखले प्रारम्भिक शिक्षा चिन्त के पक्ष में लोकमत को जाग्रत करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे, सरफीरोज शाह मेहता उसके खिलाफ थे, और तब यदि गोखले चाहते

तो बम्बई में जैसे अन्य प्रान्तों में, एक प्रमाणशाली समिति बन सकती थी। किन्तु मेहता को वे अपना नेता मानते थे, और इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया और बम्बई में लीग न बनी। नेता के प्रति अनुयायी का जो धर्म है उसका उन्हें सदा ध्याना रहता था। और इस देश में जहाँ लोग नेता के, सेहरा को अपने हाथों से अपने मिर पर बांधा करते हैं, और स्वार्थ से नेताओं को अपदब्ध करने की नीयत से दूसरों की टोपी उताने ही में सारा जीवन रातम कर देते हैं, गोखले का उज्ज्वल उदाहरण अनुकरणीय है। गोखले ने रानाडे के खरणों में जो शिक्षा पाई थी उसमें सबसे अनमोल यह थी कि सार्वजनिक कामों में व्यक्तित्व का विचार कदापि न करना चाहिये। सन् १८९७ में गोखले के ऊपर अत्यन्त अनुचित और अनुदार आक्रमण पालामेन्ट के कई मेम्बरों ने किये थे। उन्होंने ने इन आक्रमणों का समानार रानाडे के मकान पर पड़ा था यह इतने व्यथित हुए कि काश से बरामदे में जाकर टूटने लगे। रानाडे को जब इसका पता लगा तब उन्होंने ने उन से इसका कारण पूछा। बात जानने पर उन्होंने ने कहा "गोपाल राय, इसे भूल जाओ और इन आक्रमणों का उत्तर देना तुम्हारे लिए उचित नहीं।" जब तक उन्होंने ने गोखले से इसका वचन न ले लिया कि वे उत्तर न देंगे तब तक उन्हें अपने पान्हासे उठने न दिया। इसी शिक्षा का यह फल था कि गोखले ने अपनी सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत अपराधों और आक्रमणों का उत्तर नही दिया। उनके व्याख्यानो में व्यक्तिगत आरोपों की बू तक न मिली।

त्याग और तप से इस पवित्र काम में आत्म समर्पण किया। अठारह वर्ष की उम्र में, जब आभा रजित भविष्य उनको आदर से स्वार्थ साधन के पथ पर चलने को प्रोत्साहित कर रहा था, गोखले ने फरगुसन कालेज में नाममात्र के वेतन पर बीस वर्ष तक सेवा का रुठिन व्रत धारण किया और उस समय मरणान्त तक वे उसी धर्म का अनुसरण करते चले गये। यदि वे चाहते तो विपुल धन के स्वामी होते। उनको कई रियासतों की दीवानी स्वीकार करने को दी गई। भारत मन्त्रि की कौंसिल में प्रथम भारतीय मेम्बर होने का गौरव उनको मिल सकता था। वाइसराय की कार्य कारिणी कौंसिल में वे आसानी से जा सकते थे परन्तु उनके सामने ये सब तुच्छ थीं। इसी भाव से उन्होंने के० सी० आई० ई० की उच्च पदवी को भी विनम्रता के साथ अस्वीकार किया, यद्यपि इस देश के अनेक सज्जन इन सम्मानों को, पाने के लिए अपनी आत्मा को शीतान के हाथ बँचने तक को उत्सुक रहते हैं। वह गरीब ही पैदा हुए थे, और गरीब ही वे मरे-पर जो स्थान उनका आज भारतीय इतिहास है वट पर राजे महाराजों तक को प्राप्त है? फिर, संसार के सभी देशों में सार्वजनिक नेता अपने नाम के लिए जमीन आसमान के कुलावे एक धरने को तैयार रहते हैं। और वे इसही सिद्धि में सार्वजनिक कार्यों तक को तहस नहस कर देश के विद्रोही बन जाते हैं। गोखले में यह कामगोरी कदापि न थी। १९१२ में जब उनका देश में स्थान बहुत ऊँचा था, गोखले प्रारम्भिक शिक्षा मंत्रि के पक्ष में लोकमत को जाग्रत करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे, सरफ़ीरोज शाह मेहता उसके खिलाफ थे; और अगर यदि गोखले चाहते

तो बम्बई में जैसे अन्य प्रान्तों में, एक प्रभावशाली समिति बन सकती थी। किन्तु मेहता को वे अपना नेता मानते थे, और इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने खुलकर उनका विरोध न किया और बम्बई में लीग न बनी। नेता के प्रति अनुयायी का जो धर्म है उसका उन्हें सदा ध्यान रहता था। और इस देश में जहाँ लोग नेता के सेहरा को अपने हाथों से अपने सिर पर बाधा करते हैं, और स्वार्थ से नेताओं को अपदस्थ करने की नीयत से दूसरों की टोपी उताग्ने ही में सारा जीवन खत्म कर देते हैं, गोखले का उज्ज्वल उदाहरण अनुकरणीय है। गोखले ने रानाडे के चरणों में जो शिक्षा पाई थी उसमें सबसे अनमोल यह थी कि सार्वजनिक कामों में व्यक्तित्व का विचार कदापि न करना चाहिये। सन् १८९७ में गोखले के ऊपर अत्यन्त अनुचित और अनुदार आक्रमण पार्लामेन्ट के कई मेम्बरों ने किये थे। उन्होंने ने इन आक्रमणों का समान्वार रानाडे के मकान पर पढ़ा था यह इतने व्यथित हुए कि क्रोध से बरामदे में जाकर टूटने लगे। रानाडे को जब इसका पता लगा तब उन्होंने ने उन से इसका कारण पूछा। यात आनने पर उन्होंने ने कहा "गोपाल राय, इसे भूल जाओ और इन आक्रमणों का उत्तर देना तुम्हारे लिए उचित नहीं।" जब तक उन्होंने ने गोखले से इसका वचन न ले लिया कि वे उत्तर न देंगे तब तक उन्हें अपने पाठसे उठने न दिया। इसी शिक्षा का यह फल था कि गोखले ने अपने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत अवज्ञाओं और आक्रमणों का उत्तर नही दिया। उन के व्याख्यानों में व्यक्तिगत आक्षेपों की वृत्ति न मिलेगी।

कांग्रेस और कौंसिल ।

शुरू से ही गोखले कांग्रेस के अनुयायी थे कांग्रेस के सिद्धान्तों में उन्हें पूर्ण विश्वास था, कांग्रेस आन्दोलन के वे एक उज्ज्वल रत्न थे। १९०५ में बनारस की कांग्रेस में समाधि के आसन से उन्होंने ने जो व्याख्यान दिया था, वह निर्भीक ओजस्विता का अपूर्व उदाहरण है। जब वह बम्बई की कौंसिल में थे तब उनकी बजट सम्बन्धी स्पीचों से उनका सिद्धा जम गया था सन् १९०२ में वाइसराय की कौंसिल में बजटवाली स्पीच से उनका नाम सारे देश में प्रख्यात हो गया, और आर० सी० दत्त ने उसको पढ़कर यह कहा था कि ये ही भारत के भावी नेता होंगे। १९०४ में "आसिलस् सीक्रेट प्रिन्सिपल्स" पर उनकी जो स्पीच हुई थी उसका जवाब लार्ड कर्जन की अनुपस्थिति में कोई दूसरा सरकारी प्रतिनिधि न दे सका। यह निरुसन्देह है कि भारतीय कौंसिल में इनसे बढ़कर दूसरा गैर-सरकारी मेम्बर आज तक नहीं गया, और बजट पर वह सब उनके उठ जाने के बाद राम के बिना रामायण सी हो गई है। यद्यपि सरकार उनके प्रस्तावों का विरोध करती जाती थी किन्तु अवसर मिलते ही उन्हीं के अनुसार चलने की चेष्टा भी करती थी। और कौंसिल में उनकी अपूर्व सफलता को देखकर उनकी मृत्यु पर लार्ड कर्जन ने कहा था कि संसार की किसी सभा में उनका प्रथम स्थान होता।

लेख बहुत बढ़ गया है, और विषय के किनारे ही पर लेखनी अभी तक पड़ी है। इसलिए अधिक न लिखकर उनके जीवन के सम्बन्ध में हम यही शब्द उद्धृत करते हैं जो

रानाडे के विषय में उन्होंने कहे थे —“रानाडे के प्रति हमारा केवल यही कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करें। उनके जीवन के संदेश को हम सब को पवित्र और अनुकरणीय समझना चाहिये। जिन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए उन्होंने सारे जीवन परिश्रम किया—सब के लिए विस्तृत स्वाधीनता और मनुष्य के मनुष्यत्व का सार पूर्ण गौरव—ये अन्त में अवश्य ही विजयी होंगे, चाहे जितना अधिकार मय भविष्य समय समय पर क्यों न दिखाई दे। किन्तु हम सब उस विजय के दिवस को शीघ्र लाने का परिश्रम कर सकते हैं, और इसीमें हमारे जीवन का गौरव है —“मानुषमि के लिए काम करो और आत्म त्यागी बनो।”

हमारी यह हार्दिक प्रार्थना है कि पाठक इन व्याख्यानों को पढ़कर देश की दशा के समझें, उनके उपदेशों का मनन करें और उनके शब्दों से देश सेवा के व्रत का संकल्प करें जिसमें भारतवासी ससार में वही स्थान पायें, जो हमारी प्राचीन सभ्यता और गरिमा के से अधिक उज्ज्वल हो।

“मैं मातृभूमि के लिये अपनी आकांक्षाओं की सीमा को अनन्त और अपरिमेय मानता हूँ। मैं स्वदेशवासियों को अपने देश की उसी वेदी पर देखना चाहता हूँ जिस पर अन्य देशवासी अपनी भूमि में खड़े हैं। मैं, जातिपाति का कोई भेद नहीं मान, चाहता हूँ कि स्वदेशवासी नरनारी अप्रतिरोधित तथा अनियंत्रित रूप से उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि ससार के महान राष्ट्रों के बीच भारतवर्ष भी राजनैतिक, औद्योगिक, धार्मिक साहित्यिक, वैज्ञानिक विषयों में स्पर्धा की वस्तु न रहकर उचित स्थान प्राप्त करे। मैं इन सब बातों की आकांक्षा करता हूँ और साथ ही साथ विश्वास भी करता हूँ कि मेरी सारी लालसाएँ वस्तुतः तथा सारत इसी प्यासी भूमि में चरितार्थ भी होंगी”।

—गोपाल कृष्ण गोखले।

“मैं मातृभूमि के लिये अपनी आकांक्षाओं की सीमा को अनन्त और अपरिमेय मानता हूँ। मैं स्वदेशवासियों को अपने देश की उसी वेदी पर देखना चाहता हूँ जिस पर अन्य देशवासी अपनी भूमि में गड़े हैं। मैं, जातिपाति का कोई भेद नहीं मान, चाहता हूँ कि स्वदेशवासी नरनारी अप्रतिरोधित तथा अनियंत्रित रूप से उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि ससार के महान राष्ट्रों के बीच भारतवर्ष भी राजनैतिक, आधोगिक, धार्मिक साहित्यिक, वैज्ञानिक विषयों में स्पर्धा की वस्तु न रहकर उचित स्थान प्राप्त करे। मैं इन सब बातों की आकांक्षा करता हूँ और साथ ही साथ विश्वास भी करता हूँ कि मेरी सारी लालसाएँ वस्तुतः तथा सारत इसी प्यारी भूमि में चरितार्थ भी होंगी”।

—गोपाल कृष्ण गोखले ।

प्रथम भाग



आर्थिक

भारतीय बजट ।

(बड़े लाट की व्यवस्थापर सभा में बुधवार २६ मार्च १९०२ को लार्ड कर्जन के सभापतित्व में माननीय मि० गोगल की यह पहली बजट स्पीच हुई) ।

श्रीमन् । मुझे भय है कि मैं उन उधाड़्यों में जो मा० अर्थ सचिव को पारसाल के वार्षिक हिसाब में एक बड़ी ग़म की बचत होने पर दी गई है, सम्मिलित नहीं हो सकता । आज तक सरकारी आय-व्यय के इतिहास में ७ करोड़ की उचत नहीं देखी सुनी गई, विशेषकर जब ऐसी उचते कई साल से होती आती हैं और यह उस अवस्था में जब देश में बराबर दुष्काल रहा है । मेरी समझ में इसमें यह साफ़ भल्लकता है कि प्रजा की अवस्था से सरकार की आय का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि इस विषय पर जितना मैं सोचता हूँ—मुझे विश्वास है कि मेरे स्पष्ट भाषण के लिए आप तमा करेंगे—मेरी यही धारणा होती है कि इस सरकारी उचत से देश को दोहरी हानि पहुँचती है । पहले तो इस बचत का होना ही बुरा है । अर्थात्भाव और उष्ट्र के दिना में सरकार को जितने धन की ज़रूरत है उससे अधिक लेना ही बुरा है । दूसरा अन्तर्य इससे यह होता है कि उसके आगम पर तरा तरा की मिथ्या भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । और जो बुझ होता है वह तो होता ही है, साथ ही साथ भारत सचिव के मन में आशाशा की वाद आने लगती है, और वह समझ बैठता है कि

इस सर्वश्रेष्ठ देश में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। थोड़ी सी जाच से पता लगता है कि यह सरकारी वचन सम्पूर्ण रूप में सिम्के विभाग की वचन है, और उसके होने का कारण यह है कि इस समय भी सरकार उसी परिमाण से कर वसूल कर रही है जिस परिमाण से रुपये के बहुत कम मूल्य पर चलने के समय सरकारी बर्च पूरा करने के लिए आवश्यक होता था। सन् १८६४—६५ में रुपये का सबसे कम मूल्य था। उस वक्त औसत रूप में एक रुपया १३ १ पेन्स को पड़ता था। रुपये का भाव जब इस प्रकार गिर रहा था उस समय बर्च चलाने के लिये सरकार को बराबर एक बड़ी रकम से कर की वृद्धि करनी पड़ी, जिसका फल यह हुआ कि १८६४—६५ में जब रुपये की लागत बहुत ही थोड़ी थी, सरकारी आय-व्यय के खिड़के में ७० लाख की वचन दिखाई गई। उस तारीख के आगे सिम्के के इन्तजाम के लिए १८६३ में जो कानून बनाया गया, उससे लाभ दिखाई देने लगा। रुपये का निर्णय सेने के लिहाज से बढ़ता गया। १८६५—६६ में एक रुपये के बदले में १३ ६३ पेन्स मिलते थे। उस वर्ष सरकारी वचन टेढ़ा करोड़ हुई। १८६६—६७ और १८६७—६८ में विनिमय की दर १४ ४५ और १५ ३ पेन्स रही पर इन दोनों वर्षों में अकाल पड़ा और उसके दूसरे साल मगहड़ी लड़ाई में भी बहुत सर्फा पड़ने के कारण खर्च लगा कर अकाल-पीड़ितों की रक्षा और फौजी बर्च में पहले साल २१ करोड़ और दूसरे साल ६२ करोड़ का व्यय हुआ। नतीजा इसका यह हुआ कि १८६६—६७ साल के सरकारी हिसाब में १.७ करोड़ का और १८६७—६८ में ५ ३६ करोड़ का घाटा हुआ।

प्रत्यक्ष है कि यदि सरकार को यह अनुमान लगा व्यय न

उठाना पड़ता तो दोनों ही साल के हिसाब में बचत दिया लाई पड़ती। विशेष कर १८६७—६८ में अनुमान ४ करोड़ की बचत होती। सन् १८६८—६९ में करीब करीब रुपये का भाव १६ पेन्स हो गया। और इस तरह उस साल सरहद्दी लड़ाई के लिये १ करोड़ रुपया निकालने पर भी २६६ करोड़ की बचत रही। हम लोग जानते हैं कि एक्सचेंज की दर में यदि ३ पेन्स की तेजी हुई अर्थात् रुपये का भाव १३ से १६ पेन्स हो गया तो फ्रेड होमचार्ज पर ही भारत सरकार को ४ और ५ करोड़ के बीच में लाभ होने लगता है। मेरे विचार में तो सरकार की पिछले कई सालों की असामान्य बचत का इसी से पता लग जाता है। नीचे दिये हुये हिस्साब से बहुत बातें समझ में आती हैं। आय-व्यय का अन्दाजा भी मिल जाता है, जैसा उसमें रुपये के बढ़ाये हुए निर्णय से अंतर पड़ता है।

साल	घाटा वा बचत	युद्ध और अकाल के असामान्य व्यय	विशेष कर लेने से बचत	टिप्पणी
१८६७	— ५ ३६	६ २१	३ ८५	युद्ध और अकाल
१८६८	+ ३ ६६	१ ६६	५ ०५	सरहद्दी तैयारी
१८६९-७०	+ ४ १६	३ ५	७ ६६	अकाल
१८७०-७१	+ ७ ५	६ ३५	८ ८५	"
१८७१-७२	+ ७	१	८	
५ वर्ष का जोड़	१२.२६	२१ १५	३३ ४१	

अगर युद्ध और अकाल के लिये विशेष व्यय न होता तो नये रुपये की दर से देश की आमदनी शासन-व्यय कम से कम ६० करोड़ प्रति वर्ष अधिक होती। भारतीय सेना के दक्षिण अफ्रीका और चीन देश में चले जाने के कारण जो बचत हुई, इसके अलावा अकाल के कारण जो गन्ध हुआ, तथा इसका ध्यान रखने हुए कि अफीम से आमदनी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हुई यहाँ तक कि उसके हाने की ऐसी आशा न थी और न फिर हो सकती है, इन सबका विचार करते हुए भी हम सरकारी खर्च के ऊपर सरकारी आमदनी की वार्षिक ५ करोड़ रुपये की बचत रखें तो अनुचित न होगा। इतनी ही बचत सरकारों 'होम चार्ज' पर एन्स चेन्ज का भाव १३ पेन्स से १६ पेन्स बढ़ जाने के कारण और होती है। पिछले १६ साल में सरकारी हिसाब में जब कभी घाटा बढ़ा है तो अर्थ-सचिव ने उसका कारण रुपये के निर्बल का गिरना बताया है, और नये करा केलगाने की आवश्यकता दिखलाते हुए देश को, दिवालिया होने से बचाने का यही उपाय बताया है। सन १८८५-८६ के बाद १० वर्ष तक, जर्मने सर आम्ब्रुज कार्टर ने कौन्सिल में सरकारी हिमाय का सालाना समझौता देने समय कुछ ऐसी बात बताई जो पीछे बिल्कुल सत्य निकली और कहा कि हमारे काम का ढग बढ़ल रहा है तथा उस गजब की नीति पर जिसका सन १८८२ में निर्णय हुआ था, हमें पुन विचार करना पड़ेगा। उस समय स १८८६-८७ तक बराबर अर्थ-सचिव की यही कोशिश रही है कि सरकारी ग्राय चाह जैसी हो चटी बढ़ी यनी रहे चाहे आर्थिक स्थिति कितनी भी बदल रही हो। उन्ह सदा यही धुन रहती थी कि वे सब तरह के वास्तविक या काल्पनिक भय और

फट के लिये पहले से तयार रह । इस प्रकार कोई साल ऐसा नहीं जाता था जत्र अर्थ विभाग की शासन-नीति में कुछ उलट पुलट न होता हो । सरकारी आमदनी से, अकाल निवारण के लिये, जो धन अलग रिया जाता था वह सन् १८८६-८७ में ३ साल के लिये रोक दिया गया, पुन दो साल के लिए कम कर दिया गया और अन्त में एक दम बन्द कर दिया गया । इन १० वर्षों में दो बार (१८८७-८८ और १८९०-९१) गन्धक का धर अश जो प्रान्तीय सरकारों को दिया जाता था कम कर दिया गया और उसमें भारतीय सरकार के कोष में पुर १,०० करोड़ की वृद्धि हुई । १८८७-८८ में १४ लाख और १८९०-९३ में ४८ लाख । इसके अतिरिक्त इसी बीच में तीन बार (१८८६-८७, १८९०-९१ और १८९१-९२ में) प्रान्तीय सरकारों भारतीय सरकार के कोष में विणय चन्दा देने के लिये बाध्य की गई । पर उस समय के अर्थ-फट से बचने का प्रधान उपाय निरन्तर राजकर की वृद्धि करना था । इन १२ सालों में ६ साल परावर नये कर लगाये गये । सन् १८८६ में इन्कम टैक्स से श्रीगणेश हुआ । फिर धडाधड सन् १८८७-८८ (जून १८८८) में नमक के ऊपर कर उढ़ाया गया, मिट्टी के तेल पर कर पट्टारियों के लिये महसूल और १८८८-८९ में इन्कम टैक्स का वर्मा तक विस्तार हुआ । विलायती शराब पर महसूल १८८९-९० में बढ़ा, देशी बिअर पर १८९०-९१ में कर लगा । वर्मा में याहर से आई हुई नमकीन मट्ठाली पर १८९०-९३ में महसूल आरम्भ हुआ, याहर से आये माल पर कीमत के अनुसार प्रति सेकंडा पाच की दर से सन् १८९३-९४ में महसूल फिर से लगाया गया पर उसमें सूती कपडे शामिल नहीं किये गये । वही महसूल १८९४-९५ में सूती

कपड़ों पर लगा दिया गया। सन १८६६ में महसूल की दर में कुछ रद्दगदल हुई। ५ सैकड़ा महसूल देशी गने हुए सत पर से उठा दिया गया। गहर से आये कपड़ों पर ५ के स्थान में केवल ३ सैकड़ा महसूल रह गया—इससे ५० लाख का नुस्सान हुआ। यह नुकसान मैन्नेस्टर के जुलाहों के चिह्नों पर रियायत करने के कारण हुआ। साथ ही इस देश के कारखानों में तैयार हुए कपड़ों के बाहर जाने पर उनपर ३ सैकड़ा महसूल बैठाया गया, जिसमें भारतीय सोदागर अनुचित लाभ न उठाने पायें। सन् १८६६ में उस चीनी पर महसूल लगाया गया जिसे भारत में मन्ता रेचने के लिये बिलायत वाले अपने व्यापारियों को आर्थिक सहायता देते थे।

इन सब उपायों से पिछले १६ वर्षों में सन् मिलकर १० ३० करोड़ वार्षिक विनोद राजकर लिया गया। इसका यहाँ अन्त न समझिये। इसी बीच में भूमि-कर की भी आपही आप बहुत वृद्धि हुई है। अकेले माधारण लगान ही की वृद्धि २८२ करोड़ हुई। इसकी वसुली में गन् अचम्भे की बात यह है कि सन् १८६६-६७ और १८७१-७२ जब देश में दाघोर दुर्भिक्ष पड़े) में इस वसुली का औसत १७ ५३ मिलियन पौन्ड रहा जब पिछले ६ वर्षों में १८६०-६१ और १८६५-६६ तक का औसत १६ ६७ मिलियन पौन्ड था।

इन दोनों महा म जो कर की वृद्धि हुई उन्हें जोड़कर देखने से मालूम होता है कि पहले से राजकर अब १५ करोड़ अधिक हो गया है।

इस प्रकार एक कर के ऊपर दूसरे कर को निरन्तर बढ़ाना और दु गी प्रजा के बोझ को गुरुतर करना नहीं नहीं देखा गया है। भारतवर्ष में १८५७ के विद्रोह के बाद प्रथम कुछ साल तक राजकर में वृद्धि की गई थी पर उस समय थोड़े ही दिनों में देश को बड़ी अच्छी दशा हो गई थी और बिना किसी कष्ट वा झगड़े के लोगों ने उसका सहन कर लिया था। इस गत १६ वर्षों में देश की कृषि और उद्योग दोनों ही काम मन्दे पड़ गये और उसपर भी प्रति वर्ष इससे बढ़ बढ़ कर लगान लिया जा रहा था और इसके लिये कहना यह था कि इससे आर्थिक अवस्था सुरक्षित रहेगी।

लगातार टैक्स के बढ़ाने का मुख्य परिणाम यह हुआ है कि जितने धन की सरकार को आवश्यकता है उससे नहीं अधिक टैक्स मसूल किया जा रहा है। इसी तरह जबर-दस्ती बढ़ाए गए करों के कारण उनकी सामान्य वृद्धि के कारण नहीं—मन्थारन न केवल नए प्रकार के कर चलाये गये एक नए नई कर की उद्यत कर ली है जिससे देश का यूरोप के धनाढ्य देशों का भी पैदा होती होगी।

केवल सरकारी आय व्यय का हिसाब बराबर करने के लिये नहीं पर क्लेश और विपत्ति के काल में भी एक निरन्तर बढ़ती हुई सराय की उद्यत करने के लिए टैक्स का बलपूर्वक लेना किसी भी कर प्रणाली की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। पाश्चात्य देशों में असाधारण कर कर्ज लेकर चलाया जाता है। ऐसा करने का यह उद्देश्य होता है कि चाहें सरकार को रुपये की वित्तों भी जम्मा क्यों न हो पर ऐसा न हो

कि टैक्सों के एकाएक उठ जाने से देश के व्यापार और उद्योगों की यथाक्रम उन्नति में कोई बाधा पड़ने का भय हो। भारत वर्ष में जहाँ ऐसे प्रश्नों पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से कम विचार किया जाता है और जहाँ किसी सत्ता का व्यय उसी सत्ता की आय से चुकाने की नीति का एक अनुचित सीमा तम पालन किया जाता है, वहाँ अर्थविभाग के शासकों को केवल इतनी ही चिन्ता नहीं होती कि आपत्ति में और समृद्धि में एकसा निर्वाह हो जाय, वे तो ऊपर से प्रतिवर्ष बड़ी रकम की उन्नत भी चाहते हैं, माननीय अर्थसचिव अपने बजट के लेख में "सेनिक सेवा" शीर्षक में लिखते हैं —

"इसका ध्यान रखना चाहिये कि भारत अपनी मालगुजारी से नई युद्ध सामग्रियों का सर्व तथा सैनिक विभाग के कई मुख्य अंगों के सुधार का खर्च सहन कर रहा है। मेरा विश्वास है कि यह काम दूसरे देशों में बिना किसी प्रकार का भ्रूण लिये नहीं चला है। स्वतः इङ्गलैंड में किलेन्द्री और सिपाहियों के रहने के लिए घर बनाने का असाधारण स्मारक व्यय भ्रूण लेकर चलाया गया है जो पीछे से मालगुजारी की किम्मत से चुकता किया जायगा। यदि वर्तमान शान्ति में लाभ उठाकर यह फंडिन कार्य हम बिना कर्ज लिये ही और भारत की भविष्यत् जनता पर स्थायी बोझ डाले बिना संपादन कर सकें तो हम लोग अपने को एक ऐसे कार्य करने के लिए सज्जित देख सकते हैं जिसे करने का साहस यूरोप के बड़ी समृद्धिशाली जानिया को भी नहीं हुआ है।"

इस अवतरण के प्रत्येक शब्द पर टिप्पणी हो सकती है। यह तो पृथिवी में जिम्मेदार नाम के लिये युगोपचाला को ग्राह्य

नक नहीं हुआ, उसे भाग्य ने किस तरह कर दिया था। इसका स्पष्ट उत्तर तो यह है कि उन देशों में कर का संग्रह और उससे व्यय करने का भार वहाँ की प्रतिनिधि सभाओं के हाथ में है। भाग्यदर्प में कर देने वालों को इन बातों के निर्णय में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि हम लोगों की कोई राय ली जाती तोर दश या शायद भीतर २ दो दलों का हाग संचालित होता और ये दोनों दल हम लोगों के प्रसन्न करने और हमारी सहायता प्राप्त करने से इच्छुक होते तो आज अर्थसचिव कोई दूसरी लीकवा कहने। और, हम वहाँ पर इतना जरूर कहेंगे कि पश्चिमी देशों की प्रजा को याद का अधिकार होने से कारण उसका मन का जो आदर है वह अर्थसमन्धी शासन में हमें भी मिलना चाहिये। जैसा भीमान न खय वहाँ है, सरकार का चाहिये कि वह प्रजा की आवश्यकताओं को बुझिमाना स अनुभव कर।

यह भी हुआ, यूरोप की समृद्ध, धनशाली जातियाँ जिन काम को करने में भागती थी, उससे करने के उपरान्त ७५ वर्ष के भीतर अनुमान ५० करोड़ के असाधारण व्यय व्यता के निम्न 'निरन्तर बढ़ती हुई समस्या की वृद्धि' भी हुई। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जसा कनल चेन्नी न नाइन्टीन्थ मनुगी एन्ड आफ्टर की माचकी सरया में लिखा भी है कि प्रजा में उचित परिमाण में अधिक धन लिया जा रहा है, अर्थात् सरकारी जग का प्रोक्त अकारण ही बहुत कर रक्खा गया है। जो सरकारी सर्व दाता है उसे के लिये करा के लगाने की बात तो समझ में आती और दुर्दिन से समय में भी करा का ज्यों का ।

"एक निरन्तर" "समस्या की वृद्धि" ।

भायें समझ में नहीं आसकती। जो कुछ हो, जिन लोगों ने इस देश की आर्थिक अवस्था की गति का अध्ययन किया है वे इस बात को मानेंगे कि पेंडल इसीका ध्यान रखने हुए कि सरकार को एक निरन्तर उड़ती हुई समस्या की "चत" हुई है और वह आमदनी के उठने के कारण नहीं घटने के कारण है। केवलपूर्ण उठाने से, यह नहीं कहा जा सकता जैसा लार्ड जार्ज हेमिल्टन आजा करने है, कि यह देश के सुनी और सम्पन्न होने का प्रमाण है या जैसा मा० सर एडवर्ड ला का कथन है।

ऐसे लोगों के लिये एक दुसरी देश के सरकारी का का भरा पूरा होना—कोई गूढ़ समस्या नहीं है। वे जानते हैं कि जातीय कर का परिमाण उस अवस्था में भी जब सरकार उसे कम कर सकती है अकारण ही बहुत ऊँचा रखा गया है।

इस प्रश्न पर इन विचारा को रखने हुए मुझे इस बात का अत्यन्त शोक है कि विकृत ४ साल में सरकार का प्रचार बचन होने पर भी उस अधर १६ वर्ष के नीतर प्रजा पर उठे हुए करों के जोरों को हलका करना स्वीकार नहीं हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार ने जो अनुमान २ करोड़ के लगान का बकाया माफ किया है उसके लिये सारा देश उसका अनुगृहीत है। सरकार का यह उदा और निर्भीक कार्य दुर्भाग्यवश दिनों में भी बकाया न छोड़ने का पुनर्निर्माण नीति के मा लोगों को बहुत ही हर्षवर्द्धन हुआ है। शिक्षा के लिये ४० लाख का विशेष दान भी देश भर में उच्चिन्ना पायेगा। पर मेरे गिरायन तो माननीय अर्थ मन्त्रि के आगामी मात के लिये

व्यय का प्रस्ताव करने में भय नहीं, भीखना दिखलाना पर है।
 जब पिछले ४ वर्षों में इतना बड़ी शोक वचन होती आई है
 और इस समय कोई विगलन के यादग भी नहीं मउरा रहे हैं
 नय वे इस पर भी यज्ञ में मिक सवा लाग की ही वचन वगै
 रखने हैं जब उनका उसकी तिगुनी वचन रखना अधिक पुति
 सगत तथा उनकी मनवता नामुचक होता। सरकारी आय की
 अस्थायी पर यदि धादा भी था धिनाय वगत जमा पिछले
 ४ साल की वचन से उतरा था चलना है तो और कामों के
 साथ साथ वे निमकक ऊपर आठ आने मात्र का जो महसूल पीछे
 से लगाया है उठा लेते, वन न कम १०००) तर की आय पर
 इन्कम टैक्स टाउ देने, देश के अतर नगर नियुक्त मनी माल
 के ऊपर से महसूल हटा तन और फिर भी उस साल वचन
 दिखला सकते थे। धोमन रिता उलहने के प्रजाते जो पिछले
 १६ साल में एक टैक्स के यान दुमरा टैक्स सहन किया है
 उसके बदले में ऊपर का रुप तीन महसूल का हटा लेना
 उन पर कोई बड़ा महमान करना गता है। आय के उस अश
 के सम्बन्धमें जिसपर इन्कम टैक्स माफ हाना चाहिये, स्वय
 गवर्नमेंट ने राय दी है कि आय के कुछ अधिक बन्ने पर टैक्स
 माफ होना चाहिये। आय भी अपनी पहली यज्ञ-स्पीच में
 इसे चीकार किया है। देशी मनी माल पर से महसूल बहुत
 शीघ्र उठालेना चाहिये। इसलिए नहीं कि मनी व्यापार की
 हानि हो रही है विगलनक उस हाल में मिता के सम्बन्ध में
 बने हुए सरकारी कानून से बड़ी हानि हुई है। देशी मनी
 माल के ऊपर से, महसूल दमिष्ठ भागनवासियों की और न्याय
 दृष्टि से देखकर महसूल उठालना चाहिये
 पर भी उस महसूल का भार बढ़ता है

और दुर्भिक्ष से, रुषि और उद्योग की कमी से तथा सिका सम्बन्धी कानून से बहुत तंग हुए हैं और अभी तक वेदम से हों रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट का ध्यान उस व्याख्यान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो मेरे मित्र माततीय मि० मोजेज ने रमर्स के चेम्बर आफ कामर्स के चार्लिकोम्स के अरम्भ पर दिया था। उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी कार्रवाई की जो टीकाटिप्पणी करने हैं, ठोह भाव से करते हैं। उनमें प्रजा और सरकार दोनों ही का विश्वास है। वे अपने व्याख्यान में स्पष्टता और जोर के साथ उस हानि का वर्णन करते हैं जो सरकार के सिकों व सम्बन्ध के कानून से हमारे बढ़ते हुए सत के व्यापार को पहुँची है। वह कहते हैं कि सत के कारबार का कील करोड़ बीघाला ही निकल चला है। प्रायः १५ कारखानों का काम रुक होनेवाला है और उनमें कितने ही नये कारखाने सिर्फ निहार लागत पर नीलाम हो रहे हैं। नये सिक्कों के चलने से हमारे जनसाधारण को जो आर्थिक कष्ट पहुँचा है उसका भी मिस्टर मोजेज ने उल्लेख किया है।

निमरु के महसूल को कम करने के विषय में हम नहीं समझते कि किसी को यह निरालान की आवश्यकता है कि इससे हमारे निर्धन भाग्यी भाइयों को बड़ी भारी हानि पहुँच रही है। सरकार ने स्वयं इस हानि को माना है। पर वर्तमान समय में जब हम तागा को बात उठाने में समर्थ रहती हैं हम आशा है कि यही उन महानुभावा का स्थान उद्भूत करेगा जिनपर भाग्य का शासन निर्भर है लाभदायक होगा।

सन् १८८८ में इस महसूल को बढ़ाते समय सर जेम्स वेस्ट लैन्ड ने जो उस समय अर्थ सचिव थे, सरकार की ओर से कहा था "बड़े सकोच से सरकार इस महसूल को बढ़ाने के लिये बाध्य होती है।" सर जान गोस्ट ने जो उस समय अन्टर सेक्रेटरी के पद पर थे कुछ दिनों के बाद हाउस ऑफ कामन्स सभा में भाषण करते हुए इसी प्रकार रोद प्रकट किया था। लार्ड क्रॉस ने जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सरकार को अपना डिस्पैच भेजते समय ता० १० अप्रैल १८८८ को इस तरह लिखा था—“निमक के महसूल की वृद्धि को छोड़कर मुझे आपकी सरकार की और किसी कार्रवाई पर कुछ नहीं कहना है। मैं इसका विरोध नहीं करता कि आपकी सरकार ने जो वर्तमान स्थिति में इसके बढ़ाने का निश्चय अनिवार्य समझा है वह अनुचित है। पर यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह वृद्धि थोड़े ही समय के लिये होगी और जहां तक सम्भव होगा शीघ्र उसे पहले के निर्बल पर लाने का यत्न किया जायगा।”

श्रीमान् ने उसपर भारत सरकार के निरुद्ध निम्नलिखित आलोचनायें पेश की थीं —

जनता के उस भाग पर जो बहुत ही दरिद्र हैं नये टैक्स का साधारण समय में भी लगाना मेरे लिये दुःख का प्रिय है, विशेष कर जब वह जीवन के आवश्यक पदार्थ पर लगाया जाता है। पर यही और बातों का ध्यान न रखकर जिनके कारण यह उचित और न्यायसंगत है, निमक के महसूल को बहुत थोड़ा राने के सम्बन्ध में - द. १८९९ में सरकार की यह नीति थी

दाम पर जितना चाहें उतना निमक खरीद सकें, उनका यह विश्वास था कि जिस बात में प्रजा का हित है उसी से सरकारी आय की भी वृद्धि सम्भव है, और उचित प्रणाली यह होगी कि निमक की खपत न रुके और उसपर बहुतही थोड़ा महसूल लिया जाय। इसी नीति की असाधारण सफलता हुई है, महसूल के कम होने से और दूसरे कारणों से इसकी खपत बढ़ गई है। इस समय इस मद से सरकारी आय उस समय से कहीं अधिक है जब १८७७ में पहले पहल इसके सुधार हुए थे। मेरा विश्वास है कि यदि महसूल की वृद्धि द्वारा इसकी खपत नहीं रोकी गई तो भविष्यत में इससे आय बढ़ती ही जायगी।

लार्ड क्रॉस ने दो बार इंग्लैण्ड की एक पब्लिक मीटिंग में अपना विचार प्रकट किया, "मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी ही शीघ्र हो नमक के महसूल की बढ़ती रह कर देनी चाहिये"। उसी साल मार्च के महीने में बड़े लाट की सभा में इन्कम टैक्स को उठा देने के प्रस्ताव के सम्वन्ध में व्याख्यान देते हुए सर डेविड बैचर ने इस प्रकार कहा — "मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए यह निन्दा नहीं परन्तु परिहास की बात होगी यदि नमक के ऊपर का महसूल ज्या का त्यों रखा गया और इन्कम टैक्स उठा दिया गया।" सन् १८६० में सर जान गार्ण्ट ने हाउस आफ कॉमन्स में भारतीय बजट पर बोलते हुए कहा था 'निस्सन्देह (नमक का) महसूल उठा देने योग्य है और उठा भी दिया जायगा जैसे ही सरकारी कोष की अवस्था अच्छी हुई।' उसी तरह लार्ड जार्ज हैमिल्टन ने स्वयं हाउस आफ कॉमन्स में भारतीय बजट की आलोचना करते हुए,

नमक वाले महसूल को शीघ्र उठा देने पर जोर दिया था, और कहा था कि इसके बराबर और कोई दूसरा महसूल भारतवासियों को असहनीय नहीं है। चार धार इन विचारों के प्रकट करने पर भी बड़े अचम्बे की बात ही नहीं, बल्कि खेद और निराशा की बात भी है, कि सरकार ने इस वर्तमान अग्रसर पर ऐसे दुःखदायी टेक्स को नहीं उठाया। प्रोफेसर फोर्मेस्ट का कथन है कि मनुष्य-जीवन के लिए नमक बंसाही आवश्यक है जैसे पीने का जल और मांस तैने की हवा और यह उन्हीं की तरह मुरु भी मिलना चाहिये। यहा पर यह उल्लेख के योग्य है कि पिछले १४ साल में नमक का खर्च जेसे वा नेसा हो रहा ह, जितनी आजादी बढी उस हिसाब से भी इसका खर्च नहीं बढा। सन् १८८२ में महसूल के कम हो जाने पर ४ साल के अन्दर पहले से १८ सेकडे अधिक खर्च हो गया पर इधर १४ साल में केवल ६ सेकडा खर्च बढा। इससे स्पष्ट है कि नीरोग रहने के लिए जितना नमक वागा आवश्यक है, औसत रूप से इस देश में उससे बहुत कम खर्च होता है।

श्रीमन्, सरकार के लिये अर्थ-क्रष्ट के समय जेसे नये करों को लेने का अधिकार है वेसे ही बचत के साल में उसमें कमी करना उसका कर्तव्य है। प्रतिवर्ष उच्चत होने से कृपा यत नहीं होती बल्कि इसके विरुद्ध समझदार सरकार को भी बचत के रुपये को फजूल कामों में उडाने का लालच होता है। यह बात सभी देशों में देखी गई है पर विशेष कर भारत में यह बहुत ठीक है क्योंकि और देशों की प्रजा अपनी सरकार से खर्च का हिसाब समझती है पर यहा तो यह बंधेज ही नहीं है।

सत्र तरह से क़िफायत, शासन के प्रत्येक विभाग के खर्चों में कमी करना और इसका भी ध्यान रखना कि काम में अंतर न पड़े, यही राजकोष के प्रबन्ध का मूल सिद्धान्त होना चाहिये जिसमें महसूलों का बोझ जहाँ तक संभव हो हलका रह और देशी उद्योग-धन्धों में कोई रुकावट न आने पाये। हाल में 'सिक्के' के सम्बन्ध में सरकारी नीति जैसी हुई है उस पर इस नियम का पालन करना और भी जरूरी हो गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इस नीति से एक्सचेंज में बड़ी स्थिरता आ गई है और इसने अर्थसचिव को बहुत अन्देशों से भी बचा दिया है, किन्तु अन्त में जब बाजार भाव का निपटारा होगा तो जान पड़ेगा कि देश की बहुसंख्यक कर देने वाली प्रजा पर कैसा असहनीय बोझ आगिरा है। यह ठीक है कि रुपये में टक्काल से निकलने में जो रुकावट हुई उसमें उसका निर्वण्ड गया पर उसी परिमाण और गीघता से बाजार में चीजों का भाव नहीं घटा बढ़ा। यह तो मानी हुई बात थी, क्योंकि भारत जैसे पिन्डू देश में परपरा की नीति का अन्तिम काम करने में समय लगा ही चाहे। दुर्मिर्त के कारण पिछले कई सालों में इस अट्टी बढी के होने में और भी देर होगई पर यह तो निश्चय है कि आज नहीं तो कल रुपये के निर्वण्ड को बलात् बढ़ा देने के कारण सत्र चीजों की कीमत एकएक गिर जायगी। और जब यह होगा तो सरकार जमीन के जोतने वाला से कर के रूप में २० फी. पैसडा अधिक लेने लगेगी और उसी हिसाब से अपने नाकरों को भी अधिक घेता देगी। जन-साधारण के लिये यह बोझ असहनीय हो जायगा। इसमें पहिले ही पिछले कई साल के अकाल में उन्हें चाद्री स रुपया लढवाने में, जब रुपया महंगा हो चला था पर उसका निर्वण्ड

बाजार में नहीं बंढा था बहुत घाटा उठाना पडा था। जब बाजार भाव में बट बढ़ होगी तो एक विचित्र बात यह देखने में आवेगी कि उन साहकारों को जिन्होंने खेतिहरों को रुपया उधार दिया हे सरकार की ओर से उधार दिये हुए धन पर ४० फी सेरुडा इनाम मिल जायगा अर्थात् वे देनदारों से ४० फी सेरुडा अधिक वसूल कर सकेंगे। और यह सरकार की कमी नियत न रही होगी। सिक्के के सम्बन्ध में सरकारी नीति से खेतिहरों को जो हानि पहुच रही हे और पहुचेंगी उसका विचार करते हुए में समझता हूँ सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह यथासाध्य टक्स को कम करके उस क्षति को पूर्ण करे।

श्रीमन् ! टैक्स की दर का निर्धारण और सरकारी आय के प्रबन्ध पर विचार करते समय दो मुख्य बातों का ध्यान होना चाहिये। प्रथम यह कि हम उस देश के सरकारी आय व्यय का विचार कर रहे हैं जिसकी मालगुजारी का एक बडा भाग सेनिक और राजनैतिक ग्रन्थनों के कारण देश के ग़ाहर रत्न होता है पर उसके बदले में कुछ हाथ नहीं आता, दूसरा यह कि हमारे सामने उस देश के राजस्व का प्रश्न है जो लार्ड जार्ज हैमिल्टन के शब्दों में केवल निर्धन अति निर्धन ही नहीं है वरन् जिसकी अधिकांश आयोदी दिनों दिन उन आर्थिक शक्तियों के प्रभाव से जो ब्रिटिश राज्य की बढो लत यहाँ आई हैं गरीब होती जाती है। यह सत्य है कि देश की यह बढ़ती हुई दरिद्रता सरकार की ओर से नहीं स्वीकार की जा रही है इसके विरुद्ध बड़े से बड़े अफसर उसके सुखी होने ही की बात चलाते हैं। पर हम बड़ी प्रिय के साथ इतना कहने का साहस करने हूँ कि हम लोग जो इस कठिन

काल की विपदाओं के बीच में रहते हैं, यह जानते हैं कि भारतवासियों की दशा के विषय में ऐसी वहलानेवाली बातों का कोई प्रमाण नहीं है और इसीलिए हम भारत की उस गिरती और मरती हुई प्रजा को ओर से प्रार्थना करने हैं कि देश के उठते हुए दारिद्र्य को बिना सफ़ोत्र के स्वीकार कर लिया जाये और सरकार की शक्ति इसके दूर करने के उपायों में लगाई जाय। माननीय अर्थसचिव महोदय पारसाल के महसूल की वृद्धि को सुख समृद्धि का चिन्ह समझते हैं। यदि इस बात का विचार न किया जाय कि एक साल के हिसाब से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता तब भी हम पारसाल के हिसाब में कोई ऐसी बात नहीं पाते जिससे माननीय महोदय के मत का समर्थन हो। देशवासियों में अधिकांश जिन की आर्थिक अग्रस्था का यही प्रश्न है चीनी या सूती माल से जो बहुधा बारीक आते हैं कोई सरोकार नहीं रखते। बाहर से जो चाँदी आती है उससे भी उन्हें सम्यग्बन्ध नहीं क्योंकि पारसाल दुर्भिक्ष का समय था इसलिये गरीब आदमियों ने परीदने के बदले जो कुछ अपने पास था उसे भी बेच डाला। मिट्टी के तेल की आमदनी में बढ़ती इस बात की सूचक है कि देशी तेल के स्थान पर इसका व्यवहार बढ़ रहा है और इसका मूल्य कुछ ऐसी अंग्रेजी कम्पनियों की कोशिश है जो तेल का काम करनी हैं, और रेलों का खुलना। कहीं कहीं रसोई के काम में भी लकड़ी की जगह तेल ही जलाया जाता है। इन कारणों से हम समझते हैं कि माननीय महोदय जो पारसाल के महसूल की वृद्धि से नतीजा निकालते हैं वह उचित नहीं है। जमीन के लगान, एम्साइज और स्टाम्प से महसूल की वृद्धि के आधार पर भी भारत की बढ़ती हुई

समृद्धि का अनुमान किया जाता है पर लगान की वृद्धि तो जरूरदस्ती की वृद्धि है। वह इफतरफा इन्तजाम है। इजाफा लगान दीजिये या जमीन से वेदपल होइये और रोजी का जो आयरी सिलसिला है उससे भी हाथ धोइये। आयकारी से महसूल में जो वृद्धि हुई और वह जहां तक मादक वस्तुओं के प्रचार के कारण हुई है यही बतलाती है कि आयकारी विभाग की कार्रवाई से और उन लोगों के प्रति जो एक सौमा तक मादक वस्तुओं के व्यवहार करने के अधिकारी समझे जाते हैं क्याभाव दिखलाने के कारण देश में नशा खोरी बढ़ रही है। ब्रिटिश राज्य के पहले अधिकारियों की ऐसी हस्ती नहीं थी। पर इसका फल क्या है, केवल फलेश, जो देश की उन्नति और समृद्धि के ठीक प्रतिकूल है। मदिरा ऐसी वस्तुओं में नहीं है जिसे अपनी ओकात भर लोग कम बेश खरीदते हों। जय आदमी नशा पीने लगता है तो वह खाना भी छोड़ देता है और उसे अपनी खी बच्चों की सुध भी भूल जाती है। सिर्फ उस विपैली मदिरा की हवस बुझाने की लगी रहती है। उसी भांति स्ट्राम्प से सरकारी आय बढ़ने का अर्थ, मामला मुकदमों की बढ़ती है जो नाफ साफ इस बात का प्रमाण है कि लोग आपस में बहुत लड़ भिड़ रहे हैं, उनके सम्पत्तिशाली होने का प्रमाण यह नहीं। थ्रीमन् वह कर जिसके परिमाण से प्रजा की आर्थिक अवस्था का ठीक ठीक पता चलता है इन्फ्रम टैक्स और नमक का महसूल है। पहले से तो मध्यम और उत्तम श्रेणी वालों की दशा मालूम होती है और पिछले से जनसाधारण की। इधर हम यह देखते हैं कि इन दोनों मर्कों से सरकारी आय कई साल से ज्यों को त्यों रही है। नमक का महसूल

तो उस हिसाब से भी नहीं बढ़ा जितना कि आमादी की बढ़ती से बढ़ना चाहिये था। इससे कहना पड़ता है कि प्रजा दिनों दिन धनी और सुखी नहीं हो रही है।

श्रीमन्, आपने पारसाल की वज्र स्पीच में इस प्रश्न पर विचार किया था और कुछ हिसाब की जाच के बाद आपने यह सम्मति दी थी कि भारतीय आर्थिक अवस्था की प्रवृत्ति इस समय उन्नति की ओर है, अवनति की ओर नहीं। आप की जाच पड़ताल की विधि में बहुत सी त्रुटियाँ थीं जिसे आपने स्पष्ट रूप से माना भी था। श्रीमन् में समझता हूँ, कि प्रति स्त्री पुरुष की औसत आय निकालने से केवल प्रजा की आर्थिक दशा का अंका में अनुमान हो सकता है। इस दृष्टि से हमारी आय का औसत चाहे वह १८) या २०), २७) या ३०) ४० की आदमी पर हो बहुत थोड़ा है और इस बात को प्रमाणित करता है कि हम लोग बड़े निर्धन हैं। पर इन अङ्कों के द्वारा जब यह दिखलाने की कोशिश की जाती है कि हमारी आर्थिक अवस्था उन्नति पर है तो उसमें आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें जो अटकल से मानली गई हैं विश्वास योग्य नहीं हैं। यद्यपि भारत-वासियों की औसत आय का इस प्रकार निश्चय करना कि सच को सतोष हो प्रायः असम्भव है तथापि कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिससे इस समस्या को समझने में हमें सहायता मिल सकती है। और यह प्रमाण साफ साफ बताते हैं कि जनता का अधिकांश, यही नहीं कि कोई उन्नति नहीं कर रहा है उग्न आर्थिक अवस्था में प्रतिदिन हीर होता जाता है। मेरे पास कुछ मानचित्र हैं जिन्हें मैंने बहुत सी सरकारी रिपोर्टों से संकलित किया है जैसे कि (१) 'मनुष्यगणना' का लेखा

(२) जन्म मरण का लेखा (३) नमक के खर्च का हिसाब (४) गत १६ वर्ष में कृषि की उपज का लेखा (५) ब्रिटिश भारत में भूमि का वह क्षेत्रफल जो बोया जाता है (६) और वह जिसमें अच्छी फसल होती है (७) कुछ माल का आयात और निर्यात इनसे यह बातें सिद्ध होती हैं —

(१) जनसंख्या की वृद्धि पिछले दस साल में जितनी हानी चाहिये थी उससे बहुत कम हुई। राज प्रांतों की आबादी वास्तव में घट रही है।

(२) सन् १८८४ ई० से घरायश १००० पीछे मृत्यु संख्या बढ़ती ही जाती है जिससे स्पष्ट है कि ऐसे लोग अब घट रहे हैं जिन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता।

(३) इस देश में नमक का खर्च वैसे ही उस परिमाण तक नहीं पहुँचता जितना कि मनुष्य को निरोग रखने के लिये जरूरी है पर इधर जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उतना भी इसका खर्च नहीं बढ़ा।

(४) गत दस साल में कृषि का कार्य देश भर में बहुत ही मंदा रहा।

(५) पुराने प्रांतों में जोत का क्षेत्रफल घट रहा है।

(६) बढ़िया फसल की जोत भी घटती जाती है।

(७) आयात और निर्यात की भी वही कथा है। अच्छी फसल बढ़ती जाती है। मवेशियों की बहुत सी संख्या मर रही है। फसल के नाश, जानवरों की मरी और दुर्भिक्ष के दिनों में दूसरी प्रकार से कृषकों को जो क्षति पहुँची है वह अनुमान ३०० करोड़ रुपये के कुती गई है। इसके अतिरिक्त इसका भी निर्विवाद प्रमाण मिला है कि भूमि की उर्वरता

भी बहुत शीघ्र घटती जाती है और उसका कारण है निरन्तर भूमि का जोता जाना और उसमें, घाट का न डालना । सर जेम्स केयर्ड ने इसपर बहुत जोर देकर लिखा है —

" बिना अन्तर दिये फसल पर फसल उपजाई जाती है जिनसे क्रमशः यहाँ की भूमि उर्वरता से शून्य हो रही है । "

टाकूर घोषलकर ने भी ऐसी ही राय दी थी । कृषकों का ऋण भी भयानक रूप से बढ़ रहा है । मिस्टर वेन संयुक्त प्रान्त के विषय में लिखते हैं " खेतियों की ऋण सख्या को ग्रीष्म काल के कष्ट का सामना करने के लिये साहूकारों की शरण लेनी पड़ती है । "

बम्बई के विषय में मैकडानल कमीशन ने इस प्रकार लिखा था " कम से कम बम्बई हाते के चौथाई काश्तकारों के हाथ से जमीन निकल गई है । अनुमान से भी कम लोग ऋण से मुक्त हैं और शेष रोतिहर थोड़े बहुत ऋणी हैं । "

इसी तरह में ममभूता हू, और प्रमाण मिलता है कि मध्य प्रदेश और पंजाब का भी यही हाल है ।

इन्हीं बातों को जब एक साथ ध्यान में लाते हैं तो यह निश्चास हुए बिना नहीं रहता कि भारत के सर्वसाधारण का आर्थिक दशा बराबर बिगड़ रही है । मुझे इसबात का बड़ा शोक है कि ऐसी शोचनीय दशा सुस्तार भर के आधुनिक इतिहास में कहीं नहीं मिलती । येही हमारे किसान चाहे उन जिस तरह देखिये, अन्य किसी देशवालों से मेहनत, साधन और किरायतशारी तथा दुःखों के सहन करनेमें कम नहीं हैं । उन्होंने ५० साल से ऊपर निर्विघ्न शान्ति का, उपभोग किया है पर इन्हीं अवधि के अन्त में पहले से भी उनकी दुरी दशा

हो रही है। श्रीमन्, मैं कहता हूँ, ऐसी दुःसम्पद और आश्चर्यजनक घटना पर सरकार को शीघ्र ही विचार करना चाहिये और मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि अब इस बात को सरबार किसी तरह नहीं टाल सकेगी। यह कहा गया है कि यदि नमूने के तौर पर कुछ गावों की दशा का अनुसन्धान किया जाय तो इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायें और मिथ्या धारणाएँ दूर हो जायेंगी। पर सरकार की ओर से उत्तर मिलता है कि ऐसे अनुसन्धानों से कोई लाभ नहीं है क्योंकि पहिले वे किये जा चुके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इसकी बहुत सी जाच हो चुकी है और उसमें बहुत सी काम की बातों का पता मिला है पर वह सब दया दी गई हैं, प्रन्ट नहीं की गई। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। विशेष कर जब यह आर्थिक दशा की बातें हैं और उनकी छानबीन में सरकार को गैर सरकारी जिज्ञासुओं से सहकारिता स्वीकार करनी चाहिये। मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि यदि सरकार की ओर से सन् १८८२ की क्रोमर साहय वाली तहकीकात, १८८७-८८ को उफरिम साहय वाली तहकीकात और अन्त में १८९१-९२ वाली गुप्त तहकीकात के कागजात प्रकाशित किये जायें तो सर्वसाधारण को बड़ी सहायता मिले। वही हाल है गावों की निम्न थोड़ी की स्थिति के परिचायक अकों के उम लेखों का जो १८९८ के अकाल कमीशन के लिए प्रान्तिक सरकार ने प्रस्तुत किया था। तथा उस लेख का जिसकी चर्चा परसाल आपने बजट स्पीच में की थी और जो कहा गया है कि १८९८ के अकाल कमीशन के लिए तैयार हुआ था, साथ ही उस परिशिष्ट का जो १८९१ के अकाल कमीशन की रिपोर्ट में लगा था तथा रूपकों के ऋण सम्बन्धी

उस लेख का भी जिसका उल्लेख पत्राव केलेफिट्टनेन्ट गवर्नर ने पत्राव लैंड एलिनिणशन बिलजाली स्पीच में किया था। य सत्र सरकारी कागजात अकारण ही सर्वसाधारण से छिपाकर रखे गये हैं। मैं समझता हू कि वे देश की आर्थिक अवस्था का सच्चा परिचय पाने में आपको बड़ी सहायता पहुँचायेंगे यदि इन कागजात के प्रकाशन का प्रयत्न करदेंगे।

श्रीमन् ! मैंने अभी तक यही दिखलाने का यत्न किया है कि (१) पिछले ४ साल की वचत की बड़ी रकम केवल सिन्क विभाग की वचत है, (२) इस देश में बहुत अधिक कर लिया जाता है और उन्ने कम करना चाहिये, (३) यह कि भारतवर्ष न केवल एक बड़ा निर्धन देश है वरन् इसकी दरिद्रता परावर बढ़ रही है और इसलिये इसके राजकोष के प्रबन्ध में इन मुख्य बात का सदा ध्यान रखना चाहिये। प्रजावत्सल लार्ड रिपन के आधिपत्य के बाद यहाँ के राजकोष का कुछ ऐसा ढग रहा है जिससे मालूम होता है कि शासन में भारतवासियों का हित नहीं, औरों का हित देखा जाता है। जैसे, हमारे अल्प कोष से युद्ध द्वारा ब्रिटिश राज्य का प्रसार किया गया है पर उससे भारतवासियों का क्या लाभ हुआ ? इङ्गलिस्तान के सोदागरा के लिए यहाँ तक रेल खोली गई कि आजतक उतनी खुती ही नहीं थीं। कई बार तो अर्थसचिव ने प्रतिवाद भी किया, पर सुनता कौन है। यह ऐसी नीति थी जिससे अन्य कैसा ही लाभ पों न हो पर कृषि के अतिरिक्त देशी उद्योग धन्धे भी नष्ट होगये और सब के सब कृषि के आश्रित हो गये, यह रेल का प्रसार अभी तक जारी है पर दूसरी ओर जिससे सारे देश को आशा है प्रायः उपेक्षा दिखलाई गई है,

और देखिये बड़े अफसरों के हित की बात सब से पहले आती है। अनकवेनेन्टेड सिविलियनो को पेन्शन लेते समय एक रुपये में १ शिलिंग ६ पेन्स तक लेने की रियायत है। यूरोपियन अफसरों को बड़े का अलाउन्स अलग मिलता है। सेना का खर्च इस बीच में ६५ करोड़ से भी बढ़ गया है और यूरोपियन सिपाहियों की वेतन वृद्धि होने के कारण ११ करोड़ और बढ़ेगा, उधर "होमचार्ज" ३ मिलिअन पेन्ड से अलग बढ़ गया है, यह सब हुआ पर इस अंतर में शिक्षा का खर्च मालगुजारी से केवल २० लाख से बढ़ा और दूसरे आंतरिक सुधार घेसे के घेसे पड़े रहे। कुरको की दिना दिन अधिक रुमी होने की बात हाल में बहुत सुनने में आती है पर कोई ऐसा उपाय जिससे उनको सहारा मिले और जिसके लिए आवश्यकतानुसार सरकार अपनी तरफ से कुछ खर्च करने का तैयार हो नहीं किया जा रहा है। हर्ष की बात है कि पिछले ३ वर्षों में सरकार की नीति में कुछ आशाजनक परिवर्तन हो चला है। श्रीमान ने सरहद्द की स्थिति बहुत अच्छी कर दी है और इस पक्ष में यह और भी उल्लेख योग्य है कि आपके इस देश में इस उच्च पद पर आरुढ़ होने के बहुत पूर्ण आपके एक भाषण से यह प्रतीत हुआ था कि आप विजय द्वारा ब्रिटिश राज्य की सीमा बढ़ानेवालों के दल में हैं। हाल में लगान के प्रश्न पर जो सरकारी रिजोल्यूशन निकला है उसकी विशदप्रस्तुत बातों से हमारा चाहे जितना मनभेद हो पर हम इतना जरूर कहेंगे कि उससे प्रजा की ओर सरकार की गहरी सहायुभूति अवश्य प्रकट होती है और यदि उस उदार नीति का उचित रूपसे पालन किया गया जो प्रान्तिन गवर्नमेन्ट के अनुसरण करने के लिए निर्माण

हुई है तो हमारे लिए प्रजा उसकी बड़ी अनुग्रहीत होगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बम्बई हातावालों के उलाहने थे उसकी सत्यता स्वयं सरकार ने मान ली है जैसे कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि गुजरात में लगान का परिमाण बहुत ज्यादा है। दूसरे बन्दोबस्त में नियम के विरुद्ध बहुत गड़बटी हुई है यह भी मान लिया गया है। इसमें यह बड़े जोर के साथ लिखा गया है कि जहाँ किसी कारण से कृषि की दशा खराब हो गई वहाँ सरकारी लगान में कमी हो जानी चाहिये जिसमें किसानों का क्लेश हलका हो पर इसका प्रमाण मिलता है कि कितनी ही अवस्था में लोगों का क्लेश सरकारी लगान के पूरा पूरा भरने में बहुत बढ़ गया था और इस पर भी उसके हिस्से में कमी नहीं की गई। जो हो अब लगान की वसूली में अधिक दम देने की आशा दिलाई गई है ताकि फसल में कमी वेशी और गेतिहर्गों की स्थिति के अनुसार ही वह वसूल किया जाय। इस स्पष्ट स्वीकृति और उदार आश्वासन के पश्चात् यह स्मरण करना कि पारसाल बम्बई सरकार के रेयन्यू मेम्बर ने अपने भाषण में कहा था कि इकरारनामा आखिर एक रारनामा ही है और चाहे सरकार अपनी ओर से दुखी प्रजा की सहायता करे परन्तु देने के साथ उसे मँगने का अधिकार नहीं है, बड़ा रोचक मालूम होता है। नहरों के विषय में यह निश्चित है कि श्रीमान् उचित रूप से शीघ्र ही हमकी प्रधानता पर ध्यान देंगे। श्रीमान् के सन्मुख पुलिस सुधार, प्रान्तिक राजधन प्रबन्ध, कृषि सम्बन्धी एक, आरम्भिक, उद्योग, शिल्प और कृषि शिक्षा के प्रश्न भी हैं उन पर पूर्ण रूप से आप विचार कर रहे हैं। सभी ओर कुछ पैसे चिह्न

दिखाई पड़ते हैं जिनमें आशा होती है कि १६ वर्ष के बाद सरकारी कौन्सिल में फिर भी आन्तरिक सुधार का समय आयेगा, उसी समय चित में आशा और निराशाओं का मिश्रित आग्रेग भी उत्पन्न होता है क्योंकि आपके शासन के ३ साल बीत चुके अब शेष दो साल में कौन कह सकता है कि क्या होगा और क्या न होगा। धोमा आज तक इस देश में ऐसा आर्थिक कष्ट कभी नहीं देखा गया जंसा वर्तमान समय में उपस्थित है, इसलिये अधूड़े उपायों से काम चलाने का नहां है। भारतीय वाइसराय के पटल पर केवल "कार्यकुशलता" का आदर्श नहीं धरन् "निर्भीक और उदार राजनीतिनिपुणता" लिखा होगा चाहिये। यदि एक शताब्दी के भीतर प्रशिया अपनी कुरी की आवादी को घली और सुखी किमानों के रूप में परिणत कर सका तो क्या अङ्गरेज राजनीतिज्ञ भारत के स्वतन्त्र रूपकों को दासवृत्ति की अधोगति प्राप्त करने देंगे। यदि पुराने प्रान्तों में जहा वे शर्तें पूरी होगई हैं जिनका वर्णन सर स्ट्रैफोर्ड नार्थकोट साहब ने अपने डिस्पैच में किया है तो प्रजा का इसमें बड़ा कल्याण हो। टाइम्स आफ इन्डिया के एक मन्त्राद्वारा ने एक ऐसी लेखमाला में जिसकी ओर सब का ध्यान आकृष्ट हुआ है बड़े जोर से साथ उन अनर्थों को दिखलाया है जो धार धार के बन्दोबस्त से हुआ करते हैं उसमें यह भी लिखा है कि भूमि में कृषक जो सुधार करते हैं उसपर भी नियमविरुद्ध टेन्स लगता है, ऐसी भूमि पर लगान लिया जाता है जिसमें लगान की बिलकुल गुजाइश नहीं और यह भी कि कृषकों की दशा बराबर बिगड़ती ही जानी है। रेतवारी प्रदेशों में ब्रह्मी बन्दोबस्त करने की चर्चा चलाने में कम से कम

स्तान में मिल भी गया तो जाह्न का आक्रमण रोकने के लिए भी पूरी है। पर उस समय रशिया के साथ मुठभेड़ होने का इतना भय था कि उसके सामने कोई किमी की सुनता ही नहीं था और सेना के बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया गया उसके अनुसार वह बढ़ा दी गई। यह सेना की वृद्धि अकेले भारत ही में नहीं, ब्रिटिश राज्य के और भागों में भी हुई और मिस्टर ग्लडस्टन ने उसके लिये (Vote of Credit) लिया। पर आज्ञाचर्य की बात तो यह है कि और जगह भय के शान्त होते ही सेना को सख्ता घटा दी गई पर भारत में वह ज्यों की त्यों बनी रही। फल इसका यह हुआ कि सर आक्लैण्ड कालविन और उनके साथियों ने जो भविष्यदवाणी की थी वह सच निकली और साल लगते लगते अपर वर्मा पर चढ़ाई की गई, देश जीत लिया गया और वह ब्रिटिश भारत में मिला भी लिया गया। सर इस बात का दूसरा प्रमाण कि फौज की वृद्धि में भारत का कोई प्रयोजन न था यह है कि पिछले दो सालों में २०,००० से ऊपर सैनिक भारत के बाहर इम्पीरियल गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और यद्यपि इन दो सालों के बीच में एक में प्रचण्ड दुर्भिक्ष पड़ा पर देश में अन्न की शान्ति का राज्य रहा। मुझे याद है इस कान्सिल की पहिली ही सत्र में आपने उतलाया था कि जब तक आप भारत के अग्रिष्ठाता है सेना में कमी होने की कोई आशा नहीं है। अतः यदि इस समय ३ साल पहले के विचार में परिवर्तन न हुआ हो तब भी मैं इतना कहने का साहस करता हूँ कि चाहे भारत की स्थायी सेना में कमी न हो पर भारतवासियों की ओर से उस सेना के स्वर्च में विफायन होना चाहिये। सेना की कितनी सख्या भारत में होनी चाहिये यह गूढ़ इम्पीरियल नीति

की बात है उसमें हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। पर इतना कहने का हम लोगों को दावा है कि यदि भारत की आवश्यकता से यहाँ अधिक सेना है जैसा अभी मने दिखलाया तो न्याय की बात यह है कि उसके व्यय का एक अंश इम्पीरियल गवर्नमेंट भी सहन करे। यदि अपना विचार सफीर्ण करके थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि भारत में ब्रिटिश राज्य की रक्षा के लिये इस सेना की जरूरत है तब भी हम कह सकते हैं कि इसमें इंग्लैंड की उतनी ही हित की बात है जितनी हम लोगों की, इसलिये उचित है कि उसके खर्च का एक हिस्सा इंग्लैंड बरदाश्त करे। यदि ऐसा किया जाय, यदि भारतीय, सरकारी नोकरियों पर अधिक नियुक्त किये जायें, तो खास कर विशेष विभाग में सरकार टेक्स भी कम कर सकेगी और शिक्षा के प्रसार, आयोगिक उन्नति (जापानी सरकार के ढंग पर) और दूसरे सुधार के लिये उन निकाल सकेगी। तभी भारत का राजधन हट आगरा पर रह सकता है और तभी भारत ऐसे निर्भर देश के राजस्व का ठीक उपयोग हो सकता है। श्रीमन् ! आपने उम्न दिन अपने भाषण में उड़ी आत्मविश्वास के साथ इस बात की आवश्यकता दिखालाई थी कि अब भारतवासियों का चाहिये कि वे अपने सुधार विचारों को और औरजा के साथ साथ अब सार ब्रिटिश साम्राज्य के लिये उस नई संयोगात्मक देशभक्ति का स्थान दें जिसकी इस सुअवसर पर जरूरत है। यह एक ऐसी आकांक्षा है जो हम लोगों में भी बहुतेरों को ग्रिप्त है। पर इसके पूर्ण होने के पहले दोनों पक्षों को अपना हित उभर कुटुं एक कर देना पड़ेगा और भारतवासियों को ब्रिटिश राज्य में इस समय

अंग्रेज जाति जग करपना से काम ले और मन ही मन अपने को हम लोगो के रयान में मान ले तब वह हम लोगो के मनोभाव का अनुमान कर सकेगी। कहा जाता है कि भारतवासियों के प्रति अन्यत्र दयाभाव उड़ा काम करता है। यह बिल्कुल सत्य है। मला लार्ड रिपन के समय में वही समाचारपत्रों की राजभक्ति में राई मन्देह कर सकता था ? सामयिक पत्रों में उस समय बहुत कुछ व्यवहार किये जाते थे जिन पर भारतवासियों की ओर से नहीं। श्रीमन्, आश्चर्यकता है इस बात की कि हम यह समझते लगें कि हमारा शासन वास्तव में राष्ट्रीय शासन है चाहे उसका गहरी रूप ऐसा ही हो—ऐसा शासन जो सब बातों के ऊपर प्रजा का कल्याण दृष्टता है, जो भारतवासियों के दुःखों में हाथ लाज्जित होत पर वैसा ही काय करना हो माना वह लाज्जित अंगरेजों ही पर लगाई गई हो और जो सब तरह भारतवासियों की आर्थिक और नतिफ मलाई के लिए बल करता है वह राजनीतिज्ञ जो भारतवासियों के बीच के भाव उत्पन्न करेगा वह इस देश की उड़ी उच्छृंखला करा करेगा और मदा के लिए हम लोगो के अनुराग का भाजन होगा। नहीं नहीं वह अपने देश की भी सच्ची सेवा कर सकेगा। मकीर्ण साम्राज्य मात्र सब यह नहीं समझता है कि नारा ससार एक ही जाति के लिए बना है और दूसरी जितनी जातियाँ हैं वह उसके चरणों में रहने के लिए ही जन्मी है परन्तु उस श्रेष्ठ साम्राज्य भाव से वह ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत सभी मनुष्यों को इस राज्य में उपकार और सम्मान में सम्मिलित होने का अवसर देता है। श्रीमन् मैं यह सब बातें आपके सम्मुख इस विचार से नहीं कहती कि आप भारत के राजमराय ह वरन् जैसा सब लोग समझते हैं,

आप अपने देश में लोटने पर इसमें भी अधिक उत्तरदायित्व और प्रभुत्व लाभ करेंगे। यदि हम लोगों की यह आशा फलीभूत हुई तो इस देश की शासन नीति का आप पहले से अधिक मोड़ करेंगे जैसा हम लोगों की उम्मीद इच्छा है। उसी आशा से मैंने आज कुछ कहा है और मुझे विश्वास है कि यद्यपि मैं अपने कथन में कुछ असामान्य स्पष्टता का व्यवहार करने की दृष्टता की है तथापि यदि मेरी कुछ उद्दिष्ट राजभक्ति का सब से उत्तम लक्षण है, तो इसके लिए आप क्षमा करेंगे।

१९०६ का बजट ।

नमक का टैक्स ।

श्रीमान, आज दूसरी बार माननीय मिस्टर रेकर ने कोसिल के सामने बजट पेश किया है। उस सीमा का विचार करते हुए जिसके भीतर वह बजट तैयार कर सकते थे यह बड़ा मनोहर और सन्तोषप्रद चिह्न है। आय व्यय के चिह्न में प्रसादगुण के लिए इसे बहुत उच्च स्थान मिलेगा। माननीय महोदय ने नमक की खपत के ऊपर इस टैक्स में कमी के प्रभाव के सम्बन्ध में जो कुत्तु लिया है उसे पढ़कर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। बहुत दिन नहीं हुए। एक समय था जब कोसिल में यह कहने की रीति चल पड़ी थी कि जनता के ऊपर नमक का महसूल बहुत ही कम है और इससे उसकी खपत में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। यदि किसी समय सरकार इस महसूल को फिर से बढ़ाने के लिए विवश हुई तो मुझे आशा है कि उस काल के अर्थसचिव मेरे माननीय मित्र की सलाह को याद करेंगे जो उन्होंने इसको बढ़ाने के फल के विषय में दी है और फिर कोई इस बात का खगडन करने का साहस न करेगा कि नमक जैसी आवश्यक आग्न प्रभु के सम्बन्ध में उपयुक्त नीति यही है कि बढ़ने हुए सर्व एक क्रम में थोड़े परिमाण से टैक्स लेकर आय बढ़ाये।

वर्तमान समय में भी महसूल का परिमाण असली लगान से प्रति सैकड़ा १६०० गुणा अधिक है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय महोदय को अपने शासन काल में ही इसमें और भी कमी करने का दूसरा अवकाश मिलेगा जिससे सारे भारत में एक ही महसूल रमा के बराबर अर्थात् मन पीछे हो जायगा। महसूल की इस कमी के पहले भारत में नमक का खर्च प्रति मनुष्य ५ सेर था। अब वह ५½ सेर हो गया है पर अब भी यह रमा के खर्च से जहा यह प्रति मनुष्य ८½ सेर है। बहुत कम है।

भूमि, भूमि के ऊपर से छोटे छोटे करों के उठा देने और डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड के बोय से प्रान्ति और प्रयोजनाओं के लिए उन लेने की प्रथा को रद्द कर देने का बहुत अच्छा फल होगा। मैं उस नीति को उड़े सन्तोष के साथ देखता हूँ जिसके अनुसार यह सब सुधार हो रहे हैं। मुझे खेद इतना ही है कि अम्बई प्रान्त उस निवृत्ति से कोई लाभ नहीं उठा सकता जो अभी प्रदान की गई है और यदि अभी समय है तो दो एक मणसी सरतें उताऊगा जिनसे माननीय अर्थ सचिव हम लोगों की उम्मीद आगरा पर सहायता कर सकते हैं जिसपर उन्होंने दूसरे प्रान्तों को निवृत्ति दी है। एक तो उस क्षति के विषय में रहना है जो हमारे लोकल बोर्ड को सरकार की ओर से लगान की मुअत्तली या मुआफी होने पर सहनी पड़ती है। इन बोर्ड्स की आय का प्रधान अंश भूमि के ऊपर एक आने के कर से आता है इसलिए दुर्भिक्ष के कारण जब सरकार उस लगान का कोई अंश कुछ दिनों के लिए छोड़ देती है या बिल्कुल माफ कर देती है तो आने वाला कर जो उसके साथ ही चुकाया जाता

आप ही आप गन्त हो जाना है। गवर्नमेन्ट ने हिमाय लगाया है कि इस साल लगान की वह रकम जो कुछ दिना के लिए रोक दी जायगी या मुआफ कर दी जायगी, ५० लाख रु० ठहरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोकल बोर्ड की आय में इस साल ३ लाख के ऊपर घाटा होगा। एक आने के कर से उम्मीद होने भर में ३० लाख की आमदनी होती है। जिसमें से ३ लाख की कमी कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा यह घाटा भार होने के ऊपर बढ़ा हुआ नहीं है, यह खास खास जिलों का उठाना पड़ेगा। इसमें यह अभिप्राय निकला कि उन जिलों में बोर्ड के पास बहुत जरूरी कामों के लिए भी पसा न होगा। मैं इसलिए प्रस्ताव करता हूँ कि प्रान्तिक आय से जो ढान बोर्ड्स को दिया जाता है वह ३ लाख से बढ़ा दिया जाय या जितना भी एक आने का कर प्रान्तिक मालगुजारी के साथ जोड़ दिया गया हो या माफ कर दिया गया हो उसका बदले में प्रान्तिक गवर्नमेन्ट चाहे तो भारत सरकार में हरजाना भी ले सकती है। मैं समझता हूँ, पंजाब में चाल पर काम होता है। वहाँ बोर्ड अपना कर पूरा पूरा वसूल कर लेती है चाहे प्रान्तिक सरकार ट्यक्को के साथ कैसी ही रियायत करे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बोर्ड्स के साथ भी वैसा ही उपाय किया जाय। माननीय अर्थसचिव के लिए बोर्ड्स की रक्षा करने का दूसरा उपाय यह है कि वे बोर्ड्स को अकालपीडितों की सहायता करने का "फेरीन कोट" के अन्तर्गत जो भाग है उससे मुक्त कर दें। बोर्ड के नियम में अकालपीडितों की रक्षा सब से पहले बोर्ड्स को अपने उन से करना फतव्व है और उसके पीछे प्रान्तिक या भारत सरकार पर इसका उत्तरदायित्व है। हम जानते हैं कि

इन बोर्ड्स के पास उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी, यथोचित धन नहीं है जिनके वास्ते यह संस्था बनी है जैसे कि शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्यपालन और सड़क आदि । अब इनके अलावा उनके ऊपर अकालपीडितों की सहायता का कठिन भार डालना क्या है मानो उन्हें किसी भी उपयोगी काम के करने में असमर्थ कर देना है । पिछले दस सालों में बराबर एक से एक दुर्दिन आते रहे हैं, ४ बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, स्थानीय संस्थाओं के क्लेश प्लेग के प्रकोप और उसके निवारण के उपाय करने में और भी बढ़ गये हैं, इसके परिणाम से बम्बई प्रान्त भर के बोर्ड्स की वह दुर्दशा हो गई कि उनका दिवाला ही निकला समझिये । जो साहाय्य में माग रहा ॥ यह यद्यपि बहुत थोड़ा है पर इस समय वह अवश्य बहुत उपयोगी ठहरेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे माननीय महोदय पूर्व में स्थानीय संस्थाओं के साथ सहानुभूति रखते आये हैं वैसे ही इस बार भी वह साहाय्य देना आवश्यक और न्याय संगत समझेंगे ।

पूर्व इसके कि मैं उन बड़े प्रश्नों की चर्चा करूँ जिस पर आज मुझे कुछ विशेष ध्यान है मैं दो प्रस्ताव करना चाहता ॥ और अर्थसचिव से एक बात भी पूछना चाहता हूँ । मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि आप व्यव के चिट्ठे में, जैसा वह तालिका न० १ में दिया होता है, रेल और नहर के शीर्ष के नीचे आय-व्यय के चि-

कि २६ और २७ मिलियन के बड़े बड़े अंक लिखने की जगह यदि सरकारी चिट्ठे में आय के खाने में केवल २½ मिलियन का रकम लिखी जाय और दूसरी ओर यह अलग दिखलाया जाय कि कुल आमदनी खर्च इतना हुआ तो उससे सरकार की असली आय और व्यय का अच्छा अन्दाजा मिल सकता है। रेल और नहर के ऊपर का खर्च व्यापारिक आधार पर उधार ली हुई पूँजी से होता है। उसमें जितना ही ज्यादा रपया लगाया जायेगा, उससे आमदनी भी बढ़ती जायगी। वास्तव में वह अधिक पूँजी लगाने तथा और और कारणों से इधर बहुत बढ़ रही है यहाँ तक कि दस साल में करीब करीब दूनी हो गई है और जहाँ १८६६-६७ में वह १५½ मिलियन थी, आज २६ मिलियन हो गई है, पर उससे देश की आय में वैसी कुछ वृद्धि नहीं होती। उससे जो नकद मुनाफा होता है वही सरकार का लाभ है। जापान में जहाँ सब बातें लोग वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, सरकारी रेल के हिसाब में जैसा मैंने बतलाया है उसी रीति से काम करते हैं। वहाँ के आय व्यय के चिट्ठे में आय के खाने में केवल मुनाफा दिखलाते हैं, पर हमारे यहाँ जैसा लिखने का रिवाज है उससे बहुत भ्रम होता है यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें बहुत कुछ जानने का सुभीता है घोखे में आ गये हैं। इसी तरह दो साल हुए भारतीय सरकार के सैनिक सदस्य सर फ्रेडमण्ड एलिस ने एक विलकुल अनहोनी बान उड़ाई कि यद्यपि हाल में सेना का खर्च बढ़ गया है पर वह उस हिसाब से नहीं बढ़ा है जिससे कि भारत सरकार की आय बढ़ी है और बढ़ रही है। और जब मैंने उनका ध्यान इस भूल का ओर आकृष्ट किया तो वह रेल और नहर की वृद्धि आय को सरकार की आय में शामिल करते हुए बहस करने लगे

और अपनी बात से जरा भी न टले। वे बराबर कहते गये कि कोई कारण नहीं कि मैं उन अंकों पर विश्वास न करूँ जो मैंने पढ़े हैं।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि लोकल बोर्ड का जमा खर्च जो ग्रान्तिक रेड्स के नाम के नीचे दिया रहता है, भारत सरकार के हिस्से में लुप्त कर दिया जाय। यह बहुत छोटी रकम होती है, साल में केवल २ मिलियन पर इससे बड़ी गड़बड़ी मचती है। शिक्षा ही को लीजिये। स्टेटमेन्ट न० १० के देखने से यह मालूम पड़ता है कि शिक्षा में २ मिलियन खर्च होता है पर अमल में वह होता है १ मिलियन, बाकी लोकल बोर्ड का खर्च सरकारी हिसाब में मिला दिया जाता है, यह ठीक है कि ग्रान्तिक और लोकल का शीर्ष भ्रम दूर करने के लिए दिया होता है, पर उसमें फिर एक भ्रम होता है क्योंकि लोकल से यूनिर्सिटी का भी मतलब निकलता है, पर भारत सरकार के हिसाब में केवल बोर्ड का जमा खर्च होता है, यूनिर्सिटी लिटी का नहीं। मुझे विश्वास है कि माननीय महोदय यह माध्याम पर आवश्यक सुधार कर देंगे। यदि मेरे प्रस्ताव स्वीकृत हो गये तो हम लोगों की असली सरकारी आय ५२ मिलियन उतरेगी, ८७ मिलियन नहीं जैसा कि तालिका न० १ से जान पड़ता है। और एक बात जो मुझे दर्यालू लगती है वह गोल्ट रिजर्व फण्ड तथा सिके विभाग की बचत के विषय में है। लार्ड कर्जन ने दो साल हुए यह कहा था कि "यह फण्ड तब तक जमा होता जायगा जब तक वह १० मिलियन पौन्ड न हो जायगा। बस इस रकम से हम लोगों का काम चल

जायगा और उससे एक्सचेज में पूरी स्थिरता आजायगी। फण्ड इस सीमा तक कमी का पटुच गया और वह १२ मिलियन पौन्ड से अधिक जा लगा है मैं समझता हूँ कि मातनीय अर्थ मन्त्रि के लिए उचित है कि वे हम लोगों को अब यह बता दें कि आगे चलकर सिद्धि की वचत से क्या किया जायगा। मिथ प्याज के हिसाब से वह फण्ड जमा होता जायगा, हम समझते हैं जहाँ वह है वहीं उसे छोड़ देना चाहिये। उसपर ६ माल के अन्दर प्रति वर्ष औसत २ मिलियन की जो आय हुई है उसे अब से कृषकों को कर्ज देकर साहूकारों के उपद्रव से उनकी रक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार उससे कासाल खरीदने की अपेक्षा अधिक आय होगी। इस नीति के अनुसरण से उन लोगों को भी कुछ सहारा होगा जिन्हें सिका सम्यन्धी कानून से जोर का धक्का पहुँचा है। यदि वह जनता के अर्थलाभ के कामों में भी लगाया जाय जैसे कि रेल नहर इत्यादि। और उसी कदर सरकार कर्ज लेना घट कर दे तो वह कासोल में रुपया लगाने से कहीं अच्छी व्यवस्था हो। अपना रुपया २॥ सैकड़े सूद पर लगाना और जरूरत पड़ने पर दूसरों से ३॥ सैकड़े रुपया कर्ज लेना इस दोषपूर्ण नीति का कोई प्रतिकार नहीं है।

श्रीमन्, हमारा आर्थिक प्रबन्ध शासन की कई महत्वपूर्ण नीतियों पर निर्भर है और जब तक उनमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता तब तक सरकारी मालगुजारी का चेमा प्रयोग जिससे प्रजा का पूरा हित हो असम्भव है। ऐसे प्रश्नों में सबसे प्रधान पर साथ ही कठिन और नाजुक, सेना का प्रश्न है। श्रीमन्, मुझे भय है कि सरकार की फाजी

नीति का प्रतिपाद चाहे हमारे लिए यह अरुणरोदन ही क्यों न हो, हमें जब अवसर मिलेगा करते जायेंगे क्योंकि-यदि इसका समुचित समाधान हो गया तो उसके साथ ही हमारे सभी बड़े हित साधन हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई समय ऐसा हो सकता था कि जब हमारी बात सुनी जाती तो यह घतमान समय है। अभी एशिया छोड़ की राजनीति की स्थिति में एक गहन परिवर्तन हो गया है। जापान की विजय से मध्य और पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित हो गई है। सदा के लिए यूरोपियों का चीनियों पर धाधा रुक गया है। इस की शक्ति छिन्न हो गई है अब एशिया से उनकी माया उठ गई। उसके ऊपर इतनी विपत्ति है कि उसे दूसरों की विपत्ति में डालने की बहुत दिनों तक सुध न होगी। इस प्रकार यह दुःख के बादल जो ३० वर्ष से ऊपर हमारे उत्तर पश्चिम सरहद्द पर महरा रहे थे, टल गये और जहाँ तक मनुष्य अपनी बुद्धि से अटकल लगा सकता है हम लोगों के जीवनकाल में वे फिर से आनेवाले नहीं हैं। अमेज और जापानियों के बीच जो सन्धि हुई है उसके विषय में चाहे भारतवासियों का कैसा ही विचार हो, एशिया की शान्ति को यह सन्धि यदि उसमें कोई सार है तो और भी सुदृढ़ करती है। श्रीमन्, निश्चय, यही समय है जब आपके द्वारा सेना-उपय के उस असहनीय बोझ को जिसे भारतवासी इतने साल से वहन करते आते हैं हलका होने की आशा करने का अधिकार है। इस विपत्ति निवारण में पहली बात यह हो सकती है कि आप उस सुधार स्कीम पर जिसे अभी जंगी-लाट साहब ने प्रस्तुत किया है और जिसमें १० मिलियन पाउंड के करीब खर्च बैठनेवाला है कोई असली कार्रवाई न करें। यह व्यवस्था

रुम जापान की लड़ाई के आरम्भ में बननी शुरू हुई थी और १९०३ में इसकी मजूरी हुई थी जब युद्ध के परिणाम के विषय में केवल मशय ही नहीं था पर आसार जापान के विरुद्ध थे और जब रुसियों के काबुल की ओर चढ़ आने का बहुत भय था। अब बात बिलकुल बदल गई और न पश्चिमी 'समूह' अब आपद् का स्थल ही रहा तो अब क्या जख्जरत है कि इतनी बड़ी खर्च में डालनेवाली स्कीम के ऊपर, जिससे देश की सारी फौज घात की घात में समूह पर एकत्रित हो जाय काम किया जाये। इस समय जितने मिलियन पाउंड उसमें खर्च होंगे उन्ही तक हद नहीं है याद में भी उसपर संदा के लिए खर्च होता रहेगा। इस समय हम लोगों को नही मालूम कि यह खर्च कितना होगा पर अर्थसचिव ने पागसाल ही कह दिया था कि खर्च बहुत पड़ेगा। वह खर्च जो बराबर साल साल होता रहेगा, ५ साल के बाद जान पड़ेगा। तब तक इस स्कीम के अनुसार काम करने के लिए २ मिलियन रुपया चाहिये। श्रीमन्, मैं विनयपूर्वक ऐसी व्यवस्था पर ऐसे समय में कार्य करने के विरुद्ध प्रतिवाद करता हू क्योंकि इसमें इतने धन और शक्ति का व्यय होगा जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है और जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। भारतसचिव ने पार्लामेन्ट में एक प्रश्न के उत्तर में उस दिन कहा था कि इस पर विशेष विचार हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे मुलतवी करने ही का वह निर्णय करेंगे, कम से कम उस समय तक जब तक कि समूह पर कोई नया झगडा नहीं खड़ा होता। यदि सरकार ने हाल की घटनाओं पर ध्यान न देकर उस व्यवस्था पर कार्य करने की ठानी तो मैं इस पर जोर दूंगा कि यह खर्च ऋण लेकर चलाया जावे।

श्रीमन्, गत ८ साल में सरकार ने रेल बनवाने में ३५ करोड़ की सरकारी बचत खर्च कर दी और कर्ज लिया सो भलावा । वर्तमान साल की मालगुजारी का वह भाग जो ऐसे व्यापारिक कामों में लगाया जाता है जिससे कुछ मुनाफा होता है, उत्पादक ऋण में शामिल हो जाता है और इसी लिए उतने ही से वह ऋण कम कर दिया जाता है जिसके ऊपर सरकार को कोई मुनाफा नहीं होता । परन्तु जब मैंने यह साधारण सी बात इस युक्ति के सम्बन्ध में कही थी कि फीज के नये सुधार का व्यय ऋण लेकर चलाया जाय तो मुझे इसका बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मेरी बात की सच्चाई में सन्देह किया । खैर उन्होंने जो कुछ कहा, भ्रम में कहा । यह प्रकट था कि उन्होंने यह समझा कि मैं कह रहा हूँ कि देश का उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के ऋण कम कर दिये गये हैं जब कि मेरा यह कहना था कि चूंकि हमारा अनुत्पादक ऋण, जो धामनव में हमारा ऋण है, उतनी रकम से कम हो गया था जितना कि वर्तमान साल की मालगुजारी से पूँजी के तौर पर व्यय किया गया था, इसलिए फीजी सुधार का सारा खर्च ऋण से चलाया जा सकता था और इसके होते हुए भी हमारा अनुत्पादक ऋण उससे कम ही होगा जितना कि ८ साल पहिले था । श्रीमन् दक्क देनेवालों के प्रति यह बड़ा अभ्यास होगा यदि हम पिछले साल की बचत को तो पूँजी बनाकर खर्च कर दें और सेवा के सम्बन्ध में बार बार होनेवाला खर्च हम वर्तमान साल की मालगुजारी से लें जब कि उससे बचा हुआ प्रत्येक पैसा हमें अपने बच्चों की शिक्षा और सँकड़ो दूसरे आभ्यतरिक सुधार में खर्च करना है ।

अर्धसचिव कहेंगे कि जब तक वचत नहीं होती तब तक किसी को नहीं मालूम रहता कि कितनी वचत होगी। पत्रिचय ही जब वह वचत हुई है और उसे अनुत्पादक ऋण के काम करने में खर्च किया गया है तो कोई कारण नहीं है कि ऐसे कामों के घास्ते ऋण न लिया जाय और बार बार नहीं होते।

श्रीमन्, इसके पश्चात् मैं यह कहने की आज्ञा चाहता कि भारतीय सेना की संख्या कम से कम उतने से कम कमी दी जाय जितने से वह पञ्चदेह घटना के उपरान्त बढ़ा गई थी। इस साल में सेना का व्यय भयानक रूप से बढ़ गया है जैसा कि वह नीचे के अकों से जान पड़ता है।

१८८४-१८८५, १० ६ करोड़ (१८८५ की वृद्धि के पहले)

१८८८-१८८९, २२ २ " (वृद्धि के बाद)

१९०२-१९०३, २८ २ "

१९०६-१९०७, ३२ ८ "

हमारे यहाँ अब सेना का व्यय २० वर्ष पहले से ठीक दुना हो गया है। सन् १८८८ के बाद से वह करीब १० करोड़ के बढ़ गया है और यह हम बात के होते हुए कि इस बीच में एक सिपाही भी अधिक नहीं भरती किया गया है। सन् १८८५ में जो वृद्धि की गई थी वह भारत सरकार के सदस्यों की सम्मति के विरुद्ध और १८७६ वाली आर्मी कमिशन की राय के प्रतिकूल थी। कमिशन तो उस समय की सेना को देश में भीतरी शांति रखने और बाहर के आक्रमणों को रोकने के लिए केवल रूस के अकेले आने ही पर न बल्कि अफगानिस्तान को उसका साथ देने पर भी काफ़ी

समझती थी। तभी से रूस की चढ़ाई के भय का प्रभाव हमारे सब सैनिक प्रान्धों में देखने में आता है। पर अब एक ओर रूस की टांग टूट गई और दूसरी ओर हमारी सरकार से जापान की सन्धि हो गई तो अब हमारे शासकों के चित्त में भय का नाम नहीं होना चाहिये और देश को उस बोझ से श्राण मिलना चाहिये जो आज तक उस भय के कारण उस पर लदा हुआ है। कुछ दिनों से इंग्लैन्ड में सैनिकों को भर्ती करने में और भारत में सैनिक दल भेजने में जो कठिनाई पड़ रही है और उसके कारण पारितोषिक दे दे कर थोड़ी मियाद वाले सिपाहियों को सेवा की अवधि बढ़ा लेने के लिए जो लालच दिया जा रहा है उससे भी यही उचित जान पड़ता है कि यदि भारतवासियों के साथ न्याय करना है और बिना प्रयोजन उनका भार नहीं बढ़ाना है तो यहाँ की दुर्ग सैन्य की संख्या को घटा देना चाहिये और यदि इस मत की पुष्टि की गई कि सर एडमण्ड एरस के मतलाये हुए कारण के अनुसार सेना की संख्या का ह्रास नहीं किया जायगा अर्थात् यह मान लिया जाय कि भारत की संना स्थानीय सेना नहीं है जो एक ही जगह की शान्ति और रक्षा के निमित्त हो घेरने वह एशिया खण्ड की लड़ाकू जातियों की शक्ति में सामञ्जस्य रखने के लिए है तो इम्पीरियल गर्धनमेन्ट का धर्म है कि वह इस उद्देश्य से निर्मित सेना के निर्वाह के धर्म का एक अंश स्वयं वहन करे। श्रीमन्, सेना का व्यय इतना बढ़ गया है कि उसने सरकार के सारे आय-व्यय के लेखा को आच्छादित कर लिया है और उसकी ठिठुरानेवाली छाह के नीचे प्रजा का कोई व्याधिरहित विलास संभव नहीं है। दृढता और निर्भीकता के साथ यदि हमने उसके व्यर्थ ही बढ़े

हुए निरुद्ध अगों में कुट्टाड़ा नहीं लगाया तो हमारे जीवन में रोग के वैसे ही चिन्ह दिखलाई पड़ने लगेंगे जैसे इस समय इसकी वृद्धि में।

खैर, सेना के आसजनक व्यय के प्रति ही केवल हम लोगों का उलाहना नहीं है। सारी भारत रक्षा प्रणाली जो अधिवास के ऊपर निर्माण की गई है दोषपूर्ण है और यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि इसकी दशा दिनोदिन बिगड़ती ही जाती है। देश का सारी आबादी सेना में भर्ती होने से वञ्चित करी जाती है। नई व्यवस्था के अनुसार 'मद्रास कमांड' का एकयागी उठा देना क्या है मानो मद्रास हाते में सेना की भर्ती ही बन्द करनी है। इसका तात्पर्य यह है कि अब मद्रास वाले मामूली सिपाही की हेमियत से भी फीज में टापिल नहीं हो सकते। अधिकतर सरहद्दी या सरहद्द के पार की जातियों से ही बहुधा अब रकूट लिये जाते हैं अर्थात् उसमें अब विदेशी ही भरे जाते हैं जिसका फल यह हो रहा है कि कुछ ही दिनों में उसमें केवल घेतन की लालच से काम करनेवाले आ जायेंगे। आर्म्स एक्ट का प्रयोग क्रमशः कठारता के साथ किया जा रहा है और हथियार रखने के लिये अब पहले से बहुत कम लाइसेन्स दी जाती है। वर्तमान समय में मैं समझता हूँ कि इस तरह के लाइसेन्स की कुल संख्या ३० और ४० हजार के भीतर ही होगी। देशी सेना में गोरे अफसरों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है जिससे पजाबी रेजिमेन्टों में १३ और दूसरों में १२ गोरे अफसर हो जायेंगे। इस वृद्धि से हिन्दुस्तानी अफसरों को वे बड़ी जगहें भी जो कभी कभी उन्हें मिल जाया करती थीं अब न मिल सकेंगी और वे अब छोटे छोटे द्रूप और कम्पनियों पर भी अफसरों न कर सकेंगे। सेना में उड़े और ऊँचे अहदों योग्य और

उन्माहों हिन्दुस्तानियों को देने के लिये हम बहुत दिनों से कह रहे हैं पर जराय में हमें यही सुनने में आता है कि इसमें हमारे साथ पहले से भी अधिक कड़ाई की जायगी। यह सच है कि 'फेडिट फोर' के चार आदमियों को पारसाल कमीशन दिया गया था और उसके सम्बन्ध में घाइमगाय ने जो भाषण किया था उससे आशा होती थी कि इन हिन्दुस्तानी नवयुवकों को सेना में उच्च पद पाने के चैसे ही अवसर मिलेंगे जैसे गोरे अफसरों को। पर इन त्रिषय पर मेरे प्रश्न करने पर जंगी लाट साहब ने जो उत्तर दिया उससे यह आशा भी जाती रही और हम लोगों को प्रनीत हो गया कि 'लार्ड कर्जन' की प्रतिज्ञा केवल कहने सुनने की थी, उसे पूरा करने का जय समय आया तो यह तोड़ दी गई। गद्दर के पहले दो प्रणालियां थी। उनका नाम था "रेगुलर" और "इर्रेगुलर"। "रेगुलर" में प्रत्येक देशी सेना के पीछे २० गोरे अफसर होते थे और "इर्रेगुलर" में फेरल ३। मन् १८७६ वाले कमीशन ने "इर्रेगुलर" की प्रणाली पसंद की, पर बहुत वादविवाद के अनन्तर १८६३ में यह नै पाया कि प्रत्येक देशी सेना में ७ गोरे अफसर हों जो इस मध्य स्थित और पार्श्वस्थित सेनाओं पर कमान्ड करें और देशी अफसर के नीचे ड्रूप्स और कम्पनियां हों। लार्ड मेयो के आधिपत्य काल में इस प्रश्न पर फिर बहस चली और गोरे अफसरों की सख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह बहस १८७५, ७६ तक जारी रहा जब लार्ड सेलिसरी ने यह निर्णय किया कि ७ गोरे अफसर वाली प्रणाली कायम रहे और उसके साथ ही इस बात की आवश्यकता दिगलाई कि देशी अफसरों की स्थिति में उन्नति और सुधार होना चाहिये। इस चार जब प्रश्न नये सिरे से उठाया गया है तो हम देखते हैं कि निर्णय हमारे विरुद्ध ही किया जा

रहा है क्योंकि अब देशी सेना में ७ की जगह १० और १३ तक गोरे अफसरों की संख्या हो जायगी। श्रीमन् प्रजा के ऊपर इतने दिनों के ब्रिटिश शासन के बाद इतना अविश्वास जिस पक्ष से देखिये दुःख और शोच का विषय है। जब तक विश्वास की नीति पर काम नहीं किया जायगा यह सेना का प्रश्न क्या, भारत में किसी प्रश्न का निपटारा नहीं हो सकता इसमें जो कठिनाई पड़ती है तथा सावधानता की जो जरूरत है उसे मैं खूब समझता हूँ। पर जो कुछ हो अन्तमें विश्वास ही के द्वारा विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है और साहस के साथ प्रजा की राजभक्ति पर भरोसा रखने ही से वे उत्तेजित होकर राजभक्ति प्रदर्शित करेंगे। जब तक यह वशा रही जो आज है तबतक भारत रक्षा का प्रश्न चाहे कुछ कीजिये ऐसा ही रहेगा। रूसी और जापानी सेनाओं के साथ जो युद्धविद्या—निपुण कर्मचारी लड़ाई में गये थे उन्होंने राय दी है कि जब कोई बड़ा संकट आन पड़ेगा तो वर्तमान भारतीय सेना बहुत छोटी पाई जावेगी। यह तो मानी हुई बात है जबतक हम केवल सज्जित बैटेलियन पर तथा उन सेना सामग्रियों पर जो विपत् काल में इङ्ग्लैन्ड भेज सकेगा हम भरोसा किये बैठे रहेंगे। सम्य ससार में सर्वत्र सज्जित सेना का अवलम्ब सैन्य समग्र व रिजर्व पर है तथा उन दोनों का अवलम्ब देश की जनता पर होता है। केवल इसी देश में ऐसे रिजर्व नहीं हैं जो युद्ध के समय लड़नेवालों की संख्या बढ़ा सकें और इस विषय की ऐसी उपेक्षा की जाती है मानो देश के लिये इसका कोई महत्व ही नहीं।

भूतपूर्व वाइसराय ने सेना का खर्च घटाने की आवश्यकता दिखलाने के लिये जापान की धीरता का उदाहरण दिया था पर क्या कोई विश्वास कर सकता है कि बिना रिजर्व

के हाथ बढ़ाये और जापान के प्रत्येक बालक वृद्ध और युवा से सहारा पाये ही वह देश केवल सज्जित सेना के ऊपर पानी की तरह रुपया बहाने से ही क्या ऐसे गौरवपूर्ण कृत्य दिखला सकता ? सेना के लिये जापान का साधारण बजट केवल ३७ ३ मिलियन येन है जो ६ करोड़ से कुछ कम है। इतने थोड़े व्यय से वह देश १ लाख ६७ हजार सज्जित सेना रख सकता है जिसके अलावा उसके पास रिजर्व है जो समर काल में ६ लाख तक पहुँच सकता है। हम लोग इसकी अपेक्षा ६ गुना धन खर्च करते हैं तब भी हमारे पास केवल गिनेगिनाये २ लाख ३० हजार सज्जित सेना, २५ हजार देशी रिजर्वेन्ट और ३० हजार गोरे चलमटेर हैं। राजनैतिक आधार पर और धन व्यय के लिहाज से दोनों प्रकार से हमारी वर्तमान सेना प्रणाली निन्दास्पद है। श्रीमन्, विनयपूर्वक मेरी प्रार्थना है कि हमारे देशवासियों को-ससार भर की जनता के पाँचवें अंश को अपने घर द्वार की रक्षा करने योग्य न रखना, सदा के लिये उन्हें वे हथियार रखना और सैनिक जीवन के लिए इस प्रकार असमर्थ कर देना जैसा आज तक ससार में देखा सुना नहीं गया, बड़ाही निर्दय व्यवहार है। लार्ड जार्ज हैमिल्टन ने एक मरतबे विलायत में अंग्रेजों की सभा में कहा था कि भारत में ऐसे लाखों आदमी हैं जो वीरता में दुनिया की किसी भी जाति की बराबरी कर सकते हैं, देश में ऐसे लोगों को छोड़ कर और उनकी ओर उपेक्षा दिखला कर हमारी सरकार ने भारत की रक्षा के लिये एक ऐसी जाति के साथ सन्धि करना उचित समझा है जो किसी समय भारत से ही धर्म सीखता था और इसकी आश्रित था। जापान के ऊपर पश्चिमी विचारों का प्रभाव पड़े हुए केवल ४० साल हुए हैं पर इतने ही में उसने

अने शासकों के प्रतिपालन और रक्षा से पश्चिमी देशों के बड़े अभिमानी राष्ट्रों में अपनी गिनती करा ली है। हम लोग ग्रीटन की छत्र छाया में ४० वर्ष से ऊपर रह चुके हैं तब भी हम लोगों का दर्जा अपने ही देश में गुलामों से अच्छा नहीं बाहर का तो कुछ कहना ही नहीं। समय और घटनायें-परिवर्तन लायेंगे पर सच्ची नीति निपुणता तो इसमें है कि हम उसका पूर्व परिचय पा जाय। वर्तमान प्रधान मन्त्री ने पड़लो जापानी सन्धि के ऊपर इस प्रकार अपना विचार प्रकट किया था —

“यदि यह साम्राज्यवाद है तो इतना मैं साम्राज्यवादी हूँ कि मैं यह समझूँ कि भारत को सुरक्षित और अखण्डित रखना हमारा काम है, दूसरों का नहीं। और यदि रक्षा के साधनों की विशेष आवश्यकता है—जिसका पता मुझे नहीं है—तो भारतीय प्रजा के प्रति हमारी अपील होनी चाहिये, फिर रक्षा करने की अपनी योग्यता की ओर देखना चाहिये। क्या आप समझते हैं कि भारत की रक्षा में जापानियों को सम्मिलित करने में भारतवासियों की मानहानि न होगी या स्वतंत्र की दृष्टि में हमारे विस्तृत राज्य की प्रतिष्ठा न्यून न हो जायगी?”

श्रीमन्, यस गही सच्ची दूरदर्शिता और नीतिनिपुणता है। मेरे देशवासी इतना ही चाहते हैं कि भारत में सेना का प्रश्न प्रधान मन्त्री की इस घोषणा के अनुसार हल किया जावे। जिन सुधारों की आवश्यकता है, वे ये हैं भारतीय सेना में अस्थायी सेना, भारतवासियों का रिजर्व बनाना और क्रमशः नागरिक सैनिक बनने का अधिकार वापस

खास जातियों को फिर और लोगों को भी प्रदान करना जिसमें वे आवश्यकता पड़ने पर हथियार बाँध कर अपने देश की रक्षा कर सकें। चाहे सरकार कितना ही सतर्क हो कर चले पर उसे इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हम लोगों की सामरिक रक्षा का प्रबन्ध राष्ट्रीय आधार पर हो जायगा और सेना को देश भर के लोगों से पुष्टि और सहायता मिलेगी, सेना का बहुत सा व्यय कम हो जायगा और बचे हुए धन से देश के और दूसरे उपकार के काम किये जायेंगे। प्रजा केवल कर देने और चुपचाप मुह ताकने को बाध्य न होगी उन्हें सेना में विशेष रुचि और अनुराग होगा और इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति से ग्लानि या निराशा न हुआ करेगी। इस समय जब बाहर से किसी शत्रु के चढ़ आने का भय जाता रहा है, इस नीति की परीक्षा लेनी चाहिये और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि इङ्ग्लैण्ड को इसके फल से असन्तुष्ट होने का कारण न मिलेगा।

श्रीमन्, मुझे यह कहने में सकोच नहीं कि भारत सरकार की सामरिक नीति में शीघ्र ही परिवर्तन होने की बहुत कम सम्भावना है और यदि मैंने इस विषय पर विस्तार के साथ कहा है तो इसका यह कारण है कि मैं समझता हूँ कि हम प्रश्न के साथ हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न लगा हुआ है और दूसरे वर्तमान समय में इस पर पुनर्विचार करने के लिए प्रार्थना करना विशेष रूप से उपयुक्त है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सेना का व्यय इतना बढ़ गया है कि उसने समग्र रूप से सरकारी आयव्यय के हिसाब को घेर रक्खा है इसी लिए तो यह ओर खेद की बात है कि सेना के व्यय से जो थोड़ा बहुत बचता है उसका अच्छा उपयोग नहीं किया जाता। श्रीमन्,

गन ८ वर्ष में भारत सरकार को ३० करोड़ रुपये की वचत हुई जो सब की सब रेल बनवाने में खर्च कर दी गई और उस पर भी कर्ज लेना पड़ा। व्यवसाय के तौर पर रेल खोलने के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी तक उसने घाटा ही घाटा होता था, पर अब यह बात नहीं है और भविष्यत् में निस्सन्देह उस से सरकारी कोष में अधिकाधिक आय होगी। इस लिए ऋण लेकर व्यवसाय की दृष्टि से रेल खोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं यद्यपि इसमें भी ऐसे धन का अधिक भाग पहले नहरों के निकालने में लगाने के बाद ही इस का विचार हो सकता है। पर इस बात के प्रति मुझे घोर आपत्ति है कि सरकारी वचत का धन रेल में खर्च किया जाय, जब, सर्वसाधारण के हित की अनेक बातों के लिए धन का अभाव है। श्रीमन्, मेरा कथन है कि इसमें कुछ परिमाण का ज्ञान भी होना चाहिये। इस समय तक २५० मिलियन पाँड रेल के पीछे खर्च हो चुका है। बहुत काल तक सरकार की आकांक्षा की पराकाष्ठा यही तक थी कि इस देश में २० हजार मील रेल हो जाय। पर रेल का वह रास्ता जो आज खुला है २१ हजार मील से ऊपर है और जो सड़क बन रही है २ हजार मील होगी। क्या रेल ही सब कुछ है, क्या जनसाधारण की शिक्षा में कोई तत्व नहीं है, क्या स्वास्थ्य सुधार से कोई लाभ नहीं है जो अर्थसचिव वचत के धन से या ऋण से एक एक रुपया तक जो पाते हैं रेल के निर्माण में खपा देते हैं। इस विषय पर मेरी आलोचनाओं के उत्तर में अर्थसचिव ने यह कहा था —

“जब सरकार को अकस्मात् किसी भाँति वचत हो जाती है या किसी ऐसे मार्ग से धन मिल जाता है जिस पर आगामी

माल भरोसा नहीं किया जा सकता तो मैं समझता हूँ कि उसका इससे बड़ा-बड़ा कोई उपयोग नहीं हो सकता कि यह किसी ऐसी सार्वजनिक इमारत में लगा दिया जाये जिससे कुछ आमदनी हुआ करे ।”

मैं उचित नम्रता के साथ यह कहा चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव बहुत ही कष्टा है। सरकार का ऐसा करना उस दशा में बिल्कुल ठीक होता जब कोई ऐसा असामान्य व्यय कि जिससे सर्वसाधारण का भला होता हो, आवश्यकता न होती। परन्तु देश की ऐसी आवश्यकताओं के होते हुए जैसे आरम्भिक पाठशालाओं के लिये सुथरे भवन रसायन सुधार के लिए ऐसी सामग्री जो स्थानीय संस्थाओं की हीसियत से बाहर है, मैं यह जरूर कहूँगा कि घर से घसल किया हुआ धन व्यवसायिक कामों में लगाना बिल्कुल अनुचित है। यशत के अनिश्चित होने से मेरा कथन मिथ्या नहीं हो सकता जब ही वह हाथ लगे तो उन कामों में उसे लगाना चाहिये। जो अभी मैंने बताये हैं। जब वह न मिले तो उसके बिना जो हमारी वर्तमान दशा है वह हीन नहीं हो सकती।

श्रीमन्, पिछले साल की वनतोने, जो जबरदस्ती रुपये का निर्य बढ़ाकर आवश्यकता से अधिक कर लेने के कारण तथा आय को हमेशा कम बनाने और व्यय को बढ़ाकर कहने के कारण हुई थी, देश के सर्व के ऊपर अपना अपरिहार्य फल दिया गया है। राजकोष में धन का इतना ग्राह्य होने पर चारों तरफ सर्व का बढ़ता तो स्वाभाविक था। सब लोग मितरायिता से भ्रष्टा करने लगे, नये मोहरों का मुल्ता और युरोपियन रुमरों की पैतन पड़ि एक मामूली बात हो

गई। बड़ी सुगती के साथ ऊँठ का भी काम किये गये, पर कार्यकुशलता के नाम खुदे हाथ रुपये उड़ाने की आदत नहीं गई और यह अभी तक चली जा रही है। पछतावे की बात तो यह है कि राजकोष में इतना प्रचुर धन होने पर शासन-व्यय में अपरिमित वृद्धि के होने हुए भी प्रजा भी आर्थिक और नैतिक उन्नति में योग देनेवाले काम ऐसे ही पड़े रह गये और सरकार ने कोई ऐसी युक्ति नहीं की जिससे गृहसम्यक् मनुष्यों की ढगा सुनरे। हम समझते हैं भारत सरकार का यह परम कर्तव्य है कि कोई ऐसी व्यवस्था करे। इसमें उनका सब रुपया लग जायगा चाहे वह बाग्यार हो या नहीं।

श्रीमान् ! प्रजा की स्थिति के सम्बन्ध में जिन तीन घुसाइयों के साथ हमें लड़ना है वह हैं, उसका दारुण दुर्मिक्ष, उसकी अज्ञानता और रोग लाने वाली परिस्थिति। मैं आशा करता हूँ श्रीमान् धीरे-धीरे धीरे-धीरे और मुझे यह कहने की आज्ञा देंगे कि जिस ढंग पर काम होना चाहिये।

(१) पहले तो भूमि के सम्बन्ध में तीन सुधार आवश्यक हैं। यदि हम वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो इन तीनों सुधारों को एक साथ होना चाहिये। इनमें पहला, भूमि के ऊपर सरकारी लगान में कमी है, विशेष कर उम्हरे मद्रास और मयुक्त प्रान्त में इसका पूरा प्रमाण है कि पुगने प्रान्तों में कृषि का काम बहुत ही मन्द हो रहा है। जमीन की पैदावार घटती जाती है। फसल दोगे दिन खराब होती जाती है और यहाँ की उपज दुनिया के सब देशों से कम तो थी ही और भी थोड़ी होती जाती है। कृषि की अपरथा इतना गिर जाने पर भी सरकारी लगान बढ़ता ही जाता है। प्रजा पिचारी इस बीच

के नीचे दरी जानी ३ पर पेट ऐसी पुरी बला है कि उसे यह सहन करना ही पड़ता है राज्यकर के डाइरेक्टर जोकोन साहब ने लण्डन में सोसाइटी आफ 'आर्टस्' सभा के सामने एक व्याख्यान में कहा था ।

“इसमें बहुत संदेह है कि काश्तकारों को बनिये महाजनों के हाथ से बसाने की चेष्टा जा इस समय की जा रही है उससे उन्हें कोई लाभ होगा । यदि कुछ लाभ हुआ भी तो उस समय तक उनकी स्थिति में अधिक अन्न पड़ने का नहीं है जब तक भूमि की उपज का अधिक भाग उन्हीं को न मिले और जमीनदारों के इजाफा लगान से उनकी रक्षा न की जाय” और भी—

‘मुझे निश्चय है कि लगान के २० वा ३० सेकड़ा कम कर देने से और इसका ज्ञान रखने से कि काश्तकारों को भी इस निवृत्ति से लाभ हो, देश के उन अधिकांश निवासियों की बहुत ज्यादा दशा सुधर सकती है जिनके रुपये से विशेष रूप से शासन का खर्च चलता है ।”

वर्तमान प्रणाली का केवल एक नतीजा होगा । इससे देश का मुख्य व्यवसाय—रूपि सदा के लिये असमृद्ध रहेगा । इसमें रुपया लगाने से लोग भय खाएंगे और सुधार करने का नाम न लेंगे पर मने जो उपाय बताया है उससे चाहे सरकार को अभी थोड़ा फायदा हो पर प्रजा के अपरिमित लाभ से वह पूरा पट जायगा

(२) दूसरे इन बात की पूरी चेष्टा होनी चाहिये कि भारतीय रुपय ऋण के उस बोझ से जिससे वह लदे हैं छुटकारा पाये । यह प्रश्न एक बहुत व्यापक प्रश्न है और संभवतः

भिन्न भिन्न प्रान्तों की अवस्था के अनुसार पृथक् पृथक् कार्रवाई की जरूरत होगी। सब से जल्दी बात तो यह होगी कि प्रत्येक प्रान्त के अन्तर्गत एक नियत क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत परिमाण से इसका अनुभव किया जाय। उदाहरण के लिये बम्बई प्रान्त के दक्खिनी भागों को लीजिये। अच्छे जानकारी लोगों की यह राय है कि अधिक नहीं तो हमारे एक तिहाई गृहस्थ पहले ही से अपनी भूमि खो बैठे हैं और अब वे महाजनों के दाम्न बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सब से पहले मैं ऐसे लोगों की दशा पर विचार करूंगा और एक विशेष अदालत नियत करूंगा जो जगह जगह जाकर ऐसे प्रत्येक मामले पर विचार करे और यदि आवश्यकता हो तो शर्तनामों वा उस्तावेजों ही तक न रह जाय बल्कि एक दृष्टि उस अवस्था पर भी डाले जिसमें वह लिखे गये थे। मैं यह भी यत्न करूंगा कि उनके बीच बाहे मीथे मीथे या उन कानूनी अधिकारों के द्वारा जो उस अदालत का मौखे जाय उनके लैन वैन का निपटारा हो जाय। कल्पना कीजिये कि मैं, मिलियन पौन्ड उस अदालत के सिपुर्व कर दू, जिससे रुपयों को अपना ऋण चुकाने के लिये पेशगी रुपया दिया जाय और यह रुपया ४½ सैंकडे सरकारी मालगुजारी बटाकर वापस लिया जाय—३½ सैंकडे सूद के लिये और १ सैंकडे मूलधन के हिसाब में और यह ऋण ५० वर्ष के भीतर भीतर चुक जाय किन्तानों को इस तरह मुक्त करके सरकार उनकी घरवादी में रकाम डालने का न्यायपूर्वक दावा कर सकती है इसमें सन्देह नहीं कि जो कुछ ऊपर कहा गया है वह स्थूल रूप से कहा गया है और इस व्यवस्था का विवरण पीछे से सोचना और उस पर कार्य

करने के पूर्व बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी। यदि इस प्रयोग में सफलता के लक्षण दिखाई पड़े तो देश के और प्रांतों में भी इसका अनुसरण किया जा सकता है। यदि इसमें असफलता हुई तो मिर्क थोड़ा रूपा १९ होगा परन्तु इस सफ़ट का मामला बरता ही पड़ेगा। जय लार्ड लैन्सडाउन भारत का चाइसराय थे तो उन्हें कृषि की प्रगति पर इतना दुःख हुआ कि यह कहा जाता है कि उन्होंने जाने के पहिले एक स्मरण चेत छोटा जिसमें उन्होंने अपनी यह सम्मति प्रकट की कि कृषि की दशा ब्रिटिश राज्य के लिए बहुत भयंकर है और उसमें शीघ्र सुधार की नितांत आवश्यकता है। उषा हिन्दुस्तान से गये १८ साल हुए जिस पर भी सरकार के सारे प्रयत्नों की सीमा जो इस प्रगति के दूर करने को किये गये हैं वे सब उन्हीं थोड़े माननों तक हैं जिसका उद्देश्य प्रजा के उधार लेने के अधिकार को कम करना है। अजीब सी जो काम में आनेवाली पत्र कटो हो सकती थी उसमें सरकार ने मुख्य कटो बना ली। इसका परिणाम यह हुआ कि बात हमारी अथवा पहले ही जैसी शोचनीय है।

(३) परन्तु इन दो उपायों से प्रजा को उस समय तक स्थायी लाभ नहीं होगा जब तक एक तीसरे उपाय से काम लिया जाय अर्थात् जब तक कि वह सुविधायी व प्रदान की जाय जो कानूनसारी को मितव्ययिता की ओर आकृष्ट करने हुए उसे उचित रूप से योग्य बनाय कि वह अक्सर अक्सर पर अपनी आवश्यकताओं के लिए कम सदपर ऋण ले सकें। सहकारी बैंक जिसके लिए मैं अब हुए एक पक्ष पास किया गया है इस विषय में बहुत लाभदायक न होगा। जानीय

और मातृदायिक भाग भारत के अविभागा में अब भीमा पड़ गया है और कि वेहद जिम्मेदारी के नियमों पर इसमें भात वर आदमी आयेंगे नहीं। दरिद्रियों की कितनी ही सख्या इकट्ठी हो, न उनके पास बन होगा न साग जिससे वे एक दूसरे की मदद कर सकें। यदि वेहद जिम्मेदारी का नियम उठा दिया जाय और सेजिस्स रैक्स की अमागत का कुछ हिस्सा इन रैक्सों को मिले तो काम निजले। पर सबसे अधिक देश को कृषि पैको की जरूरत है उसी ढांचे पर जिसपर कि लार्ड क्रोमर ने मिश्र देश में बड़ी सफलता के साथ उनका स्थापन किया है।

(४) दो और ढग जो कृषि के अभ्युदय और उन्नति के लिए हिन्दुस्तान में आवश्यक हैं और जिनमें से कि एक ने पहिले ही से सरकार का बहुत ध्यान आकृष्ट किया है और जो हाल ही में हाथ में लिया गया है वे सिंचाई और वैज्ञानिक कृषि हैं। सिंचाई की यातन में इतना ही पूछा चाहता है कि तामीरात की चुनो हुई व्यवस्थायें सरकारी मोहकमोही की ओर से क्यो बनें, उनकी तैयारी का काम, मिश्र देश की तरह रुशियार डेकेदारों को क्यों न सौंपद किया जाय जिसमें वह मनदूर लाकर उन्हें काम सिखलायें और सरकार केवल निगरानी करें। मेरे विचार में सरकार को चाहिये कि वह इस पक्ष में भी उस प्रसिद्ध शासक लार्ड क्रोमर का अनुकरण करे। यदि ऐसा किया गया तो सिंचाई में बहुत शीघ्र उन्नति हो जायगी। वैज्ञानिक कृषि के विषय में भी भारतवासी बड़ी उत्कण्ठा से सरकार के उस काम को जो उन्होंने अभी तक किया है देख रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक चेतावनी देनी है। यदि यह गमनाच है कि इस काम के लिए यूरोपियन

पैमानिक बुलाकर रखे जायँ तो फिर काम ही चुगा । उन विदेशी पैमानिकों की विद्या जो लगातार भारत में गाय देने के लिए आते हैं और उन्हीं ने पेन्शन की अवधि पूरी कर लेते हैं और घर का लोट जाते हैं, उन गायकों की नाई है जो कुछ दिनों तक तो आकाश में उमड़ा रहते हैं पर बिना बगसे ही और पृथ्वी को उपजाऊ नपाये ही दया के स्रोतों से उठ जाते हैं । जब तक चुने हुए गायक होनाहार भारतीय युवक दूर देशों में काम मीसने और निपुण विदेशी कर्मचारियों की जगह देने को तैयार नहीं किये जाते तब तक उनके शात और अनुभव का हमारा आदमियों के बीच में प्रसार होगा कठिन है । इतना जरूर है कि भारत में विदेशी पैमानिकों के ऊपर भारीसागर पड़ेगा पर यह प्रबन्ध स्थायी नहीं रहना चाहिये ।

(५) देशवासियों की दरिद्रता दूर करने के लिए हम लोगों को औद्योगिक और शिल्पीय शिक्षा का भी प्रचार करना है । इस क्षेत्र में हम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया है, तब जा इसका क्या हुआ है, सो एक माधारण आदमी भी जानता है । इस साल के बजट में २½ लाख का दान आन्यत्रता के लिहाज से कुछ भी नहीं है, देश में कम से कम एक सहस्र शिक्षाशाला होनी चाहिये जिसकी शाखाएँ विश्व भिन्न प्रान्तों में हों ।

(६) अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा के प्रश्न पर आता हूँ । मिस्टर नथन की रिपोर्ट से पता चलता है कि समग्र भारत के बालकों की शिक्षा के ऊपर सरकारी कोष से केवल ६३½ लाख की अति थुट्टरकम खर्च होती है । उस समय से अब इसमें कुछ वृद्धि हुई

हैं पर अब भी यह आवश्यकता की दृष्टि से बिल्कुल अपर्याप्त है। श्रीमन् सर्वसाधारण की शिक्षा का प्रश्न इस देश में बहुत दिनों तक उपेक्षित और अनादृत हुआ और अब इसे अपना उत्तरदायित्व समझने में तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिये। जरूरत है एक माष्ट लक्ष्य की ओर उस पर कार्य करने की दृढ़ता और उत्साह की। इसकी पहली सीढ़ी तो भारत भर में आरम्भिक शिक्षा को नि शुर्तक कर देना होगा और यह बड़ी आसानो से हो सकता है। सन् १९०७-०८ में आरम्भिक पाठशालाओं की जाय की कुल रकम केवल ३०६ लाख थी इस लिए बहुत बड़ा त्याग न करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जितनी बड़ी म्युनिमिपैलिटिया हैं उनमें अपने हाते के भीतर ही इस घाटे के एक हिस्से को सहन करने के लिए सहना चाहिये। दूसरी सीढ़ी यह होगी कि प्रेमिडेन्सी नगरों में यह प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय शिक्षा में उल प्रयोग की बात जब लोगों की समझ में आ जायगी तब क्रमशः इसका विस्तार किया जा सकता है जिस से अन्त में २० वर्ष के भीतर के लटके और लड़कियाँ दोनों के लिए इस देश में शिक्षा बिना शुर्तक और अनिवार्य हो जायगी। विघ्न और बाधाओं से डर कर घबराने से कुछ न होगा। हमारा सारा भविष्यत इस काम के सिद्ध होने पर निर्भर है और जब तक सरकार इस पक्ष में उदासीन है वह प्रजा की ओर अपने एक बहुत ही आवश्यक कर्तव्य पालन में चूकने के लिए निन्दा की पात्र होगी।

(७) अन्त में स्वास्थ्य विभाग का बहुत जरूरी काम है जैसे शुद्ध जल का प्रयत्न करना, नालों का पनघाना इत्यादि - सा कि मैंने पारसाल वालाया था प्रायः हमारे घड़े नगरवाले

सरकार ने पिना सहारा पाये अबले इस काम को करने में असमर्थ हैं। सभी दिशाओं में त्रुटि का प्रकोप होना और मृत्यु मरणा का दिनों दिन घड़ता जाना यह जताना है कि सरकार इसको और अब उपेक्षा नहीं कर सकती। साधारण जनता के पास रोजाना गन्ध के लिए ही यथोचित धन नहीं है, पूँजी लगाने के लिए उनके पास कहा से रुपया आये। वर्तमान समय में साधारण जनता और भारतीय सरकार के बीच भाव और उत्तरदायित्व के विवरण का जो नियम है वह साधारण जनता के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है और यही उस फीतुर की जड़ है जो हम लोग पिछले कई साल से देखते आते हैं। अर्थात् एक ओर तो सरकार का कोप उमड़ा जाता है, दूसरी ओर स्थानीय संस्थाएँ धन के अभाव से उजड़ी जाती हैं। यह आवश्यक है कि इसपर सरकार अपनी एक नीति बनाकर सर्वसाधारण को सूचित कर दे।

जिनने सुधार मंने ऊपर गिनाये हैं उन सब में बड़ा गन्ध बैठेगा, कुछ तो एक मुश्त और कुछ प्रति वर्ष। पर इस समय भी जैसी हमारी आर्थिक अवस्था है हम उन सब में हाथ लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि फीज के नये सुधारों की स्कीम मुलतजी कर दी गई, और कुछ नहीं तो इसका भार भिन्न व्यय ऋण लेकर चलाया गया, तो १ और २ मिलियन के बीच में हाथ आयेगा, जिसे हम पूरे उत्साह के साथ आर्थिक शिक्षा के प्रसार में व्यय कर सकते हैं। सिक्के विभाग की बचत से जो औसतन प्रतिवर्ष २ मिलियन होता है रुपयों का ऋण से उद्धार किया जा सकता है। अकाल के लिए सरकार की ओर से जो दान मिलता है उसमें अकाल निवारण में जो वास्तविक व्यय होता है काटकर बाक

गिक और शिल्पीय शिक्षा में लगाया जा सकता है। सेविंग्स बैंक के अमानत के रुपये से सहकारी बैंक का काम चल सकता है। साधारणतः जो कुछ सरकारी बचत हो उसे स्थानीय संस्थाओं को स्वास्थ्य सुधार के लिए दिया जाय। चाहे जो हो इन कार्यों में हाथ लगाना ही चाहिये पर पहले कर्मचारियों के दिमाग पर जो जादू फिरा हुआ है उसे दूर करना चाहिये।

श्रीमन् ! जनसाधारण की उन्नति और शिक्षित समुदाय का अनुरक्षण घाम्स्तघ मे ब्रिटिश शासन के सामने भारत में दो महान् प्रश्न हैं। इस देश में इङ्ग्लैंड की सफलता वा असफलता का अनुमान इन्हीं दो क्षेत्रों में पराक्रम दिखलाने से होगा। मैं पहले ही उन कार्यों का उल्लेख कर चुका हूँ जिन्हें जनता की आर्थिक और नैतिक समृद्धि के लिये अभी से हाथ में लेना जरूरी है। यह कार्य बड़ा गुरुतर है पर अपेक्षा भाव से बहुत हल्का है। शिक्षित समाज को प्रसन्न करना जरा फटिन है क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी उलझनें आती हैं जिनके खुलझाने में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की भी बुद्धिमानी खर्च हो जायगी। एक ही मार्ग है जिससे यह मेल हो सकता है और वह यह है कि इन शिक्षित वर्गों को देश के शासन में अधिकाधिक सम्मिलित किया जाय। यही वह नीति है जिस पर कार्य करने के लिए पूर्व में इङ्ग्लैंड घब्रन दे चुका है। यही वह नीति भी है जो देश में नवीन विचार के उत्पन्न होने पर अवश्य कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त, आज सभी पूर्वी देशों में एक नये भाव का विकास हो रहा है। उनका हृदय एक नये उत्साह से आन्दोलित हो रहा है और यह आशा उठी जा सकती कि केवल भारतवर्ष ही उन नवीन विचारों से अभिभूत न हो जो आज हमारे वायुमंडल में फैल

रहे हैं। हम चाहें, तब भी उनके प्रभावों से नहीं वञ्चित रह सकते। यदि ऐसा संभव भी हो तो हम ऐसा पसन्द नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार उन गंभीर और असामान्य परिवर्तनों के आशय को जो इस देश के लोकमत में हो रहे हैं यथार्थ रूप से समझेगी। नये भावों की राशि इकट्ठी हो रही है जिसे बड़ी सावधानी के साथ काम लेना चाहिये। देश में एक नई सतति तैयार हो रही है जिसने ब्रिटिश जाति के चरित्र और आदर्शों के विषय में अपनी गाय पिछले कई वर्षों के अनुभव पर निर्माण की है और जिनके स्वतन्त्र विचार के प्रवाह में उन कामों का स्मरण कोई रुकावट नहीं हो सकता। जो ब्रिटिश सरकार ने अतीत काल में किये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन विचारों का मोड़ना सरकार के वश में है और तब वे इस साम्राज्य के भय के कारण होने की जगह उसके बल और आशा के कारण होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है कि यह शुभ फल बलप्रयोग करने से नहीं प्राप्त होगा। देश को इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शासन का अन्तर्गत राष्ट्रीय हो चाहे बाहर से वह विदेशी हो—ऐसा शासन जिससे हमें यह प्रतीत हो कि हमारी हितकामना उसके ध्यान में सब के ऊपर है और हमारी इच्छाएँ और सम्मतियाँ उसके लिए कुछ मानी रखती हैं। श्रीमन्, मैंने यह आलोचनार्थ इसलिए की है कि वर्तमान स्थिति बहुत ही असन्तोषप्रद है। मैं अपने लीज स्वर से केवल चेतावनी दे सकता हूँ, अनुनय कर सकता हूँ। शेष इश्वराधीन है।

होम चार्जेंस या विलायती कर ।

— 207 —

१५ जुलाई स० १८६३ई० को 'बम्बई प्रेसीडेन्सी एनोसि यशन' के प्रबन्ध से बम्बई निवासियों की एक साधारण सभा कामजी बाघसजी हाल में इस उद्देश से हुई थी कि विलायती कर के विषय में एक आवेदनपत्र स्वीकार करके हौस आफ कामन्स में पेश किया जाय । सर फीरोजशाह मेहता सभापति थे । मि० गोखले ने निम्नलिखित वक्तृता देकर आवेदन पत्र को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया ।

सभापति महोदय और सभ्य सज्जनों ! विलायती कर के से पैचीदा और गम्भीर प्रश्न पर किसी प्रस्ताव को पेश करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने में मैं अग्रग्न्य हो हुआ आनाकारी करता, परन्तु लगभग दो महोने हुए, हौस आफ लार्ड्स में लार्ड नार्थब्रुक की प्रेरणा से इस विषय पर जो वादविवाद हुआ था उसने मेरा काम बहुत सरल कर दिया है । महाशयो ! मैं ग्याल करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि लार्ड नार्थब्रुक ने इस अन्याय के विरुद्ध जो हिन्दुस्तान के साथ विलायती कर के विषय में उद्वृत्त गया है, अपने विरोध का स्वर स्पष्ट और जोरदार शब्दों में उठाकर भारतवासियों के सच्चा हित साधन किया है । यह स्पष्ट है कि लार्ड नार्थब्रुक

इस मामले की तब तक पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि १५ मई के बाद धियाद के अनन्तर उन्होंने अब यह प्रस्ताव पेश किया है कि सन् १८७४ और १८७६ के बीच में (उस समय जब वह भारत के वाइसराय थे) इस विषय पर जो पत्र व्यवहार भारतीय गवर्नमेंट और मेन्ट्री आफ स्टेट में हुआ, वह पेश किया जाय। महाशयो! यह वास्तव में हमारे लाभ की बात है कि लार्ड नार्थब्रुक सा दूरदर्शी और धैर्यशील व्यक्ति इस अरसर पर भारत के लिये न्याय चाहता है। क्योंकि यदि इसका कुछ अर्थ है तो यही कि वर्तमान प्रयत्नों में कुछ न कुछ ऐसे दोष अवश्य हैं जो नितान्त असहनीय हैं। स्मरण रखिये कि लार्ड नार्थब्रुक इस मामले की आवश्यकता से अधिक जानते हैं और उनका हर शब्द महत्वपूर्ण है। जब एक समय में भारत के वाइसराय वे और उसी वक्त होल आफ कामन्स की एक चुनी हुई कमेटी ने इस विषय की पूरी छानबीन करके यह रिपोर्ट की थी कि हिन्दुस्तान पर ऐसे बहुत से खर्चों का अनुचित बोझ डाल दिया गया है कि जो यदि वास्तव में न्याय किया जाय तो उन्हें इंग्लैंड के राज कोष से अदा करना चाहिये। स्वभारत ही लार्ड नार्थब्रुक को इस प्रश्न पर पूरा विचार करना पड़ा। और उन्होंने भारत सरकार की सहायता की, फिर विलायत जाकर गवर्नर तक वे बराबर जाच के उस कमीशन में सम्मिलित होने रहे जो इस मामले की छानबीन करने के लिये इंग्लैंड के कोय विभाग की ओर से नियुक्त किया गया था। इसमें आप को मालूम होगा कि लगभग २० साल में लार्ड नार्थब्रुक का ध्यान इस पर बना रहा है जैसा कि उन्होंने स्वयम् हानि आफ कामन्स में कहा था। अतः इस विषय में वे जो कुछ भी कहें

उसका प्रत्येक शब्द महत्व का है। फिर यह भी स्मरण रखिये कि यह प्रश्न लार्ड नार्थमुक ही का उठाया हुआ नहीं है। भारतवर्ष के प्रसिद्ध नेता जैसे गवर्ट नाइट, मार्टन बोड, कृष्णदास पाल, नौगोजी फरेदुजी और दादाभाई नोरोजी हमेशा इसके जिगो में ऊंची आवाज उठाते रहे हैं। मेरे मित्र मि० बाबा ने भी जातीय कांग्रेस के पहले उत्सव में इस विषय पर एक सारगर्भित व्याख्यान दिया था। मैं उस व्याख्यान को अच्छा इसलिये कहता हूँ कि यदि आप उसको पढ़ें तो आपको जान पड़ेगा कि हमारे योग्य मित्र ने उन अनेक शिकायतों का कथन उसी समय किया था जिन्हें लार्ड नार्थमुक ने अब प्रकट किया है। और फिर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे मित्र ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर कैसी नज़ीनता और मिहनत के साथ विचार करते हैं और वे इन विषयों में कैसे पारङ्गत हो गये हैं।

महाशयो! इस प्रश्न का एक यह अंश भी ध्यान देने योग्य है कि भिन्न भिन्न गवर्नर जनरलों और भारतमन्त्रियों ने इस कर की अधिकता और अनोचित्य के विरोध में अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है। लार्ड मेयो ने इसके विरुद्ध स्वर ऊँचा किया, लार्ड नार्थमुक ने थोड़े दिन हुए जब इसका विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं, लार्ड रिपन ने इसके विरुद्ध लिखा और निहायत स्पष्ट और सबल शब्दों में लिखा। मार्कुइस आफ रिपन ने ब्रिटिश सरकार के मन्त्रियों से इस प्रश्न पर बड़ी सरगमी से विवाद किया था, लार्ड डफरिन ने इन्हीं का अनुसरण किया और लार्ड नार्थमुक की १५ मई वाली वक्तृता से तो यह प्रमाणित होता है कि लार्ड लेन्स डोन ने भी इन करों के विरोध में राय दी है। अब भारत-

मन्त्रियों के समूह को लीजिये। सर चार्ल्स बोड, सर स्ट्रा फोर्ड नार्थ कोट, ड्यूक आफ अरगाइल, लार्ड सालसबरी, लार्ड हाटिंग्टन, लार्ड केम्बरले, लार्ड फ्रांस, इन सब ने अपने २ शासन काल में इंग्लैंड के कोष विभाग और सैनिक विभाग से इस बात पर वादविवाद किया है कि सैनिक खर्च जो विला यती कर के रूप में भारतवर्ष को देने पड़ते हैं वे बहुत अधिक और अन्यायपूर्ण हैं। लार्ड केम्बरले ने स्वयम् इस बात को स्वीकार किया है कि ब्रिटिश सरकार के अन्य मन्त्रियों की अपेक्षा भारत-मंत्री का प्रभाव साम्राज्य में सब से कम होता है। यही कारण है कि इन लोगों का कथन और प्रयत्न, नया अब तक का वाद विवाद सब निष्फल गया। यह बात धन्यवाद के योग्य है कि लार्ड नार्थग्रुक ने इन प्रश्न को हल करने के लिए पार्लियामेंट की सहायता चाही है और यह बात भी हमारा साहस बढ़ा रही है कि हाउस आफ कॉमन्स में हमारे मित्रों जैसे कि मिस्टर कोन, मि० मज्जरलीन इत्यादि ने लार्ड नार्थग्रुक को उत्तेजित करने के उद्देश्य से कुछ तद्वीरें आरम्भ की हैं। महाशयो। लार्ड नार्थग्रुक ने जिस प्रश्न पर विवाद करना शुरू किया है और जिससे कि इस समय हमारा तात्पर्य है वह विलायती कर के उस अंश से सम्बन्ध रखता है, जिसे सैनिक कहना चाहिये। विलायती कर की पूरी रकम तो बहुत ही अधिक है और इसी तरह फौजी खर्चों की भी कुल सरफा बहुत ज्यादा है। परन्तु यहाँ पर हम न विलायती कर की कुल रकम पर विवाद करते हैं और न सैनिक व्यय पर। हमको इस वक्त विलायती कर के केवल सैनिक अंश पर विवाद है। यह रकम इस वर्ष सात करोड़ रुपये तक पहुँची है। आप में से अधिकांश को चिदित होगा

कि इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहले भाग में एक तो वह रकम शामिल है, जो हर साल सैनिक विभाग को भेजी जाती है, इसलिए कि जो सेना भारतवर्ष में रक्खी जाती है उसकी भर्ती और शिक्षा विलायती सेना विभाग के ही निरीक्षण में होती है। फिर एक और बड़ी रकम इस कारण से भेजी जाती है कि इन सेनाओं के लिए वहीं से सामान खरीदा जाता है। एक पर्याप्त रकम इंडियन ट्रप सर्विस पर खर्च की जाती है। अर्थात् उन जहाजों पर जो इस सेना को विलायत से लाते और ले जाते हैं। इसके अनतिरिक्त अंग्रेजी सेना के अफसरों का भत्ता भी इसमें शामिल है। दूसरे भाग में अधिकांश वह रकम सम्मिलित है जो सेना विभाग को अंग्रेजी सेना के वेतन और पेन्शनों की बाबत भेजी जाती है और जो विलायत से यहाँ कुछ दिनों के लिए विशेष रूप से आते हैं। इसी में इण्डियन सर्विस की तनखाह और पेन्शनें भी शामिल हैं।

महाशयो ! यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंग्लैंड और भारतवर्ष की सेनाएँ सम्मिलित हो गई हैं अर्थात् पिछले ३० साल से यह विलायती सैनिक महसूल किसी न किसी बहाने से प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता है। यद्यपि भारत सरकार और भारत मन्त्री बराबर इसके विरुद्ध लिखापढ़ी करते रहे हैं। यह केवल इस कारण से होता है कि इंग्लैंड के मन्त्री अपने गच्छों का बोझ हलका करना चाहते हैं और भारतवर्ष पर वह बोझ डाल सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी पार्लियामेंट में भारतवर्ष की आवाज का कुछ महत्त्व नहीं। अपने मतलब को समझाने के लिए कुछ सख्याओं पर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ३० साल पहले अर्थात् १८६२ ई० में विलायती

सैनिक महसूल की कुल रकम दो मिलियन पौण्ड से कुछ अधिक थी, आज यह रकम पांच मिलियन पौण्ड तक पहुँची है। इन ३० साल में से हर साल की सरप्लस देकर में बहुत समय न लूगा। हा इन ३० वर्षों को ६ भागों में बाँट कर प्रति पाँच वर्ष का औसत आपके सामने रखूँगा। १८६२ से १८६७ तक यह औसत २½ मिलियन वार्षिक में कुछ कम था, १८६७ से १८७२ तक यह औसत ३½ मिलियन के लगभग जा पहुँचा, १८७७ में औसत ३ मिलियन डू सौ हजार पौण्ड था, १८७७ से १८८२ तक चार मिलियन से अधिक हो गया। इसके आगे पाँच वर्ष में कुछ ऐसी नहीं हुई। और पेन्शन को बढ़ाने की एक नई स्कीम १८८४ में जारी होने के कारण यह खयाल मिया गया कि अब क्रमशः ऐसी होने का भिलभिला बन्द हो गया। क्योंकि इससे पेन्शन की रकम में कुछ कमी हो गई थी। लेकिन १८८७ से १८९२ तक यह रकम बढ़कर ४½ मिलियन हो गई और १८९२—९३ में पूरे पाँच मिलियन पर पहुँच गई। महाशयो ! आप ने विचार किया होगा कि किस तरह लगातार यह महसूल बढ़ते रहे और ३० वर्षों में यह रकम दूनी हो गई। इसके अनिश्चित इन कर के कारण भारतवर्ष की मत्ता पर इस लिए जोर भी अधिक, अशक्य बोझ पड़ रहा है कि वृद्धे का भाव घट गया है। यदि आप इस वृद्धे के भाव पर भा ध्यान दें तो विदित होगा कि ३० साल पहले की अरेथा भाग्यवश इस कर की तिगुनी रकम अदा कर रहा है। फिर जब आप इस पर विचार करने हैं कि खर्च की यह रकम जिस का खर्च करना भारत सरकार के अधिकार में है, क्रमशः कम होनी जानी है। और जो कुछ सामान सेना

के लिए एकत्र किया जाता है उसका एक अंश भारतवर्ष ही में खरीदा जाता है। तो उक्त रकम की वेशी और भी अधिक असह्य प्रतीत होती है। अब मैं इन गवर्नों के विवरण का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। पहली मद में तो वह रकम है जो सेना विभाग को हर साल फौज की भर्तियों के खर्च के लिए विलायत भेजी जाती है, अनुमान से यह रकम १ मिलियन पाउंड हुआ करती है। परन्तु गत वर्ष पूरे एक मिलियन पाउंड भेजे गये हैं। १८७७ ई० से अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजें सम्मिलित रखी गई हैं इस लिए भारत सरकार को विवश होकर अपनी अंग्रेजी सेना के लिए विलायती सेना विभाग के आश्रित रहना पड़ता है। और इसी कारण से भर्तियों के खर्च के लिए सेना विभाग जो रकम मागे, देनी पड़ती है। इस भर्तियों के प्रश्न के सम्बन्ध में कई मनोरंजक बातें उल्लेख करने योग्य हैं। मैं आपको इन सब के सुनने का कष्ट न दूंगा केवल एक ही घटना सुनाऊंगा। सेना विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों ने कई बार यह विचार प्रकट किया है कि भर्तियों के गवर्नों के लिए जो रकम सेना विभाग वसूल करता है वह आवश्यकता से बहुत अधिक है। यदि भारत सरकार को इस विषय में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय तो वह इस रकम के एक थोड़े से अंश में अपनी आवश्यकता नुसार सेना प्रस्तुत कर सकती है। सर चार्ल्स डलर जो इन विषयों में पारङ्गत समझे जाते हैं अपने ग्रन्थ "इम्पीरियल डिफेंस" में लिखते हैं कि भारतवर्ष से जो रुपया इस समय उक्त उद्देश्य से लिया जाना है वह बहुत अधिक है। यदि भारत सरकार पर ही अंग्रेजी सेना प्रस्तुत करने का काम छोड़ दिया जाय तो लगभग यह सारी रकम भारतवर्ष को बच सकती है।

दूसरी मह सामान प्राप्त करने की है। यह रकम बढ़ती घटती रहती है, परन्तु १ मिलियन पाउण्ड से कम कभी नहीं होती। गत वर्ष तो यह रकम नौ सौ हजार पाउण्ड तक पहुँच गई थी। इसमें भी भारत सरकार के अधिकार परिमित हैं। और उसको अपना सामान विपणन हो कर विलायत के सेना विभाग से गरीबता पड़ता है। कई बार यह शिक्षापन की गई कि उन सेना विभाग बहुत महंगे मूल्य में हमें सामान देता है और पूरा लाभ उठाता है। तीसरी मह इंडियन ट्रूप सर्पिस की है। महाशयो ! मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि यह रकम उन जहाजों के खर्च में अदा की जाती है जो अंग्रेजी सेना को इंग्लैण्ड से भारतवर्ष को लाते और ले जाते हैं। यह जहाज भारतवर्ष की संपत्ति से तैयार होते और उसी के खर्च में रक्खे जाते हैं। गत वर्ष इस मह में २४० हजार पाउण्ड खर्च किये गये। इस विषय पर कई बार बहुत जोर दिया गया है कि वर्तमान में तान जहाजों का विशेष रीति से हर समय सेना के लिये मौजूद रखना अनावश्यक है। विशेषतः जब कि उनका खर्च इतना अधिक है। विलायती सेना मुसाफिरी जहाजों पर ही भरे प्रकार आजा सकती है। सरकार के इन जहाजों को केवल फीजी आवश्यकताओं के लिए पृथक् रखने में एक उड़ी रकम का अप्रयय होता है। क्योंकि वार्षिक में साल में पाँच महीने यह जहाज विलकुट बेकार रहते हैं और कर्मचारियों का वेतन १० हों महीने बराबर दिया जाता है।

अब भत्ते को लीजिये। यह एक छोटी सी मह है और मैं इस पर अधिक न कहूँगा। यहाँ तक तो मैंने पहले भाग का कथन किया अब दूसरे भाग पर ध्यान दीजिये।

इसमें दो मुख्य मदें हैं एक तो उस ब्रिटिश सेना की तनखाहें और पेंशनें जो भारतवर्ष से भेजी जाती हैं दूसरे इंडियन सर्विस के पेंशन पाये हुए नौकरों की तनखाहें और पेंशनें । पहली मद में अब उतना रुपया व्यय नहीं होता जितना कि १८८४ ई० से पहले खर्च होता था । और गत वर्ष इस मद में केवल १ मिलियन पौन्ड खर्च हुए । परन्तु जैसा कि १८८४ में भय था और जैसा कि लार्ड कैमरले और लार्ड नार्थब्रुक ने अपनी १५ 'मई' वाली वक्तृताओं में कहा है, यह खर्च अब दिन ब दिन बढ़ता जायगा । और यदि यही दशा रहो जैसी कि अब है तो बहुत शीघ्र यह पहले की रकम से भी अधिक हो जायगा । इसी विषय में लार्ड नार्थब्रुक ने यह भी कहा था कि गत १४ या १५ वर्ष में सेना विभाग ने लगभग नार मिलियन पौन्ड के ऐसी रकम भारतवर्ष में खर्च की है जो न्याय और नीचित्य के बाहर है । अतएव हमारे पास इसके अनिश्चित और कोई युक्ति नहीं कि इस विषय में हम पार्लामेन्ट से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें ।

महाशयो 'दूसरी' मद प्रास्तव में एक कठिन समस्या है । गत वर्ष इस मद में एक मिलियन नौ सौ हजार पौन्ड या २१ करोड़ रुपया खर्च हो गया । पिछले ३० साल में यह रकम पहले की अपेक्षा दूनी हो गई । मुझे यह मालूम है कि इस प्रश्न में बड़ी कठिनाइयाँ और अड़चने हैं । एक ओर तो गवर्नमेन्ट ने अपने कर्मचारियों को उन्नति की उन्नित आशाएँ दे रखी हैं जिन पर लक्ष्य रखना आवश्यक है । परन्तु दूसरी ओर भारतवर्ष की कंगाल प्रजा के खर्च और लाभ हानि का खयाल रखना सरकार का कर्तव्य है । यदि इस

समय इस मामले पर ध्यान न दिया गया तो नहीं मालूम यह रकम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाय। अतएव हमारी प्रार्थना है कि गवर्नमेन्ट इस मद की पूरी तरह से जाच परताल करे और कोई न कोई ऐसा प्रबन्ध करे, जिस से यह दिन २ दिन की बाढ़ रुक जाय। परन्तु महाशयो ! यदि इस परामर्श पर ध्यान न भी दिया जाय तब भी इंडियन सर्विस के उच्च अधिकारियों की पेन्शनों की भारी रकम पर दूसरी मद में पूरी धन निकाली जा सकती है। और इसके हम हर तरह से अग्रि धारी हैं। मेरी राय में इस किरायत से लगभग एक से डेढ़ मिलियन पौन्ड या १½ से दो करोड़ रुपये की धन हो सकती है। मेरा यह अनुमान कुछ अधिक नहीं। लार्ड नार्थ ब्रुक ने अपने व्याख्या में इस बात पर भी जोर दिया है, जिसका उल्लेख आपके मेमोरियल में है। गत वर्षों में उन कई आक्रमणों के लिए जो साम्राज्य-नीति के कारण किये गये, प्रायः भारतवर्ष से सेना लेकर अन्य देशों को भेजी गई। उदाहरण के लिए फारस, चीन और हम्श के आक्रमणों में लीजिये। इन सब अवसरों पर सेना का सारा खर्च भारतवर्ष ही ने किया, इंग्लैण्ड ने केवल असाधारण व्यय स्वीकार किया। परन्तु दूसरी ओर जब हिन्दुस्तान ने इंग्लैण्ड से कभी कुछ सेना मगवाई, उदाहरण के लिए १८४६ में सिन्ध की लड़ाई में १८४६ में पंजाब, और १८५६ ई० के गदर में, तो इस सेना के सारे खर्चों का एक एक पसा जिसमें उनकी भरती का खर्च भी जोड़ा गया था, भारतवर्ष से जबर-दस्ती वसूल किया गया।

महाशयो ! मेरा अनुमान है कि मैंने इस मामले का वर्णन करते हुए अधिक स्पष्टवादिता से काम लिया कि नहीं

भारतवर्ष के सूनी माल पर महसूल ।



१ मार्च सन् १९१० को माननीय मि० दादाभाई ने भारतीय व्यवस्थापक कॉमिल में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश किया था कि भारत के बने हुए सूनी माल पर जो महसूल लगाया जाता है वह दूर पर दिया जाय इस के समर्थन में मि० गोखले ने निम्न लिखित वक्तृता दी थी —

सभापति महोदय । मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो मेरे माननीय मित्र दादाभाई ने पेश किया है । यद्यपि मेरे समर्थन के कारण उनके और उनके उन मित्रों के कारणों से कुछ भिन्न हैं, जिन्होंने उनके राय व्याख्या दिये हैं । महाशय । मैं इस प्रश्न को कारखाने वालों के नेताओं की दृष्टि से ही नहीं देखता बल्कि समस्त जाति की सामान्य और व्यक्तिगत दृष्टि से देखता हूँ । साधारणतः यह बात ही है कि १५ बरस हुए जब यह महसूल लगाया गया था तो सारे देश में दुःख और असन्तोष प्रकट किया गया था । और इस दशा के प्रकट होने के चार कारण थे, उनका जिक्र मि० दादाभाई ने अपनी साम्प्रतिक वक्तृता में स्पष्टता पूर्वक किया है । अतएव मैं उन पर केवल एक सरसरी दृष्टि डालूँगा ।

पहली बात तो यह थी कि सूनी माल के कारखाने

की इस वक्त अच्छी आस्था न थी, दूसरे सिद्धा संसन्धी सरकार के नए कानून ने कम से कम इस समय तो इस काम को भारी हानि पहुँचाई थी, तीसरा कारण यह था कि यह महसूल इस कारण से नहीं लगाया गया था कि भारत सरकार या भारत मंत्री यह महसूल लगाना उचित समझते थे बल्कि इस लिए कि लकाशायर के व्यापारी प्रबल अनुरोध कर रहे थे कि यह महसूल लगाना चाहिये। भारत सरकार ने उस वक्त भी यह प्रकट कर दिया था कि वह प्रसन्नता पूर्वक इस में शामिल नहीं होती। चौथे यह कि लोगों ने भली प्रकार समझ लिया था कि लकाशायर के व्यापारी भारत मंत्री पर इस कारण से दबाव नहीं डालते थे कि भारत-वर्ष और लकाशायरवालों में प्रतियोगिता होने लगी थी, बल्कि इस कारण से कि लकाशायरवाले भारत के कारखानों की उन्नति को असन्तोष का दृष्टि से देखते थे और इस उन्नति के मार्ग में बाधाएँ डालना चाहते थे यह मालूम हो था कि लकाशायर से प्रायः बारीक सूत का माल आता था और भारत में उस वक्त तक मोटा माल बनता था। अतएव इन दोनों की प्रतियोगिता में कोई शङ्का न थी। यही कारण थे कि जब यह महसूल लगाया गया तो सब ने क्रोध और दुःख प्रकट किया। इसके विवाद में न्याय की दृष्टिगत रखने के लिए मेरी गय में यह देखना आवश्यक है कि उस समय से अब तक इन बातों में कुछ उलट फेर हुआ है या नहीं।

पहली बात को देखने से ज्ञात होगा कि सूती माल के कारबार की अवस्था अब भी अच्छी नहीं, यद्यपि पहले की अपेक्षा इस कारबार में अधिक लाभ हुआ है। सिक्के के कानून

के विषय में मेरा अनुमान है कि अब यह कारवार इस नई पद्धति को स्वीकार कर चुका है वही सामान्य अवस्था देखने में आती है। उस वक्त इस कानून से जो हानि हुई थी वह अब इस महसूल को हटाने के लिए कारण नहीं मानी जा सकती। तीसरा कारण, यह कि यह महसूल लकाशायरवालों के दबाव डालने से नियत किया गया था और यह उद्योगों का धना है और अब भी जब इस दशा का स्मरण होता है तो सर्वसाधारण में उसी क्रोध और दुःख का प्रादुर्भाव हो जाता है। अन्तिम कारण अब उतना जोरदार नहीं रहा और न्याय से हमें यह यात स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि अब कुछ भारतीय कारखाने भी भारीक माल बनाने लगे हैं हा, बहुत कम। और उसीके अनुसार लकाशायर और भारतीय कारखानों में प्रतियोगिता पैदा हो गई है। अतएव १५ साल पहिले की अपेक्षा आज की अवस्था में कुछ अन्तर पड़ गया है। और इस प्रश्न पर पुन विचार करने की जरूरत है, मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैंने भी यह प्रश्न लार्ड कर्जन के समय में इस कौंसिल में कई बार उठाया था, और इस महसूल को हटा देने पर जोर दिया था परन्तु यह आजकल की उन्नत अवस्था से पहले का तिक है। वर्तमान अवस्था ने इस मामले में कुछ फेर बदल कर दिया है, मेरा खयाल है कि हमको इस मामले पर दो तरह से दृष्टि डालनी चाहिये। अथवा तो आर्थिक दृष्टि से और दूसरे व्यापारीय नीति की दृष्टि से अर्थात् भारत के लिए सैन्यी व्यापारीय नीति उपयुक्त है।

पहिले आर्थिक अवस्था को लीजिये। यह स्मरण रखने योग्य है कि वे लोग जिनको यात प्रमाण समझी जाती

हैं इस बात से सहमत हैं कि वे महसूल जो व्यापार की रक्षा के लिए नहीं बल्कि आमदनी के साधनों को बढ़ाने के लिए लगाये गये हैं, उन्हें व्यापार की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों से नहीं जाचना चाहिये। जैसा कि मेरे मित्र मि० दादाभाई नौरोजी ने अभी कहा है। मि० ग्लैडस्टन ने भी जो व्यापार की स्वतन्त्रता के बड़े भारी पक्षपातियों में से थे और कोई सन्देह नहीं कि वे उन्नीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े प्रसिद्ध और गण्यमान्य अंगरेज थे, इस बात की शिकायत की थी कि इस देश में व्यापार की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त घटी सखी और निर्दयता के नियमों से व्यवहृत होते हैं। अतएव यह साधारण महसूल जो केवल आमदनी की दृष्टि से लगाये गये हैं, व्यापार रक्षा के सिद्धान्तों से नहीं जाचे जाना चाहिये। फिर जैसा कि मिस्टर दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि एक जमाने में, जानेवाले सनी माल पर १० फीसदी महसूल लगा हुआ था और उस समय भाग के सनी माल पर महसूल लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठा। फिर यदि जानेवाले सनी माल पर लगाये गये ३½ फीसदी महसूल को आमदनी का हार समझा जाये तो यह प्रश्न ध्यान देने योग्य है कि यह ३½ फीसदी का महसूल जो भारत के सनी माल पर लगाया जाता है क्या हमारी आर्थिक अवस्था की दृष्टि से आवश्यक है। महोदय ! भारत में इस महसूल से केवल १० १२ लाख रुपये की आमदनी होती थी जो बहुत बड़ी सी रकम थी लेकिन गत वर्ष इसने ४० लाख २० की आमदनी हुई जो एक पर्याप्त रकम है। और इस बात पर लक्ष्य रखकर कि अफ्रीका की आय अब न रहेगी, मेरी राय में कोई भी व्यक्ति यह प्रस्ताव न करेगा कि जय भव इनकी आमदनी का को

दूसरा द्वार न निकाला जाय तब तक यह आमदनी रुह की जाय ।

परन्तु मैं इसीके साथ यह कहता हूँ कि यद्यपि यह एकमात्र आवश्यक है तथापि वह और किसी दूसरे जरिये से प्राप्त की जा सकती है । और आर्थिक दृष्टि से यह महसूल आक्षेपणीय है । मेरा कथन यह है कि इन महसूलों का बोझ देश के कगाल निवासियों पर पड़ता है । हा कुछ विशेष दशाओं में उनका बोझ कारखानेदारों पर भी पड़ सकता है । इंग्लैंड के टेरिफ सुधार के विवाद के अवसर पर यह प्रश्न उठाया गया है, कि क्या किस की जेब से निकलता है ? और समय समय पर इस विषय के प्रायः अविचार-पूर्ण निबन्ध मेरे पढ़ने में आये हैं । मेरी राय में व्यापारीय नीति के परिणत इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह ठीक है अर्थात् साधारणतः इस महसूल का बोझ खरीदारों पर पड़ता है और कुछ विशेष हालतों में कारखानेदारों पर । यदि यह बात होती कि भारतीय सूती माल के महसूल का बोझ केवल कारखानेदारों पर ही पड़ता, खरीदारों पर न पड़ता, तो मैं जान इस महसूल को दूर कर देने के पक्ष में खड़ा होता । मेरे मित्र मिस्टर दादा भाई ने इस बात की शिकायत की है कि कारखानों की दशा इस समय बहुत गराब हो रही है । कुछ अन्य स्वदण्डियों ने भी कहा है । परन्तु मेरा अनुमान है कि यह बता देना आवश्यक है कि इस गराबी के पहले कारखाने वाले बहुत कुछ लाभ उठा चुके हैं । कुछ कारखानों के विषय में कहा गया है कि उन्होंने ने ३०—४० और ५० प्रति सैकड़ा वार्षिक लाभ उठाया है । अतएव वर्तमान हानि के समय हमें भूतपूर्व लाभ को भी समरण रखना चाहिये । यदि

हम अच्छे और पुरे सालों के लाभ और हानि का औसत निकालें तो मुझे विश्वास है कि कारखानों की अवस्था की दृष्टि से हम इस महसूल को दूर कराने पर अधिक जोर न डाल सकेंगे। वर्तमान समय की विशेष अवस्था से नजर घुमाने पर स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि इस महसूल का बोझ कारखानेदारों पर नहीं पड़ता बल्कि खरीदारों पर पड़ता है और इस मोटे माल के खरीदार निहायत कमाल आत्मी हैं, एतदर्थ इस महसूल का अधिकांश भाग कमालों की जेब से बसूल किया जाता है, इसी लिए यह बहुत ही आक्षेपणीय है और इसे शीघ्र ही उठा देना चाहिये। रहा जामदनी के प्राटे का प्रश्न, उसके विषय में मेरा एक प्रस्ताव है जो मैं व्याख्यान समाप्त करने के पहले निवेदन करूंगा। यहाँ तक तो आर्थिक अवस्था का उल्लेख किया गया अब व्यापारीय दृष्टि पर दृष्टि पुमाइये।

रक्षित व्यापार और स्वतंत्र व्यापार के विषय में मेरे विचार जो हैं उन्हें संक्षेप में प्रकट करता हूँ। आरम्भ ही में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मेरा यह विश्वास नहीं है कि स्वतंत्र व्यापार हर देश और हर दशा में लाभदायक होगा। जिस प्रकार कोई दुसरा उच्च सिद्धान्त जैसे मानुषिक न्यायता और जाना विनाश के सिद्धान्त सामान्यतः सारे समाज में एक से स्वीकार नहीं किये जा सकते। उसी तरह व्यापार की स्वातंत्र्यता भी सर्वत्र और सब देशों के लिए उपयुक्त नहीं। यद्यपि अनेक लोग समाज में एक दिन मानुषिक न्यायता और समानता का उपदेश देते हैं परन्तु शेष ६ दिन बिलकुल उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। और उनकी जल रणल सेना में बराबर वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार सिद्धान्त पर 'लक्ष्य' रखते

हुए व्यापार की स्वतंत्रता सारे देशों के लिए भलेही उचित हो परन्तु वह समय अभी बहुत दूर है जब वास्तव में कार्य रूप से समारंभ में इसका प्रचार हो सके। जोर जब तक वह समय आए, प्रत्येक देश को अपने व्यापार के हित पर पूरा ध्यान देना चाहिये। बहुत से देशों ने रक्षित व्यापार की नीति को पसन्द किया है। पर रक्षित व्यापार दो तरह का है। एक तो उत्कृष्ट और दूसरा अपरुष्ट। उत्कृष्ट रक्षित व्यापार का नियम यह है कि जिस में उद्योग और शिल्प की उन्नति के लिए कारीगरों को सरकार से सहायता मिले और उनका साहस बढ़ाया जाय। और इसका भी स्थाल रक्ता जाय कि कुछ समृद्धि शाली लोगों की समितियों से समस्त जाति को हानि न पहुँच सके। अपरुष्ट रक्षित व्यापार वह है जिसमें कुछ स्वार्थ परायण और प्रभावशालिनी समितियाँ मिटकर रक्षित व्यापार से लाभ उठाती हैं। और दूसरे देने वाली साधारण प्रजा को उससे हानि पहुँचती है।

मेरा विश्वास है कि यदि भारतवर्ष में उत्कृष्ट रक्षित व्यापार का प्रचार किया जाय तो इस देश का हितसाधन होगा। परन्तु भारतवर्ष की वर्तमान दशा को देखते हुए मुझे मय है कि इस तरह के व्यापार के प्रचार की आशा कम दिखाई देती है। अतएव मेरे विचार से स्वतंत्र व्यापार की नीति ही उपर्युक्त है, राँ यदि उसके नियमों का पालन उचित नीति में हो। यदि भारत के शासन का कार्य प्रजा की इच्छाओं और सम्मतियों के अनुसार होता अर्थात् भारत सरकार का इच्छा से नहीं बल्कि नियमित रूप से प्रजा की इच्छाओं के अनुकूल। तो इस देश की दशा ही और होती। स्वाधीन उपनिवेशों ला शासन, जहाँ

व्यापार को रक्षित बनाने के उद्देश्य से महाराल लगाये जाते हैं (और वास्तव में उपनिवेशों में इस नीति के द्वारा व्यापार की रक्षा के लिये एक सुदृढ़ जीवाण रच दी कर ली गई है) नियमित रूप से प्रजा की इच्छा और राय के अनुकूल होता है, जहाँ इस बात का प्रयत्न है जहाँ के विषय में यह अनुमान कर लेना ठीक है कि ईक्षस ने प्राली प्रजा अपने स्वतंत्रों की भली भाँति रक्षा पर सखती है । और गरनमेन्ट पर भी अपने विचारों का प्रभाव डाल सकती है ।

परन्तु हमारी वर्तमान दशा यह है कि हम हर तरह भारत सरकार के आश्रित हैं । और भारत सरकार से भी अधिक ऐसे विषयों में भारत मन्त्री या इम्पीरियल कौन्सिल के आश्रित, हैं क्योंकि सारी शक्ति इन्हीं के हाथ में है । हम अपनी राय दे सकते हैं, वर्तमान शासन के दोषों पर जाड़ोप भी कर सकते हैं परन्तु अभी वह समय बहुत दूर है जब नियमित रूप से प्रजा की इच्छा और भूमति के अनुसार ही शासन किया जाय । जब तक ऐसी व्यवस्था न हो, जब तक कौन्सिल में हम वह महत्व प्राप्त न कर लें कि गरनमेन्ट हमारी राय को स्वीकार करके उसी के अनुसार कार्य करे तब तक मेरी राय में स्वतन्त्र व्यापार की नीति ही काम में लाई जाय । हा उसके नियमों का पालन उन्नित नीति से हो । यह ऐसी नीति है जिससे इस देश की भलाई होगी । अन्यथा समृद्धिशाली धनवान लोगों की प्रभावशालिनी समितियाँ जो भारत मन्त्री तक आसानी से पहुँच सकती हैं और हम नहीं जा सकते, अपरुष्ट रक्षित व्यापार की नीति से पूरा फायदा अवश्य उठावेंगी और रक्षित व्यापार की शक्तिशालिनी मशीन को भारतवासियों के हित के लिये न घुमाया जा सकेगा, वह उन्हीं समितियों के काम

में आवेगी। इस दशा में हमको रक्षित व्यापार का पक्ष नहीं लेना चाहिये। कम से कम मैं इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हूँ। अतएव मैं इसका समर्थन नहीं करता कि सूती माल पर से इस कारण महसूल उठा लिया जाय कि उससे भारतीय शिल्प की रक्षा होगी। बल्कि मेरी राय है कि इस विवाद से दृष्टि हटाकर हमारा यह कहना कि भारत के सूती माल पर का कर उठा दिया जाय, कम महत्व रखता है।

धकृता को समाप्त करने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उत्कृष्ट रक्षित व्यापार को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए विलायत के दोनों दल एक से हैं। उदार दल तो स्पष्ट स्वतन्त्र व्यापार का पक्षपाती है, हा दूसरा दल रक्षित व्यापार का समर्थन करता है। परन्तु अंतिम चुनाव से पहले होनेवाले वादविवाद में यह स्पष्ट रीति में देखा गया था कि 'रेरिफार्मिफार्म पार्टी' के लोग, जिसमें मिस्टर थोमर ला, लार्ड कर्जन और मिस्टर मिलफोर्ड शामिल हैं इसके अनुकूल हैं कि इंग्लैण्ड की नीति तो रक्षित व्यापार की हो परन्तु भारतवर्ष को, जहां तक उससे व्यापारी नीति का सम्बन्ध है कठिन जमीन से जकड़ कर रखा जाय। यह सत्य है कि अनुदार दल के प्रसिद्ध पत्र "मार्निङ्ग पोस्ट" ने कई लेख प्रकाशित किये हैं जिसमें भारतवर्ष की व्यापारीय स्वतन्त्रता का उल्लेख है परन्तु यह स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पहले हमें अभी कई भीड़ियों को पार करना पड़ेगा और वर्तमान समय में तो मैं इस रक्षित व्यापार के पक्ष को राजनैतिक आन्दोलन से बाहर समझता हूँ।

अब मैं यह प्रस्ताव पेश करूंगा कि यह देखें भारतवर्ष के केवल बारीक सूती माल तक परिमित कर दिया जावे, जिस

। मैं भारतवर्ष और लकाशायर की प्रतियोगिता आ पटती है
 अर्थात् ३० नम्बर से कम के सूत पर यह महसूल न लगाया जाय।
 इसका परिणाम यह होगा कि अधिक महसूल दूर होकर काल
 जादमियों पर पड़ने वाला बाँझ हलका हो जायगा। इस
 हानि को पूरा करने के लिए मेरी राय में विदेशी सूती माल
 पर ३½ फीसदी के स्थान पर ७ फीसदी कर नियत किया जाय
 और इसी तरह भारत के सूती माल पर भी जो ३० नम्बर
 के सूत से अच्छा हो ७ फीसदी महसूल लगा दिया जाय।
 इससे उक्त घटी पूरी हो जायगी।

यदि बाहर से आनेवाला सूती माल २० मिलियन पौन्ड
 का भी रूप लिया जाय तो ७½ फीसदी अधिक महसूल का परि
 णाम यह होगा कि ३०० हजार पौन्ड अर्थात् ४५ लाख रुपया
 कोष में आवेगा। और वह उस ४१ लाख से अधिक होगा
 जो यहाँ के सूती माल से गत वर्ष वसूल किया गया। फिर
 ३० नम्बर के सूती माल से भी यहाँ महँगा कर प्राप्त हो सकेगा।
 इस तरह से कोष को हानि के बजाय अधिक लाभ की
 सम्भावना है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन
 करता हूँ।

स्वदेशी आन्दोलन ।



६ फरवरी सन् १९०७ ई० को राजा रामपाल सिंह के सभापतित्व में मान० मि० गोयले ने लखनऊ की एक सर्व-साधारण सभा में निम्नलिखित व्याख्यान दिया था —

सभापति महोदय और मध्य सज्जनो ! आज मैं आपके सामने भारतवर्ष की व्यावसायिक अवस्था और स्वदेशी आन्दोलन के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ । वर्तमान समय में सब से अधिक उड़ते हुए साहस का चिह्न स्वदेशी का आन्दोलन और उसके विचारों का प्रचार है । पिछले दो वर्ष में यह काम भली प्रकार से हुआ है और उससे पहले भी कई बार ऐसे विचार प्रकट किये गये हैं, परन्तु मेरी राय में फिर एक बार दुहराया जा सकता है कि स्वदेशी आन्दोलन केवल वह आन्दोलन नहीं जो केवल हमारे उद्योग और शिल्प के कारखानों से ही सम्बन्ध रखता हो बल्कि स्वदेशी आन्दोलन, व्यापक और सच्ची देशभक्ति का वह ओजपूर्ण अंग है जो जीवन के किसी एक ही भाग में प्रकट नहीं किया जा सकता बल्कि हमारे सारे जीवन पर उसका अधिकार रहता है । और जब तक वह हमारे जीवन पर अधिकार न जमा लेगा तब तक चैन न लेगा । पहली बात जो मैं इस आन्दोलन के विषय में कहना चाहता हूँ वह यह है कि यह आन्दोलन यहाँ से जाने का नहीं । हम ऐसे आन्दोलन प्रायः देखा करते हैं जो थोड़ा

बहुत द्वन्द्व मचा कर लुप्त हो जाते हैं और उनका कोई दृढ़ प्रभाव शेष नहीं रहता। मेरा अनुमान है कि स्वदेशी आन्दोलन उन आन्दोलनों में से नहीं। बल्कि मेरा विश्वास तो यह है कि रास्तर में इसी आन्दोलन से हमें अन्त में मुक्ति मिलेगी।

महाशयो ! इस समय में स्वदेशी आन्दोलन के व्यापक प्रभावों का वर्णन नहीं किया चाहता। इस बात का प्रश्न हमारे सामने है यह केवल यह है कि स्वदेशी आन्दोलन का हमारी वर्तमान व्यवसायिक अवस्था से क्या सम्बन्ध है। इसकी असलियत क्या है और इसके प्रभाव की परिधि कितनी विस्तृत है। इसके पास अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या प्रयास उपाय हैं ? और इस मार्ग में, इससे पहले कि जब यह भारतवर्ष की व्यवसायिक स्वतन्त्रता का कारण हो, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं ?

महाशयो ! एक बार मि० गनाट ने कहा था कि राजनैतिक मामलों में एक जाति का दूसरी जाति के आधीन होना जितना अधिक विचारणीय विषय है, उतना किसी जाति को व्यवसाय, उद्योग, शिल्प का दूसरी जाति के आधीन होना, विचारणीय नहीं। व्यापारिक परतन्त्रता इतनी प्रभावजनक नहीं होती और चुपके चुपके अपना काम करती रहती है परन्तु राजनैतिक परतन्त्रता की विपत्तियाँ सामने ही खड़ी रहती हैं। हम रोज देखते हैं कि एक अन्य जाति हमारी सारी शक्ति और स्वत्व अपने अधिकार में किये हुए है और हमारी जाति को विवश और शासित रखती है। यह हम रोज देखते हैं और क्षण क्षण में अनुभव करने हैं। मनुष्य प्रभाव

के अनुकूल हम कभी २ उन बातों का, जिनसे हमारे हृदय पर चोट लगती है, उन बातों से अधिक अनुभव करते हैं जिन पर हमारा हानि लाभ निर्भर है जब कि आपके हृदय पर जरा जरा सी बातों से चोट लगती है, जैसा कि शासित अवस्था में होने पर अनिर्णाय है। (मैं किसी विजातीय पर अनुचित अपारोपण नहीं किया चाहता) तो आप अवश्य ही गन दिन इसी विचार की उधेड़ पुन में रहते हैं कि हम दूसरों के आधीन हैं। हमारी व्यवसायिक परतन्त्रता चित्त आकर्षण करनेवाला नवीन परिधान पहिन कर हमारे सामने उपस्थित होती है और राजनैतिक परतन्त्रता साधारण आवश्यकताओं के रूप में हमारे सामने आती है। भारतवर्ष में तो हम इस परतन्त्रता पर विषम हो लड़कूँ रहते हैं और उसकी चित्तरजक, मनोहारिणी बातों के शिकार बन जाते हैं और अन्त में जब यह रोग बहुत बढ़ जाता है तब हम इसकी ओर ध्यान देने हैं। ज्यों की त्यों यही दशा भारतवर्ष में हुई। जैसे ही पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे देशवासियों की आँखें खोलीं तो उनमें चेत होते ही पहले तो अपनी राजनैतिक परतन्त्रता का गयाल आया फिर अपने सामाजिक दोषों पर उन्होंने ध्यान दिया। जो लोग गन ५० वर्षों के इतिहास से परिचित हैं वे जानते हैं कि राजनैतिक और सामाजिक सुधारों का प्रयत्न एक साथ ही आरम्भ हुआ था। इस अवसर पर मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह प्रताने का है कि उस चेत भारतवर्ष को व्यापारीय परतन्त्रता का गयाल नहीं आया और यदि आया भी तो उसने उनके हृदय पर प्रभाव नहीं डाला, जैसा कि राजनैतिक परतन्त्रता उनके हृदय पर गहरा जमा रही थी।

इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे सारे प्रयत्न राजनैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने की अभिलाषाओं के लिए होने लगे। और २० वर्ष पहले जब राजनैतिक सुधार के लिए कांग्रेस स्थापित की गई तो व्यावसायिक तयारी की ओर हमारे सुधारकों ने दृष्टि नहीं डाली जिसकी वर्तमान अवस्था इसके योग्य थी। यद्यपि कुछ बुद्धिमान लोगों ने इस पर ध्यान दिया परन्तु वह काफी न था। अस्तु। अब हमारी औद्योगिक अवस्था अपनी ओर हमारा पूरा ध्यान आकर्षित करा रही है और आज रक्त तो हम इस ओर इतने सहज जान पड़ते हैं कि यह भय होने लगा है कि हमारे औद्योगिक प्रश्न कहीं राजनैतिक प्रश्नों पर अधिकार न जमा बैठें जो वास्तव में उन सब में मुख्य हैं।

महाशयो! जब हम भारतवर्ष की औद्योगिक परतन्त्रता पर लक्ष्य करते हैं तो हमें जान होना है कि अंगरेजी शासन का यह सब से बुरा प्रभाव पड़ा है। और मामलों में तो लाभ और हानि दोनों ही जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिये अंगरेजी शासन के राजनैतिक प्रभाव को लीजिये, एक ओर तो सारी जाति के अधिकार और मान के द्वार बन्द कर दिये गये हैं जिससे जाति के स्वभावों पर धरवादी का प्रभाव पड़ गया है। जाति को जबरदस्ती अस्त्र आर्स्त्र से जकड़ कर चिन्न कर दिया गया है जिससे जातीय शक्ति और यहदुरी का लोप होता जा रहा है। इन बातों पर लक्ष्य रखते हुए जाति विपत्तियों के गड्ढे में गिर रही है। परन्तु दूसरी ओर इसके विनिमय में कुछ भलाई की सूरतें भी हैं और यह भी निश्चय रीति से नहीं कहा जा सकता कि इनका पला भारी नहीं। उदाहरण के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार और स्वतंत्रता का जलवायु जाति के लिये उड़ा लाभदायक प्रकाशित हुआ

हे, समानता की आवश्यकताओं को हम अच्छी तरह समझने लगे हैं। हम यह भी अनुभव करने लगे हैं कि जयतक स्त्रियाँ को उचा पद नहीं दिया जायगा, केवल पुरुष उन्नति क्षेत्र में पग आगे नहीं बढ़ा सकते। निर्दोश पाश्चात्य शिक्षा इस देश में अच्छा काम कर रही है फिर ब्रिटिश राज्य में सत्य के साथ समान न्याय होता है, अर्थात् भारतवासियों के बीच में। जहाँ भारतवासी और अंगरेज का प्रश्न उपस्थित होता है तो उसकी रात ही दूसरी है। परन्तु भारतवासियों के बीच में एक सा न्याय आवश्यक होता है। हा इसके प्राप्त करने में रुपये का विशेष व्यय होता है, पहले शासक के जमाने में यह रात नहा थी। रेल, बिजली का तार, डाक तथा उच्च सभ्यता के अनेक साधन इन्हीं की बदौलत भारतवर्ष में प्रचलित हुए हैं। और सच तो यह है कि इन्होंने व्यावहारिक जीवन में बड़े सुभीते पैदा कर दिये हैं और सविष्य की उन्नति में उनसे बड़ी सहायता मिलनी है। फिर चारा और शान्ति का साम्राज्य है यह भी सत्य से पूरी रात है।

उन हानियाँ के विनिमय में जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है यह लाभ भी हमें प्राप्त है। और मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूँ कि लाभ का पल्ला भारी नहीं है। परन्तु जब आप औद्योगिक अवस्था पर दृष्टि डालते हैं तो ज्ञान होता है कि ब्रिटिश शासन का इस पर नाशकारक प्रभाव पड़ा है। हम उभर हानि ही हानि देख रहे हैं लाभ उठने कम दिखाई देता है यह बड़ा भारी दोष है। परन्तु मैं समझता हूँ कि यह उचित प्रमाणित किया जा सकता है। मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि पहले तो भारतवर्ष की उस औद्योगिक अवस्था पर दृष्टि डालिये जो अंगरेजों के आने के पहले थी। यह ठीक

है कि इसकी साक्षी रूप में सख्याण नहीं पेश की जा सकतीं परन्तु उन यात्रियों के लेगों से जो उस जमाने में भारतवर्ष में आये थे, यहा की अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है यद्यपि उनसे जो परिणाम निकलता है वह विलकुल ठीक और विश्वासयोग्य नहीं कहा जा सकता, उदाहरण के लिये हम अनेक जगह भारतवर्ष की समृद्धिशालीनता का वर्णन पाते हैं तो किसी किसी जगह सर्वसाधारण की दीनता का उल्लेख मिलता है, तथापि यह कहना न्यायसगत है कि भारतवर्ष की दशा उनदिनों खराब न थी बल्कि अनेक देशों की अपेक्षा उसकी अवस्था अच्छी थी और यह अवस्था मुसलमानी राज्य के अन्त तक रही ।

भारत पर अनेकों आक्रमण होने का कारण उसकी समृद्धिशालीनता का चर्चा ही था ।

यहा अत्याधिक सम्पत्ति भरी हुई थी । और जहा तक सर्वसाधारण जनो का उल्लेख है—भूमि उर्वरा थी—किसान लोग परिश्रमी और मितव्ययी थे । अधिकांश शराब आदि नशेराज़ी की आदतों से कतई अलग थे । इन सब बातों पर लक्ष्य रख कर यह निष्कर्ष निकालना कि किसानों हेतुयत्न से उनकी आर्थिक अवस्था सतोषजनक थी, कोई अनुचित नहीं जान पड़ता । भारतवर्ष की २०० वर्ष की प्राचीन अवस्था का पश्चिम की तत्कालीन अवस्था से मुकाबिला करना जब कि वहा मशीनों और जहाजों की शक्ति से पूरा लाम उठाया जाता था, उचित नहीं । हुए के जहाजों तथा अन्य कलों का आविष्कार होने से पहले पश्चिम में भी धा पेटा करने के साधन प्रायः ऐसे ही थे जैसे हमारे यहा । और वहा के

देश भी कृषि प्रधान थे । उस जमाने के उद्देश्य और अवस्थाओं में यदि अनुमान किया जाय तो ज्ञात होगा कि हम बहुत निर्धन नहीं थे बल्कि प्रायः पश्चिमी देशों से धनवान् थे । यहाँ के माल की उत्तमता पर पाश्चात्य जातियाँ भी आसक्त हो रही थीं । और ढाके की बारीक मलमल तथा अन्य चीजें जो यहाँ से बाहर जाती थीं बड़ी बढ़िया होती थीं । इससे इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि हमने उद्योग और शिल्प में केंसी पूर्णता प्राप्त की थी । जब मुसलमान यहाँ आये तो वे यहीं बस गये, सम्पत्ति को बाहर खींच कर लेजाने का कोई प्रश्न नहीं उठा । अतएव पहले ही की तरह सब उद्योगों में बराबर सुधार होता रहा । इसके बाद ब्रिटिश शासन का समय आता है । महाशयो ! मैं इस अवसर पर भूतपूर्व बातों का उल्लेख इस लिये करता हूँ कि उनके प्रकाश में हम वर्तमान और भविष्य की अवस्था के पाठ पढ़ सकें ।

भारतवर्ष की औद्योगिक हीनता के लिए 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के शासन का समय उतना ही हानिकारक था जितना कि हो सकता था । कम्पनी ने जान बूझ कर ऐसी नीति का अनुसरण किया कि जिससे भारतवर्ष के उद्योग और शिल्प का सर्वनाश हो और पाश्चात्य पदार्थ उनका स्थान प्राप्त कर सकें । इसे स्वयम् अंग्रेज लेखकों ने भी स्वीकार किया है । इंग्लैंड की यह कूटनीति भारतवर्ष ही तक परिमित न थी । बल्कि अमेरिका और आयरलैंड के साथ भी यही सुलूक किया जा रहा था ।

अमेरिका ने तो परतत्रता का तौक ही गले से उतार फेंका और उससे मुक्त हो गया, आयरलैंड ने प्रबल आन्दोलन किया

परन्तु सफलता भाग्य में न थी और भारतवर्ष ने तो महान् आपदा में भेली।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का यह उद्देश्य था कि भारतवर्ष को कतई खेती का देश बना दिया जाय जिसमें कच्चा माल स्वयं पैदा हो परन्तु माल तैयार करने के लिए कारखानों का नामनिशान न रहे ! हमारी औद्योगिक हीनता का यह पहला सूत्र था । दूसरा सूत्र उस समय आरम्भ हुआ जब कि इंग्लैंड ने जबरदस्ती हमें स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अनुसरण करने पर बाध्य किया, जिसके कारण हमसे सारे देश प्रति योगिता करने लगे । इंग्लैंड ने सैकड़ों बरस तक रक्षित व्यापार की नीति का अनुसरण किया और उसने उद्योग और शिल्प के क्षेत्र में जो कुछ उन्नति की वह सब इसी की बदौलत । परन्तु साठ बरस हुए जब उसने इस नीति को बदल डाला क्योंकि अब रक्षित-व्यापार की आवश्यकता बाकी न रही थी । इसलिए उसने स्वतन्त्र व्यापार का अनुसरण किया जिससे रक्षित व्यापार से होनेवाली कुछ हानिया भी दूर हो जायें ।

कच्चा माल हासिल करने के लिए इंग्लैंड सदा ही दूसरी जातियों पर निर्भर रहा है जिसके विनिमय में वह सारे ससार को देने के लिए नये नये पदार्थ अपने देश में बना कर प्रस्तुत करता है । इंग्लैंड का लाभ इसमें था कि आने जाने वाले किसी भी माल पर महसूल न हो क्योंकि ऐसे महसूल का अनिवार्य परिणाम यह होता कि पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता ।

परन्तु भारतवर्ष को इस नीति की स्वीकारी के लिए

बाध्य करना एक बिल्कुल दूसरी बात थी और इसका अनिवार्य परिणाम भारतीय उद्योग का सर्वनाश था। हम अपने यहाँ हाथों से चीजें तैयार करते थे, हमारे-यहाँ पश्चिम की 'सौ' शिक्ता, उतना साहस और सहयोगी समि-
 निया नहीं थीं। फिर यहाँ जहाजी शक्ति और कलों का भी प्रचार न था। अतएव यह अनिवार्य था कि हमारे यहाँ की शिल्पकारियाँ इस प्रतियोगिता का सामना न कर सकें और बरबाद हो जायँ। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति का प्रचार होने के बाद वही सही थोड़ी बहुत शिल्पकारी का भी सर्वनाश हो गया। और लोगों को विचित्र होकर पेटों के व्यवसाय में लग जाना पड़ा। मुझे इन शिल्पकारियों के सर्वनाश का कभी गिला न होता यदि गवर्नमेन्ट यहाँ नये नये उद्योग और शिल्प के कारखानों के खोलने में महायत्ना देती जो उनका स्थान ले सकने। जर्मन एकात्मिस्ट तस्ट ने, जिसका व्यापार विद्या पर लिखा हुआ एक ग्रन्थ भारतीय विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य है, स्पष्ट रीति से समझाया है कि गवर्नमेन्ट, किन्हीं ऐसे देश को किस तरह सहायता दे सकती है कि जो सदा से कृषि प्रधान रहा हो और अब उसको अकस्मात् उद्योगी देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ी हो, जिससे वह अपने नये उद्योगों का प्रचार कर सके, वह लिखता है कि उस देश के लिए, जो उद्योग और शिल्प में औरों से पीछे है और उन देशों से मुकाबिला करना चाहता है जो जहाजों और कलों की शक्तियों तथा विधान के आविष्कारों की सहायता लेते हैं, यह आवश्यक है कि वह अपनी दस्तकारियों का नाश होने दे क्योंकि यह मार्ग भी तै करना ही है। जब कि कलों स

यनी हुई चीज़ों का मुकाबिला दस्तकारियों को करना पड़ेगा तो अनिवार्य है कि उनका सर्वनाश होगा। परन्तु जब यह मार्ग ते हो जाता है तो फिर सरकार का कर्तव्य आरम्भ होता है। उस समय गवर्नमेन्ट को उचित है कि रक्षित व्यापार के उचित उपायो से नये २ उद्योगों और कारीगरियों को इस तरह सहायता दे कि वह फल फूल सकें। और जब तक यह कारीगरिया अपने पैरों पड़ी न हो सकें, उस वक्त तक गवर्नमेन्ट को उचित है कि उनके आस पास रक्षित व्यापार की परिधि खींच कर उनकी मदद करे। यही अमेरिका ने किया जो सब से अधिक धनवान देशों में से है और सब से बड़ी समृद्धिमान जाति बननेवाली है। फ्रान्स और जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ।

इंगलिस्तान की कृत्रिनीति का परिणाम भारतवर्ष में यह हुआ है कि गैर देशों का सामान यहां सुभीते से रोज बगेज धडाधड चला आता है। सारे सप्ताह में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जो गैर देशों के सामान पर इतना निर्भर हो जितना कि भारतवर्ष। यहाँ से जितना माल बाहर जाना है उसमें प्राय ७० फी सदी माल कच्चा होता है। यदि हमारे पास पूँजी और कलें होतीं और हम में योग्यता और साहस होता तो हम कच्ची पदार्थों से अनेकों पदार्थ तैयार करते और आज इस देश में उद्योग और शिल्प का बहुत विस्तार होता, परन्तु यह सब माल बाहर चला जाता है और वहां से महँगे और अच्छे पदार्थों के रूप में परिणत होकर यहाँ आया करता है।

॥ फिर यदि आनेवाले माल की ओर ध्यान दें तो जान

पड़ेगा कि ६० फीसदी चीजें इसमें से कलों के द्वारा तैयार की हुई होती हैं। यह वह चीजें हैं जो दूसरों ने बनाई हैं और आपका केवल यही काम है कि आप इन्हें उपयोग में लावें। यदि केवल यही होता—अर्थात् सब में बड़ी आपत्ति यही होती कि हमारे शिल्प में कोई लग रही होती और सेती ही पर हमारा जीवन निर्भर हो जाता, तथा वर्तमान नीति के विरुद्ध हमें केवल यही गिला होता, तो यह भी बहुत ही शोक जनक और शोचनीय था ! तथापि यह अवस्था भी उतनी असहनीय न होती। परन्तु राजनैतिक परतन्त्रता और उक्त विपत्ति ने मिलकर एक ऐसी अवस्था पैदा कर दी है कि जो सर्वथा असहनीय है। हमारे देश में १०० करोड़ का माल बाहर से आता है परन्तु इसके बजाय जो माल बाहर जाता है वह १५० करोड़ का होता है।

तात्पर्य यह कि हमारे यहां बाहर से १०० करोड़ का माल आता है और १५० करोड़ का जाता है। इसपर लक्ष्य रखते हुए भी, कि इस हानि के बदले में कुछ सोना चादी देश में आता है, यह बात जरूरी है कि ३० ४० करोड़ रुपया वार्षिक हानि उठानी पड़ती है। उपस्थित महानुभावों से मैं एक साधारण प्रश्न करूंगा यदि सौ रुपया हर महीने आपके पास आवें और डेढ़ सौ बाहर जायें तो आप बनवान हो जायेंगे या कगाल ? और यदि यह सिलसिला बहुत वर्षों तक अथवा जुगों तक जारी रहे तो क्या दशा होगी। हर साल ३० ४० करोड़ रुपया भागतत्पर्य से बाहर जाता है जो कमी वापस नहीं आता। यदि इस तरह से बराबर रक्त चूसा जाता रहे तो ससार का बड़े से बड़ा धनाढ्य देश भी अवश्य ही एक दिन बरबाद हो जायगा। रक्त चूसना यह एक कठोर

शब्द है परन्तु इसी सम्बन्ध में पहले पहल इस शब्द का एक गण्यमान्य अंग्रेज ने प्रयोग किया था अर्थात् लार्ड सालसवरी जो इंग्लैंड के प्रधान मंत्री थे और उससे पहले भारत मंत्री भी रह चुके थे। वास्तव में इस तरह से रक्त का विनाश होना ही हमारी उन व्यवसायिक विपत्तियों का मूल कारण है जिन का हमें सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि रुपया यदि देश ही में रहता तो लोगों के काम में आता और उद्योग और शिल्प के कारखानों में पूँजी के स्थान पर लगाया जा सकता परन्तु अब हम उसे खो बैठे। परिणाम यह हुआ है कि अब व्यापार व्यवसाय में लगाने के लिए हमारे पास कठिनाता से थोड़ी बहुत पूँजी निकलनी है। इस बात पर न भूलकर कि कुछ लोग धनाढ्य हैं और उनके पास व्यापार में लगाने के लिए पर्याप्त पूँजी है, हमें इस सम्बन्ध में भारतवर्ष का मुकाबिला अन्य देशों से करना चाहिये, तब आपको जान पड़ेगा कि आपके पास बहुत थोड़ी पूँजी बचती है जिसे आप किसी व्यापार व्यवसाय में लगा सकते हैं। मि० जस्टिस रानाटे ने जो व्यापार और अर्थशास्त्र के अच्छे विद्वान् थे, एक बार यह हिसाब लगाया था कि समग्र भारतवर्ष में ₹ १० करोड़ रुपया साल से अधिक बचत नहीं हो सकती। यदि यह २० करोड़ भी मान लिया जाय तो भारतवर्ष जैसे विशाल देश में इतनी बचत की क्या हकीकत रह जाती है! विशेषतः जब हम इसका मुकाबिला उन सहस्रों करोड़ से करते हैं जो पाश्चात्य देशों के निवासी प्रतिवर्ष बचाया करते हैं!

यही हमारी सय शिकायतों का मूल है। मैं यह नहीं कहना कि दूसरी ओर से इसके प्रतिपाद में कुछ बातें नहीं कही जा सकतीं। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि

रेलवे अग्रेजी पृजी से बनी है और इनमें लगभग ३७५ करोड़ रुपया लगा हुआ है तो यह न्यायसंगत है कि, भारतवर्ष इस पृजी का कुछ मुनाफा दे, फिर अग्रेजों ने नील, चाय तथा दूसरे कारगरों में इंग्लैंड की पृजी लगा रखी है। परन्तु यह भी निर्निवाद है कि इस पृजी का कुछ अंश तो वह मुनाफा है जो उन्होंने इस देश में प्राप्त किया है प्रत्येक वंश में चाहे रुपया विलायत से लाया गया हो चाहे यहाँ पैदा किया गया हो, रुपया लगाने वाले इसके अधिकारी अग्रज है कि उन्हें उसपर उचित ध्यान दिया जाय। तथापि इस व्याज की रकम को अदा करके भी भारतवर्ष हर साल ३० करोड़ की भारी हानि उठाता है। सम्भव है कि आप यह प्रश्न लें कि राजनैतिक मामलों से उसका क्या सम्बन्ध? बात यह है कि इस हानि का अधिकांश भारतवर्ष की अर्थात् भाषिक राजनैतिक अवस्था के कारण होता है। मेरा खयाल है कि यदि हम इस आर्थिक हानि का अदाजा, जो राजनैतिक कारणों से प्रतिवर्ष भारतवर्ष को सहन करनी पड़ती है, २० करोड़ रुपया करें तो अनुचित न होगा। होम चार्जस की २७ करोड़ वाली गहरी रकम का अधिकांश इसी मद में लिया जायगा। फिर इसमें अग्रेज, डाक्टरों, वैरिस्टर्स, सौदागरों और दूसरे उद्योगियों की खालाना वस्तु का रुपया जोड़िये क्योंकि युरोपियन होने के कारण अग्रेजों के साथ इस देश में विशेष न्यायन की जाती है जो उनके भारतीय नागरिकों के विषय में नहीं की जाती। फिर अग्रेज शासक और विलायती सेना की श्राय भी इसमें जोड़िये, कुल मिलाकर मैं बिना अयुक्ति के निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इंग्लैंड के अंगीन होने के कारण भारतवर्ष को २० करोड़ रुपया प्रति-

घर्ष तायान देना पड़ता है और याही वस करोड़ की हानि विलापती उद्योग और शिल्प की श्रेष्ठता के कारण उठानी पड़ती है।

यहां तक प्रति घर्ष हमारा रक्त चूसा जाता है आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा संकट है और जब तक कि यह भली भांति दूर न किया जाय तब तक मनोव्यजनक स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि थोड़ी सी पूजी से आप क्या कर सकते हैं। कभी २ आप सुनते हैं कि एक कारखाना यहाँ खुला और दूसरा वहाँ खोला गया। इससे आप धोखा न खाइये यह दशा बड़ी भयावह है—यह मानो एक हाथी और च्योटी का युद्ध है। जब आप पाश्चात्य जातियों की आर्थिक शक्ति का अनुमान करेंगे तब आपको विदित होगा कि इस औद्योगिक सत्सार में हमें जो सामना करना है वह कितना भयानक है। यदि हमारे रक्त की खुसाई का यह सिलसिला बन्द करना स्वीकार है तो यह अनिवार्य आवश्यकता है कि सरकारी उच्च पदों पर हमारे ही आदमी नियुक्त किये जायें जिन्होंने कि पेन्सनी इत्यादि के द्वारा जो रुपया बाहर जाता है वह देश ही में रहे। फिर जो माल अमयात्र भारत सरकार इंग्लैंड से परीक्षती है उसे यथा सम्भव भारतवर्ष ही से परीक्षे और अन्य विभागों में भी हमारी दशा अच्छी बनाना चाहिये परन्तु मेरा चिन्ता है कि भारत घर्ष और इंग्लैंड के राजनैतिक सम्बन्धों में कार्यरूप में बड़े बड़े परिवर्तन धीरे धीरे क्रमशः ही हो सकते हैं, अकस्मात् किसी उलट फेर से हमारी दशा नहीं सुधर सकती। हमारी भलाई इसमें है कि धीरे धीरे हम अपनी शक्ति को बढ़ाने लें और फिर उस शक्ति का सरकार पर दबाव डालें। ज्यों-ज्यों

हमारी शक्ति बढ़ती जायगी वैसे ही भारतवर्ष की सम्पत्ति का बाहर को गिचना भी कम होता जायगा ।

इस कारण से कि हम विदेशी चीजों पर बहुत कुछ निर्भर हैं, जो आर्थिक हानि हमें उठानी पड़ती है वह वास्तव में हमारी पूरी हानि का एक छोटा सा अंश है अर्थात् यह हानि केवल दस करोड़ की है जो पूरी हानि का लगभग $\frac{1}{5}$ है । इसका अर्थ यह है कि यदि हम व्यापारिक दृष्टि से पूरे स्वतन्त्र भी हो जायें तब भी शेष $\frac{4}{5}$ की हानि पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा । फिर इस तरह की पूरी व्यापारिक स्वतन्त्रता स्वप्न की सी बात है । वर्तमान में इसके प्राप्त होने की आशा नहीं । मुझे खेद है कि कुछ सख्ताओं पर ध्यान देने का कष्ट मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह का प्रश्न बिना सख्ताओं के हल नहीं हो सकता । ध्यान दीजिये कि क्या हालत है ? आपको मालूम है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है । गन जनसंख्या के अनुसार ६५ प्रति सैकड़ा और लार्ड कर्जन की गणना के अनुसार भारत के ८० प्रति सैकड़ा निवासी घेती के व्यवसाय से अपना पेट पालते हैं । पृथ्वी में उपज की अब वह शक्ति नहीं रही । प्रति एकड़ की पैदावार क्रमशः घटती जाती है । यदि आप अब तक के समय की पैदावार का मुकाबिला, जिसका उत्कृष्ट आर्देन अकबरी में मिलता है, आजकल की पैदावार से करें तो आपको यह दखकर आश्चर्य होगा कि भूमि की दशा अब कितनी खराब हो गई है । इस पर लक्ष्य रखते हुए कृषि की उन्नति का प्रश्न बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित करना है । आपको पुराने नियमों के स्थान पर यथासम्भव उन नये नियमों का, जो पश्चिम में देखे जाते हैं प्रचार करना है, आपको कृषि विज्ञान और अच्छे अच्छे नवीन औजारों से काम लेना सीखना है । फिर

एक आपत्ति यह है कि इस देश में पैदावार का सिलसिला बहुत छोटे परिमाण पर स्थित है। भूमि छोटे छोटे भागों में विभाजित है, जिस के कारण नए और बहुमूल्य औजारों का उपयोग दुःसाध्य है, फिर किसानों की अल्पज्ञता और असमर्थता मार्ग में रुकावटें डालती है। तात्पर्य यह कि कृषि की उन्नति धीरे धीरे ही होनी सम्भव है। यह एक उपाय है जिससे इस देश के नवयुवक देश की सहायता कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए परस्पर झगड़ने या बकालत के धन्धे में ही बीड़ कर घुस पड़ने के बजाय जिसमें अब स्थान रिक्त नहीं रहा है, आप में से कुछ नवयुवकों को चाहिये कि कृषि की शिक्षा के लिये विदेशों में जायें। नये नये उपायों और औजारों का उपयोग सीखें। और फिर वहाँ से लौटकर कृषि की उन्नति का प्रयत्न करें। ऐसा करने पर तुम केवल अपनी ही खेतीबारी को न सभाल लोगे। बल्कि दूसरों के मार्गदर्शक बनोगे और जब लोग तुमको इससे लाभ उठाते देखेंगे तो वह अवश्य ही आपका अनुसरण करेंगे। गवर्नमेन्ट जिसको अपने कर्तव्यों का अनुभव अभी हाल ही में हुआ है, कृषि के विषय में अब कुछ कर रही है परन्तु इस काम का अधिकांश हमों को करना होगा। कृषि के अतिरिक्त दूसरा काम सूती माल के कारखाने का है। विविध कारखानों के कारखाने पर दृष्टि डालने से जान पड़ता है कि इन कारखानों ने उसतमाम माल का केवल १/३ अंश बना कर तैयार किया जिसकी भारतवर्ष को जरूरत थी अर्थात् २/३ भाग बाहर से जाया। सूती माल के कारखानों में इस देश का १६—१७ करोड़ रुपया लगा हुआ है। शायद आपको यह रकम अधिक जान पड़ेगी परन्तु इसका मुकाबिला उस रकम से कीजिये जो इसी कारखाने में विलायत

के कारखानों में लगी हुई है। केवल लकागायर में इन कारखानों में ३०० करोड़ रुपया लगा हुआ है और इस रकम की सच्चा बराबर बढ़ती चली जाती है। आप हिसाब लगायें तो ज्ञात होगा कि यदि हम चाँगुना माल तैयार करना चाहें तो लगभग ४०—५० करोड़ की पूँजी और लगानी पड़ेगी यह एक दिन में नहीं हो सकता। कोई सन्देह नहीं कि हाथ के करघे काम अच्छा कर रहे हैं और भविष्य में भी उनसे काम की आशा है। परन्तु इससे धोखा न खाना चाहिये। इस काम का अधिकार कलों ही के द्वारा हो सकता है क्यों कि दूसरे देशों से हम इसी दशा में प्रतियोगिता कर सकते हैं। यदि हम उक्त पूँजी उस या पंद्रह वर्ष में भी लगा सकें तो मैं बहुत समझूंगा परन्तु मुझे भय है कि इसमें दस वर्ष से अधिक समय लगेगा। यदि भावी दस वर्षों में भी हम इतना माल प्रस्तुत कर सकें जितने की देश का आवश्यकता है तो मैं समझूंगा कि हमने बहुत कुछ किया। हम सबको चाहिये कि हम अपने सारे प्रयत्न इसी ओर लगा दें और जितना शीघ्र सम्भव हो इस मैदान में विजय प्राप्त करें और इस पर भली भाँति अधिकार जमा लें। यदि समय हमारे अनुकूल भी हो तो भी यह कार्य बहुत कठिन है अनप्यय यह सरासर अनुचित है कि अपनी कठिनाइयों में अनावश्यक और कथोत्पादक वादविवादों की वृद्धि करें। इस प्रश्न को अपनी इच्छानुसार हल करने के लिए हमको चारों ओर से जिसमें गवर्नमेन्ट भी शामिल है, सहायता और सहानुभूति की आवश्यकता है। कम से कम वर्तमान में तो हम कपड़े आदि प्रस्तुत करने के लिये विदेशों पर निर्भर हैं। यदि अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए इस घात का पूरा-पूरा ध्यान न रखें।

गया कि अकारण ही दूसरों को न छोड़ा जाये तो गवर्नमेंट को मशीनों पर २० या २५ फीसदी महसूल लगा देने में कोई रुकावट न होगी और हमको यह हानि पहुँचेगी कि सूती माल तैयार करने की रही सही आशा भी जाती रहेगी ।

इन्हीं के साथ इस देश में अच्छी रई के पैदा करने का प्रश्न भी सामने है । एक समय था कि भारतवर्ष में अच्छी से अच्छी रई पैदा होती थी जिससे बढिया से बढिया मलमल तैयार होती थी । दुर्भाग्य से अब वैसे अच्छी रई भी यहाँ पैदा नहीं होती । इसके अनेक कारण हैं अब जो रई पैदा होती है वह उतनी अच्छी नहीं होती अतएव भारीक सूत प्राप्त नहीं होता । हमें पिछले अनुभव से यह मालूम है कि इस देश में उम्दा किस्म की रई पैदा हो सकती है । बम्बई की गवर्नमेंट कुछ दिनों से यह कोशिश कर रही है कि इस देश में मिश्र देश की सी रई पैदा होने लगे और उसको इतनी सफलता भी हुई है कि भारत और मिश्र के बीच का मेल भारत में पैदा होने लगा है । यदि सिन्ध के सारे रक़्ते में जिसकी दशा मिश्र से मिलती जुलती है, उस रई की खेती में सफलता हो तो भारीक सूत का प्रश्न हल हो जावे । इन विषय में सरकार की सहायता परमावश्यक है । अतएव जो लोग गवर्नमेंट आन्दोलन का जिक्र बड़े जोर शोर से किया करते हैं उनको यह स्मरण रखना चाहिये और समझना चाहिये कि उन पर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, जो लोग यह कहते हैं कि हमको गवर्नमेंट की सहायता की कोई जरूरत नहीं वे हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं और इस तरह से वह हमारी उद्योग और शिल्प की उन्नति को पेंसी हानि पहुँचाते हैं जिसे वे नहीं समझते । तथापि

इस सूती माल के उद्योग के विषय में मेरा आनुमान है कि वर्तमान अवस्था साहस बढ़ानेवाली है।

अब मैं शकर की ओर ध्यान देता हूँ। एक समय था जब हम शकर बाहर भेजा करते थे परन्तु अब लगभग ७ करोड़ रुपये की शकर प्रतिवर्ष हम बाहर से मगाते हैं। दूसरे देशों के शासक अपनी प्रजा को शकर के बनाने में आर्थिक सहायता देते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय निकाले हैं जिससे शकर बहुत सस्ती लागत में तैयार होती है। इसके विरुद्ध हम अभी तक उन्हीं पुरानी तरकीबों से काम ले रहे हैं। भारतवर्ष में और विशेषतः आपके प्रान्त में ईस अधिकता से पैदा होती है यदि हम शकर की तैयारी में उन्नति करने का निश्चय कर लें, और इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि आप विलायती शकर से कुछ सम्बन्ध न रखें तो हम गवर्नमेंट की सहायता से थोड़े ही दिनों में उतनी शकर तैयार करने लगेंगे जितनी हमें अपने देश के लिये अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में कुछ दिन हुए, आपके लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का एक लेख मेरी दृष्टिगत हुआ था, जिसे पढ़ कर मुझे प्रसन्नता होती थी। उन्होंने कहा था कि वह बड़े खुश होंगे यदि बाहर से शकर की आमद बिलकुल बन्द हो जावे। गवर्नमेंट और प्रजा के सम्मिलित प्रयत्नों से शकर की तैयारी का प्रश्न सुभीते से हल हो सकता है। इसी प्रकार बंगाल में इङ्गलैंड से बहुत सा नमक आता है यद्यपि अन्य प्रान्तों में अधिकांश भारतीय नमक का ही इस्तेमाल होता है। इतने बड़े विस्तृत समुद्री किनारे के होते हुए भारतवर्ष बहुत अधिक नमक तैयार कर सकता है। इसके अतिरिक्त लगभग २० लाख की लुनरिया, ५० लाख की दियासलाईयाँ और ६० लाख का

कागज हर साल बाहर से आना है। यह सब चीजें अब यहाँ बनाई जा रही हैं यदि हम यह निश्चय कर लें कि हम इन्हीं का उपयोग करेंगे और यथासम्भव उनकी तैयारी और उनके प्रचार में सहायता देंगे तो हम एकदम बाहर से इस माल की आमदनी रोक सकते हैं परन्तु इन सारी बातों के बाद मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि सम्प्रति इस विषय में अधिक आशा नहीं। मैं यह इसलिये नहीं कहता कि आपका उत्साह भग्न हो जाये बल्कि मेरी इच्छा यह है कि आप में भरपूर उत्साह और साहस बना रहे परन्तु इसके साथ ही यह याद रखिये कि एक हाथी और च्योटी का मुकाबिला है। यदि हम इस बात का दृढ़ इरादा कर लें कि हम विदेशी वस्तुओं से कोई सम्बन्ध न रखेंगे तब भी भारतवर्ष की व्यापारिक हीनता का सुधार न होगा। सम्प्रति भारत वर्ष सारे ससार में सब की अपेक्षा निर्धन देश है इसके विरुद्ध इंग्लैंड सम्पत्ति का भाण्डार है। भारत सरकार के हिसाब के अनुसार भारतवर्ष में प्रत्येक आदमी की आमदनी का औसत ० पौन्ड या ३०/ ४० सालाना पड़ता है। इसके विरुद्ध इंग्लैंड में प्रत्येक पुरुष की औसत आमदनी ४० पौन्ड सालाना है अर्थात् इस देश की आमदनी से २० गुना अधिक। यह तो आमदनी का पड़ता हुआ। अब देखिये कि बाहर से माल खरीदने का पड़ता की आदमी पर क्या पड़ता है? इंग्लैंड में बाहर से आनेवाले माल का पड़ता आदमी पीछे १५ पौंड या २२५ २० है, स्वाधीन उपनिवेशों में १३ पौंड, की आदमी पड़ता है, लका में दो पौंड का औसत है परन्तु भारत में यह औसत केवल ६ शिलिंग ५ पेन्स की आदमी पड़ता है। कुछ पसी ही आश्चर्यजनक सत्याप

और भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए बैंकों का प्रचार इस देश में बहुत कम है और हम अभी इस सम्बन्ध में बहुत सचे हैं तथापि इनका खयाल रखने के बाद भी आप देखेंगे कि दोनों में पृथ्वी आकाश का अन्तर है। इंग्लैंड की बैंकों में १२०० करोड़ रुपया अमानतों का जमा है और वहाँ की जन-संख्या केवल चार करोड़ है परन्तु सारे भारतवर्ष में ५० करोड़ से अधिक रुपया बैंकों में नहीं जमा है और फिर इस रकम में वे अमानतें भी सम्मिलित हैं जो अंग्रेज दुकानदारों और मोदगारों की हैं। मेविंज बैंको को लीजिये। इंग्लैंड में इन बैंको में ३०० करोड़ रुपया जमा है, इस देश में १२ करोड़ से अधिक नहीं अर्थात् इस देश का औसत सात आना की आदमी पड़ता है और इंग्लैंड का आदमी पीछे ७५ रु०—इस से आप मरलता से जान सकते हैं कि इंग्लैंड और भारत वर्ष की शक्ति और साधनों में कितना बड़ा पृथ्वी और आकाश का अन्तर है। फिर यह भी खयाल रखिये कि मशीनें सब विलायत से आयेगी और जब तक आप मशीनें लगावेंगे और काम शुरू करेंगे, तब तक इंग्लैंड आप से कुछ और आगे बढ़ जायगा। अस्तु ! इस समय जो प्रश्न हमारे सामने है वह बहुत फठिन है और स्वदेशी के प्रत्येक पक्षपानी का यह कर्तव्य है कि यथासम्भव वह इन फठिनाइयों में वृद्धि न होने दे।

हमारे पास साधन कम हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं। अतएव हमें उचित है कि जिस रू से जो सहायता हमें मिले उसको व्यर्थ न जाने दें। यह स्मरण रखना चाहिये कि छोटी छोटी आर्मीय दस्तकारियाँ स उन्नति की गुजायश हैं। परन्तु हमको सारे सस्तर का जमाना करना है, अतएव सामान्यतः हमें

मशीन और इजनों की शक्ति पर ही भरोसा करना पड़ेगा। इस पर लक्ष्य रखते हुए देखिये कि हमारी वर्तमान आवश्यकता क्या है ? प्रथम ससार की व्यापारिक अवस्था का ज्ञान हमारे देशनियामियों को साधारणतः बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि सारे ससार की अपेक्षा हमारी क्या दशा है और हमारी ऐसी दशा क्यों है ? तथा दूसरों की दशा हमसे कहीं बढ़ी बढ़ी है इसके क्या कारण हैं ? दूसरे हमारे पास पूँजी बहुत कम है और उसे लगाने में लोग हिचकते हैं। पारम्परिक विश्वास, मिलजुल कर काम करना, सामे का कारबार इत्यादि बातों का यहाँ अभाव है। तीसरे उद्योग और शिल्प की शिक्षा की यही कमी है। अन्त में यदि हम कुछ नवीन वस्तु बनाने में सफल भी होते हैं तो सारे ससार से प्रतियोगिता करने की आफत हमारे सर पर पड़ी होती है। अगे आरम्भ में इन नई चीजों का मूल्य कुछ अधिक होना और चीजों का कुछ घटिया होना दोनों बातें अनिवार्य हैं अतएव भारत के बाजारों में उनका प्रचार बहुत कम होता है।

जिस तरह से हमारी आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न हैं उसी तरह स्वदेशी आन्दोलन का काम करने के नियम भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। और हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जो लोग स्वदेशी का काम हमसे भिन्न ढंग पर करते हैं उनसे न झगडे। जो लोग देश में ससार की व्यापारिक अवस्था के ज्ञान का विस्तार करते हैं और हमको उन्नति का मार्ग सुझाते हैं वह भी स्वदेशी के सहायक हैं। फिर जो लोग अपना रुपया स्वदेशी कारबार में लगाते हैं और स्वदेशी उद्योग, शिल्प की उन्नति के लिए रुपया

खर्च करते हैं- वह भी स्वदेशी के शुभचिन्तक और हमारे
 आन्दोलन के प्रक्षरानी हैं। इसी प्रकार जो भारतीय विद्यार्थी
 विदेशों में उद्योग और शिल्प की शिक्षा के लिए रुपया जमा
 कर के भेजते हैं या वे विद्यार्थी जो इस शिक्षा को प्राप्त करने
 के लिए विदेशों का प्रवास करते हैं और वहां से लौटने के बाद
 नये नये उद्योगों का प्रचार करते हैं, या जो उद्योग शिक्षा को
 देश ही में वृद्धि करते हैं वे सब स्वदेशी के सहायक और पक्ष
 पाती हैं। स्वदेशी आन्दोलन के यह तीन उपाय वर्तमान में
 थोड़े ही से लोगों तक परिमित हैं। हाँ एक चौथा उपाय
 अवश्य ऐसा है जिसमें कि हम सब योग दे सकते हैं और कुछ
 लोगों के लिए तो केवल यही एक उपाय है, कि जिससे वे
 स्वदेशी आन्दोलन में भाग ले सकते हैं वह यह कि हम स्वयम्
 जहां तक हो, स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार करें। और ओरों
 को भी इसके लिए उत्साहित करें। इसी तरह से हम उन
 चीजों की बिक्री का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं जिन्हें देशी
 कारीगरों ने तैयार किया है। ओर नई चीजें भी मांग पैदा
 कर के कारखाने वालों का साहस बढ़ा सकते हैं। सर्व
 साधारण-व्यवसायिक उन्नति के लिये बहुत रुपया नहीं दे
 सकते, न वह उद्योग, शिल्प प्रीत्यक्ष शिक्षा के प्रचार में कुछ
 सहायता दे सकते हैं परन्तु वे अपने यहां के उद्योग और
 व्यापारों की उन्नति के आरम्भ काल में स्वतन्त्र और उदारता से
 काम देकर उनकी रक्षा करके स्वदेशी का बहुत कुछ उपकार
 कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीतना जायगा स्वदेशी माल
 सस्ता और बढ़िया तैयार होने लगेगा। और यह बात प्रजेमा
 के योग्य न होगी कि आप उनकी उस वक्त प्ररीदें। जब वे
 अपने अच्छे और सस्तेपन के कारण पिलायनी माल से

प्रतियोगिता करने में समर्थ हो जायें। यदि हम अपने यहां की चीजों की धिकी का प्रयत्न ऐसी दशा में कर सकें जव यह बहुत बड़ी भी नहीं होती और महंगी भी होती है तो निस्सन्देह हम अपने व्यापार की गथा उसी तरह कर सकेंगे, जिस तरह से कुछ राज्य रक्षित व्यापार की नीति का अनुसरण धाँके कर सकते हैं। जो लोग यह उपदेश देते फिगते हैं कि लोग यथासम्भव स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करें वही एक पवित्र कार्य कर रहे हैं और मैं उनसे कहूँगा कि वीरों की भाँति आगे बढ़े रहो। और बड़े उत्साह और ओजपूर्ण उपदेश दो। हाँ इसे न भूलो कि इस ढंग के अतिरिक्त भी स्वदेशी आन्दोलन के कई ढंग हैं। अपना काम मेज़ीर्ण और विद्वेष पूर्ण विचारों के जोश में न करो। यह न कहो कि वह हमारे साथ नहीं, वह हमारे विरोधी हैं, बल्कि ऐक्यता और उदारता के उस जोश में काम करो, जिसका यह मूल मंत्र है कि जो हमारे विरोधी नहीं वह सब हमारे साथ हैं। अपने चित्त के इस दोष को जो दुर्भाग्य से आज भारतीय जनों का स्वभाव सा हो गया है, और जो छोटे छोटे जन्यों को बहुत बड़ा कर दिखाया करता है दूर कर दो क्योंकि हम अपनी वर्तमान दशा में मेल मिलाप, पारम्परिक सहानुभूति और सम्मिलन से ही अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा खयाल है कि मुझे कुछ शब्द उस धारा के विषय में भी कहने चाहिये जो वर्तमान में मेरे कुछ देशवासियों को एक बड़ी भ्रान्ति में डाल रहा है अर्थात् "विलासनी वस्तुओं का अधिकार" मुझे पूरा विश्वास

कि इनमें जो प्रायः वहिष्कार का उल्लेख किया करते हैं, उससे केवल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विलायती चीजों की अपेक्षा स्वदेशी वस्तुएँ ही व्यवहार में लानी चाहिये। ध्यान दीजिये तो मालूम होगा कि यह उद्देश्य स्वदेशी के सर्वथा अनुकूल है परन्तु दुर्भाग्य से, वहिष्कार-वायकाट के शब्द के साथ यह दोष लगा हुआ है कि आपका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को हानि पहुँचाना और उनसे घटला लेना है चाहे उसने आपको भी कुछ हानि क्यों न पहुँचे। इसलिए मैं रायाल करता हूँ कि यही अच्छा होगा कि हम केवल स्वदेशी शब्द का प्रयोग करें और वहिष्कार का तिलाजलि दें क्योंकि उससे लोगों के हृदय में अविश्वास ही हमारी ओर से मनोमालिन्य पैदा होता है। फिर यह भी याद रखिये कि वर्तमान औद्योगिक दशा में विलायती माल का कतई वहिष्कार करना सर्वथा असम्भव है क्योंकि जहाँ आपने, विलायती माल का वहिष्कार किया तो आपको-बाहर-से आई हुई कोई चीज भी न छूनी चाहिये।

परिणाम यह होना है कि हम ऐसी बातों की चर्चा चला कर, जिन्हें कार्यक्रम में परिणत करने के लिए हम सर्वथा असमर्थ हैं, दूसरों की दृष्टि में अपने को हीन बनाने हैं।

समाप्त करने से पहले मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, हम मुठभेड़ में जिसका हमें सामना करना है, हमें असफलताओं के लिए भी तैयार रहना चाहिये। हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमारी उन्नति कम-कम से होगी और आरम्भ में हमारी मफलताएँ विलकुल साधारण सी होंगी। परन्तु यदि हम अपनी धुन के पक्के हैं और दृढ़ इरादों के साथ काम करने हैं तो कैसी हा-बाधाएँ क्यों न हों, अधिक

समय तक वह हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। यह माना कि औद्योगिक प्रश्न बड़ी कठिनता से हल होनेवाला है परन्तु राजनैतिक प्रश्न से ज्यादा कठिन नहीं है। आगे मेरी गय में तो दोनों एक दूसरे से जुटे हुए हैं। महाशयो ! भारतवासियों को इस बात जो मार्ग न उग्न के लिए सामने प्रस्तुत है वह बहुत कटकाफीर्ण है, जो काम हमें स्यापा गया है वह बहुत कठिन है। ऐसा दुष्कर कार्य हमारे सामने क्या रक्खा गया ? क्यों हमें इस संझाग में झोटा दिया गया ? इस भयानक सप्राप्त में हमें क्या भिडा दिया ? यह तो भाग्य ही जानता है परन्तु यह मेरा विश्वास है और मुझे इसकी आशा है कि हम इस मार्ग को पार कर के ही रहेंगे, काम को पूरा करके झोड़ेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतमाता की सेवा अच्छे हृदय से थड़ा के साथ करें। इस सेवा में अधिक महत्त्वमयी, परिश्रम और उच्च क्या वस्तु हो सकती है। यदि हम भारत की सेवा करेंगे जिस की परिश्रम भूमि में उत्पन्न होकर हम उठे पड़े, जिसमें हमारे पूज्य गुरुजन बाप दादा बड़े पड़े हैं और जिसमें हमारी सन्तान फले फलेंगी, यदि हम उस देश की सेवा करें जिसका प्रवृत्ति न हर तरह से समृद्धिवाली बनाया है परन्तु खेद है कि मनुष्य ने उसका मान नहीं किया और उसकी सेवा से जी चुराया यदि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल इस समय अपने दश की सेवा के लिये कटिबद्ध हो कर तयार हो जायें तो मन्देह नहीं कि भारतमाता उन्नति के मार्ग में आगे पग बढ़ाती हुई फिर एक दिन सत्कार की अन्य जातियों के समान होकर सम्मान और गौरव के स्थान पर पहुँचेगी।

सन १९०८ का बजट।

अप्रैल सन १९०८ में गवर्नमेंट हाउस कलकत्ते में वायसरॉय के सम्भाषित्व में बजट पर जो बहस हुई थी उस पर व्याख्यान देते हुए मि० गोखले ने अराल इत्यादि सामयिक घटनाओं की विवेचना करने हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, और वर्तमान राजनैतिक अवस्था के विषय में कई प्रभावशाली और निवार और बुद्धि से भरी हुई बातें कहीं। शिक्षा के विषय में उन्होंने कहा। "मेरी समझ में यह आवश्यक है कि जिन बातों पर हमारे देश के सर्व साधारण की आर्थिक और सवचाचार की दृष्टि निर्भर है उनमें हमारे दिव्य हुए लगान का जितना भाग व्यय किया जाता है उससे अधिक व्यय होना चाहिये। सेना, पुलिस इत्यादि में उतना ही खर्चा व्यय करना चाहिये जितना विश्रान्ति एपने के लिये आवश्यक है, किन्तु वर्तमान समय में शिक्षा एसे विषय में जितना व्यय किया जाय उतना थोड़ा है। मुझे शोक के साथ कहना पड़ता है कि इस विषय में गवर्नमेंट अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है। ससार भर में और सब राज्य अपने राज्य में मरकट बालकों का मुक्त और जबरदस्ती शिक्षा देना अपना धर्म समझते हैं। गायकवाड़ ने भी अपने राज्य में मुक्त और जबरदस्ती शिक्षा देना आरम्भ कर दिया है। अन्य मध्य राज्य और गायकवाड़ अपनी प्रजा के लिये जा कुछ कर रहे हैं भारतवर्षीय गवर्नमेंट को भी हमारे लिये

करना चाहिये । ऐसे स्पष्ट कर्तव्य का पालन अप्रत्यक्ष ही करना पड़ता है और एक दिन भी इसके पालन में विराम करना लोगों के ऊपर अन्याय करना है । हम से कभी ? यह कहा जाता है कि इतने बड़े काम के लिये रुपया मिलना, असम्भव है ।

किन्तु, श्रीमन्, मैं फिर कहता हूँ कि रुपया माजबूत है या बिना किसी बाध के मिल सकता है । यदि कार्य करने की इच्छा और सकलप हो तो केवल हम बात की गहस करने में समय नष्ट न होगा, कि कार्य में ये २ कठिनाइयाँ ह । दूसरा प्रश्न शिल्प, मस्यन्धी और औद्योगिक शिक्षा का है, २० लाख रुपये के व्यय से शिल्प, और औद्योगिक शिक्षा देने के लिये एक ऐसा विद्यालय खुल सकता है जिसकी सत्कार के बड़े विद्यालयों में गिनती हो सके । इससे न केवल देश में शिल्प और औद्योगिक शिक्षा की उन्नति होगी किन्तु लोगों में उत्साह और मन्तोष की भी वृद्धि होगी । म सफाई के विषय में कह चुका हूँ । अन्त में खेती का विषय है । इसकी वृद्धि और सुधार के लिये जो रुपया आवश्यक होगा उसके लिये बर्ज लिया जा सकता है, और ऐसे कार्य के लिये रुपया कर्ष लेने की गुञ्जाइश भी है क्योंकि सरकार का साधारण कर्जा केवल लगभग ४३ करोड़ २० लाख रुपये के है ।

श्रीमन्, वर्तमान समय बहुत चिन्ताजनक नल विचारशील और उत्सुक मनुष्य इसी बात लो लुण हैं कि इस चिन्ताजनक समय के कौमी अग्रगण्य होगी । वर्तमान समय में ऐसी रहो हैं जिनका स्वाभिमान और सहृदय मनुष्यों अमह्य मालूम होना स्वाभाविक है और

सरकारी व्यय की वृद्धि ।

[भारतीय व्यवस्थापक सभा का अग्रिवेशन ता० २२वीं जनवरी, १९११, को था। श्रीमान् गार्ड हार्डिन्ग सभापति थे। माननीय मिस्टर गोरखे ने यह प्रस्ताव किया कि पिछले वर्षों में सरकारी व्यय में जो बड़ी वृद्धि हुई है उसके कारणों की जांच की जाय। इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए, 'मिरर' गोरखे ने यह बक्तना दी —]

माननीय मिस्टर गोरखे — श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह कौंसिल गवर्नर-जनेरल इन कौंसिल से यह सिफारिश करती है कि सरकारी और गैर सरकारी मंत्रियों के सम्मिलित कमिशन द्वारा उन कारणों की सार्वजनिक जांच कराएँ, जिनके कारण पिछले वर्षों में दीवानी और सैनिक दोनों ही विभागों के सरकारी खर्च में बड़ी बाढ़ हुई है, जिसमें जहाँ आवश्यक और सम्भव हो व्यय के घटाने के साधन निश्चित किये जायें।

श्रीमान्, पिछले वर्ष इस कानून की बजट पर यह मत और विशेष कर अर्थ-सचिव के उस अवसर पर प्रयोग किये हुए शब्दों से मुझे आशा हो चली थी कि सरकार स्वयम् ही कम से कम देश के दीवानी खर्चों की जांच करवाएगी। परन्तु वह आशा निर्मूल सिद्ध हुई, और मैं, अनन्त अपना यह

कर्त्तव्य समझता हूँ कि यह प्रस्ताव में कांसिल के विचार के लिए पेश करें। श्रीमन, पिछले वाग्ह साल भागतवर्ष, की आर्थिक अवस्था में कई बातों में, बड़े ही मार्के के हुए हैं। कई घटनाओं के संयोग से, जिनका वर्णन मैं अभी करूंगा, भागतीय सरकार को साल व साल बहुत बड़ी चढ़ी आमदनी होती गई—बहुत बड़ी चढ़ी से मेरा अर्थ है, इस देश की दशा को देखते हुए। और कर देने वालों का थोका किसी हद तक हलका करने में यद्यपि सरकारी कोष की समुन्नति का उपयोग किया गया, परन्तु हिन्दुस्तान ऐसे देश में भरे हुए राजाने के अनिवार्य परिणाम निस्संदेह प्रकट हो गये, और व्यय का निर्गम प्रत्येक दिशा में इस ढंग से चढता गया कि इस देश के इतिहास में सचमुच उसका दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़ी और अपूर्व यह वृद्धि हुई है इसका, अन्दाजा इस बात से होता है कि दोही साल हुए, अचानकक और बिना किसी चेतावनी के हमें भारी घाटे के साल का सामना करना पड़ा और घटी भी इतनी कि उलवे के बाद उतना घाटा इस देश को कभी नहीं सहना पड़ा है। और गत वर्ष, मानो स्थिति की गम्भीर दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिये, अर्थ सचिव को ₹० १,८७५० ००० का नया टेक्स, एक ऐसे साधारण वर्ष में लगाने को विवश होना पड़ा, जिसमें न तो दुर्भिक्ष था, न युद्ध ही हुआ था उनमें से कोई ऐसा आशका-जनक कारण ही उपस्थित था जिनका गत वर्षों में सम्यन्ध हमारे मन में नये कर के साथ होता आया है। आर्थिक दशा के इतने अपूर्व और इतने अशान्ति पैदा करने वाले विकास की, मेरी विनम्र सम्मति में, कड़ी जांच करना आवश्यक है, और आज मैं इस कांसिल में यह बहस इस

लिये उठाई है कि मैं चाहता हूँ कि सरकार इस मामले को जाचे ।

श्रीमन्, पिछले वर्षों में सरकारी व्यय में कितनी अधिक वृद्धि हुई है, इसको ठीक ठीक समझने के लिये यह आवश्यक है कि भागीय आर्थिक इतिहास के कुछ विस्तृत समय की सक्षिप्त रूप से आलोचना की जाय । और यदि कौंसिल मुझे अवकाश दे तो मैं सन् १८७५ से लेकर पिछले ३५ वर्षों की अत्यन्त संक्षेप से आलोचना करने की कोशिश करूँ । मैं १८७५ से इसलिये आरम्भ करता हूँ क्योंकि, कई बातों में वह वर्ष टंकसाली है—साधारण साल भी था—टंकसाली इस लिये कि लार्ड लारैन्स, लार्ड मेयो और लार्ड नार्थटुक के पुराने शासन काल से उसका सम्बन्ध है। उस वर्ष से आरम्भ कर पिछले ३३ साल के सरकारी आयव्यय की संक्षेप से मैं आलोचना करना चाहता हूँ । लेकिन इसके पूर्व मैं इस देश की आर्थिक दशा के विषय में एक या दो साधारण विचार कौंसिल की बैठक में उपस्थित करना चाहता हूँ । जो लोग हमारे आय व्यय के चिट्ठे ही को रिफ देखते हैं उनके विचार हमारी असली आमदनी या असली व्यय की वास्तव कुछ भ्रान्तिमूलक होते हैं । चिट्ठों में कुछ महँ तो थोड़ा और कुछ खर्च घटाकर दिगाई जाती है । लेकिन मेरी राय में न तो थोड़ा और न असली महँ ने हमारे वास्तविक आय व्यय का ठीक ठीक पता चलना है । असली आमदनी जानने के लिये यह जरूरी है कि घड़ी महँ से, जिन्हें चिट्ठे में प्रिंसिपल हेड्स कहते हैं, मुद्राज, तगादिले, ग्रापिनी तथा अफीम की लागत की रकम घटाई जाय । इसके सिवाय रेल, नहर, डाक और नगर आदि से व्यापारी महकमों का खर्च घटाकर आमदनी

नीलाम, और इनमें दीवानी और फौजी महकमों की आमदनी जोड़ देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस रीति से हम अपनी असली आमदनी को ठीक २ जान सकते हैं। गत वर्ष के बजट के अंको को देखने से—क्योंकि वे ही अभी ताजे हैं—हमें पता चलता है। हम पता लगता है कि चिट्टे की थोक या वास्तविक आय से एक ठम भिन्न, हमारी असली आमदनी लगभग ५३० लाख पाँड़ या ८० करोड़ २० होती है। इसमें से ८६० लाख पाँड़ की आय बड़ी मद्दा से, १० लाख पाँड़ रेल और नहर से, २० लाख पाँड़ दीवानी के महकमा से और ४० लाख पाँड़ से कुछ अधिक सैनिक विभाग से हुई है। इस आय से ४० लाख पाँड़ ने उपजाऊ ऋण के सूझ में और १० लाख पाँड़ प्रतिवर्ष अकाल-फड में दे दिया जाता है। यदि हम ये २० लाख पाँड़ लाय तो मुरक की दीवानी और फौजी सत्तनत के लिए ५१० लाख पाँड़ बचने ह। इसमें से ३०० लाख पाँड़ से कुछ अधिक तो दीवानी में और २१० लाख पाँड़ से कुछ कम फौज में सर्फ किया जाता है। दीवानी के खर्च की मद्दा में १० लाख पाँड़ तो आमदनी के जमा करने में, १५० लाख पाँड़ दीवानी के महकमों की तनखाहों और इमराजान में, ५० लाख पाँड़ दीवानी मुतफरिकात में और ४५ लाख पाँड़ दीवानी कामों में खर्च होते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में यह पहिला बात है जिस में चाहता हूँ कि कोसिल याद रखते। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि यह असली आय, अफीम की आमदनी को छोड़ कर क्योंकि वह अनिश्चित है और शीघ्र ही एक ठम बन्द हो जाने को है, प्रतिवर्ष १॥॥ की सदी के हिसाब से खयमेव बढ़ सकती है।

जिस रीति से मैं इस परिणाम को पहुँचा हूँ वह बहुत ही गूढ़ है और उसके वर्णन में मैं कासिल को यकाना उचित नहीं समझता। जहाँ तक मुझसे हो सका है, जहाँ तक मैंने इसकी कोशिश की है कि निर्णय ठीक हो और मैंने निर्णय करने के क्रम के विषय में उन सज्जनों से पृच्छा-पाठ भी कर ली है जिनको ऐसे मामलों पर सम्मति देने का अधिकार है मैं समझता हूँ कि मैं यह कह दूँ कि मैंने इसका पूरा प्रयत्न किया है कि जिन रकमों को छोड़ देना उचित था वे, इस निर्णय से निकाल दी गई हैं और मेरा विश्वास है कि परिणाम प्रायः ठीक मान लिया जाय। इस निर्णय के अनुसार जमीन की आय को छोड़ कर हमारी आय में भूँडे और बुरे सालों को लेकर प्रतिवर्ष १॥ फीसदी की औसत प्राप्ति हो सकती है। इससे, अतएव, यह परिणाम निकलता है कि साधारण आवश्यकताओं के लिए व्यय में वृद्धि, अर्थात् किनो विशेष कार्य के लिए विशेष खर्च को छोड़ कर, इसी १॥ फीसदी सालाना के भीतर ही होना चाहिये। मुझे आशा है कि कॉन्सिल इन दो बातों का खयाल रखेगी। ओर पिछले ३० या ३३ साल में व्यय की वृद्धि की आलोचना में मेरा साथ देगी। १९०८—०९ ही को इस ३३ साल की अवधि का अन्तिम वर्ष लेना उचित होगा, क्योंकि पहले तो इस वर्ष तक व्यय की किसी रोक टोक के बिना निरन्तर वृद्धि होनी आई है और दूसरे जनसाधारण को इसी वर्ष तक के पूरे जक अभी मिल सकते हैं। इन ३३ वर्षों का समय लगभग समान अवधि के चार भागों में विभाजित होता है पहिला ६ वर्षों का सन् १८७१ से लेकर सन् १८८४ तक, दूसरा १० वर्षों का सन् १८८४ से लेकर सन् १८९४ तक,

तीसरा ७ वर्षों का सन् १८६४ से १९०१ तक, और चौथा ७ साल का सन् १९०१—०२ से सन् १९०८ से १९०९ तक। अब श्रीमन्, निष्पक्ष तुलना के लिए यह जरूरी है कि चुने हुए वर्षों की रकमों को समान परिणाम में परिवर्तन करके, जिसमें आय और व्यय दोनों ही के अर्कों में से विशेष रकमें निकाल दी जाय अथवा, यदि एक्सचेंज की दर (या रुपये का भाव) किसी दो सालों में भिन्न २ हो तो उसके लिए उचित संशोधन करना चाहिये। यदि बीच में कर बढ़ाया या घटाया गया है, यदि नया प्रान्त सम्मिलित किया अथवा पुर्गना संपन्न निकाला गया है, यदि कोई पुर्गानी स्वर्च या जामदानी की मदों में हेरफेर हुआ है अथवा कोई उठा दी गई है तो इन सब के लिए तुलना के समय उचित संशोधन कर लेना उचित है। मैं कॉमिश्नर को विज्ञापन दिलाता हूँ कि मैंने प्रस्तावित तुलना में यथाशक्ति इन सब बातों का विचार कर पूरा २ संशोधन कर लिया है। इस तरह से पहिले ६ वर्षों में लार्ड लिटन के शासन-काल में कर बढ़ाया और लार्ड रिपन के समय में घटाया गया था। मैंने इन दोनों ही बातों को ध्यान में रख कर समुचित संशोधन कर लिये हैं। उन दिनों में भी रुपये का भाव बढ़ता घटता रहता था। सन् १८७० में १० रु० का भाव १८ शिलिंग और सन् १८८४ में १६ शिलिंग और १ पेनी था। मैंने यह भी संशोधन कर दिया है अर्थात्, इन संशोधनों के बाद, आप क्या पाते हैं? लार्ड और अकाल सम्वन्धी विशेष व्यय को छोड़कर, इन वर्षों में हमारा कुल दोबाना और फौजी खर्च लगभग ६ फीसदी के हिसाब से बढ़ा, जिसका अर्थ यह है कि व्यय ३ से बढ़ा प्रतिवर्ष बढ़ा जब आय में १½ फीसदी की वृद्धि हुई। इस तरह से

सामान्य आय की वृद्धि की दर माध्वारण व्यय की दर से कहीं अधिक थी, और इसी के कारण लार्ड रिपन की सरकार को घटाने में समर्थ हुई थी। दीधानी और फौजी महों में व्यय की कुल वृद्धि इन ६ वर्षों में, अर्थात्, १८७५ से १८८४ तक, लगभग ₹० २,५०,००,००० हुई। यह प्रथम युग की बात हुई।

दूसरे १० वर्षों के युग की आलोचना करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि उसके पहिले और आधिरि साल में किसी बात में मुश्किल से समानता है। उत्तर पश्चिमीय सोमा प्रान्त में आशक्ति घटनाओं के कारण इन दिनों फौजी चहल पहल रूख रही। और इसी युग में रुपये की दर तथा अफीम से आय भी बराबर गिरती चली गई। फल यह हुआ कि देश के करा में निरन्तर वृद्धि होती चली गई। इस समय के व्यय का विचार करने में हमें चार बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहिले तो सन् १८८५ में ३०,००० नई सेना बढ़ाई गई १०,००० यूरोपियन और २०,००० हिन्दुस्तानी, दूसरे, सन् १८८६ में उत्तरीय चम्पा, सम्मिलित किया गया। फिर सन् १८८५ और १८८४ के बीच रुपये का भाव गिरना ही गया, अर्थात्, दस रुपये की दर जहाँ पहिले १६ शिलिंग और १ पैनी थी वहाँ अन्त में गिरकर वह केवल १० शिलिंग और ११ पैस रह गई। इससे नीचे रुपये का भाव नहीं गिरा। इसी युग के अन्तिम दिनों में यूरोपियन अधिकारियों को रुपये की दर गिरने के कारण जो हानि हो रही थी उसकी पूर्ति के लिये भत्ता मिलने लगा, जिससे व्यय में लगभग सवा करोड़ की वार्षिक वृद्धि हो गई। इन सब बातों से कर पर कर लगते गये इन १० वर्षों में से = वर्षों में पुनः नये टैक्स लगे।

इसलिये युग के प्रारम्भिक वर्ष के साथ उसके अन्तिम साल की तुलना करना बहुत कठिन हो गया है। लेकिन बहुत अंशों में ठीक इस युग का मामूली खाका खींचा जा सकता है। इससे यह मालूम होता है कि इस युग में देश के दीवानी और फौजी खर्च में लगभग १४ करोड़ की वृद्धि हुई इसमें से ₹० ७,७५,००,००० नवीन करों से आये, इसलिए व्यय की मही में साधारण बाढ़ इस युग में लगभग ₹० ६,२५,००,००० की हुई। दूसरी ओर आमदनी में लगभग १२ करोड़ की वृद्धि है जिसमें से लगभग ₹० ६ करोड़ तो नये टैक्सों से मिले और अकाल फड की मद्द को उठा देने तथा अन्य मही में व्यय घटाने से ₹० २ करोड़ की बचत की गई। इस तरह से लेखा बरामद किया गया। इस दूसरे युग में, खास खर्च की मही को छोड़कर, जिनके लिए नये टैक्स लगाये गये थे, दीवानी और फौजी मही में खर्च लगभग ₹० ६,२५,००,००० से घटा। अथवा, १० साल में १४॥ फीसदी या प्रतिवर्ष १॥ सैकड़े की औसत वृद्धि हुई, जहा पुरानी आयकी मही से आमदनी कुछ कम १॥ सैकड़े सालाना घटी। अग्रे में तीसरे युग का जिक्र करता हूँ। इस युग में गडबडी पैदा करने वाली बातों की संख्या अधिक नहीं, सिर्फ भस्मे ही का सवाल था। इस युग के प्रारम्भ में रुपये का भाव १ शिलिंग और ११ पैन्स तक गिर गया था, परन्तु वह निरन्तर बढ़ते २ सन १८६६ में १ शि०—४ पै० को चढ़ गया, और युग के पिछले तीन बरसों तक रुपया का यही भाव बना रहा। और यदि पिछली सदी के सब से बड़े दुर्भिक्ष इसी युग में न हुए होने और न शुरू में सगृहद पर लड़ाई ही छिड़ती, तो इस युग में राज काय की अग्रस्था

उसकी वास्तविक दशा से कहीं अच्छी होती। लेकिन इनके होते हुए भी रेलों से आमदनी बढ़ने लगी थी, अफीम से आय भी सुधरती जाती थी, और साधारण आमदनी की वृद्धि जो १८६८ से १९०८ तक बराबर होती गई, शुरू हो गई थी। इस युग के पिछले तीन साल में हर तरफ आय का अपूर्व विस्तार हुआ, और रुपये का भाव गिरने के कारण जो अंगरेज अफसरों को भत्ता मिलता था सिर्फ उसी में १८६४ के मुकाबिले में १८६६ में ५ करोड़ रुपये की वचत सरकार को हुई। इस बढ़ती हुई आमदनी के कारण सरकारी खर्च भी बढ़ने लगा, और इसका सब प्रधान कारण यह था कि इस युग के पिछले तीन वर्ष उनके शासन के तीन साल थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि युग के अन्त समय पर प्रारम्भिक वर्षों को देखते हुए व्यय की चाल ज्यादा तेज हो गई थी, किन्तु इतना सब होते हुए भी वह पूरी तौर से सीमा के भीतर ही किया गया। इन बरसों में दीवानी और फौजी खर्च में लगभग ७ करोड़ की बढ़ती हुई, अथवा युग भर में ११ फीसदी या १½ फीसदी प्रतिवर्ष—दीवानी खर्च में लगभग १४ फीसदी या दो फीसदी प्रतिवर्ष, और फौजी खर्च में ६½ फीसदी या कुछ कम १ फीसदी फीसाल के हिसाब से वृद्धि हुई। तुलना के लिए मैंने रुपये को १ शि०—४ पै० के बराबर मानकर भत्ते की ग्यकम ली है।

अब आइए, हम अन्तिम युग की ओर दृष्टि पात करें। तीसरे युग की तरह, इसकी भी अवधि सात साल की है। लेकिन इस युग में जैसा पिछले वर्ष इसी कौंसिल में कहा गया था, निरा निरा कार्य क्षमता पर विशेष रूप से ध्यान

दिया गया और इसी उद्देश की सिद्धि के लिए सरकारी मह-
कमों के सुधार और उन्नति की ओर अधिक ध्यान रहा।
हर तरफ इसी की पूर्ति में खूब सरगर्मी दिखाई देती थी,
और धडाधड नये २ महकमों खोले गये, ओहदे कायम हुए
और यूरोपियन अफसरों की तनखवाहों, पेशनों और उनको
जल्दी २ तरफकी देने के प्रस्ताव मंजूर किये गये। इस सब
का परिणाम क्या हुआ ? प्रत्येक दिशा में व्यय की वृद्धि, जो
पूरी तौर से अचम्भे में डालने वाली है। इस युग में खल
बली डालनेवाली घटनाओं में ये सम्मिलित हैं—(अ) बेरार
के हिसाब भारतीय बजट में शामिल किये गये, (इ) स्थानिक
बोर्डों के हिसाब अधिकतर भारतीय आय-व्यय के चिट्ठे से
निकाल दिये गये, (उ) टैक्स घटाये गये, और (ए) जमीन—
नायिकमद की रकम दीवानी मद से फौजी मद में मिलाई गई।
इन सब घटनाओं के कारण जो कुछ हिसाब उलट फेर हुआ
है उस का उचित सशोधन करने के बाद, हमें पता लगता है
कि इन सात वर्षों में, १९०१—०२ से १९०७—०८ तक दीवानी
और फौजी मदों के खर्च में साधारण रूप से १८ करोड़ की
वृद्धि हुई। इस हिसाब से औसत खर्च सात साल में ३३
फीसदी बढ़ा, अथवा प्रतिवर्ष लगभग ५ फीसदी व्यय की
वृद्धि हुई। दूसरी ओर, भाग की उन्नति, जो स्वयमेव अत्यन्त
असाधारण थी, सब जाता का खेचते हुए २ फीसदी प्रतिवर्ष
के हिसाब से हुई। इससे इन इन नतीजे पर पहुँचत हैं—

पहिले ६ वर्षों में १८ में ०३ करोड़ की वृद्धि हुई, फिर
उसके बाद १० वर्षों में लगभग ६ करोड़ अधिक खर्च हुए,
सात साल के तीसरे १८ में लगभग ६ करोड़ का अधिक
व्यय हुआ, और अन्तिम ७ साल में १८ करोड़ की वृद्धि हुई।

यदि प्रति सैकड़ा का हिसाब लिया जाय, तो पहिले युग में व्यय की सागरण वृद्धि ३ फी सदी हुई, दूसरे और तीसरे युग में यह ३ और ३ फी सदी के आसपास रही और पिछले युग में ५ फी सदी हो गई अगर दीवानी और फौजी मदों का अलग अलग लें तो पिछले सान साल में दीवानी खर्च में ४० फीसदी अथवा ६ फी सैकड़ा प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई और फौजी व्यय २० फी सैकड़ा अथवा ३ फीसदी फी साल के हिसाब से बढ़ा !

श्रीमद्, मैं सोचता हू कि इन आँकों का वर्णन मात्र ही पिछले वर्षों में सरकारी व्यय की वृद्धि की जाच के महत्व को प्रमाणित करना है। शायद यह कहा जायगा कि बहुत से उप-यागी कामों में खर्च की वजह से यह अपूर्व वृद्धि हुई है। मैं यह तुरन्त मानने को तैयार हू कि सरकार ने कई जरूरी कामों के लिये भी इस समय में अधिक रुपया दिया है। इतने वर्षों के भीतर दीवानी की कुल मदों में कुल वृद्धि १३ करोड़ हुई है। इस १३ करोड़ में सलगभग ३ करोड़ फी रकम पुलिस, शिक्षा, स्थानिक बोर्डों की इम्दाद पर खर्च की गई। पुलिस की मद में १½ करोड़ का खर्च बढ़ाया गया है परन्तु उससे क्या फायदा होगा, यह कहना अभी कठिन है। कम से कम में तो इससे नहीं मनुष्ट हू कि जो कुछ पुलिस के ऊपर खर्च हो रहा है वह सब उचित है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिये यह माने लेता हू कि इस अधिक व्यय से पुलिस सुधर जायगी। फिर ७५ लाख शिक्षा की मद में बढ़ा हू—रूपि-सम्बन्धी और औद्योगिक शिक्षा को मिला कर। और अन्त में लगभग १ करोड़ स्थानिक बोर्डों की शिक्षा, सफाई तथा अन्य कामों के लिये, दिया गया है। इस तरह से, स्थूल रूप से, इन मदों पर लगभग

तीन करोड़ का सालाना मर्च बढ़ाया गया है। यात्री १० करोड़ की वृद्धि बची, जिसकी उपयोगिता प्रमाणित हानों चाहिये।

श्रीमन्, अगर कॉमिल मुझे इजाजत देगी तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह पहिला ही अग्रसर नहीं है जब मैं व्यय में वृद्धि की शिकायत कर रहा हूँ। पांच बरस हुए, जब अन्तिम युग के बीचोंबीच मैं हम सब थे, और जब चर्चा चारों तरफ धड़ाधड़ बढ़ रहा था, मैंने कॉमिल में इस विषय पर आलोचना करने का साहस किया था। यदि कॉमिल पिछली स्पीच का एक अग्रतर्ण पढ़ने के लिये मुझ क्षमा करें तो मैं उसके सामने कुछ पकिया पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि उस समय पर मैंने क्या कहा था। १९०६-०७ के बजट पर बहस के अग्रसर पर मैंने यह कहने का साहस किया था —

— पिछले सालों में खर्च होने के कारण कृत्रिम रूप से रुपये की दर बढ़ा दी गई थी, और प्रथमतः तो रुपये के भाव के बढ़ जाने से आवश्यकता से अधिक टैक्सों के लाने और दूसरे सालाना बजट में अनुमानित आय को घटाकर और व्यय को बढ़ाकर दिखाने से हरमाल अधिकाधिक खर्च होती रही। इसका देश के व्यय पर अनिवार्य प्रभाव पड़ा। राजकोष में इतना अधिक घन होने से, व्यय का निर्या हर तरफ बढ़ता गया किरायत—मितव्यय का तिरस्कार किया जाने लगा और जिधर देखिए उधर ही नए नए महकमे और युरोपियन अफसरों की तनख्वाहें, पेंशनें और भत्ते बराबर बढ़ने लगे। टैक्सों में बहुत सफाई के साथ कुछ कमी अवश्य की गई,

परन्तु शासन संचालन को उत्तम बनाने के नाम पर प्रत्येक दिशा में व्यय की उच्छृङ्खल वृद्धि की बुराई रोकी नहीं गई, और उसका फल हम अब भोग रहे हैं। इसमें सब से अधिक शोचनीय बात तो यह है कि यद्यपि राजकोष में रुपया भरा पड़ा था और शासन सम्बन्धी व्यय बराबर बढ़ता जाता था, परन्तु जनता की आर्थिक और नैतिक उन्नति सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर प्रायः उदासीनता दिखाई गई। और लोगों की स्थिति सुधारने के लिए राजकोष की आर्थिक समृद्धि से राष्ट्र द्वारा एक भी विस्तृत कार्य छेड़ने में लाभ न उठाया गया। ऐसे राष्ट्रीय कार्य का छेड़ना, मेरी विनम्र सम्मति में, भारतीय सरकार का अब प्रधान कर्तव्य है, और माननीय अर्थसचिव जितना रुपया साधारण और असाधारण वचत से दे सकते हैं इस कार्य के लिये उस सब की जरूरत होगी।”

यह शिकायत सारत न्यायसंगत है, इसको भारतीय सरकार ने अथवा उनके अर्थ विभाग के प्रतिनिधि ने मान लिया है, जैसा माननीय सर एडवर्ड बेकर के महत्वपूर्ण कथन से प्रमाणित होता है। सन् १९०७—०८ के बजट पर बहस के मौके पर यह प्रस्ताव किया गया था कि कुछ सरकारी मुलाजिमों का वेतन बढ़ाया जाय इसका प्रतिवाद करते हुये उन्होंने कहा कि हम उस प्रस्ताव को अचभे और विवाद के साथ देखते हैं इसके बाद उन्होंने कहा कि “भारत सरकार के अर्थ विभाग से मेरा सम्बन्ध पांच साल से बराबर है, और इतने समय में एक भी दिन ऐसा नहीं गया, जिसमें मुझे किसी न किसी की तनख्वाह बढ़ाने अथवा किसी मुहकमे के पुनः संगठन अथवा उनके मुलाजिमों की तादाद के प्रस्तावों से

सहमत न होना पड़ा हो। तमाम तजुर्वा इस बात को साबित करता है कि जब कभी कर्मचारियों की सख्या अथवा उनके वेतन बढ़ाने की आवश्यकता हुई, तब प्रान्तिक सरकार और मुहकमों के प्रधान उसको सरकार के पास भेजने में बड़ी ही तत्परता दिखाते हैं। और न भिन्न २ विभागों के कर्मचारी अपने २ दावों को पेश करने में किसी तरह से पीछे रहते हैं। मैं किसी तरह से भी इस प्रथा को अधिक उत्तेजना देने की आवश्यकता मानने को तैयार नहीं हूँ।"

इससे पता चलता है कि पिछले कनिषथ वर्षों में व्यय की जो वृद्धि हुई है, वह स्थायी है। और ऐसी वृद्धि उसी हालत में सम्भव थी, जब सरकार को सालाना अधिक बचत होती रही। इस बात को ध्यान में रखकर और यह भी देखते हुए कि सरकार की आर्थिक स्थिति तर से बिगड़ गई है, मैं समझता हूँ कि सरकार को यह लाजिमी है कि वह सम्पूर्ण स्थिति की आलोचना फिर एक बार करे। श्रीमन्, ऐसा ही लार्ड डफरिन ने अपने जमाने में किया था, यद्यपि सरकारी व्यय का प्रसार उस समय इतना विस्तृत न था, जितना पिछले १० वर्षों में हुआ है। जब लार्ड डफरिन चाइसराय हुए थे तब उन्होंने इस देश में फौज को बढ़ाना ठान लिया था, और इसके लिये उन्हें अधिक रुपये की जरूरत थी। अतएव उन्होंने एक फिनेन्स कमेटी अपने आने के पहले के व्यय में वृद्धि की जाच के लिए नियुक्त की जिसमें यह मालूम हो कि बचत किन महीनों में हो सकती है। उस कमेटी की नियुक्ति के प्रस्ताव को वर्तमान भारत सरकार को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये। उस प्रस्ताव में दीयानी रर्चमें बाढ़, जो पहिले के पाच वर्षों में हुई थी,

“बहुत बड़ी” बताई गई है। यद्यपि जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूँ, सन् १८७५ और १८८४ के बीच मैं वृद्धि की दर सिर्फ ३ फीसदी प्रतिवर्ष थी, या आय के जमा करने के खर्च को और दीवानी व्यय को मिलाकर वृद्धि केवल डेढ़ फीसदी थी—इन दो मर्हों की वृद्धि और मर्हों की याद से ज्यादा थी। यदि वह वृद्धि फी गति लार्ड डेफरिन की सम्मति में “बहुत ज्यादा” थी तो मुझे ताज्जुब होता है कि पिछले १० वर्षों में व्यय की वृद्धि को वह किन शब्दों में वर्णित करते।

श्रीमन्, अब मैं प्रस्तावित जाच के स्वरूप का जिक्र करूंगा। मैं पहिले तो यह प्रस्ताव करता हूँ कि जाच खुली जाच होनी चाहिये, और मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि सरकारी और गैर सरकारी सज्जनों की सम्मिलित कमेटी द्वारा जाच हो। जैसा मैं पहिले कह चुका हूँ कि मान० अर्थसचिव के पिछले वर्ष के शब्दों से यह आशा हो चली थी कि सरकार स्वयम् ही इस मामले की जांच करेगी। लेकिन गत अगस्त में शिमले में मैं ने मान० अर्थसचिव से एक प्रश्न किया तब उन्होंने कहा कि उनका मतलब केवल मुहकमे की जांच मे था। श्रीमन्, स्थिति इतनी गम्भीर है कि सिर्फ मुहकमे की जांच से काम न चलेगा। इस विचार की पुष्टि मैं मे अपने मान० मित्र के ही शब्दों को पेश करूंगा, उन्होंने गत वर्ष कहा था कि मितव्यय का प्रश्न उन्हीं के मुहकमे ही तक परिमित नहीं है, यह भारतीय सरकार के ऊपर निर्भर है, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि खर्च घटाना है तो इस देश और इंग्लैंड दोनों ही में मितव्यय के पक्ष में लोकमत होना चाहिये। लोकमत को उसके पक्ष में लाने का एक मात्र साधन केवल मार्गजनिक जाच ही हो सकता है—जैसा लार्ड डेफरिन ने

किया था—जिसमें लोगों को पता चले कि गर्न किम तरह बढ़ते गये हैं और अब हमारी क्या स्थिति है। श्रीमन्, मैं केवल अर्थ विभाग द्वारा ही जांच नहीं चाहता, शिमले या कलकत्ते की जांच केवल वृद्धि के आंकड़ों की जांच होगी। हम जो चाहते हैं वह लार्ड एफरिन की कमेटी की सी कमेटी है। जिसमें एक या दो गैर सरकारी मेम्बर भी शामिल हों, जो देश भर में घूम फिर कर जांच करें और भिन्न भिन्न विभागों के प्रधानों से पूछ ताछ करे कि कौन से मुद्दों में घटाये जा सकते हैं और उस मोच विचार तथा गम्भीरता के साथ अपनी सम्मति दे, जो सदा सायजॉफ जाचों में पाई जाती हैं। मैं इस तरह की जांच पर जोर देता हूँ क्योंकि इस समय के भारत का शासन जिस तरह का है उसको देखते हुए व्यय की वृद्धि में समय समय पर जांच ही एक ऐसा साधन हो सकता है कि हमारे राजकोष का प्रयत्न उचित ढंग में हो। ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में ऐसे मामलों में स्थिति कई बातों में अच्छी थी। इंग्लैंड की सरकार अब आम्नानी से उन व्ययों को भारत के ऊपर डाल सकती है जिनका विरोध उस समय कम्पनी करती थी। दूसरी ओर कम्पनी के मामलात पर पार्लामेन्ट की तीव्र दृष्टि रहती थी। और हर तीसरे साल जांच हुआ करती थी जिसका फल यह होता था कि प्रत्येक बात का भावधानी के साथ सशोषण हो जाता था, और इस के कारण बहुत कुछ प्रयत्न नियन्त्रित रहता था। लेकिन जब इस देश का शासन कम्पनी के हाथ से छीन कर सम्राट् ने ले लिया तब से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। अब सारी शक्ति भारत-सचिव के हाथ में है और जो राजमन्त्री होने के कारण हास आफ कामन्स में

बहुमत का सहाय ले सकता है। इसके मानी यह है कि यद्यपि भारतीय व्यय के ऊपर पार्लामेंट का अधिकार सिद्धान्त रूप से अब भी मौजूद है परन्तु वास्तव में वह केवल नाममात्र का रह गया है। ऐसी अवस्था में हमारे आर्थिक शासन की समय समय पर सार्वजनिक जाँच का महत्व और उपयोगिता प्रत्यक्ष हो गई है। कम्पनी से शासन अलग होने के बाद ऐसी तीन जाँचें हो चुकी हैं। पहली जाँच सन् १८७० के बाद पार्लामेंट की कमेटी द्वारा हुई थी। कमेटी लगभग चार वर्ष तक बैठी और बहुत ही उपयोगी मसाला जमा किया। दुर्भाग्य से १८७४ में पार्लामेंट भंग हो गई और उसके साथ ही कमेटी का भी अन्त हो गया। दूसरी जाँच सन् १८८६-८७ में लार्ड डफरिन की कमेटी थी। और तीसरी जाँच सन् १८९७ में लार्ड बैलघी की अध्यक्षता में रायल कमोशन द्वारा हुई थी। तब से अब १४ वर्ष गुजर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि देश के हित में एक सार्वजनिक जाँच व्यय की दृष्टि में की जाय। ताकि यह बताने में सक्षम हो सके और कितना घटाया जा सकता है और साधारण व्यय की दर को कम करने में सक्षम हो सके। यह जाँच न तो लंडन, शिमले और न कलकत्ते में होनी चाहिये। जाँच एक ऐसी कमेटी द्वारा हो जो देश में दौरा करे और गवाही ले।

श्रीमान्, अब मैं उन सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का जिक्र करूँगा, जिनके प्रयोग की इस अवसर पर जरूरत है। मेरे प्रस्ताव चार हैं, और वे ये हैं—पहिले तो जिसको मिस्टर ग्लैडस्टोन व्यय का भूत कहा करते थे और जो बहुत वर्षों से विरोध कर सन् १९०१-०२ से १९०८-९ तक इस देश में स्वच्छन्द रूप से विचर रहा है। उसको जकड़ने और काबू में लाने की जरूरत है और उसके स्थान में मितव्ययता की मूर्ति को स्था

पित करना चाहिये। यदि सरकार, लार्ड डफरिन की तरह, सब विभागों को आज्ञा दे कि हर तरफ खर्च घटाया जाय और व्यय की दर कम रखी जाय, खासकर ऐसा खर्च जो घटाया जा सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ लाभ होगा। लार्ड डफरिन की सरकार को फौजी तैयारी के लिए रुपये की जरूरत थी, मैं साफ़ आशा करता हूँ कि श्रीमान् की सरकार को शिक्षा को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। चाहे ऐसा हो या न हो खर्च घटाने की परम आवश्यकता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि सरकार सब मुद्दकों को हुक्म जारी करेगी कि यथामुम्भव शासन सम्बन्धी व्यय कम ही रखा जाय। यह मेरा पहिला प्रस्ताव है। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि आय की साधारण वृद्धि की सीमा को व्यय की साधारण वृद्धि उल्लंघन न करने पाये। अगर हमें दिवालिया नहीं बनना है तो उसके उस के भीतर ही रखना उचित है। हमले के रोहने तथा ऐसी ही मुन्नीबतों के से जरूरी कामों के लिए यदि खर्च आवश्यक हो तो विशेष कर लगाया जाय, और ऐसा करने में हम सरकार को सहायता देंगे। किन्तु साधारण समय में व्यय आय के भीतर होना चाहिए।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि फौजी खर्च में अब काफी कमी की जाय। श्रीमान्, यह कुछ टेढ़ा सवाल है और मैं आशा करता हूँ कि कोसिल ठूपा पूर्वक एक दो बातों को जो मैं कहना चाहता हूँ सुनेगी। हमारा फौजी खर्च जो सन् १८८७ तक लगभग १६ करोड़ प्रति वर्ष के था, अब ३१ करोड़ से अधिक हो गया है। गदर के बाद सन् १८५६

में जो कमीशन बैठा था उसने सेना की सख्या को स्थिर किया था, और वही सख्या लगभग ६०,००० अंग्रेजी और १२०,००० देशी सेना १८८५ तक बनी रही। इस अवसर में कई बार जो सैनिक शासन के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने सैनिकों को सख्या बढ़ाने के लिए जोर दिया, किन्तु वे सफल न हुए। १८८५ में ३०,०००—१०,००० अंग्रेजी और २०,००० हिन्दुस्तानी सेना बढ़ाई गई। तब से इसमें कुछ और वृद्धि हुई है। और इस समय ७५,००० यूरोपियन और १,५०,००० हिन्दुस्तानी सेना है। श्रीमन्, मेरा प्रथम निवेदन यह है कि यह देश इतनी बड़ी सेना का भार नहीं सह सकता, और मध्य एशिया की राजनैतिक स्थिति में आशा जनक परिवर्तनों को देखते हुए इस सख्या को बहुत कुछ घटाना चाहिए। न केवल सरकार के प्रतिष्ठित समालोचक ही परन्तु उनमें से भी बहुतोंने, जिन्होंने देश के शासन में भाग लिया है जोर जोर इस मसले पर दावे के साथ राय दे सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कहा है कि केवल भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय सेना बहुत बड़ी है। जैम्स, जनरल ट्रैकनबेरी ने, जो एक समय इस कौंसिल के फौजी मेम्बर थे, सन् १८६७ में भारतीय व्यवस्थान्धी रायल कमीशन के सामने गवाही देते हुए कहा था कि भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय सेना बहुत ज्यादा है और उसका एक भाग पूर्व में साम्राज्य की रक्षा के लिए रखा गया है। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि १८७६ के आर्मी कमीशन ने, जिसके लार्ड राबर्ट्स भी मेम्बर थे यह सम्मति दी थी कि उस समय की भारतीय सेना की सख्या (६०,०००) अंग्रेजी और १२०,००० हिन्दुस्तानी-सब जरूरियात को काफी थी—रूसियों के हमले का मुकाबिला

करने हों के लिए, चाहे अफगानिस्तान भी रूस की सहायता करने लगे। फिर, श्रीमन्, जब दक्षिण अफ्रिका की लड़ाई ठिड़ी तब यहाँ से फौज काफी तादाद में इस देश के बाहर भेज दी गई, यद्यपि भारत की दशा उस समय आशङ्काजनक थी। उसी समय कुछ फौज चीन भी भेजी गई और तो भी यहाँ कुछ न हुआ। यह नमाम घात इस बात को साबित करती है कि जितनी फौज है वह जरूरत से ज्यादा है।

यह कहा जा सकता है कि यह विषय सैनिक सुसज्जिता का है, जिस पर गैरसरकारी सभासद किसी प्रकार की सम्मति देने के अधिकारी नहीं हैं। यदि सैनिक शासन के किसी विशेष अंगपर राय देता तो मैं अपने को इस धृष्टता के लिए दोषी ठहराता, परन्तु यह तो विषय है नीति का, जिसपर मैं यह कहने को साहस करता हूँ कि प्रत्येक साधारण आदमी—हिन्दुस्तानी भी समझ सकता है और उसको सम्मति प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। यह सब कोई देख सकते हैं कि मध्य एशिया और भारत की सरहद पर स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। और इसको देखते हुए मैं सोचता हूँ कि इस देश के निवासियों को, जिन्होंने इस विशाल सैनिक व्यय के भार को बहुत वर्षों तक सहा है, ईदृश घटा कर कुछ शान्ति मिलनी चाहिये और इससे जो कुछ रुपया बचे उसे दूसरे अधिक उपयोगी और आवश्यक कार्यों में लगाना चाहिये। श्रीमन्, जैसा लार्ड सालीसबरी ने एक बार कहा था, सैनिक तैयारी सदैव स्थिति के अनुकूल होनी चाहिये। वह केवल इसी पर निर्भर नहीं है कि सैनिक अफसरों की राय में क्या आवश्यक है, लेकिन वह इस सम्मिलित विचार में निर्धारित होनी चाहिये कि देश की रक्षा

कैसे हो सकती है और इसके लिए वह कितना खर्चा दे सकती है इस कसौटी पर कसने से हमारा सैनिक व्यय अनावश्यक रूप से अधिक है, और मैं साग्रह अनुरोध करता हूँ कि फौज की संख्या सन् १८८५ के पहिले की तादाद के बराबर कर दी जाय और इस तरह से सैनिक व्यय का एक भाग बच सकता है ।

श्रीमन्, मेरा तीसरा प्रस्ताव यह है कि सरकारी नौकरियों में देशी हिन्दुस्तानी अब से भी अधिक विस्तृत रूप से भर्ती किये जायें । इस सम्बन्ध में मैं इसकी आवश्यकता के मानने को तैयार हूँ कि एकही उद्देश्य पर हिन्दुस्तानी को अंग्रेज के मुकाबिले में कम तनख्वाह दी जाय । यही तो हमारा पक्ष है । यदि हम इस पर जोर दें कि हिन्दुस्तानियों को उतना ही वेतन मिले जितना अंग्रेजों को तो हमारा पक्ष बहुत कमजोर हो जायगा । कार्यकारिणी काँसिलों की मेम्बरी, हाईकोर्ट की जज्जी आदि उच्च पदों का वेतन समान ही होना चाहिये क्योंकि यह पद विशेष सम्मान के हैं । परन्तु और नौकरियों में हिन्दुस्तानी और अंग्रेजों को भिन्न २ वेतन मिलना उचित है । आवश्यकता इस बात की है कि यह भेदभाव ऐसे न हो कि वे खुर्से में । वर्तमान प्रान्तिक और भारतीय विभागों, अथवा यह नियम बनाने कि हिन्दुस्तानियों को अङ्गरेजों का दो तिहाई वेतन मिलेगा, के स्थान में प्रत्येक पद का वेतन निश्चित होगा और यह नियम रहेगा कि जब कभी उस पद पर कोई अङ्गरेज होगा तो उसको विशेष भत्ता दिया जाएगा क्योंकि उसे अपने स्त्री और बच्चे इङ्ग्लैण्ड भेजने पड़ते हैं और उसे खुद भी वहाँ जाना पड़ता है । मीरपुर राजत के तकाने को भी हमें पूरा

करना है और हमें उचित ढंग से उनका सामना करना चाहिये। अतएव मैं प्रत्येक पद का वेतन निश्चित कर दूंगा और सब के लिए वह पद खुला होगा जिनमें उचित योग्यता है। केवल शर्त यह रहेगी कि यदि उस पद पर अङ्गरेज हुआ तो उसको विशेष व्यय के लिए विशेष भत्ता दिया जायगा तब आपको नियुक्ति के समय यह देखना होगा। हिन्दुस्तानी को मान लीजिये, पाँचसी रुपये महीने का वेतन दिया जायगा, यदि अङ्गरेज है, तो उसे पाँचसी रुपये और १६६। का भत्ता दिया जायगा। इस तरह से यदि आप सचमुच खर्च घटाना चाहते हैं तो आपको उस पद के लिये हिन्दुस्तानी ही को लेना होगा यदि और बातों में उसमें समान योग्यता है।

मेरा चौथा और अन्तिम प्रस्ताव यह है कि इस देश में सरकारी हिसाब की स्वतंत्र जाँच का प्रयत्न होना चाहिए। श्रीमन्, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और वह बहुत पुराना है। १८८० के बाद भारतीय सरकार और भारत सचिव के बीच में इस पर बहुत गम्भीर विचार हुआ था। इस मामले पर पहिला प्रस्ताव भारतीय सरकार ही ने भेजा था, यह उस समय की बात है जब लार्ड क्रोमर अर्थ सचिव और लार्ड रिपन वाइसराय थे। सन् १८८२ में भारत सचिव के पास भारत-सरकार ने एक खरीता भेजा था, जिसमें उन्होंने हिसाब की स्वतंत्र जाँच पर जोर दिया था। वह सम्पूर्ण खरीता विशेष रूप से पढ़ने के योग्य है। यूरोप के भिन्न २ देशों में ऐसी जाच की प्रथाओं की, जिन पर भारतीय सरकार ने ग्रास तीर से विचार किया था, आलोचना करने के बाद, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इस परिणाम को पहुँचे हैं कि सरकार के मातहत अफसरों द्वारा जाच की प्रथा असतोषजनक है और उस

का बदल देना चाहिये । ये दो घातों पर जोर देते हैं — एक यह कि वह अफसर जो रय कंट्रोलर जनरल और अब कांट्रोलर और आडिटर-जनरल के नाम से पुकारा जाता है, भारतीय सरकार के मातहत हरगिज न होना चाहिए । उसे भारतीय सरकार का मुह तरबकी के लिए न ताकना पड़े, और न वह भारत सचिव की अनुमति के बिना अपने पद ही से हटाया जाय । दूसरी बात यह थी कि उसके पद का घेतन अर्थ विभाग के मंत्री की तनम्माह के बराबर हो और बीस बरस में वह उस पद पर क्रम २ से उन्नति करता हुआ पहुच जाय । उस समय के भारत सचिव ने अपनी कौंसिल की अनुमति के साथ, — और यह कौंसिल ऐसे परिवर्तन और सुधार के विरुद्ध सदा ही रहती है — इस प्रस्ताव को नामजूर किया है । उनकी राय थी कि यह भारत के लिए उपयुक्त न था । उसकी कोई जरूरत भी न थी और उसके कारण खर्च भी बढ़ जायगा । लेकिन यह कौतुक से घाली नहीं है कि पाच, छ साल बाद भारत सचिव ने स्वयम्ही इस प्रस्ताव को फिर से उठाया । लार्ड फ्रांस उस समय पर भारत सचिव थे, और वह परीता भी जिसमें उन्होंने इस मसले को फिर से उठाया और उसपर बहस की है, ध्यात से पढ़ने के काबिल है । १८८२ की भारतीय सरकार की तरह, उन्होंने भी भारतीय जाच की असतोषजनक दशा पर जोर दिया है, विशेषकर इसलिये कि जाच के विभाग का प्रधान अफसर भारत सरकार का मातहत होता है । और उन्होंने दिखाया है कि कितना जरूरी यह है कि वह भारतीय सरकार के आधीन न रहे । किन्तु उस समय इस प्रस्ताव का विरोध भारत-सरकार ने किया — लार्ड लेइसडौन तब वाइसराय थे — और प्रस्ताव रद्द होगया । अब मैं, श्रीमन्, विनम्रता

के साथ आग्रह करता हूँ कि यह सवाल फिर से उठाया जाय और आडिटर जनरैल भारत-सरकार के मानहत कदापि न न होना चाहिये। इङ्ग्लैंड में आडिटर-जनरैल सत्र गलतियों पर सालाना रिपोर्ट होस आफ कामन्स के पास भेजता है और होस उसे एक कमेटी के पास भेजदेता है जो उसकी विस्तृत और कड़ी आलोचना करता है। चकि अभीतक हमारी कांसिल वजट को स्वीकृत नहीं करती है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान स्थिति में भारत सचिव को जो आर्थिक मामलों में प्रधान है, आडिटर जनरैल की रिपोर्ट भेजी जाय। लेकिन रिपोर्ट को प्रकाशित करना चाहिए—पार्लामेंट में भी उपस्थित और भारत में भी प्रकाशित का जाय। उस समय हम लोगों की आर्थिक विषयों की समालोचना सचमुच महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होगी। इस समय तो गैर-सरकारी मेम्बर आर्थिक शासन की छोटी २ बातों का ध्यान फेरल न होने के कारण मोटी मोटी बातों पर सम्मति प्रकट कर देते हैं। यह सब बदल जाय यदि स्वतंत्र आडिटर जनरैल की सालाना रिपोर्ट से उनको सहायता मिलने लगे।

श्रीमन्, मैं अत्र ग़म करना हूँ। मैं चार कारणों से इस जाच को चाहता हूँ। पहले तो, व्यय की आसाधारण वृद्धि स्वयमेव आलोचनीय है। कम खर्च या किफायत शारी हर मुल्क में जरूरी है। लेकिन वह इतनी आवश्यक और कहीं नहीं जितनी भारतवर्ष में। लार्ड मेयो ने, ४० वर्ष पहले इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह इतना समय हो जाने के बाद भी दुहराया जा सकता है। फौजी खर्च पर गोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के निवासियों से लेकर एक २० का भी फौज के ऊपर अनापश्यक रूप से खर्च करना हिन्दुस्तानियों के

खिलाफ एक जुर्म है, जिनको उसकी जरूरत अपनी नैतिक और साम्प्रतिक उन्नति के लिए है। दूसरे, श्रीमन्, 'गैच' और 'कदापि न बढ़ने पाये' क्योंकि हमारे राजकीय की आर्थिक स्थिति इस समय नाजुक है। अफीम से और जूट वस्त्र होने को है। तीसरे, मैं समझता हूँ कि प्रान्तिक सरकारों को शीघ्र ही आर्थिक अधिकार विस्तृत रूप में देने के प्रस्ताव पेश किये जायगें, और इन सरकारों को अपनी आय-व्यय के ऊपर अधिक सत्ता मिल जायगी। अगर ऐसा हुआ तो पहले इसकी जांच कर लेना चाहिये कि उनके प्रस्ताव व्यय का निर्य समुचित है। और यह निर्वृत्तना घंटा दिया जाय जितना व्यर्थ है, इसने बाद उनको अधिक अधिकार मिलने चाहिये। अन्तिम, परन्तु कम महत्व का नहीं, कारण यह है कि हम सब को आशा है कि शिक्षा—प्रारम्भिक, औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी—के विस्तृत प्रसार का प्रयत्न किया जाने वाला है। श्रीमन्, मैं समझने देशवासियों के भाव को व्यक्त करता हूँ जब मैं यह कहता हूँ कि हम सब इस बात की आशा करते हैं कि अगले पांच वर्षों में शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न में विशेष दृढ़ता दिखाई जायगी। यदि इस ओर उन्नति करना है तो बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। इसलिये सरकार को चाहिये वह अपनी स्थिति की जांच करे और देखे कि मौजूदा आय से वह इसके लिये कितना रुपया निकाल सकती है। श्रीमन्, यह उद्देश्य—शिक्षा, सफाई, वास्तुकारों का अंगण में उद्धार, देश के लिये इतने व्यापक महत्व के ह कि कम से कम में उनके लिये नये करों के लगाने का प्रस्ताव करने से न हिचकूंगा यदि ऐसा करना आवश्यक होगा। लेकिन इसके पहले कि सरकार नये करों का प्रस्ताव करे, या नये सरकारों

मेम्बर उठाया समर्थन करें, यह प्रेरणा आवश्यक है कि मौजूदा आय से कितनी उन्नत हो सकती है। देश के प्रति सरकार का यही दम्भ है, और प्रजा के प्रतिनिधियों का भी यही कर्तव्य है कि वे इस बात पर सरकार के सामने जोर दें। इसी कारण से मने आज यह प्रश्न कामिला में उठाया है, और मैं साग्रह आशा करता हूँ कि सरकार उसी भाव से इन प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिन भाव से वे आज पेश किये गये हैं। श्रीमन्, मैं उस प्रस्ताव को, जो मेरे नाम के आगे है, उपस्थित करता हूँ।



द्वितीय भाग

— * —
राजनैतिक



लार्ड कर्जन का शासन ।



[श्रीमान् गोखले बनारस की कांग्रेस, १९०५, के सभापति थे। उन्होंने जो सम्भाषण दिया था वह कांग्रेस के साहित्य में सर्वोच्च कोटि का माना गया है। स्थानाभाव से वह अवि-
कल रूप से उद्धृत नहीं किया गया परन्तु लार्ड कर्जन के विषय में जो कुछ उन्होंने कहा वह नीचे दिया जाता है।
धन्यवाद, प्रिंस आफ वेल्स को स्वागत और नये वाइसराय को अभिनन्दन देने के बाद उन्होंने कहा —]

सज्जनों, यह किनना सच है कि सभी बातों का अन्त होता है। अतएव लार्ड कर्जन का शासन भी समाप्त हो गया। सात दीर्घ वर्ष तक सभी की आँखें देश में एक परम प्रभावशाली व्यक्ति ही की ओर लगी थीं—कभी प्रशंसा में, कभी आश्चर्य में बहुधा क्रोध में और शोक में, यहाँ तक कि अन्त में यह अनुभव करना कठिन हो गया है कि परिवर्तन सचमुच हुआ है। ऐसे शासन की तुलना करने के लिए हमें, मेरी राय में अपने देश के इतिहास में औरगजेय के समय को लेना पड़ेगा वहाँ भी हमें वैसाही अत्यन्त केन्द्रित और ग्रास तौर से शस्त्री शासन करने का प्रयत्न, वही दृढ़ उद्देश, कर्तव्य पालन का वैसाही प्रेरक भाव, न्याय क्षमता की अपूर्व शक्ति, वही अकेले होने का ग्याल, अवि-

श्वाल और दमन की नीति में वैसीही दृढ़ धर्मी, जिसने चारों ओर घोर असन्तोष उत्पन्न कर दिया, दिखाई देता है। मैं सोचता हूँ कि लार्ड कर्जन के परम भक्त भी यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की नींव मज़बूत की है। कुछ घातों में लार्ड कर्जन उन सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजों में गिने जायेंगे जो इस देश में कभी आये हैं। उनकी अपूर्व मानसिक शक्तियाँ, उनकी चमत्कारिक गण्डचातुरी, उनकी अद्भुत कार्यक्षमता, उनका काम करने के लिए अपरिमित उत्साह—इनकी सदा न्याययुक्त और भरपूर प्रशंसा की जायगी। लेकिन दबनाओं को डर होता है, और जहाँ गुणों की वर्षा इसी उदारता से की गई वहाँ उन्होंने उनकी महानुभूति पूर्ण रूप से संचित रक्खा, जिसके बिना कोई मनुष्य विदेशीय जनता को कभी नहीं समझ सकता है। और यह एक दुर्गन्धित सत्य है कि शासन की समामि पर लार्ड कर्जन भारतवर्ष के लोग को नहीं समझ पाये। यही उनकी अनेक त्रान्तियों की जड़ थी और इसी के कारण लोग उनके वास्तविक स्वरूप को समझने में परेशान होते थे। और इस तरह मैं वह आदमी जो शासन की बागडोर हाथ में लेने के समय गिलगुल मस्टार्ड के साथ अपने अधीन प्रजा के भावों पर उनके पक्षपातों तक को भी अत्यन्त सम्मान के साथ देखने की दृष्टि भरता था, उसी ने अन्त में न केवल हिन्दुस्तानियों की माजूदा समस्या का निःकुश शब्दों में भला बुरा कहा किन्तु उनके पक्षों और उनकी जाति के सर्वोपरि दृष्ट्य आदर्शों तक को उल्टा जिन्ने अपने शासन के आरम्भ में हाकिमों को सुझा हुआ यह चिन्तायनी भी कि "अफसरों की बुद्धि इनकी उच्छ नहीं है कि वह जात्यन्त की उत्तेजना और नियन्त्रण

के परे हो" और जिसने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान की मीजदा हालत में "शिक्षित समुदाय की अउद्देलना या उम्मा तिरस्कार करना राजनीतिज्ञता नहीं" उसी ने अन्त में विशेष रूप से उम्मा लोकमत का परों से कुचला और अपने तथा अपने अधिकारी सहकारियों की सम्मति के लिए निन्नात होने का पास्तयिक दावा किया। यान तो यह है कि लाह फर्नो मास एके पकाये विचारों का लेकर हिन्दुस्तान का आये थे। उनकी दृष्टि में भारतवर्ष वह देश था जहाँ अंग्रेज सब फाल के लिये शक्ति को तो अपने हाथ में रखें और हमेशा कर्तव्य का राग अलायें। हिन्दुस्तानी का ता काम अपने ऊपर दुफुनन पराने का था किन्तु कोई दूसरी आकाशा करना उसके लिये घोर पाप था। उनकी रचना में देश के पढ़े लिख लोगों के लिये कोई स्थान नहीं, और जब वह उन्हें बहुत फाल तक अपना विश्वासपात्र धनाने के निस्तार ढको सल से पुसलाने में समर्थ न हुआ तब अन्त में उसने उन्हें डगना शुरू किया। बम्बई के पारफला क्लय में विद्वार् की बतृना में भी भारतवर्ष अंग्रेजा के केवल परिधम की राग गाला है जिसमें देश की अगणित जनता—आरादी की ८० फीसदी—दर्शक है।

यदि लाह फर्नो कुछ कम अहम्मन्य होते, यदि उनमें कुछ अधिक विनम्रता होती, तो सम्भव है वह अपनी गलती समय से जान जाने। इससे वह उतना अमतोय न पैदा करत और न उतनी चोट ही पहुचाते, जितना उन्होंने अपने आपिरी दो साल में उत्पन्न की लेकिन मुझे सन्देह है कि उनके शासन की मुख्य धारा दूसरी तरह से प्रभावित होनी। लाह फर्नो के लिये राजनीतिज्ञता का सर्वोच्च आदर्श शासन-संचालन की

विशिष्टता थी जिसको मिस्टर ग्लेडस्टन स्वधीनता का सिद्धान्त कहा करने थे उसको वे मानव उन्नति का एक साधन मानते थे । उन्हें जन-साधारण की आकांक्षाओं के साथ कुछ भी सहा नृमृति न थी, और जब एक पराधीन प्रजा में उन्हें वैसी आकांक्षाएँ दिखाई देती हैं तब उनकी दृष्टि में उनको दवाना ही अपने देश की सेवा करना है । जैसे उन्होंने अपनी वाइ-कला क्लब गाली स्पीच में साफ साफ कहा था कि उन्होंने राजनैतिक सुधार इसलिये नहीं किया क्योंकि उममें उन्हें कुछ विश्वास न था । लार्ड कर्जन के गुणों ही पर ध्यान दें तो हम उनको इस दुस्साध्य कार्य की पूर्ति की कोशिश करते हुए देखते हैं कि भारतवर्ष में अगणों की ताकत और मजबूत होती जाय और सार्वजनिक आन्दोलन और असतोष का प्रवाह रोक दें । इसकी सिद्धि के लिये उन्होंने अधिकारियों में अपना ना कर्तव्य पालन का भाव उत्तेजित करना और हर तरफ शासन प्रणाली को अधिक सुन्यवस्थित बनाना चाहा । उनका यह प्रयत्न निष्फल हुआ जैसा उसको होना चाहिये था । इतना असतोष भारतवर्ष में घोर और विस्तृत पहिले कभी न था जितना तब जब उन्होंने शासन की यागडोर अपने हाथों में डोड़ी । और अधिकारियों की सत्ता पर एकाधिकार के विषय में मैं जानता हू कि हम उस समय के बहुत करीब हैं जब उस सफलता के साथ आक्रमण किया जायगा ।

लार्ड कर्जन ने यम्बई में बिदाई वाली घटना में एक दावा किया था जिसकी कुछ विस्तार के साथ आलोचना करना आवश्यक है । उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा, जैसा वे पहिले कह चुके थे—पिन्तले बजर पर बहस के समय पर कि यद्यपि नको शिक्षित भारत की शत्रुता का सामना करना पडा है

किन्तु जनता उस सबके लिए उनकी कृतज्ञ होगी, जो कुछ उन्होंने उसके लिए किया है। शिक्षित समुदाय और हिन्दु-स्तानी जनता के हितों में भेदभाव दिखाने का प्रयत्न उन लोगों का एक प्रिय साधन है, जो हमारे देशवासियों की न्याययुक्त आकाक्षाओं का दमन करना चाहते हैं। यह मार्क की धारणा है कि लार्ड कर्जन ने इसका आशय नहीं लिया जब तक उनका शिक्षित समाज से पूरा घिगाड़ न हो गया। हमें मालूम है कि यह भेदभाव क्रबिम और हास्यजनक है, और हम यह भी जानते हैं कि जो शिक्षित समुदाय की निन्दा करने का सरल साधन समझ इसका प्रयोग किया करते हैं उनको हममें कुछ विश्वास नहीं है। लार्ड कर्जन अपने पक्ष की पुष्टि में निमक कर के घटाने, अकाल के कारण लगान के बकाये की माफी, नहर और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अधिक धन और पुलिस सुधार की तजवीजों का जिक्र करते हैं। इस कथन से ध्यान दे यह निकलती है कि शिक्षित समुदाय के विरोध करने पर भी, कम से कम उनकी अवहेलना के होते हुए भी—उन्होंने इन तजवीजों को मजूर किया, यद्यपि असल बात यह है कि कांग्रेस घरसों से इनके लिए बिटलाती रही है और वर्षों के अधिक आन्दोलन ही के बाद, कांग्रेस इस ओर ध्यान देने में समर्थ हुई है। चार साल हुए जब ७ करोड़ की बचत होने पर भी सरकार ने टैक्सों में कुछ कमी न की थी और मैंने इसकी शिकायत करने की गुस्ताफी की थी और निमक कर को तुरन्त घटाने को कहा था, तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैसे लार्ड कर्जन ने उनका मजाक उड़ाया था जो "जनता के बोझ" और निमक-कर को घटाकर उनका भार हलका किया जाय। यह लार्ड कर्जन का सौभाग्य था कि वे हिन्दुस्तान

में ऐसे समय पर आये जब लार्ड लेंसडौन और सर डेविड
 यारवूर की निका सम्बन्धी नीति ने रुपये का भाव-कृत्रिम
 रूप से बढ़ा दिया था जिसके कारण भारत सरकार को
 "होमचार्जेंस" की मद में सालाना लगभग ६ करोड़ का
 बचन होती थी। इससे और उफीम की आमदनी में बाढ़ से
 लार्ड कर्जन को अपने शासन कालमें बहुत बड़ी बचत
 होने लगी और उन्हें अपने पूर्वजों की तरह आर्थिक तंगी
 से पल भर के लिए भी व्यथित न होना पड़ा। बचत की,
 बड़ी-०-रकमें देखते हुए मैं यह नहीं मान सकता कि लार्ड
 कर्जन ने प्रजा का योश्र घास तीर से हलका किया है।।
 पिछले मार्च में उन्होंने ने स्वयम् यह अनुमान किया था कि
 टक्कों में उलट करों के घटाने से जो आय घटी है वह
 लगभग १०½ करोड़ के थी। किन्तु उन्होंने ने साथ ही यह भी
 न कह दिया कि इतने ही समय में साधारण आवश्यकताओं
 की पूर्ति के लिए जिनने धन की जरूरत थी, उसके अलावा
 भारतीय सरकार न टैक्स देने वालों से ४६½ करोड़ अधिक
 बसल किये। फिर, निम्नक का के घटाने और अकाल के
 बकाये की माफी के कारण जो कुछ लाभ कर देने वालों को
 हुआ है वह उस बड़ी हानि के सामने कितना दुष्ट है, जो
 प्रजा को कृत्रिम रूप से रुपये के भाव बढ़ाने से हुई है। इससे
 जो कुछ थोड़ा उन्होंने ने जमा कर बादी के गहनों में लगा दिया
 था उसका मूल्य तुरन्त ही गिर गया।। अप्रत्यक्ष रूप से
 उनका लगान बढ़ा और उन पर जो फर्ज था वह भी रुपये
 के भाव में उलट फेर के कारण अधिक हो गया। इस तरह
 से उन पर जो सख्ती भार लदा है वह और भी अधिक
 हो गया। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए लार्ड कर्जन के

समय में बहुत कुछ किया गया है। किन्तु जब हम यह देखते हैं कि भारत में जनसाधारण की शिक्षा के लिए सरकार कितना कम खर्च करती है यह आश्चर्य की बात होनी यदि इतनी अधिक खर्च के होते हुए भी देश के शिक्षा सम्बन्धी व्यय में लार्ड कर्जन कुछ वृद्धि न करते। लेकिन यदि उन्होंने शिक्षा के लिए ३७½ लाख दिए ह तो फौज पर ७½ करोड़ सालाना अधिक व्यय होने लगा, और आख मूढ़कर चांगे तरफ युरोपियन अफसरों के घेतन बढ़ाये गये। मिस्टर ग्लेडस्टन के शब्दों में "व्यय का भूत" देश में खड्डकता से विचर रहा है और लार्ड कर्जन ने मितव्ययता के मनातनी सिद्धान्त का अनुसरण कभी नहीं किया, यद्यपि देश का हित इसी में है। जो शासक उतनी ही दृढ़ता के साथ शासन-प्रणाली के सुधार का काम करता, जितनी लार्ड कर्जन ने पिछले सात साल में दिखाई, वह अग्रेय ही बहुत से शासन-सम्बन्धी दोषों को या तो निकाल देगा या उनके कुपरिणामों को कम करेगा। किन्तु यह इस दावे से बिल्कुल भिन्न है कि वे जनता के स्वाभाविक नेताओं, देश के शिक्षित लोगों, से बढ कर जनसाधारण के हितैरी थे।

मैं समझता हूँ कि जय माननीय मेम्बर ने यह बात कही थी तब वह थोड़ी दिव्यगी कर रहे थे। यदि दिव्यगी नहीं कर रहे थे तो उनके कथन का कुछ अर्थ ही नहीं समझ पड़ता। मेरा अनुमान है कि किसी प्रस्तावित आईन के मसौदे का प्रकाशित करने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों पर उसका कुछ भी प्रभाव पड़ता हो उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। लोग तब ही विचार प्रकट कर सकते हैं जब उन्हें सब नियमों की समीक्षा करने का समय मिले। सरकार पर कोई अनुचित अन्याय या दोषारोप न हो, इसलिये आवश्यक है कि यह समीक्षा मसौदा पेश करने वाले मेम्बर के उतलाये हुये कारणों का ध्यान में रखते हुये, की जाय। अच्छा तो यह मसौदा अक्टूबर को शिमले में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से इसके नियम तार द्वारा देश के दैनिक समाचार पत्रों के पास भेजे गये और १० तारीख को प्रातः काल प्रकाशित हुए। समस्त भारत में केवल सात या आठ नगर हैं जहाँ से दैनिक समाचारपत्र निकलते हैं। दूसरे बड़े नगरों में यह पत्र एक या दो दिन बाद और कुछ नगरों में तीन चार या पाँचदिन बाद पहुँचने हैं। सामान्यतः छोटे छोटे नगरों में तो दैनिक पत्र जाते ही नहीं, उनको तो साप्ताहिक पत्रों से ही सतोष करना पड़ता है। इस लिये माननीय मेम्बर को मानना पड़ेगा कि शिमले से तारद्वारा भेजे हुए किन्नी समाचार को भारत के समान विशाल देश के सब भागों में फैलाने के लिये कमसे कम एक सप्ताह चाहिये। फिर मसौदा कॉसिल में १८ अक्टूबर को पेश किया गया था और पेश करने वाले मेम्बर की वक्तृता की सक्षिप्त रिपोर्ट दैनिक पत्रों में १६ तारीख को प्रातः काल निकली। वक्तृता

का दश भर में फैलाने के लिये कम से कम एक सप्ताह अवश्य लगा होगा। इस प्रकार सरकार का पूरा पक्ष देश के सामने विचार के लिये २६ अक्टूबर से पहिले किसी तरह नहीं पहुँच सकता। इसके बाद विचार करने के लिये, आपत्तियों को स्पष्ट प्रकट करने के लिये और उन आपत्तियों को सरकार के पास तरु पहुँचाने के लिये भी कुछ दिन चाहिये। इसक लिये अगर एक महीने का समय दिया जाना तो भी वह काफी न होता। पर यहाँ हुआ क्या? मसौदे पर विचार करने के लिये नियुक्त की हुई विशेष कमिटी ने २२ अक्टूबर को पहिली बैठक की, २३ तारीख को अपना काम खत्म कर दिया और २४ को रिपोर्ट पेश कर दी। सभी जानते हैं कि विशेष कमिटी के रिपोर्ट दे चुकने के बाद और कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस लिये जनता की कोई सम्मति मसौदे के व्यापक लक्षणों या छोटी २ बातों में कोई परिवर्तन कराने में इसी शर्त पर वृत्तकार्य हो सकती है कि यह सरकार के पास विशेष कमिटी का काम खत्म होने के पहिले ही पहुँच जाय। यही कारण है कि कांसिल का नियम है कि सामान्यतः विशेष कमिटी मसौदे के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के तीन महीने बाद ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आज के मामले के सम्बन्ध में विशेष कमिटी को किसी भी लोकमत से लाभ उठाने का अवसर न मिला। और तो क्या, तारद्वारा जो थोड़े बहुत प्रतिवाद सरकार के पास आये थे और जिन की प्रतिलिपियाँ हम में से कुछ लोगों के पास भी आई थीं वह भी विशेष कमिटी के सामने नहीं रखे गये। इस अवस्था में यह कहना कि हमने जनता को विचार के लिये काफी समय दिया, लोकमत की हँसी खाना मात्र है। अच्छा होता

यदि माननीय मेम्बर ने साफ २ यह कहा होता कि "भारतवर्ष में व्यवस्थापक कॉंसिल का एक मात्र कार्य यह है कि वह शासकवर्ग की आज्ञाओं को बिना कुछ कहे सुने मान लिया करे और लेखबद्ध कर लिया करे। कॉंसिल से कोई मसौदा पास कराना निरी रस्म है और वर्त्तमान के समान अवसरों पर इस रस्म को पूरा करना हमें बहुत चलता है। यदि आज भी हम इस रस्म को पूरा कर रहे हैं तो इसका कारण मजबूरी है और कुछ नहीं। जनता को हमारे पास निवेदन पत्र भेजने का कष्ट न उठाना ही अच्छा है क्योंकि हम इस मसौदे को आईन बनाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और कोई चाहे कुछ भी कहे सुने हम अपने निश्चय से ढलने वाले नहीं हैं। दूसरे जनता का यह काम नहीं है कि हम से किसी घात का कारण पूछे या हमें जवाब देने की दिठाई करे। उसका काम तो केवल हमारी आज्ञा का पालन करना है"। माननीय मेम्बर स्वयं अपने मन में जानते हैं कि हम ने मसौदे के हानि लाभ के पूर्ण विचार के लिये, सब पूछिये तो, कुछ भी समय नहीं दिया क्योंकि तभी तो उन्होंने अपने पक्ष की रक्षा के लिये दूसरी दलील की आवश्यकता समझी। वह कहते हैं कि "यद्यपि मसौदा जनता के सामने थोड़े ही दिन रहा है तथापि इसी आशय की, पूर्वीय घगाल और पंजाब के लिये प्रचारित, विशेष आज्ञा, पांच महीनों से देश के सामने है"। खूब ! उन्होंने यह भी क्यों न कह दिया कि आयरलैंड का इतिहास वर्षों से आपके सामने है और रूस में जो कुछ आज कल हो रहा है उससे भी आप सर्वथा अपरिचित नहीं हैं"।

मे ऐसी अत्यंत आवश्यकता और ऐसे घोर सकट की अवस्था की कल्पना कर सकता हू कि इस प्रसार का कानून

बनाना और इसी ढंग से बनाना आवश्यक हो पड़े। यदि देश में शासन के विरोध का प्रबल क्रियाशील और सुविस्तृत आन्दोलन होता, यदि बहुत से दगा फसाद हुआ करते, यदि लोगों को बलवा करने का गृह्यम गृह्या उपदेश दिया जाता तो मैं समझ सकता कि शासकवर्ग अपने को इस प्रकार के दमनशील अस्त्रों से क्यों सुसज्जित कर रहे हैं। पर क्या कोई सत्यवक्ता यह कह सकता है कि आज देश में ऐसी भयकर दशा उपस्थित है। इसके विपरीत, मैं कहता हूँ और मेरे यह कहने का कोई प्रतिपाद नहीं कर सकता, कि देश की अवस्था में ऐसी कोई बात नहीं है जो ऐसी दशा से तनिक भी मेल खाती हो। माना कि सारे देश में असतोष व्याप रहा है, माना कि दो प्रान्तों में तीव्र असतोष भरा हुआ है, माना कि सरकार की दमन नीति ने इस असतोष में क्रोध की मात्रा जो प्रतिदिन बढ़ती जाती है और प्रयत्न होती जाती है, और भी जोड़ दी है। पर सब पूछिये तो देश में क्रियाशील अशांति बहुत कम है और जो कुछ है भी उसके कारण प्रत्यक्ष हैं, उसका समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मसौदे के साथ लगे हुये "उद्देश्यों और कारणों के विवरण" में कहा गया है कि "गत छ मास की घटनाओं से सरकार को विश्वास हो गया है कि देश की शांति-रक्षा के लिये और नियमानुपालक जनता की रक्षा के लिये आवश्यक है कि राजद्रोहात्मक सभाओं को रोकने के लिये एक नया कानून बनाया जाय और उस कानून को आवश्यकता अनुसार भागत के किसी भी भाग में प्रचलित करने की व्यवस्था की जाय" और इस मसौदे को पेश करते समय माननीय मेम्बर ने कहा था —

"हमें आशा थी कि विशेष आज्ञा की अग्रिम समाप्त होने पर इस प्रकार का कानून बनाने की कोई आवश्यकता न रहेगी। पर हमारी यह आशा दुराशा मात्र सिद्ध हुई। हम दुःख के साथ स्पष्ट देखते हैं कि लोग राजद्रोह फैलाने की और शान्ति भङ्गकारी जातीय विद्वेष फैलाने की परापूर्व कोशिश कर रहे हैं, और यह कोशिशें विशेष आज्ञा के अन्तर्गत दो प्रान्तों के अलावा और जगह भी हो रही हैं।"

यह कथन भयंकर, किन्तु अनिश्चित शब्दों में किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी पुष्टि में घटनाओं का कुछ प्रमाण देना माननीय मेम्बर ने आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने ने न तो कोई एक उद्धृत किये और न किन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया। बस, स्मभारण शब्दों में एक बात कह मारी कि देश में राजद्रोह फैलाने के धगर प्रयत्न हो रहे हैं और समझ लिया कि सारे देश के लिये ऐसा भयंकर कानून बनाने की आवश्यकता प्रमाणित हो गई। मैं समुचित नम्रता के साथ कहता हूँ कि यह ईमानदारी का काम नहीं है। भारतवर्ष के अधिकांश निवासी जो पूर्णतः राजभक्त हैं, इस बात से अग्रिम रुष्ट होंगे और उनका रुष्ट होना बिल्कुल न्यायमग्न होगा। अच्छा आइये अब हम माननीय मेम्बर के दावे की जरा समीक्षा करें। पहिले तो वह यह कहते हैं कि हमें आशा थी कि गत मई मास की विशेष आज्ञा की अग्रिम समाप्त होने पर दोनों प्रान्तों में उस आज्ञा की नीति जारी रखने की आवश्यकता न होगी पर हमारी यह आशा पूरी न हुई। दूसरी बात वह यह कहते हैं कि यदि भारत के अन्य प्रान्तों में भी इस नीति का प्रयोग किया जायगा तो वहा भी शान्तिभङ्ग होने का खटका बना रहेगा। अच्छा असली बात

क्या है। पहिले पञ्जाब को लीजिये। जहा तक मुझे मालूम है कि विशेष आज्ञा प्रचारित होने के बाद सारे प्रान्त में केवल एक सार्वजनिक सभा हुई है। वह दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में विशेष आज्ञा प्रचारित होने के पहिले हुई थी। सभा का उद्देश्य लाला लाजपत राय जी के निर्वासन पर शोक प्रकाश करना था। उसमें हिन्दू मुसलमान दोनों सम्मिलित हुए थे। इस असे में प्रान्त भर में कहीं भी शान्तिभङ्ग नहीं हुई। माननीय मेम्बर शायद कहेंगे कि अजी यह सुन्यवस्था विशेष आज्ञा के कारण ही है। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि यही बात है तो भी उन्हें पञ्जाब के विषय में निराश होने की शिफायत करने का कोई कारण नहीं अब पूर्वोक्त बंगाल की ओर देखिये। वहाँ भी हिन्दू मुसलमानों के उन दलों के बाद जिनके कारण विशेष आज्ञा प्रचारित की गई थी, कोई झगडा फसाद नहीं हुआ। जहा तक लोगों की मालूम है, विशेष आज्ञा का विरोध करके वहा कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई है। लोगों ने जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत से फरीदपुर में एक जिला परिषद् करना चाहा था पर जब मजिस्ट्रेट ने कार्यक्रम के दो प्रस्तावों पर, जिनमें से एक लाला 'लाजपत-राय के निर्वासन के सम्यन्ध में और दूसरा विदेशी माल के बायकाट के सम्यन्ध में था, आपत्ति की तब लोगों ने कान्फरेंस का विचार छोड दिया इससे लोगों में धोर असतोष और क्रोध फैला था पर शान्तिभग जरा भी न हुई। सम्भव है कि गुप्त पुलिस ने सरकार के पास पूर्वोक्त बंगाल में निजी घरों में छिप कर होने वाली सभाओं के वर्णन भेज हों। माननीय मेम्बर ने अपनी १८ अक्टूबर की बक्तृता में कुछ ऐसी ही बात कही है। पर एक तो जैसा कि रावलपिंडी के मुकदमे से ओर हाल की

घटनाओं से सिद्ध होता है, गुप्त पुलिस की भेजी हुई सब रिपोर्टों पर बहुत समझ बूझकर विश्वास करना चाहिये दूसरे मान लीजिय ऐसी सभायें हुई हैं, तो भी शान्ति भङ्ग नहीं हुई और मालूम होता है, कोई बड़ी हानि भी नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि घरेलू जीवन के समान राजकीय मामलों में भी ऐसी बातों को, जो किसी को कुछ बड़ी हानि नहीं पहुँचाती और जिनको रोकना भी कठिन है, आस मीचकर टाल देना ही बुद्धिमानी है। यह तो हुई उन दो प्रान्तों की बात जिनमें गत मई मास से विशेष आशा प्रचलित है। इन प्रान्तों के बाहर, देश भर में केवल दो जगह दंगे हुए हैं—एक तो कुछ दिन हुये मद्रास प्रेसीडेन्सी के अन्तर्गत कोकोनद में और दूसरा हाल में कलकत्ते में। पहिले का कारण यह था कि एक अग्रेज अफसर ने एक विद्यार्थी को “बन्दे मातरम्” चिल्लाने पर पीटा था। दूसरे के विषय में कहा जाता है कि स्वयं पुलिस ने पहिले आक्रमण किया। पर इन दोनों दंगों का मूल कारण कुछ भी क्यों न रहा हो और हमें उनका कितना ही शोक क्यों न हो, उनसे कदापि यह सिद्ध नहीं होता कि सारे देश को ऐसे कठोर कानून की जजीर से, जैसा कि आज कौन्सिल से पास करने को कहा गया है, बाध दिया जाय। मित्र २ प्रान्तों में जो सार्वजनिक सभायें हुई हैं उनमें, कलकत्ते की कुछ सभाओं को छोड़कर, ऐसी कोई नहीं है कि विशेष प्रकार से जनता का ध्यान आकर्षित करे। निस्सन्देह कुछ सभाओं में सरकार के विरुद्ध कड़ी २ बातें कही गई हैं और शायद दस पाँच सभाओं में बहुत बड़ बड़ कर बातें कही गई हैं पर बहुत करके इसका कारण सरकार की, गत मई मास से प्रयुक्त की हुई, दमन नीति है। मेरी समझ में तो देश की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं

है जिसका निपटारा सरकार वर्तमान कानून के अनुसार प्राप्त शक्ति से अच्छी तरह नहीं कर सकती । हा, उस शक्ति का प्रयोग कुशलता, बुद्धिमानी और दृढ़ता के साथ होना चाहिये चाहे जिस दृष्टि से देखिये, ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई विषम अवस्था उपस्थित नहीं है जिसके कारण इस मसौदे के भयंकर नियम बनाने की, या इसको इस तरह झपट्टी से कौन्सिल से पास कराने की, आवश्यकता हो। माननीय मेम्बर कहते हैं कि 'मई मास की विशेष आज्ञा की अवधि आगामी १० नवम्बर को समाप्त हो जायगी, यदि उस तारीख तक नया आईन न बनेगा तो बड़ी गड़बड़ मच जायगी' । यह कथन केवल पंजाब और पूर्वीय बंगाल के लिये लागू हो सकता है । फिर पंजाब में तो ऐसी शान्ति विराजमान रही है कि यदि सरकार उसे एक बार फिर साधारण कानून के नीचे रहने का अवसर दे तो अच्छा होगा । रहा पूर्वीय बंगाल तो यदि वहाँ की स्थिति में घस्तुत चिन्ताजनक लक्षण दीख पड़ते तो सरकार दूसरी विशेष आज्ञा निकाल सकती थी या पूर्व बंगाल और आसाम प्रान्त की व्यवसायिक कौन्सिल में कानून बनाया जा सकता था । मैं समझता हूँ कि यदि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया ही जाय तो बहुत अच्छा हो कि प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रान्तीय कौन्सिलों में ही रखा जाय। ऐसा करने से दोनों पक्ष पूरे ज्ञान से सम्पन्न होकर, प्रान्त का उन विशेष परिस्थितियों पर अच्छी तरह विचार कर सकेंगे जिन्के आधार पर शासकवर्ग असाधारण अपिहार मांगते हैं ऐसा करने से उन प्रान्तों के लिये विशेष दयाकारी नियम न बनेंगे जिन के लिये साधारण आईन काफी है ।

भारत के अधिकांश शिक्षितजनों के हृदय में यह बात

चुम गई है। कि गत छ महीनों में उद्देश्य और आन्दोलन-
 प्रिटिश जनता के सामने बहुत नमकमर्च लगाकर असत्य
 रूप में रखे गये हैं और हमारे साथ ईमानदारी का पताच
 नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने थोड़े से कल्पनाशील
 व्यक्तियों की चकृताओं को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है
 और प्रत्येक प्रासांगिक घटना का अनुचित लाभ उठाकर सुधार
 के लिये और निर्दिष्ट फटिनाइयों के निवारण के लिये होने
 वाले आन्दोलन को घगावत के रूप में दर्शाया है। यह कार्य-
 मुख्यतः कुछ विद्वेपी उच्छृङ्खल पत्रसम्पादकाओं का रहा
 है पर अभाग्यवश सरकार के दमननीति स्वीकार कर लेने से
 भी उनके कथनों का कुछ समर्थन सा हो गया है। सबसे
 अधिक शोक की बात यह है कि स्वयं भारत सचिव इन
 असत्य निरूपणों के शिकार हो गये हैं। स्वयं इस देश के लोगों
 को कुछ ज्ञान न होने से और अपने पद के उत्तरदायित्व के
 भाव के नीचे दब जाने से उनकी दृष्टि ने ठीक २ काम करना
 छोड़ दिया है और उनका, वस्तुओं का पारस्परिक परिमाण
 घुट्टि घिगड गई है। समय समय पर ब्रिटिश पार्लामेंट के
 हाँस आफ कामन्स में उन्होंने विपत्ति सूचक सकेत किये हैं
 और अनेक बार अपने भाषण में ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं
 कि मानो देश में बड़ा भारी विप्लव होनेवाला है और बड़ी घोर
 आपत्ति आनेवाली है। इस अवस्था में वर्तमान मसौदे के पास
 होने से और ऐसी अप्रती के साथ पास होने से, इङ्ग्लैंड में
 हमारे विषय में प्रचलित असत्य भावनाएँ और भी गहरी जड़
 पकड़ेंगी। और इसने अपो साथ होनेवाले अन्याय और अप-
 कार का पह भाव और वह आभ्यन्तर क्रोध जिसके साथ मेरे
 देशभाई अत ६ महीना में लगातार घटनाओं का निरीक्षण

करते रहे हैं, और भी बढ़ जायगे। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सरकार अपनी उस भूल को दुहरा रही है जो उसने बंगाल के दो टुकड़े करने में की थी। बगविच्छेद से शासन सम्बन्धी सुव्यवस्था के चाहे जिन लाभों की आशा रही हो पर उसका फल यह हुआ है कि उस प्रान्त के अधिकांश जन अब सरकार की ओर प्रेम और प्रसन्नता की दृष्टि से नहीं देखते। महान् से महान् शासन सम्बन्धी लाभ भी इस छति की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी तरह से जहाँ सरकार इस आईन से एक आदमी की घे सिर पैर की बातचीत रोकेंगी वहाँ भी सौ निन्यानबे आदमियों के मन में यह भाव उत्पन्न करेगी कि बिना किसी अपराध के हमारे सिर पर यह कठोर कानून लाद दिया गया है, चुपके २ धीरे २ किन्तु निश्चित रूप से उनके मन सरकार से हटते जायगे और अन्त में सरकार की आर उनका सारा भाव बदल जायगा।

हाल में भारत में राजद्रोह के विषय में इतना कहा सुना गया है, कि आज की सभा में सक्षेप से यह परीक्षा करना अनुपयुक्त न होगा कि वास्तव में राजद्रोह है या नहीं, याद है, तो कितना है, उसका मूल कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं? मैं समझता हूँ कि पाँच वर्ष हुए जब लाड कर्जन ने दिल्ली दरबार में यह घाषणा की कि भारतवर्ष की प्रजा राजभक्त है और हृदय से चाहती है कि इंग्लैंड से हमारा सम्बन्ध बना रहे तब उन्होंने कोई अत्युक्ति न की थी, एक बिल्कुल सच बात कही थी। जब हम भारतीय राजभक्ति का जिक्र करने हैं तब हमारा अभिप्राय यूरोप में जमीन्दारी प्रथा के समय में प्रचलित या भारत में राजपूतों के समय में प्रचलित राजभक्ति भाव से नहीं है हमारा अभिप्राय यह है कि लोग यह

समझकर कि अंग्रेजी शासन ने भूतकाल में हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंग्रेजी शासन भविष्य उन्नति के लिए आवश्यक परिस्थितियों को स्थिर रखेगा, अपने आत्महित के उत्कृष्ट भाव से प्रेरित हो कर अंग्रेजी शासन से प्रेम करते हैं और उसकी स्थिरता के अभिलाषी हैं। इस अर्थ में भारत का शिक्षित समुदाय सदा से पूर्णतः राजभक्त है। पर यह अवश्यभावी था कि वह धीरे-धीरे अपनी स्थिति से और वर्तमान शासनपद्धति से असन्तुष्ट हो उठें और चाईस वर्ष हुए उन्होंने सुधार के लिए सुव्यवस्थित आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन के उद्देश्य और कार्यप्रणाली पूर्णतः राजनियमानुकूल थी, यह प्रतिवर्ष देश में तेजी के साथ फैलने लगा। इसको सरकार से बहुत प्रोत्साहन न मिला था पर इसके मार्ग में कोई बड़ी अड़चन भी नहीं डाली गई थी और लार्ड कर्जन के समय तक इसकी धारा बहुत करके बाधाहीन मार्ग से, जातीय विद्वेष की कटुता से सामान्यतः पृथक्, बहती रही। इसके बाद एक महान्, और कुछ अंशों में, विस्फोर्ककारी परिवर्तन हो गया। लार्ड कर्जन की अग्रगतिशील नीति ने, महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र को बातों में उड़ा देने के उनके प्रयत्न ने कलकत्ते में विभिन्न विद्यालय के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर उनके धुद्धिमत्ताहीन भाषण ने सारे देश में ज्वलत क्रोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। यह अग्नि बंगाल में सब से अधिक थी क्योंकि यद्यपि लार्ड कर्जन के कानूनों और व्यवस्थाओं का प्रभाव सारे देश पर पड़ा तथापि बंगाल पर उनकी जैसी चोट पड़ी वैसी और प्रांतों पर नहीं पड़ी थी। और जब इन सब बातों के ऊपर बंगाल को दो टुकड़े कर दिये गये तब तो घहा एक

तीक्ष्ण और उत्तेजित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसमें सुधार के लिये सामान्य आन्दोलन विलकुल मिल गया। मानो एक प्रकार की सदाबुध्ति के द्वारा बंगाली आन्दोलन की कटुता सारे देश के आन्दोलन में व्याप गई। और प्रान्तों की अपेक्षा बंगाल में सदा से विचारों और भावों की अधिकता रही है। बगविन्द्रे के विरुद्ध आन्दोलन की असफलता लोगों के विल में चुभ गई। अस्वस्थ आदमियों के मन में नये प्रश्न उठने लगे और वह "नये सिद्धान्तों" का उपदेश करने लगे। सच है कि इन लोगों की बातें देश के कुछ लोगों ने सुन और मान ली हैं पर इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि लोग उनके सिद्धान्तों के व्यवहार योग्य होने में विश्वास करते थे पर इस कारण से वह उनकी चतृताओं के ज्वलन्त, ओज और काव्य से मोहित हो गये थे। आज इनका जो कुछ प्रभाव है उसका कारण सरकार और जनता के बीच का वह मनमुटाव है जो अब बढ़ गया है लेकिन जिसको ठीक कर देना अब भी सरकार की सामर्थ्य में है। दमनशील कानून तो मनमुटाव को और भी बढ़ा देंगे और इस प्रकार नये उपदेशकों के प्रभाव को भी प्रगल्भ कर देंगे।

इस वर्ष के प्रारम्भ में नई बस्ती के सम्बन्ध में प्रस्ताविन आर्देन के कारण एवं अन्य कृपिसम्बन्धी कष्टों के कारण, पञ्जाब में भी एक तीव्र आन्दोलन उत्पन्न हुआ। जब सरकार ने "सिविल और मिलिटरी गजट" को एक कोमल चेतावनी देकर छोड़ दिया पर "पञ्जाबी" पर जातीय विद्वेष भड़काने का अभियोग लगा कर, स्वयं मुकदमा चलाया तब आन्दोलन में कटुता का एक नया अंश आ मिला। थोड़े दिन के लिये पञ्जाब में साधारण सुधार-आन्दोलन नये आन्दोलन

में विलकुल मिल गया। अन्य प्रान्तों पर इसका प्रभाव पडना ही चाहिये था और पडा भी। इसके बाद लाहौर में वृहत् सभाएँ हुई और रावलपिडी में दंगा हुआ। तत्पश्चात् सरकार ने दमनशील कार्रवाइयाँ कीं, जिनमें से मुख्य लाला लाजपतराय का निर्वासन, रावलपिडी के वकीलों की गिरफ्तारी, उन पर मुकदमा चलाना, और सार्वजनिक सभाओं के सम्बन्ध में विशेष आज्ञा की घोषणा थी। सारे देश में बेचैनी फैल गई, पंजाब को तो लकवा सा मार गया, दूसरे प्रान्तों के अत्यंत शान्त और विचारशील मनुष्यों के लिये भी समय पूर्वक सम्मति प्रकट करना कठिन हो गया। लाला जी के समान मनुष्य, जिनसे उनके प्रान्तों के ही नहीं किन्तु अन्य प्रान्तों के हजारों आदमी प्रेम करते हैं, जो उद्यत चरित्र और उत्कृष्ट भावों से सम्पन्न हैं, जो हृदय से धार्मिक और सामाजिक सुधारक हैं, जो राजनैतिक कार्यकर्ता भी हैं, जिनके दोष चाहे कुछ भी क्यों न हों पर जो अपना सारा काम खुल्लमखुल्ला बिना किसी गोपनीय रहस्य के करते थे, ऐसा मनुष्य अचानक गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाये ही निर्वासित कर दिया गया, यह देखकर सारा देश सन्न हो गया।

रही रावलपिडी की बात। उसकी विषय में मैं क्या कहूँ। चार महीने तक सारा देश यह दृश्य देखता रहा कि पृथ्वीय लाला हसराम, जो इस-कौंसिल में बैठे हुए किसी मेम्बर की ही तरह, दंगा फसाद कराने का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकते, अन्य माननीय सज्जनों के साथ मारपीट के लिये प्रोत्साहन देने के और-राजराजेश्वर के विरुद्ध पड़्यन्त्र रचने के अभियोग के कारण, हवालात में सड़ रहे हैं। इन महानुभावों के कष्ट जनता के मन

से जल्द नहीं भूल सकते । अब देश यह प्रतीक्षा कर रहा है कि देयें अधिकारीवर्ग उन लोगों को क्या दंड देने हैं जिन्होंने ऐसी गवाही देकर जिसे मजिस्ट्रेट ने अत्यंत अविश्वासनीय और बहुत कर के जाली बतलाया है, इन महानुभावों को ऐसे कष्ट दिये । जब देश में यह बातें हो रही हैं तो क्या आश्चर्य है कि जेय, नर्मी और आत्मसमर्पण का उपदेश देने वालों की आवाज कुछ न सुनी जाय ? गत छ महीने की घटनाओं ने उन लोगों को उड़ा सहारा दिया है जो सख्त और कभी-कभी वे सिर पर की भी बात चीत करते हैं ।

अच्छा तो देश की ऐसी स्थिति है । बंगाल में कुछ लोग नये मंत्र का उपदेश देने लगे हैं और देश में कहीं-कहीं उनके उपदेश की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । पर जनता पर प्रभाव डालने की उनकी जो कुछ सामर्थ्य है वह मुख्यतः इस कारण से है कि शासनसम्यन्धी सुधारों के विषय में और निर्दिष्ट कठिनाइयों के निवारण के विषय में देश के मन में अत्यन्त दीनता और निराशा का भाव प्रचलित है । स्पष्ट है कि इसका इलाज कोरी दमन नीति नहीं है किन्तु यह है कि सरकार बुद्धिमानी और दृढ़ता के साथ जनता को प्रसन्न करने की रीति अङ्गीकार करे । जहाँ तक पञ्जाब का सम्यन्ध है वहाँ तक श्रीमान् लाट् साहब ने नई बत्ती जाले । कानून को नामजूर करके, इस नीति का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रयोग किया है । जनता को राजी करने के काम का और भी बड़ा इश्वे, निर्वासित केलियों को मुक्त कर दीजिये, यदि सरकार को उनके विरुद्ध कोई शिकायत है तो न्यायालय में न्याय्य रीति से उनका विचार होने दीजिये, विशेष आशा की अवधि समाप्त होने पर प्रान्त में साधारण कानून का ही

राज्य रहने दीजिये । जैसे पञ्जाब में नई बस्ती वाला और नई रद्द कर दिया गया है वैसे ही बंग विच्छेद में भी कुछ ऐसा परिवर्तन कर दीजिये जो बंगालियों को अच्छा लगे । तब इन दोनों प्रान्तों के तीव्र असन्तोष के कारण दूर हो जायेंगे और सुधार आन्दोलन की पुरानी धारा उन कड़वी सहायक धाराओं से, जो हाल में आ मिली है, पृथक् हो जायगी । तब सरकार सुधार के प्रश्न पर उसके गुण दोष के अनुसार विचार कर सकेगी और यदि वह उस पर उदार राजकौशल के साथ विचार करेगी तो वह ऐसा निपटारा कर सकेगी जो सब को सतोष-जनक हो । इस सम्बन्ध में मैं सर हार्वे ऐडमसन की एक बात के धारे में जो उन्होंने १८ तारीख को कही थी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ । दमन की आवश्यकता बतलाते हुए माननीय मेम्बर ने कहा था कि "भारत सरकार ने धरावर यह स्वीकार किया है कि अशान्ति का एक मात्र कारण राजद्रोहात्मक आन्दोलन नहीं है किन्तु उसका आधार शिक्षित भारतवासियों की स्वाभाविक उच्च आकांक्षाओं पर है । इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये और भारतवासियों का देश के शासन में धनिष्ठता से सम्बन्ध करने के लिये हमें सुधार का एक बड़ा और उदार प्रस्ताव प्रकाशित किया जो समालोचना के लिये जनता के सामने है" । इतना कहने के बाद उन्होंने खेद प्रकाश किया कि लोगों ने प्रस्ताव का स्वागत अच्छी तरह नहीं किया जिससे मालूम होता है कि सरकार का ऐसा आदमियों से पाला पड़ा है जो किसी तरह सतुष्ट ही न होंगे । मुझे विश्वास है कि माननीय मेम्बर उन मध्य लोगों को इस श्रेणी में नहीं गिन रहे हैं जो सरकार के प्रस्तावों का जोश के साथ अभिनन्दन नहीं कर सकते ।

पर जैसा कि यम्बई प्रान्तीय समिति के तार से मालूम होना है, उनके शब्दों का यही अर्थ समझा गया है। यह अभिम्य की बात है। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। यदि सरकार की आशा थी कि उनके प्रस्तावों के प्रकाशित होने से देश के असतोप की मात्रा कुछ भी कम हो जायगी तो उनको केवल निराशा ही हो सकती थी। प्रस्ताव न तो महान हैं और न उदार हैं और कुछ अंशों में तो वह सुधार से बिलकुल ग्याली हैं। उससे जो खेद उत्पन्न हुआ है उसने प्रचलित असतोप को और भी बढ़ा दिया है। मानो यह भी काफी नहीं था, इसलिये प्रस्तावों को समझाने में बिना किसी आवश्यकता के कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं जो कुछ घणों का चित्त दुप्राये बिना नहीं रह सकते। मुझे खेद है कि लगभग सारा प्रस्ताव उस गौरव और गम्भीरता से ग्याली है जो मनुष्य महत्वपूर्ण राजकीय पत्रों में देखना चाहता है।

यह कहा गया है कि यद्यपि यह आईन सारे देश के लिये बना रहा है तथापि किसी भी स्थान के लोगों के लिये, इसके नियमों से रक्षा के हेतु, दो साधन प्रस्तुत हैं। एक तो यह कि भारत सरकार इसको किसी प्रान्त में प्रचलित करने की आज्ञा दे और दूसरा यह कि प्रान्तीय सरकार उस स्थान को उद्घोषित करे। जरा सा विचार करने से मालूम हो जायगा कि इन सरक्षक विधानों में कुछ भी नहीं है। पहिला तो नाम मात्र का है। एक स्थान राजद्रोह से सर्वथा शून्य है यद्यपि यदि यह समझा जावे कि उसी प्रान्त के किसी दूसरे स्थान में इसके नियम प्रचलित करने की आवश्यकता है तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती कि सारे प्रान्त के लिये आईन को लागू कर दे। इस प्रकार एक

स्थान के कारण सारे प्रान्त के लिये आईन लागू हो जायगा। फिर जब एक बार सारे प्रान्त के लिये आईन लागू हो गया तो लगभग सारे निवासियों के पूर्णतः राजभक्त होने पर भी और राजद्रोह की आशका से पूर्णतः मुक्त होने पर भी इने गिने दस पांच आदिमियों की वास्तविक या काल्पनिक राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों के कारण किसी भी स्थान में एक दम आईन की घोषणा की जा सकती है। जब घोषणा हो गई तब सारी जनता, बिना किसी भेद भाव के, पुलिस शासन के हवाले कर दी जायगी। अन्य आपत्तियां दूर रहें, यही आशका उस चिन्ता और घबड़ाहट का मूल कारण है जो इस मसौदे का देखकर लोगों के हृदय में उत्पन्न हुई है। माननीय मेम्बर कहते हैं कि "जब किसी स्थान की घोषणा करना आवश्यक समझा जाय तब यह बेजा नहीं है कि राजभक्त प्रजा सावजनिक हित के लिये थोड़ी सी असुविधा सहन करने को तय्यार हो।" मुझे आश्चर्य है कि थोड़ी सी असुविधा से माननीय मेम्बर का क्या अभिप्राय है। क्या यह जरा सी घात है कि आपके घर पर दिल दुराने वाला, पुलिस के हमले, हुआ करें? क्या यह जरा सी घात है कि आप बीस से ज्यादा मनुष्यों का सामाजिक सम्मिलन करें, तो पुलिस आपके सड़को तित्तर वित्तर कर दे, और घराती घराती सड़को बिना नोटिस के सार्वजनिक समा करने का अपराध लगा कर, मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर दे? मान लीजिये कि आपने अदालत में अभियोग को झूठा सिद्ध कर दिया और मजिस्ट्रेट ने आपको छोड़ दिया। पर जरा यह तो देखिये कि कितनी अनावश्यक चिन्ता और चिपत्ति का सामना आपको करना पडा। हमारे देश के समान उच्छृङ्खल

और हृदय हीन पुलिस के होते हुए यह भय-कोरे कार्टपनिक नहीं है। अभी हम रावलपिंडी में देख चुके हैं कि पुलिस क्या कर सकती है। और उदाहरण भी इस बात के दिये जा सकते हैं कि पुलिस ने आदि से अन्त तक मुकदमे गढ़ डाले। माना कि मसौदे की मशा सामाजिक सम्मिलनों में हस्ताक्षेप करने की नहीं है। माना कि चौथे विभाग के अनुसार मजिस्ट्रेट को केवल उन सार्वजनिक सभाओं की नोटिस देने की आवश्यकता है जो कुछ विशेष विषयों पर विचार करने के लिये की जायें। लेकिन यदि कोई पुलिस अफसर किसी मनुष्य को आपत्ति में फसाना चाहता हो तो वह सदा यह बहाना कर सकता है कि बीस से अधिक मनुष्यों की सभा सार्वजनिक सभा है और वह कुछ गवाह भी यह गवाही देने के लिये तय्यार कर सकता है कि सभा का उद्देश्य राजनैतिक था। यह बहाना करके लोग अपराध कर रहे हैं अर्थात् बिना नोटिस दिये २० से अधिक मनुष्यों की सभा कर रहे हैं कोई पुलिस अफसर अन्दर घुसने का दावा कर सकता है। यदि घर का स्वामी दंड मनुष्य है और अपने स्वयं को अच्छी तरह समझता है तब शायद वह अफसर का विरोध करेगा और उसे घर के अन्दर न जाने देगा। पर तब शायद वह मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जायगा और उस पर मुकदमा चलाया जायगा। पर यदि एक मनुष्य इस तरह पुलिस का सामना करेगा तो दूसरे नौ मनुष्य बिना कुछ कहे सुने दब जायेंगे। दूसरे जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के सामने जायगा तब न जाने वह "सार्वजनिक सभा" इन शब्दों का क्या अर्थ लगायगा। स्वयं माननीय मेम्बर इस बात के उदाहरण हैं। गत शुक्रवार को

उन्होंने कहा था कि चीथे नियम में ताँसरा उपनियम मिलाने का अभिप्राय यह है कि म्युनिसिपैलिटी इत्यादि के अधिवेशनों की भी नोटिस मजिस्ट्रेट के पास भेजने की कोई आवश्यकता न हो। उन्होंने कहा था कि "यदि उस नियम का कठोर प्रयोग किया जाय तो उद्घोषित स्थानों में म्युनिसिपैलिटी की बैठक करने के लिये भी नोटिस देने की और इजाजत लेने की आवश्यकता पड़ेगी"। इस प्रकार माननीय मेम्बर के मतानुसार म्युनिसिपैलिटी की बैठक सार्वजनिक सभा है। इसके विपरीत मेरे माननीय मित्र डाक्टर घोष कहते हैं कि मसीदे की परिभाषा के अनुसार म्युनिसिपैलिटी की बैठक सार्वजनिक सभा नहीं कही जा सकती। माननीय मेम्बर अपने वर्तमान पद पर नियुक्त होने के पहिले चर्मा प्रान्त में मुख्य न्यायाधीश थे। डाक्टर घाष देश के अत्यन्त विद्वान और प्रसिद्ध कानूनवेत्ताओं में से एक हैं। कानून बनने के पहिले ही जब ऐसे दो प्रामाणिक व्यक्तियों में सार्वजनिक सभा के अर्थ लगाने में इतना मतभेद है तब सीधे सादे अनुभव शून्य मजिस्ट्रेट न जाने क्या अर्थ लगावेंगे।

इस मसीदे में और भी बहुत सी आपत्तिजनक बातें हैं पर मैं उन सब का वर्णन कर के कौन्सिल को थकाना नहीं चाहता। यह मसीदा बड़ा भयंकर है। इसको सुधारने का एक मात्र सतोष जनक उपाय यह है कि इसको एक दम रद्द कर दो। पर स्वयं मसीदे की अपेक्षा अधिक आक्षेपणीय मसीदे की नीति है। मैं इस नीति को अत्यन्त बुद्धिहीन समझता हूँ। यह नीति सारे ससार में व्यर्थ सिद्ध हुई है और भारत में भी

व्यर्थ सिद्ध होगी। इससे जनता के मन में कठोरता की ऐसी स्मृतियाँ शेष रह जायेंगी कि वह समय के धोए भी न धुलेंगी। इससे शासन के कार्य में कोई सुगमता न होगी। बहुत करके तो यह दवा रोग को और भी बढ़ा देगी।

बंगाल और बंगाली ।



(नवम्बर, सन् १९०७, को शिमले में बड़ी व्यापक फॉसिल में राजद्रोही सभा सम्बन्धी विल पर अन्तिम बहस के अवसर पर सरकारी मेम्बरों ने कई आलोचनायें यातें कही थीं। उनका जो उत्तर मिस्टर गोपले ने उसी समय पर दिया था, वह निर्भीकता और गम्भीरता के लिये बहुत प्रसिद्ध है। उसी का निम्नलिखित अनुवाद है —

श्रीमन्, मैं इस समय मसौदे के सम्बन्ध में थोड़े ही शब्द कहना चाहता हूँ और वह भी आपके सामने अपील के तौर पर। माननीय सर हर्बर्ट एडमसन ने इस कानून के उत्तर दायित्व के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं जिनका प्रतिपाद करना परमावश्यक है और जिनके जवाब में कुछ कहना भी आवश्यक समझता हूँ। उनका कहना है कि इस कानून के बनाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो भारतीय सुधारक दल के नरम विभाग के सदस्य कहलाते हैं। मैंने स्वयं नरम गरम इन शब्दों को कभी पसन्द नहीं किया। गरम कहलाने वाले कुछ लोगों में भी कभी २ बड़ी नरमी दिखालाई देती है और नरम कहलाने वाले लोगों में भी बहुत ही काफ़ी गर्मी देखी जाती है। तो भी मुझे आशंका है कि यह शब्द प्रचलित रहेंगे, और इस समय में उनका प्रयोग उसी अर्थ में करूँगा जिसमें

माननीय मेम्बर ने किा है। मुझे तो यह घोर अन्याय मौलमे होता है कि देश में यदि थोडा बहुत राजद्रोह है तो उसका उत्तरदायित्व नग्न दल के माथे मढा जाय।

आज कुछ देर हुई, मने अपने भाषण में कुछ विस्तार से इस प्रश्न पर विचार किया था कि वर्तमान स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है। मैं फिर उसी प्रिय पर कुछ कहना नहीं चाहता पर एक दो बातों को कहना और उनपर जोर देना मैं अवश्य चाहता हूँ। जब इस देश में सरकारी अफसर राजद्रोह का जिक्र करते हैं तब उन सब का अभिप्राय एक ही वस्तु से नहीं होता। भिन्न २ अफसर 'राजद्रोह' का भिन्न २ अर्थ लगाते हैं। कुछ अफसर तो यह समझते हैं कि यदि कोई भारतवासी हम से दूरी जवान से ओर सास रोक कर बात चीत नहीं करता तो वह राजद्रोही है। कुछ यह समझते हैं कि यदि कोई हमारे कार्यों और शासन की प्रतिकूल समा लौचना करता है तो यह राजद्रोही है। कुछ ऐसे हैं जो स्थिति को दीर्घ दृष्टि से देखते हैं ओर समझते हैं कि राजद्रोह शब्द केवल उने प्रयत्नों के लिये प्रयोग किया जा सकता है जो देश के शासन को उत्पन्न देने के लिये किये जाते हैं। इस समय में पहिली ओर दूसरी श्रेणी वालों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। तृतीय श्रेणी वाले लोग राजद्रोह का जो अर्थ करते हैं वह मैं भी करूंगा। मैं जोर दे कर कहूंगा कि यदि ऐसा राजद्रोह उत्पन्न हो गया है तो वह हाल में ही उत्पन्न हुआ है, गत तीन चार वर्षों के भीतर ही उत्पन्न हुआ है और उसका उत्पत्ति का उत्तरदायित्व यदि बिलकुल नहीं तो मुख्यतः सरकार के पास कहना चाहिये कि अधिकारीवर्ग के ऊपर है। १९८५ ई० से

अर्थात् लार्ड रिपन के उदार शासन के अन्त से कांग्रेस शासन में बहुत आवश्यक सुधार कराने का प्रयत्न कर रही है। शासन की वर्तमान पद्धति और कोई पचास वर्ष की पुरानी है। अब बहुत दिन से वह पद्धति हमारे लिये अनुपयुक्त हो गई है। सरकारी अफसर भी यह मानने लगे हैं। पर यद्यपि सामान्य प्रकार से स्वीकार करते हैं कि परिवर्तनों की आवश्यकता है तथापि वह प्रत्येक प्रस्तावित परिवर्तन पर कुछ न कुछ आक्षेप अग्रथ करते हैं। इसका फल यह है कि इतने वर्षों बहुत प्रयत्न करने पर भी हम जग भी आगे नहीं बढ़ सके हैं और बहुत धैर्य न रखने वाले भारतीयों का व्यर्थ नष्ट गया है। कांग्रेस के पहिले दिनों में इस आशा के लिये स्थान था कि शासन में अभिलषित परिवर्तन कर दिये जायेंगे। लार्ड रिपन के बाद लार्ड एफगिन आये जो यद्यपि कुछ सशयालु थे, तथापि कांग्रेस के विरोधी न थे। उन्होंने ने सरकार की नोकियों की जाच करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उन के बाद लार्ड लैन्सडाउन आये जो, यद्यपि बहुत डरते २ पैर उठाते थे तथापि हमारे पक्ष से मैत्रीभाव रखते थे और उन्होंने ने व्यवस्थापक कोसिलों को आदि रूप में स्थापित किया। उन के बाद लार्ड एलगिन आये और उनके समय से सुधारक दल का भाग्य लगातार मन्द होता गया। उनके समय में भूग आया, अकाल पड़ा, सीमा प्रान्त में लडाइया हुई। शासन के अन्तिम समय में समाचार पत्रों की दबाने की नीति का भी अदलभूत हुआ। तत्पश्चात् लार्ड कर्ज़न आये। वह बड़ २ के चतृता देना खूब ही जानते थे और उनके शासन काल के पहिले दो वर्षों में बड़ी २ आशाएँ उत्पन्न हुई। पर उनकी अग्रतिशील कार्यवाहियों ने इन सब आशाओं को धूल में मिला दिया। उनके शासन के अन्तिम

तीन वर्ष में। बराबर हमारे चिढ़ाने और हमारा क्रोध भड़काने वाली बातें होती रही। इससे कांग्रेस का एक दल वे तरह तग आ गया और कहन लगा कि इंग्लैंड में हमारा ज़ा पुराना विश्वास था वह अब मिट गया। तब विपत्ति का प्याला लया लय भरने के लिये बंगविच्छेद की घटना घड़ी। इस आपत्ति को दूर रखने के लिये बंगाली लोग जो कुछ कर सकते थे सो उन्होंने किया। सारे प्रान्त में सैफर्टी सभाएँ हुई। सरकार पर प्रार्थनाओं और प्रतिवादों का मेह सा बरसने लगा। लोगों ने जो कुछ हो सकता था वह सब किया कि लार्ड कर्जन साहब अपना विचार छे ड डे। पर वह सारे आन्दोलन को जगहा की दृष्टि से देखने रहे। और बंगविच्छेद करने से बाज न आये। नरम कहलाने वालों ने बार २ सरकार को चिता दिया था कि जान मृपना कर रहे हैं। उन्होंने चिता दिया था कि यदि आप लोगों के प्रबल विरोध की कुछ भी परवा न करके जबरदस्ती बंगाल के दो टुकड़े कर देंगे तो सब लोगों की राजभक्ति को भारी प्रताप पहुचेगा और कुछ लोगों की राजभक्ति नष्ट हो जायगी। उनकी कड़ी हुई बातें ठीक निकलीं। माननीय मेम्बर साहब जब शिकायत करते हे कि बंगाल में खुलमखुला राजद्रोह का उपदेश दिया जा रहा है। पर जब समय था तब आपने “नरमों” की बात क्यों न मानी, जब शराबत हो चुकी तब मेम्बर साहब घूमकर हम पर हो उल्टा दोषारोपण करते हैं।

रही यह बात कि नरम लोग गमा की पूरी २ नित्या क्यों नहीं करते सो, महाशय, यह कोई आसान बात नहीं है। एक तो गमा के प्रति प्रसन्नता प्रकाश करने का वैसा अभाव नहीं है जैसा माननीय मेम्बर समझते हैं पर दूसरे इस प्रकार

निन्दा करना बहुत कुछ अपने २ मिजाज की वान है। माननीय
 मेम्बर के प्रश्न का उत्तर मैं एक दूसरा प्रश्न कर के ही देता हूँ।
 कुछ ऐंग्लो इन्डियन समाचारपत्र सदा भारतवासियों को
 गालियाँ सुनाया करते हैं। क्या माननीय मेम्बर ने उनके किसी
 लेख को कभी निन्दा की है? मुझे विश्वास है कि वह तथा
 और बहुत से लोग "सिविल और मिलिटरी गजट"-या इंग
 लिशमैन में प्रकाशित होने वाले विचारों को पसन्द नहीं
 करते पर क्या कभी कहीं किन्हीं दस पाँच अंग्रेजों ने मिल कर
 इन पत्रों की निन्दा की है। फिर हमारे लिये एक और कारण
 भी है। हम प्रचलित गडबड को और भी बढ़ाना नहीं चाहते।
 देश में काफी फूट फैली हुई है और जहाँ तक सम्भव हो हम
 फूट का एक नया कारण उत्पन्न करना नहीं चाहते। पर मैं
 यह कहना चाहता हूँ कि "नरम" लोग चाहे चुप रहें और
 चाहे "गरमी" की भरपूर निन्दा करें इससे गरमी का प्रभाव
 कुछ भी कम न होगा। असतोष के पर काटने का एक मान
 उपाय यह है कि सरकार दृढ़ता और साहस के साथ लोगों
 को प्रसन्न करने की नीति का अवलम्बन करे। श्रीमन्,
 इस प्रस्ताव पर सम्मति ली जाने के पहिले मैं कुछ शब्द
 कहना चाहता हूँ। अब सरकार दमनकारी अर्थों से सुस
 जित हो चुकी है। मैं नम्रता के साथ आप से प्रार्थना
 करता हूँ कि इन शक्तियों को सरक्षित रखिये जहाँ तक हो
 सके अभी इनका प्रयोग न कीजिये, और गंगाल को सन्तुष्ट
 कीजिये। सारी आपत्ति वही जड़ वही है। जब तक वंग
 रिज्लेट्ट के मामले में गंगाल सन्तुष्ट न होगा तब तक गंगाल
 में ही क्या मार भारत में कभी सच्ची शान्ति स्थापित नहीं
 हो सकती। इस मामले में गंगाल में जो कटुता उत्पन्न हो

गाई है उसने सारे देश के सार्वजनिक जीवन की सारी धारा को कलुषित कर दिया है। मैं स्वयं बंगाली नहीं हूँ और इस लिये बिना संकोच के आरंभित इस भय के कि कोई मेरे श्रम का अर्थ करेगा, मैं बोल सकता हूँ। सारे भारत में बंगालियों से बढ़ कर भावुक जाति और कोई नहीं है। वह रुपये पैसे की हानि को जल्दी भूल सकते हैं पर भावों का घोट पहुँचाने वाली बात को नहीं भूल सकते। मुझे इस समय इससे कुछ प्रयाजन नहीं है कि बंगविन्देद से क्या लाभ और क्या हानि होगी पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विषय हृदय के गहरे से गहरा भावों से सम्बन्ध रखता है। बंगाली समझते हैं कि हम पर नले कुचल दिये गये हैं और जब तक वह यह समझते हैं तब तक कोई शान्ति नहीं हो सकती। लोगों के मन सरकार से बहुत काफी फिर चुके हैं और स्थिति प्रतिदिन अधिकाधिक बुरी होती जाती है।

हाल के दिनों में हानि उठाने वाले लोगों ने मि० वेस्टन के सामने उपस्थित होने से इन्कार किया। इसने मालूम होता है कि बंगाल में क्या परिवर्तन हो रहा है। सरकार चाहती है कि दमननीति से परिवर्तन को दबा दें। मैं बङ्गालियों को जानता हूँ और भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ कि आप इन्हें कभी नहीं दबा सकते। कुछ बातों में तो बंगालियों से बढ़ कर कोई जाति भारत में नहीं है। उनके दोष बताना सहज है। वह तो स्पष्ट ही हैं पर उनमें बहुत से गुण हैं जो लोग कभी नहीं भूल जाते हैं। जीवन के जिन विभागों में भारतवासी प्रवेश कर सकते हैं प्रायः इन मंत्र में ही बंगालियों ने सब से ज्यादा नाम पड़ा किया है। हाल के कुछ सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और सामाजिक सुधारक बंगालियों में ही

उत्पन्न हुए हैं। हाल के कुछ सर्वश्रेष्ठ चक्ता, सम्पादक और गजनीनिष्ठ बंगाल में ही हैं। पर यहां में इन लोगों का जिक्र न करूंगा क्योंकि इस स्थान पर लोग जग टेट्ही नजरों से देखे जाते हैं। साहित्य, कानून या विज्ञान का ले लीजिये, सारे भारत में आपको डाकूर जगदीशचन्द्र घोस या प्रफुल्लचन्द्र राय सा विज्ञानवेत्ता कहा मिलेगा? डाकूर घोष सा कानून वेत्ता कहा मिलेगा रवीन्द्रनाथ ठाकुर सा कवि कहा मिलेगा? यह लोग आफस्मिक कारणों से नहीं उत्पन्न हुए हैं। यह जाति के सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं—मैं फिर कहता हूँ कि जिस जाति में ऐसे रत्न उत्पन्न हो सकते हैं वह ढलाई नहीं जा सकती। उनके जातीय चरित्र पर बहुधा यह लाञ्छन लगाया जाता है कि उनमें शारीरिक साहस नहीं है पर वह श्रम इस को दूर कर रहे हैं। इस कलङ्क की बात बंगालियों के मन में इतनी खुर गई है कि यदि हम कुछ एंग्लो इंडियन पत्रों में प्रकाशित होनेवाली कहानियों को सच मानें तो, शारीरिक सग्राम से दूर भागने की कौन कहे उनका मूल तो सग्रामों के लिये मानो उबला ही पड़ता है। यदि सरकार और बंगीय जनता का वर्तमान मनमुटाव बना रहेगा तो दस वर्ष के बाद हजार में एक बंगाली भी ऐसा न मिलेगा जो अङ्गरेजों से तनिक भी अनुराग रखता हो। सरकार के सामने एक भयंकर समस्या उपस्थित हो जायगी। बंगालियों की संख्या तीन करोड़ तीस लाख है। ऐसी जनता में कूट कूट कर असन्तोष भरने की मूर्खता और भय स्पष्ट है।

श्रीमन्, मैं आप से अगील करता हूँ कि आप समय रहते इस बात को ठीक कर दीजिये। मुसलमान शत्रु आशा करने लगे हैं कि बंगविच्छेद से हमें कुछ शिक्षा सम्बन्धी तथा दूसरे लाभ होंगे। इससे समस्या और भी जटिल हो गई है।

मैं यह मानता हूँ। भारत का कोई सच्चा हितैषी यह नहीं चाहता कि वह इनमें से किसी भी लाभ से वंचित किये जाय क्योंकि मुसलमानों की जितनी अधिक उन्नति हो देश के लिये उतना ही अच्छा है। पर ऐसी व्यवस्था करना राजबौशल की सामर्थ्य के मवधा बाहर नहीं है कि मुसलमान सब अपने क्षित लाभ उठाते रहें और बगालियों का महान कष्ट भी दूर कर दिया जाय। लोगों को प्रसन्न करने के मार्ग में प्रति पत्ति के सरकारी रोषदोष के जो विचार अब तक अडचन डालते रहे हैं वह शायद अब भी अडचन डालेंगे। पर मैं नहीं समझ सकता कि जिस सरकार के पास ऐसे विशाल साम्राज्य का बल है उसकी प्रतिपत्तिहमारी उत्लाई नीति का अवलम्बन करने से कैसे कम हो जायगी। श्रीमन्, आप चाहें तो इस मामले को ठीक कर सकने हैं। यदि आप बहुता ओर विद्वेष के इस महान कारण को देश में दूर कर दें तो बगाल ही नहीं किन्तु सारा भारत आपकी जय मनायेगा।

सुधार के प्रस्ताव ।

(दिसम्बर १९०८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास धाते अधिवेशन में माननीय मि० गोखले ने यह भाषण किया —)

श्रीयुत सभापति जी, महिलाओं और सज्जनों, मैं यह प्रस्ताव आप की स्वीकृति के लिये पेश करना हूँ ।

(क) "कांग्रेस एलन आस्टेवियन ह्यूम के पास यह सन्देश भेजे कि हम हृदय से आप का अभिनन्दन करते हैं और आप को बधाई देते हैं । लार्ड माले के उद्घोषित सुधारों से कांग्रेस का २३ वर्ष का प्रयत्न थाड़ा रहन सफल हो गया । आप कांग्रेस के जन्मदाता हैं । हमें यह सोच कर उठा हर्ष होता है कि आप को इनसे परम हार्दिक मनोप होगा ।

(ख) कांग्रेस सर विलियम वेडरबर्न को उनकी हाल की भयंकर बीमारी में मुक्त हो जाने की बधाई देती है । कांग्रेस इस अवसर पर उनके उस अथक उत्साह, भक्ति, प्रेम और एकाग्रता को भी स्वीकार और प्रकाश करती है जिससे उन्होंने बीस वर्ष कांग्रेस पक्ष के लिये काम किया है और बहुत करके जिसके कारण ही इंग्लैंड में कांग्रेस और सम्मनियों और निवेदनों पर इतना अनुग्रह पूर्ण विचार हुआ ।

(ग) ब्रिटिश कमिटी ने भारतीय राजनैतिक उन्नति के

लिये नि स्वार्थ सेवाभाव से जो तात्काल परिश्रम किया है उसके लिये कांग्रेस उसको कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देती है।

प्रतिवर्ष साधारण कांग्रेस समाप्त होने के बाद कांग्रेस ब्रिटिश के द्वारा हमारे लिये इंग्लैंड में किये हुए कार्य का कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करती है। पर इस वर्ष धन्यवाद के साधारण प्रस्ताव के अलावा हम दो और प्रस्ताव पास करने वाले हैं जिनमें से एक मि० ह्यूम को आर दूसरा सर विलियम वेडरबर्न को भेजा जायगा। कमिटी के विषय में मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। कमिटी ने गत वर्षों में जैसा उपयोगी कार्य किया था वैसा इस वर्ष भी किया है। यह सच है कि इस वर्ष उसे कुछ असुविधाओं के बीच काम करना पड़ा है। एक तो उसे हमारे समय के सर्वोत्तम भारतीय मज्जन, पूर्णतः नि स्वार्थ, पूर्णतः कलङ्क रहित, हमारे घयोवृद्ध परन्तु यौवन काल के ज्वलन्त उत्साह से सम्पन्न नेता, दादा भाई नवरोजी (हर्षध्वनि) की सहायता और व्यवस्था से वंचित होना पड़ा। दूसरे सर विलियम वेडरबर्न जो सदा से ब्रिटिश कमिटी के प्राण रहे हैं इस वर्ष भयंकर रोग के कारण कमिटी के कार्य की ओर स्वयं ऐसा ध्यान न दे सके जो गत वर्षों में दिया करते थे। उनके स्थान पर सर हेनरी फाटन ने सभापति का आसन ग्रहण किया तथा अन्य सदस्यों के साथ मिल कर सदा की तरह काम किया। अच्छा तो आज हमारा पहिला कर्तव्य ब्रिटिश कमिटी को धन्यवाद देना है कि उन्होंने इतनी प्रयत्न और सावधानी के साथ इङ्ग्लैंड में हमारे पक्ष का समर्थन किया। इसके बाद हम उन दो अंग्रेज सज्जनों की ओर ध्यान देते हैं जो इङ्ग्लैंड में हमारे सर्वोत्तम मित्र हैं। हमारे प्रस्ताव का पहिला भाग मि०

हम के सम्बन्ध में है। हम सब जानते हैं कि मि० ह्यूम कांग्रेस के जन्मदाता हैं (हर्षध्वनि।) हम सब जानते हैं कि प्रारम्भ में कैसे प्रेम के साथ, कैसी सावधानी के साथ उन्होंने इसकी व्यवहारी की थी। हम सब जानते हैं कि जब स्वास्थ विगट जाने से वह इस देश में रह कर कांग्रेस की उन्नति में भाग न ले सकते थे तब इङ्ग्लैण्ड में उन्होंने कांग्रेस-आन्दोलन के लिये कितना काम किया। इस आन्दोलन से आज तक उनका अनुराग वैसा ही बना हुआ है जैसा पहिले था। जब हमें उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और नेतृत्व की आवश्यकता हुई तब उन्होंने जपश्य हमें सलाह और नेतृत्व प्रदान किया। गत वर्षों के अवनतिशील काल में कांग्रेस आन्दोलन की ऊपरी असफलता का जितना रोह मि० ह्यूम को हुआ उतना और किसी को नहीं हुआ। जब गतवर्ष सूरत में कांग्रेस पर आपत्ति आई तब जितनी वेदना और चिन्ता मि० ह्यूम को हुई उतनी और किसी को नहीं हुई। मुझे व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव है कि जब गत मासों में लन्दन में इन सुधारों के सम्बन्ध में निन्ताजनक बातचीत हो रही थी, जब हमारे सामने कभी तो जाणा का उज्ज्वल प्रकाश होता था और कभी निराशा की घटा छा जाती थी तब सारी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में मि० ह्यूम को जितनी चिन्ता थी, जितना अनुराग था उतना और किसी का न था। अब जन्धकार दूर होता मालूम पड़ता है—आग भवीन प्रातः काल की उषा प्रगट हो रही है। इस समय कांग्रेस के जन्मदाता को जितनी प्रसन्नता होनी चाहिये उतनी और किसे होगी। मैं कहूँगा कि मि० ह्यूम को यह संदेश भेजने में हम केवल अपना वह कर्तव्य पालन कर रहे हैं जो पिता की ओर-पुत्र का है। मि० ह्यूम की अवस्था

८० वर्ष से अधिक है। हमें यह सोच कर परम हर्ष है कि वृद्धावस्था में उनको यह आश्वासन मिल सका। हम सब की हार्दिक आशा और अभिलाषा है कि यह बहुत दिन जीते रहे और इस नये मार्ग में जो उन्नति हम करना चाहते हैं उसको देखते रहें।

प्रस्ताव का तीसरा भाग सर विलियम वेष्टर्न के सम्बन्ध में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी ७६ वर्ष की अवस्था में सर विलियम भयकर रोग से पीड़ित हुये थे। ७६ वर्ष की अवस्था में भयकर रोग उठा ही भयकर होता है। परम डयालु ईश्वर ने हमारे लिये सर विलियम को अच्छा कर दिया। यह ठीक ही है कि इस अवसर पर हम आनन्द मनायें। मजबूत, जिन्होंने इंग्लैंड में हमारे लिये सर विलियम का कार्य देखा है वही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस अग्रेज महामा के हम किनने आभारी हैं। गत तीन वर्षों में इस कार्य के सम्बन्ध में तीन बार मैं इंगलंड गया था। मैं बराबर उनकी अत्यन्त घनिष्ट सहायता में और उनके प्रेम पूर्ण उपदेशानुसार कार्य करता था। मैं इस विषय में कुछ प्रामाणिक ढंग से बोलने का दावा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि सर विलियम ने हमारे लिये जैसा काम किया है वैसा किसी दूसरे अग्रेज ने कभी नहीं किया। माना कि कुछ महान् अग्रेजों ने, इंगलैंड के सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्ध स्थान रखने वाले अग्रेजों ने, हमारे पक्ष को सहाय्य दिया है, वाइट, फाकेट और वेडला के पूजनीय नामों को हम सदा प्रेम और श्रद्धा से स्मरण रखेंगे। पर उनका सारा ध्यान भारत की ओर नहीं था। उनको और विषयों से अनुराग था, वह और विषयों की ओर ध्यान देते थे, यह और काम करते थे। सर विलियम में यह

बात नहीं है। जब से वह लौटकर इंगलैंड गये हैं तब से एक मात्र भारत से ही उनका अनुराग रहा है, एक मात्र भारत के लिये ही उन्होंने काम किया है, एकमात्र भारत की सेवा का ही जोश उनके हृदय में रहा है। गत बीस वर्षों में परापर उन्होंने अपना सारा समय, अपनी सारी शक्ति, अपना बहुत सा धन भी निःसङ्कोच हमारे लिये लगा दिया है, (हर्ष ध्वनि।) हमारे लिये उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, विपत्ति का समय हो चाहे संपत्ति का, इस अग्रेज महात्मा ने सदा हमारा साथ दिया है। हमारे लिये ही वह पार्लामेंट के मेम्बर हुये। जब उन्होंने देखा कि वह अपने निर्वाचकों की सेवा के साथ हमारी सेवा नहीं कर सकते नव वह पार्लामेंट से अलग हो गये। हमारे लिये ही वह भारत में अपने वेश चन्नु अग्रेजों के बुरे बने। उन्होंने हमारे आनन्द में आनन्द मनाया है, हमारे शोक में शोक मनाया है। जब हमारे लिये चिन्ता का समय आता था तब उनका हृदय चिन्ता से भर जाता था। पर जब हम निराश हो जाते थे तब वह निराश नहीं होते थे। अब नवीन प्रातःकाल होने पर नये मित्र आकर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे पर रात्रि के अन्धकार में हमारी रंग बाली संर विलियम ने ही की थी। इस लिये मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन अवसर पर कांग्रेस संघ विलियम को अच्छी तरह धन्यवाद दे क्योंकि मुझे विश्वास है और जो लोग उनके कार्य से परिचित हैं उनका भी निस्सन्देह यह विश्वास होगा कि इंगलैंड में भारतीय पक्ष के आगे बढ़ाने में और आज उसका सानुग्रह विचार कराने में उनका बड़ा हाथ है।

प्रश्नाच के व्यक्तिगत अंश के बारे में इतना कहने के बाद, यदि आशुकी आशा है तो मैं प्रस्ताव के प्रथम भाग के एक वाक्य

के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मि० ह्यूम को जो सन्देशा हम भेज रहे हैं उसमें हमने यह वाक्य रखा है कि "लार्ड माले के उद्घोषित सुधारों से कांग्रेस का २३ वर्ष का प्रयत्न थोड़ा बहुत सफल हो गया"। मैं समझता हूँ कि इस स्थान पर मेरे लिये इस बात की परीक्षा करना अप्रासंगिक और अनुचित न होगा। इस वर्णन से पता चलेगा कि कांग्रेस के २३ साल के उद्योग कैसे कुछ थोड़े बहुत सफल कहे जा सकते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि पहिले तो आप कांग्रेस के २३ साल के उद्योगों का विचार करें और फिर उन सुधारों पर जो प्रकाशित किये गये हैं। इन सुधारों के साथ आप को उन बातों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि जो इनके पहिले निश्चित हो चुकी हैं, या जिनके अभी हाल ही में निश्चित होने की आशा है।

कांग्रेस के सम्बन्ध में सन्नेप से आप यह कह सकते हैं कि गत तेईस वर्षों में इसने तीन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये प्रयत्न किया है। पहिले उद्देश्य को हम सामाजिक कह सकते हैं। वह यह है कि कांग्रेस ने देश के भिन्न-२ वर्गों में अधिकाधिक ऐक्यता का भाव और सारे देश में अतिराष्ट्रिय राष्ट्रीयता का भाव फैलाने की चेष्टा की है। गतवर्ष की शान्तिजनक फुट के बाद भी कांग्रेस के मंच पर बड़ा हारर, वर्गों की भिन्नता का विचार करके मैं कह सकता हूँ कि दश में तेईस वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज ऐक्यता का भाव अधिक वास्तविक, अधिक गम्भीर और अधिक दृढ़ है। (हर्यध्वनि।) राष्ट्रीयता के भाव का भी वही हाल है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक नई उत्तेजना, नई भावना, नई लहर फैल रही है। प्रत्येक मनुष्य जिसे भारत की उन्नति से अनुराग है वह देख

कर प्रफुल्लित होगा कि देश में यह भाव सच्चा है, गर्भीर है, वास्तविक रूप में है। पर आज हमें कांग्रेस के इस कार्य पर विचार नहीं करना है। इसके अलावा दो अन्य उद्देश्य हमारे सामने थे जिनका सम्बन्ध इस बात से था कि हम सरकार पर कितना प्रभाव डालना चाहते थे। हमारा एक उद्देश्य सरकार का ध्यान सुधार के या कठिनता के निवारण के उपायों की ओर दिलाना था। इनका उल्लेख करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। पर हमारा दूसरा उद्देश्य जो हमारे बतलाये हुए सब उपायों का आधार था और जिस पर हम बराबर जोर देते आते हैं वह यह है कि अधिकारी तब शासन के लक्षणों में, जितना हो सके उतना, परिवर्तन किया जाय। कुछ अशों में तो कांग्रेस का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य यही है कि उसने इन लक्षणों में परिवर्तन कराने का बड़ा उद्योग किया। जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है, वहाँ तक यह कहना न्याय संगत है कि प्रस्तावित सुधारों से बहुत कुछ वाञ्छित परिवर्तन हो जायगा। यह प्रस्तावित सुधार क्या है ?

सब सुधारों पर एक साथ में एक दृष्टि डालना चाहता हूँ और तन्पश्चान् देखना चाहता हूँ कि हमारा दावा कहा तक न्यायसङ्गत है। इस प्रयोजन के लिये मैं चाहता हूँ कि आप भारत सचिव की कांसिल में दो भारतवासियों की नियुक्ति पर और डिसेन्ट्रलाइजेशन कमीशन (स्थानिक शासन के अधिकार सम्बन्धी कमीशन) की रिपोर्ट के फलस्वरूप होने वाले सुधारों का विचार भी प्रस्तावित सुधारों के साथ कर। तीनों बातें एक ही व्यवस्था का अङ्ग हैं, तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप हमारी गतवर्ष की राजनतिक स्थिति की तुलना सुधार के बाद होनेवाली स्थिति

से करें। आप चाहें तो शासनविभाग की तुलना एक भवन से कर सकते हैं। सड़ के नीचे ग्रामीण और नागरिक आत्मशासन है। बीच में साधारण शासन अर्थप्रबन्ध और व्यवस्थापना है। चोटी पर कार्यकारी कौन्सिल और भारतसचिव की कौन्सिल है जिनको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें शासन की नीति स्थिर की जाती है और महत्त्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार चोटी, मध्य और तले की कल्पना करके आप निश्चय करें कि गतवर्ष हम कहा थे और इन सुधारों के पूरे हो जाने के बाद कहा होंगे।

स्थानिक आत्मशासन के विषय में हम कह सकते हैं कि उसका बहुत थोड़ा अंश हमारे पास है। नाम को आत्मशासन है। मैं चार वर्ष तक एक म्युनिसिपैलिटी का प्रधान था, हम जानते हैं कि हमारे पास कितना आत्मशासन है, मैं जानता हूँ कि बहुत नहीं है। शासन के मध्यभाग की ओर देखिये। आज कल हम वर्ष में एक बार सरकारी बजट पर बहस करने समय अर्थ प्रबन्ध पर—आय-व्यय पर—अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और जब कोई नया कानून बनाया जाय तब उस पर विचार प्रकट कर सकते हैं। साधारण शासन के सम्बन्ध में हमारे पास अधिकारीवर्ग के सामने अपने विचार उपस्थित करने का कोई सुव्यवस्थित साधन नहीं है। रही कार्यकारी कौन्सिलों और भारतसचिव की कौन्सिल की बात, जो आज वहाँ तक किसी तरह भी हमारी पहुँच नहीं है। नई व्यवस्था के अनुसार हमारा क्या पद होगा ? पहिले तो अपने स्थानिक जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी के मामलों का पूरा प्रबन्ध और अधिकार हमारे हाथ में आ जावेगा। लार्ड रिपन ने भारतीय स्थानिक स्वराज के

जिस भवन की नींव डाली थी वह अच्छी तरह पूरा हो जायगा। यह बड़ी भारी बात है। बहुत से लोगों ने स्थानिक स्वराज्य की ओर ही परिभाषा की है कि यह जनता के लिये राजनैतिक शिक्षा का क्षेत्र है। वहाँ हम राजनैतिक शिक्षा के लिये जितना चाहें उनका ही क्षेत्र मिल सकता है। फिर शासन के मध्य भाग में तो स्थिति इतनी बदल जायगी कि माना राज्यकान्ति ही हो गई। इस समय, सब बातें निम्न श्रेणी के अफसरों से लेकर वाइसराय और भारत सचिव तक अधिकारीवर्ग की गुप्त लिखा पढ़ी के छाग ही तै होती हैं। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं होना तब तक हमको कुछ मालूम ही नहीं होना। यदि निर्णय हमारे प्रतिकूल या हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो हमको गोक प्रकाश करके चुप हो रहना पड़ता है, हम और कुछ नहीं कर सकते। नई व्यवस्था के अनुसार साधारण शासन-सम्बन्धी सब महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकारीवर्ग के सामने उत्तरदायित्व पूर्ण रीति से प्रान्तीय व्यवस्थापक कमिटी में उपस्थित किये जायेंगे। इन कमिटी में, बहुपक्ष गैरसरकारी सदस्यों का रहेगा। गैर सरकारी बहु-पक्ष को शासन सम्बन्धी प्रश्न उठाने का अधिकार दे देना अत्यन्त महत्व की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे शासन के अधिकारी तन्त्र के लक्षण में बड़ा अन्तर पड़ जायगा। फिर रुपये पैसे के मामले में हमारा अधिकार बढ़ जायगा। इन मामलों पर हमको पूरा अधिकार तो तब ही होगा जब प्रान्तों को अपने आर्थिक मामलों का प्रबन्ध आप ही करने का अधिकार मिल जायगा। पर इसका पता तो डिसेन्ट लाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार की आज्ञा प्रचारित होने पर लगेगा। तथापि यह आशा है और सर्वसा

[illegible]

संसार पौछे हटती जायगी, प्रान्तीय सरकार आगे अती जायगी और हमको प्रान्तीय शासन पर प्रभाव डालने के आवश्यकतानुसार अवसर मिलेंगे । कल लोग यह शिकायत कर रहे थे कि बड़ी व्यवस्थापक कौंसिल के सम्वन्ध में भारतसचिव की व्यवस्था भारतीय सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था से बुरी है और निर्वाचन की व्यवस्था से विशेष बंगा को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सिद्धान्त बहुत बढ़ जायगा । सज्जनों, मैं समझता हू कि इन दोनों बातों के सम्वन्ध में कांग्रेस से जाने के पहिले, आप अपने विचार सुस्पष्ट कर लें । (सुनो सुनो की ध्वनि ।) जहा तक बड़ी व्यवस्थापक कौंसिल का सम्वन्ध है, प्रस्तावित पद्धति पूरी व्यवस्था का एक भाग है । भारत सरकार का प्रस्ताव यह था कि बड़ी कौंसिल तथा सातों प्रान्तीय कौंसिलों में सदा सरकारी बहुपक्ष रहे । कलकत्ते में होने वाली बड़ी कौंसिल में सरकारी मेम्बरों को भिन्न २ प्रान्तों से बड़ा लम्बा रास्ता तै कर के आना पड़ता है । इस लिये सरकार ने प्रस्ताव किया था कि सरकारी बहुपक्ष वहा सदा उपस्थित न रहे किन्तु जब आवश्यकता पड़े तब बुला लिया जाय । व्यवहारिक दृष्टि से तो वहा सरकार का बहुपक्ष रहता ही । इसके अलावा प्रान्तीय कौंसिलों में भी रहता । भारत सचिव इन प्रस्तावों से बहुत आगे बढ़ गये हैं । इन सब कौंसिलों में सरकारी बहुपक्ष रखने के बजाय उन्होंने ने सातों प्रान्तीय कौंसिलों को उसमें मुक्त कर दिया है । यह तो मानी हुई बात है कि सरकार कहीं न कहीं अपने पास सर्वोच्च अधिकार रखेगी क्यों कि हमारी प्रगति की वर्तमान दशा में यह आशा करना बुद्धिमानी नहीं है कि वह शासन और व्यवस्थापन का नियंत्रण हमारे हाथों

में सौंप देगी। पर घड़ी कौंसिल में बहुपक्ष रखने से मत्र प्रान्तीय कौंसिलें सरकारी बहुपक्ष के बन्धनों से मुक्त हो गई हैं। भारत सरकार पीछे हटती जायगी और उसका बहुपक्ष बहुत करके सरक्षित शक्ति के समान है। इसलिये व्यवहार कुशल लोगों की तरह हमको सतुष्ट रहना चाहिये। हमें कृतज्ञता पूर्वक इस व्यवस्था को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करना चाहिये क्योंकि या तो हमें पूरी व्यवस्था स्वीकार करनी होगी या पूरी व्यवस्था रह करनी होगी।

अब रही निर्वाचकत्व और विशेष जातियों के पृथक् प्रतिनिधित्व की बात, सो भाई यह कहना तो बहुत अच्छा मालूम होता है कि हमारा आदर्श देश में पूर्ण एक्य स्थापित करना है, भिन्न २ वर्गों में पूर्ण एक्यता स्थापित करना है। अजी जीवन में हमारे और भी बहुत से आदर्श हैं। कुछ वर्गों के अनुयायी आदर्श जगत देखने की आशा करते हैं पर हमको वर्तमान परिस्थितियों का सामना करना है। आज त्रेष की जातियों में तीक्ष्ण भेदभाव विद्यमान है। इस लिये मेरी समझ में तो ऐसी व्यवस्था देश की एक्यता की वृद्धि ही करेगी, जिसके अनुसार महान विशेष वर्गों को प्रतिनिधित्वसंस्थाओं में अपने ही विश्वासपात्र जन चुन कर भेजने का प्रयत्न हो। इससे आपस में उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या द्वेष के भाव मिट जायगे। बहुत से मुसलमान सज्जन मेरे बड़े मित्र हैं। मुसलमान जाति के विषय में मैं कह सकता हूँ कि जब व्यवस्था का प्रवृत्त व्यवहार होगा और वह अपने ही निर्वाचित, अपने विश्वासपात्र सज्जनों को कौंसिल में भेज देंगे तब उनका यह अन्याय पूर्ण आर्शका मिट जायगी कि हिन्दुओं के सामने हमारा कुछ भी न चलेगी तब उनको इस महान राष्ट्रीय कार्य

में सम्मिलित होने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा (हर्ष ध्वनि ।)
 सज्जनो मैंने इन थोड़े से शब्दों में यह बतलाया कि वर्तमान
 स्थिति क्या है और नई व्यवस्था के कार्य में परिणत होने पर
 हमारी क्या स्थिति होगी । अब मैं अपनी वक्तृता की अन्तिम
 बात कहना चाहता हूँ ।

एक वाक्य में परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार किया
 जा सकता है । अब तक हम चाहर से आन्दोलन करते
 रहे हैं, अब से हम उत्तरदायित्व पूर्ण रीति से शासन
 के कार्य में सम्मिलित किये जायेंगे । इस का अर्थ शासन का
 नियंत्रण करना नहीं है, पर तो भी शासन के कार्य में सम्मि-
 लित होना है—उत्तरदायित्व पूर्ण रीति से सम्मिलित होना
 है । यहाँ घुड़ के लिये बहुत स्थान है । ज्यों २ हम उन्नति
 करने जायेंगे और अपने कर्त्तव्य को यथोचित रीति से पालन
 करने जायेंगे त्यों २ हम उत्तरदायी शासन पद्धति के 'गादर्श'
 के पास पहुँचते जायेंगे । कोरे आन्दोलन से हम शासन में
 उत्तरदायित्व पूर्ण भाग लेने की अवस्था तक पहुँच गये ।
 इस अवस्था से हम किसी न किसी दिन उत्तरदायी शासन
 प्राप्ति की अवस्था तक अवश्य ही पहुँचेंगे (हर्षध्वनि ।)
 अच्छा, सरकार ने जो महान् और उदार स्वत्व हमको दिये
 हैं उनका हमें यथायोग्य अभिवादन करना चाहिये । विशेष
 कर हमारे दो कर्त्तव्य हैं, एक तो यह कि सरकार के कोरे
 छिटान्वेषण के स्थान पर हमारे हृदय में सरकार के
 साथ सहकारिता का भाव उत्पन्न होना चाहिये । यदि
 हम सरकार का निरन्तर विरोध करेंगे तो नई व्यवस्था
 का उद्देश्य कभी पूरा न होगा और वह बिलकुल व्यर्थ

प्रमाणित होगी। इस लिए हमारे ऊपर पहिला कर्तव्य भाग यह है कि हम अपने हृदय में सरकार की सहकारिता करने के भाव को स्थान दें। दूसरा कर्तव्य यह है कि हम अपनी नई शक्तियों का प्रयोग समय और नम्रतापूर्वक करें और उनका प्रयोग जनसमूह के हितसाधन के एक मात्र उद्देश्य से करें (सुनो, सुनो की ध्वनि ।) बहुत से प्रश्न हैं जिनका निपटारा करना आवश्यक है पर इस समय सरकारी अपसरा को उनका यथोचित विचार करने के लिए समय नहीं मिलता। जनसमूह की शिक्षा का प्रश्न है, सफाई का प्रश्न है, रूपरङ्ग के ऋण का प्रश्न है, शिलपीय शिक्षा का प्रश्न है, इसी तरह और भी प्रश्न हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है पर जब सरकार को कौंसिल की सहायता मिल सकेगी तब और भी अधिक काम हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि इन मन्त्र दिशाओं में भूतकाल की अपेक्षा भविष्य में बहुत ज्यादा काम होगा। इस लिये हमें अपनी नई शक्तियों का प्रयोग समय और नम्रता के साथ एक मात्र जनसमूह के हितार्थ करना होगा। यदि ऐसा होवे तो फिर भविष्य के विषय में मुझे कोई आशंका नहीं है। सज्जनों, मेरे कुछ मित्र इस विषय में बहुत कुछ कर रहे हैं कि कौंसिल के फागून और प्रस्तावों को मानने न मानने का अन्तिम अधिवेशन सरकार ने अपने ही हाथ में रक्खा है। पर हमें इस सम्यन्ध में बहुत कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार पर आक्षेप करना अथवा यह आशा करना कि सरकार इस अधिकार को जल्द ही छोड़ देगी, वैध शासन प्रणाली समझन में अपनी असमर्थता दिखलाता है। इस समय लन्दन पार्लामेंट के होस आफ कामन्स के ऊपर भी इस प्रकार के दो

अधिकार हैं, एक तो हौस आफ लार्डस का वास्तविक अधिकार और दूसरा राजराजेश्वर का नाम मात्र का अधिकार। अंग्रेज लोग आत्मशासित जाति हैं पर तो भी वह इन अधिकारों की अनुविधा को सहन करते हैं। पहिले हमें अपने को नये अवसरों के सर्वथा योग्य बनाना चाहिये, तब सरकार के इस अधिकार को कम करने की बातचीत का अवसर बहुत मिलेगा।

यस, एक बात कहने में बैठ जाना चाहता हूँ। हम अधिकांश भारतवासी—हिन्दू, मुसलमान और पारसी कुछ कटपनाशील मनुष्य हैं—दूर २ के स्वप्न बहुत वेग्या करते हैं। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि हिन्दू इस बात में सब से बढ कर हैं। मैं मानता हूँ कि यदि स्वप्नों से और कुछ नहीं होता तो कभी २ आनन्द तो होता ही है। भविष्य के लिए आदर्श और आकांक्षाएँ बनाने में स्वप्नों की महिमा को भी मैं मानता हूँ पर व्यवहारिक मामलों में हमको व्यवहार कुशल मनुष्यों की भाँति व्यवहार करना चाहिये और दो बातें याद रखनी चाहिये। जीवन यात्रा सर्वथा स्पष्ट कोरी पट्टी पर लिखना नहीं है। पट्टी पर पहिले ही से बहुत से शब्द लिखे हुए हैं। हम कुछ अन्य ऐसे शब्द जोड़ते हैं कि सार्थक घान्य बन जाय। दूसरी बात यह है कि आप चाहें जो कुछ माँगे पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको वह चीज मिल जायगी, अथवा यह कि आप उसके योग्य हैं और प्राप्त होने पर आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिये हमें उचित है कि कोरे स्वप्नों के पीछे न पड़ें और वर्तमान अवकाशों की उपेक्षा न करें। देश का भविष्य इसपर निर्भर है कि हम लोग ओर विशेष करके हमारे नवयुवक माँदें, अपने को

नये अवसरों के लिये पूर्णतः उपयुक्त किस प्रकार सिद्ध करते हैं। वर्तमान स्थिति से कोई भी सतुष्ट नहीं रहना चाहता। पर अन्य उत्तरदायी अधिकार मागने के पहिले हमें यह प्रमाणित करना चाहिये कि हम वर्तमान वर्तव्यों को अच्छी तरह पालन कर सकते हैं। मैं अनेक बार कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देशवासियों की वृद्धि में किसी प्रकार की कोई रुकावट होवे। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के सब स्त्री पुरुष अन्य देशों के स्त्री पुरुषों की तरह, सब तरह की पूर्ण उन्नति करें। पर हमारी उन्नति कर्तव्यपालन के द्वारा ही हो सकती है। नये अधिकारों की धान सोचने के पहिले हमें अपने वर्तमान वर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करना चाहिये। महिलाओं और मजदूरों, आपने जिस ध्यान से मेरी वक्तृता सुनी है और जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया है उसके लिये मैं आप सब से हादिब धन्यवाद देता हूँ।

भारतवासी और सरकारी नौकरियाँ ।

— २०१२ —

१७ मार्च सन् १९११ ई० को माननीय मि० सूगाराय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश किया था कि सरकारी शासक और गैर सरकारी सदस्यों का एक कमीशन इस उद्देश्य से नियुक्त किया जाय कि वह भारतवासियों के उन मतालम्बों पर विचार करे जो वे देश के शासन विभाग में उच्चपद और अधिकार पाने के विषय में पेश करते हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में मि० गोमले ने निम्न लिखित घक्तृता दी —

सभापति महोदय ! मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके विषय में कुछ कहने के पहले मैं माननीय मि० सूगाराय को उस परिश्रम और योग्यता के लिए अनेकशः अभ्यवाद् देता हूँ जो उन्होंने इस प्रस्ताव के तैयार करने और पेश करने में खर्च की है। जि सन्देह यह प्रश्न बड़े महत्व का है, और महत्व के दूसरे प्रश्नों की भाँति इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए यथासम्भव न्याय ने काम लूँ क्योंकि इसके दो भाग हैं। यद्यपि मेरी यह मुख्य कामना है कि मेरे देशवासियों की अभिलाषाएँ गवर्नरमेंट की ओर से उचित और सच्चे मान की दृष्टि से देखी जायें तथापि मैं यथासम्भव उन कठिनाइयों

की अपहेलना नहीं करना चाहता जो इस प्रश्न को हल करने के मार्ग में गवर्नमेन्ट के लिए बाधक हैं ।

इस देश में विलायती शासन जिन सिद्धान्तों पर अवलम्बित है उनमें से एक यह है कि शासन की नीति हमेशा उन्नति पक्ष की ओर ले जाने वाली रहे, मैं समझता हूँ कि सभी बुद्धिमान चाहे वह किसी जाति के क्यों न हों, इन सिद्धान्त का समर्थन करेंगे । मैं इस बात की जाँच के लिए चार बातें पेश करता हूँ कि यहाँ का शासन उन्नति का सहायक और उन्नति की ओर ले जाने वाला है या नहीं । पहली बात ध्यान देने योग्य यह है कि वर्तमान सरकार देश के सर्वसाधारण निवासियों की सभ्यता शिक्षा और आर्थिक उन्नति तथा उनकी भलाई के लिए किन किन उपायों का उपयोग करती है इस में मैं उन उपायों और साधनों को नहीं गिना, जिनका ब्रिटिश सरकार ने इस देश में उपयोग किया है क्योंकि वे साधन तो ऐसे थे जो स्वयम् राज्य की दृढ़ता के लिए अनिवार्य थे, यद्यपि इनसे प्रजा का भी लाभ अवश्य पहुँचा । उदाहरण के लिए, रेलवे का बनाना, डाक और तार का प्रचार करना, तथा जीर भी ऐसी अनेक चीजें हैं । शिक्षा के साधन और उन्नति के उपायों से मेरा तात्पर्य यह है कि राज्य की ओर से प्रजा की शिक्षा, आराम्यता, कृषि की उन्नति और उद्योग शिक्षा आदि के प्रचार के लिए क्या किया जाता है । यह मेरे मियाल में पहली कसौटी है । दूसरी बात जाचने के योग्य यह है कि सरकार हमको राज्य के प्रान्तिक मामलों में भाग और अधिकार देने की क्या व्यवस्था कर रही है ? मेरा तात्पर्य लाकल और डिस्ट्रिक्टोर्ड से है । तीसरी बात यह है कि

सरकारी कौमिलों में जहा सरकारी नीति का निर्माण होता है और उस पर विचार किया जाता है, गवर्नमेन्ट हमको किस कदम भाग देने के लिए तैयार है। और अन्त में यह भी विचारणीय है कि सरकारी उच्च पदों पर भारतवासी कहाँ तक नियुक्त किये जाते हैं ?

पहली बात के विषय में यह अनुमान किया जाता है कि सरकार इस सम्बन्ध में आगे पग बढ़ानेवाली है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को मिलकर सच्चे दिल से कोशिश करना चाहिये। दूसरी बात के विषय में मैं विश्वास करता हूँ कि "डोसेन्ट्रीलायजेशन" कमीशन की सिफारशों के अनुसार शीघ्र ही उन्नति होगी। आरम्भ तो आशाप्रद है यदि कुछ और उन्नति हुई तो हमें कुछ दिनों के लिए सतप करना पड़ेगा। यही व्यवस्थापक सभा तथा ग्राम्नीय छाती कौंसिलों में जो सुधार हाल में हुए हैं वे भी उन्नति के साधन कहे जा सकते हैं और यह प्रश्न भी कुछ दिन न उड़ेगा। परन्तु जब हम अन्तिम प्रश्न पर आते हैं तो हमको यह अनुभव होता है कि मामलात में सुधार करने के लिए अवश्य कुछ होना चाहिये, और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही कुछ न कुछ किया जायगा।

महाशयो! मैं कह चुका हूँ कि गवर्नमेन्ट को बराबर उन्नति पर लक्ष्य रखना चाहिये। और इन में से किसी मामले में भी गवर्नमेन्ट जिस स्थान पर अनिकाठ से ठहरी हुई है बराबर खड़ी नहीं रह सकती। भारतवासियों के उच्च पदों पर नियुक्त होने की प्राप्ति में उन बातों का कुछ ध्यान किया चाहता हूँ जिनका उल्लेख मेरे माननीय मित्र मि० मूवागाव ने अभी किया है—अर्थात् अंग्रेजी शासन के जमाने में इस यात्रा की चार या

पांच मजिलें तै हुई हैं। पहली मजिल उह थी जब स १८३३ ई० में पार्लामेन्ट ने स्पष्टत यह निश्चय किया था कि इस देश में सरकारी पदों की नियुक्ति के विषय में किसी प्रकार के धार्मिक या जातीय पक्षपात का व्यवहार न किया जायगा। अंग्रेज जानि ने यह उदारता पूर्ण वादा स्वयम् ही किया था उस समय इस विषय में यहां वालों ने कोई आन्दोलन नहीं किया था। वास्तव में यहां उस समय तक पाश्चाय शिक्षा का प्रचार भी नहीं हुआ था। यह एक बड़ा कौल फगर था जो अपने आप ही प्रसन्नता पूर्वक किया गया था। दूसरी मजिल वह थी, जब १८५३ ई० में सिविलसर्विस की परीक्षा का द्वार युरोपियन की भांति भारतवासियों के लिए भी मुक्त कर दिया गया। पुगनी शिक्षा पद्धति रह की गई नई परीक्षाएं स्थापित की गई और उनका द्वार सब के लिए एकसा खोल दिया गया। आगे चलकर मरकामुअजमा की १८७८ वाली राज-घोषणा तीसरी मजिल थी।

उस वक्त तक भी प्रजा में इसके लिये कोई असतोप नहीं फैला था, कारण यह था कि तब तक यूनीवर्सिटियां कायम न हुई थीं, शिक्षित लोगों का सरया बहुत कम थी। स १८६१ में भारत मंत्री ने वह कमेटी नियत की, जिसका उद्देश्य मेरे माननीय मित्र ने किया है, और यह भी अंग्रेज जाति की ही ईमानदारी थी अन्यथा भागतीयों की ओर से इस कमेटी की नियुक्ति के लिये भी कोई आन्दोलन नहीं किया गया था। फिर जब १८७० वाला एक्ट पास किया गया, जो इस मामले की चौथी मजिल थी तब इस विषय पर सर्वसाधारण राय जनी करने लगे थे, और कुछ भारतीय विशेषत मिस्टर दादा भाई

नॉरोजी भारतवासियों को उच्च पद दिये जाने के लिये इङ्ग्लैण्ड में आन्दोलन कर रहे थे। परन्तु उस मीके पर भी उस काम का अधिकांश अप्रेजों ही के हाथ में हुआ अर्थात् उन योग्य अप्रेजों के हाथ से जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं के विषय में यह अनुभव करने लगे थे कि भारतवासियों के लिए वर्तमान प्रचलित न्याय-विरुद्ध है। परन्तु जब सन् १८८६ में "पब्लिक सविसेज कमीशन" नियत हुआ जो इस मामले की पाँचवीं मजिल रूही जा सकती है। तो मामला की दशा चिरकुल बदल गई, उस वक्त शिक्षित जनता का एक अच्छा समूह तैयार हो चुका था और यह समूह इस बात का भली भाँति अनुभव कर रहा था कि उसको सरकारी उच्च पदों से वृत्त रखा जाता है। कमीशन के नियत किये जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह उन सुधारों पर विचार करे जिनसे भारतवासी अधिक सज्ज्या में उच्चपदों पर प्रतिष्ठित हो सकें। परन्तु कमीशन के प्रयत्नों का परिणाम उलटा हुआ और उसने हमारे साहस में बाधा डाली।

महोदय ! इस प्रश्न की दशा बड़ी मनोरंजक है। कितने समय में हमने एक मजिल ली थी, १८३३ से १८५४ या १८५८ तक, काई ले लीजिये कम से कम २० २५ वर्ष का समय लगा, १८५८ से १८७० तक १४ वर्ष हुए, १८८६ में जब इस प्रश्न की फिर जाँच पड़ताल की गई तो १६ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस वक्त से फिर गत २५ वर्षों में काई जांच पड़ताल इस मामले में नहीं हुई, एक यह भी कारण है, जिसके सहारे मैं कहता हूँ कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जावे। यह ठीक बात है कि गत ३—४ वर्षों में कई प्रधान उच्च पदों पर कुछ भारतवासी नियुक्त किये गये हैं, मेरे मित्र मि० अली इमाम

कानून के परामर्शदाता हैं, दो माननीय सज्जन भारत मंत्री की कौंसिल में भी शामिल किये गये हैं। एक हिन्दुस्तानी हाल ही में, कलकत्ता हाईकोर्ट के एटवोकेट जनरल थे, और भिन्न भिन्न भारतीय हाईकोर्टों के अस्थायी चीफ जस्टिस भी रहे हैं। इन उच्च पदों पर भारतवासियों का नियुक्त किया जाना निमन्त्रेह मेरे देशवासियों ने पसन्द किया है और साधारण प्रजा पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। परन्तु हमारी शिकायत तो हिन्दुस्तानियों को अधिक सल्लाह में उच्च पदों पर नियुक्त करने की है। इन मुख्य मुख्य थोड़े से पदों पर हिन्दुस्तानियों के नियुक्त होने से हमारी शिकायत दूर नहीं होगी। और जहां तक इस शिकायत का सम्बन्ध है, एब्लिक सर्विनेज कमीशन की सिफारशों से काय रूप में बहुत कम लाभ और थाड़ा सा सुाग हुआ है उक्त कुछ विभागों में तो उल्टी हानि हुई है। मेरे माननीय मित्र मि० स्यामाय ने यह दिग्याया है कि सिविलसर्विस के सम्बन्ध में नौ कमीशन की सिफारशों और भारतमंत्री की आज्ञाओं ने, १८७८-८० की सर्विस के नियमों की व्यवस्था के मुकाबिले में भी हमें और पीछे हटा दिया है।

१८७६-८० के नियमों के अनुकूल सारे देश के सिविल सर्विस के पदाधिकारियों में से ३ भाग हमको मिलना चाहिये। यदि उनकी संख्या १००० रक्खी जावे तो थोड़ी बहुत कमी वेशी की परवा नहीं पर कम से कम १६० जगहें हमें अग्रथ्य मिलना चाहियें। परन्तु कमीशन ने १६० के बजाय सिर्फ १०८ नियत कीं, और भारत मंत्री ने उनमें भी काट छांट करके ६३ ही पदों के देने का निश्चय किया। यही सन्या हमारे भाग में आई। फिर यह कुल ६३ जगहें भी अभी हमारे

नौरोजी भारतवासियों को उच्च पद दिये जाने के लिये इङ्ग्लैण्ड में आन्दोलन कर रहे थे। परन्तु उस मौके पर भी उस काम का अधिकांश अग्रेजों ही के हाथ से हुआ अर्थात् उन योग्य अग्रेजों के हाथ से जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं के विषय में यह अनुभव करने लगे थे कि भारतवासियों के लिए वर्तमान प्रबन्ध न्याय-विरुद्ध है। परन्तु जब सन् १८८६ में "पब्लिक सचिसेज कमीशन" नियत हुआ जो इस मामले की पाँचवीं मजिल कही जा सकती है। ता मामला की दशा धिक्कुन बदल गई, उस वक्त शिक्षित जनता का एक अच्छा समूह तैयार हो चुका था और यह समूह इस बात का भली भाँति अनुभव कर रहा था कि उसको सरकारी उच्च पदों से वृत्त रखा जाता है। कमीशन के नियत किये जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह उन सुझावों पर विचार करे जिनसे भारतवासी अधिक सरकारी उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो सकें। परन्तु कमीशन के प्रयत्नों का परिणाम उल्टा हुआ और उसने हमारे साहस में बाधा डाली।

महोदय ! इस प्रश्न की दशा बड़ी मनोरंजक है। कितने समय में हमने एक मजिल ले की, १८३३ से १८५४ या १८५८ तक, काई ले लीजिये कम से कम २०-२५ वर्ष का समय लगा, १८५८ से १८७० तक १४ वर्ष हुए, १८८६ में जब इस प्रश्न की फिर जाँच पड़ताल की गई ता १६ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस वक्त से फिर गत २५ वर्षों में काई जाँच पड़ताल इस मामले में नहीं हुई, एक यह भी कारण है, जिसके सहारे मैं कहता हूँ कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जावे। यह ठीक बात है कि गत ३-४ वर्षों में कई प्रधान उच्च पदों पर कुछ भारतवासी नियुक्त किये गये हैं, मेरे मित्र मि० अली इमाम

कानून के परामर्शदाता हैं, दो माननीय सज्जन भारत-
मन्त्री की कौंसिल में भी शामिल किये गये हैं। एक हिन्दु-
स्तानी हाल ही में, कलकत्ता हाईकोर्ट के एटवोकेट जनरल थे,
और भिन्न भिन्न भारतीय हाईकोर्टों के अस्थायी चीफ जस्टिस
भी रहे हैं। इन उच्च पदों पर भारतवानियों का नियुक्त किया
जाना निःसन्देह मेरे देशवासियों ने पसन्द किया है और
साधारण प्रजा पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। परन्तु हमारी
शिकायत तो हिन्दुस्तानियों की अधिक सख्या में उच्च पदों
पर नियुक्त करने की है। इन मुख्य मुख्य थोड़े से पदों पर
हिन्दुस्तानियों के नियुक्त होने से हमारी शिकायत दूर नहीं
हागी। और जहाँ तक इस शिकायत का सम्बन्ध है, पब्लिक
सर्विसेज कमीशन की सिफारशों से कार्य रूप में बहुत कम
लाभ और थाड़ा ना सु गार हुआ है उरिह कुछ विभागों में
तो उलटी हानि हुई है। मेरे माननीय मित्र मि० सुधागन्ध ने
यह दिखाया है कि सिविलसर्विस के सम्बन्ध में तो कमी-
शन की सिफारशों और भारतमन्त्री की आज्ञाओं ने, १८७६ ई०
की सर्विस के नियमों की व्यवस्था के मुकाबिले में भी हमें
और पीछे हटा दिया है।

१८७६ ई० के नियमों के अनुकूल सारे देश के सिविल
सर्विस के पदाधिकारियों में से १ भाग हमको मिलना
चाहिये। यदि उनकी सख्या १००० रक्खी जावे तो थोड़ी बहुत
कमी वेशी की परवा नहीं पर कम से कम १६० जगहें हमें
अग्रण्य मिलना चाहिये। परन्तु कमीशन ने १६० के बजाय
सिर्फ १०८ नियत कां, और भारत मन्त्री ने उनमें भी काट उँट
करके ६३ ही पदों के देने का निश्चय किया। यही सख्या
हमारे भाग में आई। फिर यह कुल ६३ जगहें भी अभी हमारे

अधिकार में नहीं है, मेरे मयाल से इस मस्य्या में जिसका श्रीमान् भारतमत्री ने वादा किया था अभी लगभग दस की कमी है। ब्रह्मा और आसाम के लिये जे वाद में बढ़ाये गये हैं मैंने उनकी गणना नहीं की है। श्रीमान् भारत मत्री ने इस विषय में १८९०-९१ में आक्षापें प्रकाशित की थी, इसको २० साल का समय हुआ। यदि और किसी आधार पर, नहीं तो मैं केवल इस कारण से, कि कमीशन को नियुक्त हुए २५ साल हो गये और उसकी सिफारशों पर भारत मत्री को आज्ञा प्रकाशित किये २० साल हुए हैं, प्रार्थना यह है कि इस मामले की फिर से छानबीन होना चाहिये। मेरा कथन है कि पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सिफारशों के कारण कई विभागों में भारतवासियों की दशा और खराब हो गई उसे ठीक करना चाहिये। श्रीमान्, प्रथम तो पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने यह सिफारिश की कि सरकारी नौकरी के विभागों को दो भागों में विभाजित करना चाहिये अर्थात् इम्पीरियल और प्रान्तिक। यह सिफारिश शोचनीय है मैं विश्वास करता हूँ कि पब्लिक सर्विसेज-कमीशन के सभापति अर्थात् तत्कालीन पञ्जाब के छोटे लार्ड जो एक उदार शासक थे वे हिन्दुस्तानियों को पीछे नहीं रखना चाहते थे परन्तु परिणाम यही हुआ कि हिन्दुस्तानी पीछे रहे। इस के दो कारण हैं एक तो प्रान्तिक सर्विस के शासकों की हेमियत, हीन दृष्टि से देखी जाती है। जो उन्हें अवश्य ही बुग लगता है फिर यदि आपने इम्पीरियल और प्रान्तिक सर्विस के लोगों में यह भेद भाव रक्खा तो वे योग्य व्यक्ति जो कई इम्पीरियल सर्विसवाले शासकों से भी अधिक अनुभवी और चतुर हैं, बराबर यह अनुभव करते रहेंगे कि उनके साथ अन्याय किया जाता है अनपेक्ष

में अनुरोध पूर्वक राय देता हूँ कि इस इम्पीरियल और प्रान्तिक भेद का अस्तित्व मिटा देना चाहिये ।

मैं आशा करता हूँ कि यह अन्तर न रहेगा और यदि रहा तो चारदार इम मामले को कासिल में उठाना पड़ेगा । दो विभागों में तो इस अन्तर ने बहुत ही हानि पहुँचाई है । शिक्षा विभाग और तामीर के मोहकमे में इससे बहुत क्षति हुई है । हाँ कुछ दूसरे विभागों में प्रान्तिक सर्विस के कायम हो जाने से भाग्यवांसियों को कुछ लाभ हुआ है । पर्योँ कि इन विभागों में पहले भारतवासी लिये हो न जाते थे अब प्रान्तिक सर्विस कायम होने से उन्हें अक्सर मिलने की आशा हुई है परन्तु तामीर और शिक्षा विभाग में हमें बहुत नुकसान पहुँचा है । उदाहरण के लिए प्रान्तिक सर्विस कायम होने के पहले शिक्षा विभाग में भाग्यवासी और अगरेजों को समान पद मिलते थे । निम्नन्देह उनका वेतन अगरेजों के वेतन का $\frac{1}{2}$ होता था परन्तु जीग सब बातों में समान थे । अब इनको केवल मातृहती का स्थान दिया जाता है और चारों ओर ऐसे अन्याय के उदाहरण मिलने हैं जिनसे हर शास्त्र के दिल पर चोट लगती है । हम देखते हैं कि कुछ योग्य पुरुष प्रान्तिक सर्विस में केवल इम कारण से रक्खे गये हैं कि वे हिन्दुस्तानी हैं और वह शास्त्र जो कलही कालेजों से अलग हुए हैं, जिन्होंने कोई अच्छा काम करके प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की है, केवल इस कारण से इम्पीरियल सर्विस में हैं कि वे युरोपियन हैं । मैं केवल एक उदाहरण पर सतोष करूँगा, कलकत्ते के एक महा शय डा बी सी राय विज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित हैं । फ्रान्स और जर्मनी के नामी विद्वान भी उनका मान करते हैं, उनके विद्यार्थी उन्हें हृदय से भी अधिक चाहते हैं । विज्ञान के केमिस्ट्री

विभाग में आज २० साल से वे नई नई खोजें और आविष्कार कर रहे हैं। परन्तु वे भी प्रान्तिक सर्विस में ही हैं और कल के लड़के जो अभी कालेजों से निकले हैं जिन्होंने कोई कर्तूत करके नहीं दिखाई, जो वास्तव में उनकी उगाड़ी नहीं कर सकते, वे इस देश में लाकर उनके अफसर बनाये जाने हैं।

केवल इस कारण से कि वे प्रान्तिक सर्विस में हैं और यह विलायत ही से इम्पीरियल सर्विस के मेम्बर बना कर लाये गये हैं। श्रीमन्, इस तरह की बातें केवल उन्हीं का दिल नहीं दुखातीं जो इस अन्याय के शिकार होते हैं वलिकुल उन्का प्रभाव उन विद्यार्थियों पर भी पड़ता है जो उनसे शिक्षा पाते हैं, और विभागों में जो अन्याय भारतीयों पर किया जाता है उसका प्रभाव एक सीमा तक परिमित रहता है परन्तु शिक्षा विभाग में यह प्रभाव विद्यार्थियों तक पहुँचता है। अध्यापकों से चल कर यह जहर विद्यार्थियों में फैलता है और उनमें असतोष और घृणा के चिन्ता उत्पन्न करता है।

अब तामील के मोहरूम-पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को लीजिये। एक जमाना था, जब भारतीय इजिनीयर यूरोपियन के समान ही पद और अधिकार पाते थे यदिक वेतन भी बराबर ही मिलता था। स० १८६२ में पहली बार वेतन में अन्तर किया गया अर्थात् भारतीय इजिनीयर का वेतन यूरोपियन इजिनीयर की अपेक्षा $\frac{३}{४}$ रक्का गया। अब नई योजना के अनुसार प्रान्तिक इजिनीयर का पद भी घटा दिया गया है क्योंकि उनकी फेहरेस्न पृथक् तैयार की गई है। पहले तो हम इस विभाग में अगरेजों के मिलकुल समान थे, बाद को वेतन $\frac{३}{४}$ कर दिया गया, और बातों में समानता रफ्तगी गई। अन्त में यह तै हुआ कि यह समानता भी न

रकरी जाय । अतएव अलग फेहरिस्त बनाई गई और यह सुलूक केवल नये आदमियों के साथ ही नहीं हुआ बल्कि अत्यन्त विवादास्पद और अन्याययुक्त प्रयत्न इस बात के लिए किया गया है कि उन लोगों के साथ भी जो १८६२ में नाकर हुए थे, यही सुलूक किया जाय । लगभग १०० कर्म चारी ऐसे हैं जो इस अन्याय के शिकार हुए हैं । १८६० में सरकार ने इन लोगों के साथ निश्चय वादा किया था कि इनके नाम भी उसी फेहरिस्त में रहेंगे जिसमें इम्पीरियल इजिनीयरों के । इसके होते हुए भी अब इनके नाम पृथक् किये जाने की कोशिश की जा रही है यह दुःख की बात है । इन लोगों ने अभी इस सरकारी प्रबन्ध को स्वीकार नहीं किया है, और शिकायत करते हुए ३ साल होगये परन्तु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है । भारत मंत्री, भारत सरकार के मन्तव्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अभी तक पहुँच जाना चाहिये था । कुछ दिन हुए मैंने इस विषय में एक प्रश्न किया था और मि० कारलायल ने उसका जवाब दिया था, इस जवाब से कुछ आशा भलकती थी अतएव आज मैं उस सवाल पर जोर नहीं दूँगा परन्तु अगर जरूरत बाकी रही तो मैं शिमले की कांसिल के अधिवेशन में इस पर एक प्रस्ताव पेश करूँगा ।

पहली बात जो मुझे कहना है यह यह है कि इम्पीरियल और प्रान्तिक भेद दूर होना चाहिये । दूसरा मामला, जिससे हमने भूतपूर्व पब्लिक सर्विसेज कमीशन के जमाने से नुकसान उठाया है, चुनाव की परीक्षाओं का है, इन परीक्षाओं वाला नियम न्यूनाधिक सारे देश से दूर कर दिया गया है । और अब हमारे भाग्य का निपटारा केवल सरकारी नाम

जदगी पर रह गया है। चुनाव की परीक्षाओं के द्वारा सरकारी पदाधिकारियों के निर्णय में जो दोष हैं, में उनसे अपरिचित नहीं। निस्सन्देह यह व्यवस्था अच्छी नहीं। परन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि वर्तमान दशा में जो कुछ सम्भव है इसमें ही सुधार किया जाय। हमारे से देश में जहाँ अंग्रेज शासक है, जो हमारे स्वभावों से सर्वथा अपरिचित है, और दो व्यक्तियों की जाच कठिनता से कर सकते हैं, उनका दिखावे की बातों, सिफारिशों तथा और ऐसी ही बातों से धोखा खा जाना बहुत सम्भव है। अतएव मैं प्रार्थना करूँगा कि उक्त परीक्षाओं में कुछ दोष होते हुए भी वे नामजदगी के तरीके से फिर भी कहीं अच्छी ह। यदि किसी अंग्रेज को किसी दूसरे उम्मेदवार अंग्रेज की परीक्षा करनी हो तो सम्भव है कि चुनाव की परीक्षा आवश्यक न हो क्योंकि सजातीय होने और एक ही समाज में चलने फिरने, उठने बैठने के कारण वे एक दूसरे के स्वभावों से भली भाँति परिचित हो सकते हैं। परन्तु जब दो व्यक्ति दो जातियों और दो देशों के हैं और एक दूसरे से कतई परिचित नहीं हैं तो उस दशा में नामजदगी वाले नियम से बुरे परिणाम निकलेंगे। चुनाव ठीक नहीं होगा और पक्षपात से काम किया जायगा। अतएव मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि सरकारी नौकरी के लिए फिर नये सिरे से उक्त परीक्षाओं का प्रयत्न किया जाय।

अब मैं एक या दो विभागों के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। अभी कह चुका हूँ कि तामीर और शिक्षा विभाग में हमारी दशा खराब हो गई है। डाकूरी विभाग में यद्यपि हमारी दशा बुरी नहीं हुई है तथापि वह भी बहुत असन्तोष

जनक है। अध्यापकों के ओहदे इंडियन मेडिकल सर्विस के शासकों के हाथ में है और अस्पतालों में सर्विस के बाहर के लोग नहीं लिये जा सकते। हाल में कलकत्ता कालेज के 'एनाटोमी' (शरीर-विज्ञान) के अध्यापक के पद का द्वार बाहर के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। परन्तु ऐसा करते ही इस नौकरी में शर्तें ऐसी रख दी गई हैं जो आकर्षक नहीं हो सकतीं। इस पद के लिये अब तक पेन्शन नियत थी और निजी तौर से भी इलाज करने का स्वत्व प्राप्त था, परन्तु अब निश्चय किया गया है कि इस पद में न पेन्शन होगी, न उक्त रीति से डाकूरी करने का अधिकार रहेगा, और न रहने के मकान का खर्चा मिलेगा जो हर किसी को मिलता है। मैं पछुता चाहता हूँ कि यह सब क्यों किया गया है? फिर केमिकल एफजामिज बम्बई और कराची को लीजिये, कुछ दिन हुए भारत मंत्री ने यह तो किया था कि इन पदों पर इंडियन मेडिकल सर्विस वालों का ही अधिकार न रहना चाहिये। बम्बई में इस वक्त एक उठे ही योग्य पुरुष इस पद के लिए प्राप्त हैं। इंडियन मेडिकल सर्विस के लोग जो इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं वे उनमें प्राइवेट रीति पर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके अफसर बना दिये जाते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि बम्बई गवर्नमेंट इन महाशय की सहायता किया चाहती है परन्तु मामला भारत सरकार के हाथ में है। अस्तु। इन महाशय के प्रकाण्ड पारिडल्य के स्वत्वों का अब तक कुछ मान नहीं किया गया है।

अन्त में मैं रेलवे विभाग की ओर आता हूँ। मेरे मित्र मि० मधोलकर इस विषय पर भली भाँति कथन कर चुके हैं अतएव मैं आज इस प्रश्न पर संक्षिप्त विचार करूँगा। इस

विभाग के उच्च पदों से हम बिल्कुल अलग रखे गये हैं और यह सरासर अनुचित है। यह तो किसी दशा में नहीं कहा जा सकता कि रेलवे विभाग के काम के लिए हिन्दुस्तानी २००] से ऊपर के वेतन वाले ओहदों के योग्य नहीं, विशेषतः जबकि तुम इनको जिलों और कमिश्नरिया का शासक बनाते हो हाईकोर्टों का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हो, और भारत के मन्त्रिमंडल में सम्मिलित करते हो। मैं उन लोगों को जो हमारी अयोग्यता के चर्च चलाया कर रहे हैं एक मनोरंजक घटना का हाल सुनाना चाहता हूँ जो रेलवे विभाग के सम्बन्ध में नहीं बल्कि पेमायश के मोहकमे के सम्बन्ध में है। बात लगभग एक ही सी है। बहुत समय नहीं हुआ कि पेमाइश विभाग में यह विवाद उठा या कि हिन्दुस्तानियों की भी इस विभाग में कदम होनी चाहिये यूरोपियन अधिकारियों की ओर से यह बड़े जोर शोर से कहा गया कि हिन्दुस्तानी अयोग्य होते हैं अतएव उन्हें इस विभाग से दूर ही रखना चाहिये। दुर्भाग्य से इस विभाग के उच्च अधिकारी कर्नल डियोपर की ओर से हिन्दुस्तानियों के दाखिल के विरोध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें निम्न लिखित बातों का उल्लेख था.—

“मैं यहां पर, यह कहा चाहता हूँ कि मुझे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाच करने के बाद मालूम हुआ है कि यूरोपियन अफसरों में प्रायः यह बात पाई जाती है कि वे हिन्दुस्तानियों से तो डाइर और नकशों के बनवाने का काम लेते हैं और स्वयम् केवल सड़े खड़े देखा करते हैं, मानो वे इस काम को हीन, समझते हों। यह एक भूल है और भविष्य में

यह दुहराने न दी जायगी। फिर युरोपियन अफसरों को यह अगीकार करना, कि कोई भी काम हिन्दुस्तानी उनसे अच्छा कर सकते हैं वहन ही हानिकारक होगा। उन्हें इस बात का दावा रखना चाहिये कि यह हर बात में उनसे बड़े बड़े हैं। और हिन्दुस्तानियों को केवल तुच्छ काम देना चाहिये। अपने प्रारम्भिक समय में मैं भी किसी हिन्दुस्तानी को अमली और बढिया काम नहीं देने देना था। इस निदान्त पर कि पैमाइश का उच्च बाय उडे युरोपियन अधिकाारियों का है। और इसी एक तरीके से मैं युरोपियन और हिन्दुस्तानियों में भेद कायम रख सकता था कि इन दोनों की पृथक् प्राप्त की हुई सरयाओं के लिये कोई विवाद बाकी रहे। हिन्दुस्तानी पैमाइश के कार्य और दूसरे के कामों में युरोपियन के समान है। हिन्दुस्तानी नकशा बनाने का काम करना है और युरोपियन और कोई तुच्छ काम।”

श्रीमान्, मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक विनीत वचनों में इस न्याय के लिये घायस चेयरमैन रेलवे बोर्ड की सेवा में एक प्रार्थना पत्र पेश किया चाहता हूँ। अब मैं केवल एक ही शब्द और कहूँगा। मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि यह प्रश्न कठिन है परन्तु फिर मैं यह कहता हूँ कि क्रमशः उन्नति होना चाहिये। यह कोई नहीं कहता कि अङ्ग्रेजी भाग बिलकुल उठा दिया जाय या अधिकांश हटा लिया जाय। परन्तु यदि हिन्दुस्तानी उच्च वर्गों पर दिन प्रतिदिन नहीं नियुक्त किये जायेंगे तो फिर वह असन्तोष जिसे सरकार दूर किया चाहती है, और भी अधिक बढेगा। इन शब्दों के साथ मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जिसे मेरे माननीय मित्र ने उपस्थित किया है।

वर्तमान स्थिति के अनुकूल कार्यनीति ।

४ फरवरी स० १९०७ ई० को प्रयाग में होने वाली एक सार्वजनिक सभा में एडिड मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में मि० गोखले ने निम्न लिखित वक्तृता दी थी —

मित्रों को उस स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए जो उन्होंने अपने मन्चे हृदय से किया था, मि० गोखले ने कहा —

यह प्रयाग में पहली बार ही नहीं आए थे । इससे पहले भी वे दो बार प्रयाग आ चुके थे । उन्होंने उस दिन का जिक्र किया, जब पहली बार उन्होंने इस नगर में पदार्पण किया था, और गंगा जमुना के मङ्गल के दृश्य ने जो हिन्दूमात्र के लिए आज अनेक शताब्दियों से महन्त्र की गीज है, जो प्रभाव इनके हृदय पर डाला था, उस का उल्लेख करते हुए मि० गोखले ने कहा कि उस समय चित्त में अपूर्व उत्साह उमड़ आया था, अकारण ही आनन्द का अनुभव हो रहा था । वह इस मङ्गल पर खड़े आश्चर्यचकित से हो रहे थे और मस्तिष्क, इस पवित्र भूमि का प्राचीन गौरव, उसकी वर्तमान असफलता, अपनी जाति के उत्साह पूर्ण धार्मिक विश्वास की उन सफलताओं और कठिनाइयों का अनुभव कर रहा था जो उस पर गुजर चुकी थीं । इस बात को १७ साल बीत गये उस वक्त से प्रयाग का नाम उनके हृदय पर अद्भुत प्रभाव डालना —

है। और उनके दिल में ऐसे उसाहों की लहरें उठने लगती हैं जिनका पैदा होना ही गौरव और महत्त्व का कारण है। इसी से अनुमान किया जा सकता है कि वह प्रयाग इस बार किस प्रसन्नता से आये होंगे और वह रुनन्न हों रहे थे कि मित्रों ने उनको उस दिन विचार परिवर्तन करने का अवसर दिया।

सब से महत्त्व का प्रश्न उनका सामने यह था कि राज नैतिक क्षेत्र में उनकी वर्तमान अवस्था कौसी है? और भविष्य में कौसी होनी चाहिये? मि० गोग्रले ने कहा कि यह इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं कि उनके सामने कौन सा काम करने के लिये पड़ा हुआ है, जो हमें अपनी जातीय स्वतंत्रता की कामनाएँ पूरी करने के लिये अवश्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा देश की अवस्था बड़ी नाजुक है यह वह समय है, कि जातीय उन्नति के पथ में लोग अग्रसर हो रहे हैं। और यदि हम उचित परिणाम पर पहुँच सकेंगे तो जातीय शक्ति में वृद्धि होगी, इसके विरुद्ध यदि हम उचित परिणाम पर न पहुँच सकें तो उसके परिणाम साधारण में अधिक हानिकारक होंगे। कई बातों से इस समय देश की ऐसी अवस्था है, जिसमें प्रत्येक देशप्रेमी स्तुष्ट होगा। नवीन शताब्दी का आरम्भ पूरे के लिए बहुत शुभ जान पड़ता है। हमने अपनी आत्मा के सामने एक ऐसा नाटक होत देखा है, जिसने पूरे और पश्चिम के सम्बन्धों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। आज कल के नवीन विचारों ने वायु के रख में विज्ञान पर धर्तन कर दिया है, हम में एक नई शक्ति और उत्साह का समावेश हो रहा है। अपना अस्तित्व हमें एक नया

रूप दिखा रहा है। लार्ड कर्जन की कड़ी नीति अंग्रेजों के रूप में प्रमाणित हो रही है। स्वदेशी आन्दोलन का इतना शीघ्रता के साथ सारे देश में फैल जाना प्रत्येक देशवासी के हृदय में आनन्द और गौरव की लहरें पैदा कर रहा है। क्योंकि स्वदेशी का अर्थ व्यापक देशभक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं निदान उषा का उजाला हमारी आशाओं के आकाश पर एक नई भलक डाल रहा है, जो बढ़ते बढ़ते सूर्य की भाँति प्रकाशित होगी। वर्तमान अवस्था में कुछ बातें ऐसी हैं जो चिन्ता को प्रसन्न करती और हृदय में साहस पैदा करती हैं। परन्तु उसीके साथ ही यह भी कहना कि कुछ चिन्हाँ ऐसे भी हैं जिनसे असंतोष होता है और हर तरह का सोच विचार पैदा हो जाता है। अनन्व आपने कहा कि हम वर्तमान अवस्था पर एक सख्त दृष्टि डालें और स्पष्ट यह देने की चेष्टा करें कि हमारा उद्देश्य क्या है अथवा क्या होना चाहिये और हम उसकी ओर कितना बढ़ें ? यह विचार कर लेना लाभदायक होगा।

वर्तमान अवस्था के मुख्य मुख्य रूप क्या हैं ? हमारे एक ओर तो विजातीय शासकों का समूह है जो सारी शक्ति और शासन पर अधिकार जमाये हुए हैं। इन लोगों ने जिनका सरक्षक एक बड़ा भारी साम्राज्य है, एक शताब्दी के मध्य में हमारे देश में अपने शासन का एक बड़ा उद्योग भवन तैयार कर लिया है, और यद्यपि यह भवन हमारे जीवन के व्यवहारों से विलकुल पृथक् है तथापि यह उनकी उत्तम प्रगतिशैली का हमारे लिये पूरा प्रमाण है और उससे यह प्रकट होता है कि उनके हृदयों में नियमों की पान्दी का कैसा महत्त्व है और कार्यों को श्रद्धालावट करने में वे कैसे निपुण

हैं। प्रजा की दृष्टि में इन के शासन का बड़ा महत्व है। हमारी दूसरी ओर प्रजा का एक बहुत बड़ा समूह है जो एक मिट्टी के ढेर की तरह लथंग पथर पड़ा हुआ है जिसमें से कभी, २ धार्मिक उत्साह की दशा में एक आध चिनगारिया निकल पड़ती है। जिनसे एक नये जीवन के अस्थिर प्रभाव देखने में आते हैं। यह समूह पारम्परिक ढंग के कारण दुर्गो है, इसमें न जातीयता का कुछ मान है और न मेलमिलाप की कुछ इज्जत है। यह मूर्खता और दीनता के गड्ढों में पड़ा हुआ है। और ऐसे रीति रयाजों को मानता है कि जानोय भागों को जोड़ित रखने के लिए उनकी आवश्यकता भले ही हो पर जाति के द्विभ्रमिन्न समूहों से एकत्र करके उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ाना उनकी शक्ति के बाहर है।

इन दोनों के बीच में शिक्षित जनों का समुदाय है जिसकी सख्या में दिन दिन वृद्धि होती जाती है और जो अब भी उक्त बड़े समूह पर अपना अधिकार रखता है। और जो अपनी शिक्षा य ग्यता, अवसर की आवश्यकताओं की जानकारी, और देश भक्ति के उत्साह से भविष्य में अनिवार्य रीति से उक्त अरुणित समाज का माता वर्शक बनेगा। यह समुदाय जो किसी समय ब्रिटिश शासन से पूरी सहानुभूति रखता था, अब घट अपना अमतोष प्रकट करने लगा है। उसको सरकार का, आशाजनक वादे न करना अनुचित प्रतीत होता है और अपनी निर्मलता और प्रियता उसे असहनीय जान पड़ती है। यह इस पर तुला हुआ है कि सभ्य जातियों की भांति यह भी ससार की दृष्टि में जातीय मान प्राप्त करे। प्रश्न की कठिनाइयों और गम्भीरताओं का उल्लेख करने के बाद जिन

का हमें मुकाबिला करना है, मि० गोखले ने कहा कि अब हमको यह देखना है कि ऐसी दशा में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिये ? आपने कहा कि मैं आरम्भ ही में यह कह देना चाहता हूँ कि मैं अपनी जाति की इच्छाओं और कामनाओं को परिमित नहीं समझता । मैं अपनी जातिवालों को अपने देश में वैसा ही स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहता हूँ जिस तरह अन्य देशों के लोग अपने देशों में होते हैं । बिना किसी मतमतान्तर के भेदभावों के मैं अपने सजातियों के लिए वे अवसर और सुभीते चाहता हूँ जिनसे वे अनुचित और अस्वाभाविक बन्नों से मुक्त हो कर बड़ें और फलें फूलें । मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष, धार्मिक, राजनैतिक, उद्योग शिल्प इत्यादि जीवन के सभी गुणों में ससार की जीवित और प्रसिद्ध जातियों के पार्श्व में स्थान पावे और अपना सम्मान स्थापित कर सके । मैं यह सब कुछ चाहता हूँ परन्तु इस के साथ ही यह भी विश्वास करना हूँ कि हमारी यह सब कामनाएँ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रह कर पूरी हो सकती हैं । हमारे सामने यह प्रश्न नहीं कि श्रेष्ठतम बातों में ही हमारे उद्देश्यों की पूर्ति क्या होनी चाहिये ? यदि यह कि घासन में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कहा तक सम्भव है ? यह केवल मनमोहकों का प्रश्न नहीं है, भरसक योग्यता और साहस दिवाने तथा जाति के लिए तन, मन, धन समर्पण करने का है ।

केनाडा में फ्रांसिसियों और दक्षिण अफ्रीका में बोयर्स के उदाहरणों से द्योत होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की परिधि के भीतर भारतवर्ष को भी स्वाधीनता के विकास के लिए स्थान है । हमारे कई एक मित्र मार्ग की कठिनाइयों से आरंभ

आकर यह सोचते हैं कि वहाँ तक पहुँचना असम्भव और है, एक दूसरे नए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जो पहले से भी अधिक कटकाकीर्ण है। वे लोग उनकी तरह हैं जो ऐसी विपत्ति से जिम्मे से वे परिचित हैं, प्राण बचा कर उस विपत्ति की ओर भागते हैं जिससे वे अनजान हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में स्वाधीनता का एक ऐसा मार्ग है जिससे हम परिचित हैं चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। इससे अतिरिक्त हमारे विचार और प्रयत्नों में निम्न पड़ सकता है। फिर हमारे इस उद्देश्य के साथ उन अंग्रेजों की सहानुभूति होगी, जो स्वाधीनता के समर्थक, विश्व और उच्च प्रकृति के आदमी हैं। और इसमें सन्देह नहीं कि इंग्लैंड में ऐसे लोगों की पर्याप्त संख्या है। कहीं कहीं पर उनकी कूटनीति अवश्य ही रोद प्रकट करने योग्य है, वे अपनी टेढ़ी और तिरछी चालों सासारिक मामलों को पार करने में अनिवार्य रीति से चला करते हैं तथापि इन सब बातों के होते हुए भी ब्रिटिश जाति का एक परमोत्तम गुण जो इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ से झलकता है वह उनकी जातीय स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता के वे सदा ही पक्षपाती रहे हैं। यह मूर्खता है, मरासर उन्माद है कि इस झगड़े और मुकाबिले में जिसका हमें सामना करना है, हम उनकी सहायता से लाभ न उठावें।

मि० गोखले को यह देख कर प्रसन्नता हुई कि उस दल के एक नेता ने जो नया दल कहा जाता है, अपने समाचारपत्र के एक अंक में स्पष्ट रीति से लिखा है कि वह ब्रिटिश-छत्रछाया में स्वाधीनता प्राप्त करने पर सतुष्ट होने के लिए तैयार हैं। और वे इसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं। यह

अच्छी तरह प्रमाणित करके कि हमारे लिए ब्रिटिश छत्रछाया में ही स्वाधीनता प्राप्त करने का उद्देश्य सर्वोत्तम है, मि० गोखले ने उन नियमों और उपायों पर सबका ध्यान दिलाया जिनसे हम इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा कि इसके लिए मैं कोई सरल मार्ग नहीं बता सकता, भिन्न भिन्न उपायों में कठिन प्रयत्न की आवश्यकता है परन्तु एक बात हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि जिस दशा में हमारा उद्देश्य यह है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया, तो उसके प्रयत्न भी नैतिक समर की परिधि में परिमित रहना चाहिये।

प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि नैतिक समर का क्या तात्पर्य है मैं इसका उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। नैतिक समर उस समर को कहते हैं जिन के द्वारा हम कानूनी कठिनाइयों में परिवर्तन करके अपना अभीष्ट प्राप्त करना चाहें, और उन उपायों का प्रयोग करें जिन के प्रयोग करने का स्वत्व हमें प्राप्त है। इस के अनुसार नैतिक समर का अर्थ बहुत विस्तृत होता है, परन्तु हममें दृढ़ता से मानना जरूरी है, प्रथम तो यह कि जिन उपायों का हम प्रयोग करें, उनके प्रयोग करने का हमें अधिकार हो। दूसरे यह कि जो परिवर्तन हम कराना चाहते हैं वह कानूनी फेरफार ही से प्राप्त किया जावे।

वे कौन से उपाय हैं जिन का हम उचित रीति से प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात जो ध्यान में आती है, वह यह है कि इस समर में हाथपाई और शारीरिक शक्ति का कुछ काम नहीं—अर्थात् तीन बातें इस समर से भिन्न हैं, प्राणी हा जाना पाप पूर्ण चाले चलना, किसी श ने लक्षण में सहायता

कम्पा। इन तीन बातों के अतिरिक्त सब उपाय नैतिक समझ में परिगणित हैं। यद्यपि इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह प्रत्यक्ष नियम जो नैतिक और उचित हैं, वह प्रायश्चित्त भी हैं परन्तु यह दूसरा प्रश्न है। एक ओर तो अनुनय विनय करना, अपने कष्टों पर न्याय चाहना नैतिक लड़ाई में शामिल है और दूसरी ओर निष्क्रिय प्रतिरोध और टैंक्स और फर्गों का भी उस समय तब भडा न करना जब तक कि अभीष्ट प्राप्त करना पूर्ण न हो। यदि हम ग्याल से देवा जाय तो तब तब हमारे देश में जो कुछ आन्दोलन हुआ उसमें नैतिक नियमों के विचार कोई धात न थी। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों ने अयुक्तिपूर्ण बात चीत की हो। ग्या यह प्रश्न कि उचित और अनुचित क्या है ? यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है, तथापि हम पर फिर विचार होना। दूसरी बात यह कि हमारे उद्देश्या की पूर्ति मनुष्यी मशीन के द्वारा ही होना चाहिये अर्थात् इन पर लगाने जोर डालने से इस विषय में यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सरकार और सरकारी मामला से कुछ सम्बन्ध न रखना चाहिये, यह सब सगमर अनुचित और अयोग्य है। यह जरूर है कि आप सरकार पर उतना ही जोर और दबाव डाल सकेंगे जितना संसाधारण की सम्मति और शक्ति में प्राबल्य होगा और इस सम्मति का शक्तिशाली बनाने का प्रश्न ही मत्र में आवश्यक प्रश्न है, तथापि यह विचार कि संसाधारण को सरकार से कुछ सम्बन्ध रखना ही नहीं चाहिये और अपने भाग्य का फैसला थला ही अलग से कर लेना चाहिये, सरासर मिला और अनुचित है।

इसके बाद मि गोयले ने कहा कि लोग कभी कभी यह भी

यहकी बातें किया करते हैं कि नैतिक समर हमारे देश में बिलकुल व्यर्थ साबित हुआ। यह उचित नहीं क्योंकि अभी तो आप ने वास्तविक नैतिक समर में कुछ भी उद्योग नहीं किया। इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस ने २० वर्ष में भारतवर्ष में जातीयता पैदा करने का जो काम किया वह सर्वथा प्रशसनीय है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि यदि हम को अपनी पूर्ण सम्पत्ति में कुछ वृद्धि प्राप्त हुई तो इसके साथ ही अनेक कष्ट भी उठाने पड़े। इन कष्टों को सहन करने के लिए हम सफलता के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस के काम ने हम में जातीयता पैदा की, हमारी आवश्यकताएँ हमारे सामने खड़ी, पक्क हो कर काम करना सिखाया, हम में सार्वजनिक जीवन के उत्तरदायित्व के भार को उठाने की आदत डाल दी। इस में सन्देह नहीं कि हम ने पूरे साहस और सच्चे हृदय से जाति की सेवा की होती तो जितना काम हुआ उससे कहीं अधिक हो सकता था। परन्तु इसका उत्तरदायित्व सब पर एक समान है। और यह भी अनेकाश में सत्य है कि हर काम तभी होता है जब उसका समय आता है। गत २० वर्षों में भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी विरोध वायु के शोके चलते रहे। अतएव यदि हम उन सुधारों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, जो हम चाहते थे तो यह हमारे उपायों और प्रयत्नों का दोष नहीं। राजनैतिक स्वतन्त्रता मागने से ही नहीं मिल जाते हैं, अन्य जातियों को तो बड़े लम्बे चौड़े युद्धों के अनन्तर प्राप्त हुए हैं। यदि हम अपने प्रयत्नों का अनुमान करें और देखें कि कार्यरूप में उनका परिणाम क्या हुआ तो हमारे आन्दोलनों में शिष्टता का भाग तो बिलकुल नज़र से जोखल हो जाता है। उस घातकीत को स्मरण करें मेरे कुछ भिव किया करते

हैं, कभी कभी मेरी ऐसी इच्छा होती है कि यदि यह थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भी जो हमें दूरदर्शी महानुभावों की यत्नोलत मिल गई, इस तरह न मिलती बल्कि इसके लिए भी हम को रक्त और पसीना एक करना पड़ना तो अच्छा होता। शासन के उच्च अधिकारियों में जिन पर हमें दयाव डालना है, जप्रेजी शासकों के विषय में तो हमें समझ लेना चाहिये कि वे त्रिगोध करंगे, परन्तु इंगलैण्ड में भिन्न भिन्न वर्गों की दृशा में गतधर्म से जो अन्तर दिखाई दे रहा है, और स्वतंत्रता और जातीयता का प्रभाव जो वर्तमान होस आफ कामन्स और इंगलैण्ड निवासियों में इस वर्ग पाया जाता है, उससे हमें सहायता की पूरी आशा रखनी चाहिये। हा इससे हम कहा तक लाभ उठा सकेंगे, यह हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। मेरा सदा ही यह गयाल रहा है कि हमारे काम का बड़ा भाग भारतवर्ष के भीतर ही है, जहा हमें अपनी जातीय शक्ति की वृद्धि करना है। परन्तु वर्तमान अवस्था में हमें इंगलैण्ड में भी जाकर उत्कट प्रयत्न करना है। यदि हम ब्रिटिश प्रजा को अपने दुःख दुर्घट का परिचय देते रहें तो हम यहां के शासकों पर एक प्रकार का दबाव रख सकेंगे जिस के कारण वे अपने अनुचित व्यवहारों से हमें पीडित न कर पावेंगे। इस के अनिरिक्त वैसे भी जातीय जीवन का भवन तैयार करने के लिए आरम्भ में हमको इंगलैण्ड की प्रजा से सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के प्रश्न को लीजिये। प्रारम्भिक शिक्षा को हमारे भारत में फैलाने के लिए ५-६ करोड रुपये के खर्च की आवश्यकता होगी। यदि हम केवल यहां के शासकों पर ही भारोसा रखें, तो मुझे यह आशा नहीं कि यह शासक कभी भी शिक्षा के लिए इतने रुपये का व्यय स्वीकार करें। और न स्वयम् अपने

प्रयत्न से यह बड़ा भारी काम पूरा पड़ सकता है। परन्तु यदि हम ब्रिटिश प्रजा-इंग्लैंड की प्रजा—के द्वारा दबाव डलवाएँ तो आशा है की हमारी इच्छा के अनुकूल परिणाम निकले।

कुछ काल से देश में यह वायु बह रही है कि व्यक्ति गत-मुधारों की अयहेलना की जाती है, परन्तु हमें समझना चाहिये कि हम एक दम किसी विशेष परिवर्तन की चेष्टा करके सफल-मनोरथ न हो सकेंगे बल्कि क्रम क्रम से आगे बढ़ते हुए अभीष्ट स्थान पर जा पहुँचेंगे। हम विरोधो के समूह को दूर करना है, फिर मार्ग से भी हम भली भाँति परिचित नहीं। अतएव हमको अपनी विचरता से उकताना नहीं चाहिये, बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिये कि हम अपनी आत्मशक्ति को प्रयत्न उतारें, यह हमारा मुख्य कार्य है। यह काम तीन बातों पर निर्भर है। पहले तो भाग्य-वश की विविध जातियों जैसे हिन्दुओं और मुसलमानों तथा हिन्दुओं के अन्तर्गत अनेक जातियों में परस्पर मेल-मिलाप का दृढ़ बनाना चाहिये, फिर हमारी जाति के व्यक्तियों में वे उत्तम गुण होने चाहिये, जिनसे हम अपनी धुन के पक्के और कार्य के समय आशाकारी सिपाहियों की भाँति तैयार रहें। हम में जातीयता का भाव ऐसा होना चाहिये, जिस के द्वारा जाति-पाति और मत-मतान्तर के झगड़े का पूरा हो जाय। और देश के लिए प्राण अर्पण करने में ही मरने से बड़ा आनन्द हो। इसके साथ ही सत्यसाधारण में राजनैतिक शिक्षा का भी प्रचार बढ़ता रहे। मि० गोपाल ने कार्य के विविध भागों की कठिनाई पर जोर डालते हुए हिन्दू मुसलमानों के प्रश्न के विषय में कहा कि वास्तव में यह सत्य से अधिक उलझा हुई गाँठ है परन्तु पेसी नहीं जो मुल

झाई न जा सके। उच्च शिक्षा अपना काम कर रही है तथापि समय की अवस्था के अनुकूल हमें चाहिये कि सहानुभूति और सहनशीलता से अधिक काम लें। मुझे पूर्ण आशा है कि बहुत समय नहीं गुजरेगा जब उदार और देशभक्त मुसलमान द्वेषभाव को त्याग कर हर काम और हर बात में हमारे कन्धे में कन्धा मिलाते हुए देग पड़ेंगे।

अन्त में मि० गोपले ने नवीन शिक्षा की आलोचना की। आप ने कहा कि व्यर्थ विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। जब हमने कहा जाता है कि हम नए नियमों को स्वीकार करें, उन्हीं में हमारा कल्याण है तो हमको यह अधिकार है कि हम नए नियमों की भली भाँति जाच पड़ताल करें। हमसे कहा जाता है कि हमको सरकार से कोई सम्बन्ध न रखना चाहिये और यदि हम केवल एक व्यापक वहिष्कार आरम्भ करें तो हमारा कार्य सिद्ध हो जायगा। मि० गोपले ने पहले व्यापार सम्बन्धी वहिष्कार पर ध्यान दिखाते हुए कहा कि वह लोग जो व्यापारी वहिष्कार के पीछे हैं और सारे विदेशी मालों का वहिष्कार करना चाहते हैं, वास्तव में उनका यह तात्पर्य होता है कि स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रचार होना चाहिये, चाहे ऐसा करने में कितना ही कष्ट और श्रमिक आर्थिक व्यय पड़ो न हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वदेशी आन्दोलन को लाज पहुँचाने का एक यह भी उपाय है। आर गवर्न साधारण के लिये, जिनकी आवश्यकता बहुत कम होती है, और जो नये नये उद्योगों में अधिक रुपया नहीं लगा सकते हैं, स्वदेशी आन्दोलन से सहायता पहुँचाने का केवल यही एक उपाय है। इस उपाय से जो माल देश में बनाया जाता है उसकी बिक्री का प्रबन्ध हो

जाता है। और नए उद्योग और शिल्पकारियों के आरम्भ करने में उत्तेजना मिलती है। जिससे आरम्भ में नए उद्योग और शिल्प को प्रतियोगिता करने में सुविधा होती है। यह सब स्वदेशी आन्दोलन के भाग हैं। इनका अर्थ यह नहीं कि हम केवल कथन मात्र ही से स्वदेशी उद्योग की उन्नति चाहते हैं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार सहायता करके स्वदेशी घाण्डिय्य की उन्नति करने का पक्षपाती है। हाँ, बहिष्कार का शब्द इस विषय में कुछ खटकने वाला है क्योंकि बहिष्कार से बदला लेने का अर्थ प्रकट होता है जिसमें दूसरों को हानि पहुँचाना मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे ऐसा करने में स्वयम् अपने ही को हानि पहुँचे। इसी लिये स्वदेशी आन्दोलन के विरुद्ध बहुत कुछ अनावश्यक विरोध लोगों में पैदा हो गया है। और हमारे मार्ग में इस कारण से कुछ अनावश्यक बाधाएँ आ गई हैं। स्वदेशी आन्दोलन में सफलता प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं, उसके लिये हमें दूर तरफ से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप ने इसका उदाहरण दिया कि हाल में बम्बई की गवर्नमेन्ट ने अनुभव के लिये सिन्ध में मिसर की रई का प्रचार किया है, उससे बहुत कुछ उन्नति की आशा है। प्रत्येक दशा में आप ने कहा कि इस प्रश्न के इस भाग पर विशेष जोर मैं नहीं दिया चाहता। मेरे कथन का निष्कर्ष यह तात्पर्य है कि हमको अपनी मंडियों में से बाहर के माल को (जो वर्तमान में लगभग १०० करोड़ का आता है) कतई निकाल कर बाहर कर देने के लिये बहुत समय की आवश्यकता है। और यदि यह उद्देश्य पूर्ण रूप से सिद्ध भी हो गया तो वह हमारे उपायों और साधनों में बड़े ही वृद्धि कर्द पर हमारी वर्तमान शासित

अवस्था में उससे कोई विशेष अन्तर नहीं आ सकेगा। यह नम्र है कि कुछ दशाओं में वह हमारी शासित अवस्था को और भी अधिक सख्त और असहनीय बना दे।

इसके बाद मि० गोखले ने साधारण या राजनैतिक वहिष्कार की ओर, लक्ष्य रखते हुए, जिसका कुछ लोग उप देश दे रहे हैं, कहा कि यह बात विचार में लाने के सर्वथा अयोग्य है कि कोई मनुष्य यह समझे कि देश की वर्तमान अवस्था में राजनैतिक वहिष्कार का प्रयोग करना उचित है। अपनी निज की पूजी से सारे देश में जातीय पाठशालाओं, और कालेजों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करने के लिये एक जमाना चाहिये, इसके अतिरिक्त इसके लिये उच्च उदारता से काम लेना पड़ेगा। इसके पहले कि हम इस ओर कुछ कर के दिखलाए, वर्तमान स्कूलों का वहिष्कार कर देना सरासर उन्माद है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जातीय शिक्षा के बुद्धिमान पक्षपाती यह नहीं कहते कि वर्तमान स्कूलों को हात मार दो, बल्कि जातीय शिक्षा के विषय में वे गवर्नमेन्ट का हाथ बंटाना चाहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष हैं परन्तु इससे बहुत कुछ लाभ भी पहुँचा है और पहुँच रहा है, और जातीयता को जान जो इस वक्त भारतवर्ष के शरीर में पड़ी हुई दिखाई देती है वह इसी वर्तमान शिक्षा का फल है।

सरकारी नौकरियों के वहिष्कार का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि मैं स्वयम् प्रसन्न हूँ कि सरकारी नौकरियों के प्राप्त करने के लिए हमारे नवयुवकों में जो अभिलाषाएँ रहा करती हैं वे समाप्त हो जायें। या कम से कम हमारे —

युवकों की एक बड़ी सख्या स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन बिता का निश्चय करले। यदि ऐसा हो तो स्वदेश का काम कर चातों की सख्या में वृद्धि होगी। मैं स्वयम् कुछ दिनों से बराबर यह कह रहा हूँ कि उनमें से कुछ नवयुवक जो प्रति वर्ष यूनीवर्सिटियों से निकलते हैं, ऐसे होते कि अपने व्यक्तिगत मान सम्मान का ग्याल परित्याग करके उदारता के साथ जाति की सेवा करने पर कटिबद्ध होते। परन्तु वर्त्तमान अवस्था में सरकारी नोक़रियों का एक दम बहिष्कार करना उपहासमात्र है। गवर्नमेन्ट पर बहिष्कार का प्रभाव उस समय पड़ सकता है जब इतने आदमी गवर्नमेन्ट को न मिल सकें जितनों की उसे कार्य संचालन के लिए जरूरत है। मैं नम्रता पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस विचार को कार्य रूप में परिणत करना सर्वथा अयोग्य है। अन्त में सम्मानित पटों के बहिष्कार का प्रश्न है जैसे म्युनिस्पल बोर्ड और कोसिलों की मेम्बरी। यदि वर्त्तमान मेम्बर आज पदत्याग कर दें तो दूसरे ही दिन ग्राह्य हो जायगा कि उनके स्थान पर दूसरे आ डटे और उन्होंने उस अवसर को जो उन्हें जाति सेवा के लिए प्राप्त था, हाथ से छो दिया। आवश्यकता इस बात की है कि साम्राज्य के प्रवन्ध में नाममात्र के लिए जो अधिकार हमें प्राप्त हैं उन्हें क्रमशः बहानों को कोशिश करें, और अधिक अधिकार जमायें। इसका विरुद्ध यदि उक्त उपाय के अनुसार कार्य किया जाये। तो राम के बजाय हम देश की उन्नति को और भी हानि पहुँचावेंगे। हमारे सार्वजनिक जीवन के मूल को हिलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसका विरोध करना हमारे लिए परमावश्यक है। जो लोग इस तरह के बहिष्कार को पक्षपाती हैं, और जो सोचते

हैं कि स्वराज्य प्राप्त करने का केवल यही एक उपाय है, उन के सामने मैं एक प्रस्ताव पेश करता हूँ, महसूलों का बदला न करना वहिष्कार का सब से अधिक प्रभावशाली और सीधा सादा नियम है, इसमें विशेष गुण यह है कि प्रत्येक पुरुष को अपनी कार्य नीति के परिणामों के उत्तरदायित्व का भली भाँति अनुभव हो जाता है । यदि उन लोगों में से कुछ, जो निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा वर्तमान-अवस्था में स्वराज्य प्राप्त करने का दावा रखते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध की रीति का उपयोग करें तो उन्हें भली भाँति हात हो जायगा कि वह कितने गहरे पानी में है और कहा तक उन्हें इससे सहायता मिलती है ।

अग्ने व्याख्यान को समाप्त करने हुए जो १½ घण्टे से हो रहा था, मि० गोखले ने अपने देशवासियों को छोटी मोटी विभिन्नताओं को दूर कर देने और सच्चे हृदय से देश की सेवा करने के लिए उत्तेजना दिलाई । आपने कहा कि जरा जरा से तुच्छ अन्तरों के कारण दलबन्दी करके लड़ना झगड़ना उचित नहीं । अन्त में प्रारब्ध ही हमारे परिणाम को घनाता और बिगाड़ता है । हम तो उसके हाथ में केवल आराज की तरह हैं । वह प्रत्येक व्यक्ति जो दश में मेल मिलाप की जड़ को दृढ़ बनाता है, स्वदेशी आन्दोलन का उपदेश देता है उदारता आदि सद्गुणों का अनुसरण करता है, अथवा व्यवसायिक, राज नैतिक सामाजिक, इत्यादि किसी तरह से भी जातीय शक्ति की वृद्धि करता है, वह अपना बन्धु और सहायक है । हमारे सामने जो सपना है वह बहुत बड़ा- और शूकाने वाला प्रमाणित होगा । और यद्यपि इस का खयाल चाहिये कि हमारा उत्साह और जोश हर समय ताजा रहे, तथापि आवश्यकता से अधिक असतोष काम बिगाड़ देगा । जातीयता के भवन का निर्माण

कहीं भी सरल काम नहीं, विशेषतः भारत वर्ष में तो ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो वास्तव में माहस छुड़ाने वाली हैं, और जो बिना हमारी पूरी योग्यता और विज्ञता के किसी भाँति तै हो ही नहीं, सकती। हमें क्षणमात्र के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिये कि हम वर्तमान में देशोन्नति की अवस्था के उस स्थान पर हैं जहाँ सफलताएं बहुत कम और असफलता और निराशाएं अधिक हैं। जो हमें, हैरान करेगी। हम सग्राम में सघनशक्तिमान ने जो पद हमें प्रदान किया है, वह यही है। जो हमारा उत्तरदायित्व वहाँ पर समाप्त हो जाना है जब हम अपने पद के अनुकूल कार्य करके सर का भार उतार डालें।

भावी पीढ़ियों का यह सौभाग्य होगा कि वह सफलता और विजय के साथ देश की सेवा करेंगी। वर्तमान पीढ़ी के लोगों को सिर्फ इसी पर सताए करना चाहिये कि उन्होंने भी देश की सेवा की, भलेही वे असफल रहे हों। चाहे यह अच्छा न मालूम हो परन्तु अन्त में, इन्हीं असफलताओं से जातीय शक्ति में वृद्धि होगी और यही शक्ति आगे चलकर बड़े बड़े सग्रामों में विजय प्राप्त करेगी।

हिन्दू मुसलमानों का मेल ।



३ जुलाई सन् १९०६ को एक सार्वजनिक सभा में जो दक्षिण सभा, पूना, के प्रबंध से हुई थी, माननीय गोखले जी ने निम्न लिखित व्याख्यान महाराष्ट्रभाषा में दिया था —

अवतक जो हिन्दू मुसलमानों के भेद सत्य साधारण क सामने आते थे, उनका कारण प्रायः धर्मभाव ही होता था, यद्यपि वे भेद बहुत दुःखदायी हुआ करते थे। उदाहरण के लिये गोश्रद्ध या त्योहारों पर जलूस निकालने और याजा यज्ञान के झगड़ों का ही घण्टन काफी है। इसमें संदेह नहीं कि कभी कभी समाचारपत्रों और मुसलमानों की सभाओं में पढ़े हुए व्याख्यानों में इस प्रकार की शिकायत हुआ करती थी कि सरकारी नौकरियों, स्थानिक सस्थाओं, और म्यूनिसिपल बोर्ड में मुसलमानों को काफी हिस्सा नहीं मिलता। परन्तु शासन और राजकार्य में मुसलमानी जाति को विशेष सुविधाएँ दिलवाने के लिए मुसलमानी नेताओं की ऐसी चेष्टा, जिसका नियमानुसार सगठन हो और जिसका कार्यक्रम स्पष्ट हो, अभी दो तीन वर्षों से ही आरम्भ हुई है। यद्यपि घरों में राजनैतिक मामलों से अलग रह कर और उनकी उपेक्षा करके अब हमारे मुसलमान भाइयों का उनमें भाग लेना ऐसा काम है जिसपर उनको बधाई दी जा

सके, तो भी मुसलमानों का अपनी एक अलग सभा बनाना और विशेष सुविधाओं का मांगना हमारे सार्वजनिक जीवन की बढ़ती हुई कठिनाइयों को घटायेगा नहीं ।

इसके बाद माननीय गोखले ने हिन्दू और मुसलमानों के पुराने इतिहास तथा समार की सम्यता और उन्नति की वृद्धि के लिये दोनों जातियों की कोशिशों का जिक्र करके उनकी वर्तमान दशा पर विचार करना आरम्भ किया ।

भारतवासियों का पाचवाँ हिस्सा मुसलमान हैं, जो मित्र २ प्रान्तों में, कहीं कम और कहीं ज़ियादा फैले हुए हैं । पंजाब और पूर्वी बंगाल में उनकी संख्या बहुत अधिक है । पंजाब में यह आधे के लगभग है । पूर्वी बंगाल में $\frac{1}{2}$ के लगभग है । इसके विरुद्ध बम्बई में केवल $\frac{1}{4}$ मुसलमान हैं और पश्चिमी बंगाल में $\frac{1}{4}$ । संयुक्त प्रांत में उनकी संख्या $\frac{1}{4}$ है, मद्रास और मध्यप्रदेश में $\frac{1}{4}$ है और $\frac{1}{4}$ । हिन्दू और मुसलमानों का बहुत बड़ा भाग एक ही पूर्वजों की सतान है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि हमारे जीवन पर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और 'कभी २' जातीय' वंश-परंपरा की आदतों को बहुत कुछ बदल भी देता है, हिन्दुओं की संख्या शिक्षा, धर्म और सार्वजनिक हित के भाव मुसलमानों की अपेक्षा इस समय अधिक है । भारतवर्ष में जातीयता के भाव उत्पन्न करने में भी हिन्दुओं ने मुसलमानों की अपेक्षा अधिक

* स्मरण रहे कि सन् १९०६ में जब यह व्याख्यान दिया गया था, पूर्वी बंगाल एक मित्र प्रांत था । सन् १९११ में उसका वर्तमान बंगाल प्रांत में समावेश हो गया, अनु० १ ।

भाग लिया है, परन्तु जाति पाति के बधन हिन्दुओं के मार्ग में बड़ो रुकावटें डाल रहे हैं, आचरणों के विचार से भी वे नम स्वभाव के ओर दब्वू हैं। इसके पिरद्ध मुसलमानों में इतो भेद और श्रेणिया नहीं हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था सर्व साधारण ही प्रधानता पर स्थिर है उनमें आपस में मेल अधिक है और वे ज़ियादा मुस्नेद होते हैं। वास्तव में कठिनाई यह है कि हिन्दू और मुसलमानों में विरोध तथा शत्रुता की जनश्रुति भारे भारत में फैली हुई है। साधारण तोर पर वह दूरी पड़ी रहती है, पर जरा सी भी उत्तेजना मिलने से उग्र हो उठती है। हम को इन पुगनी जनश्रुतिओं पर विजय प्राप्त करना है। यद्यपि हमारे मार्ग में कुछ कठिनाइया हैं और कभी २ उद्दिष्ट स्थातक पहुचना असम्भव मातृम होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यूरोप में भी तो २०० वर्ष तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मप्रदायों की आपस में घोर शत्रुता रही है, शिक्षा का प्रचार, राजनैतिक कर्तव्यों का ज्ञान जातीय गौरव ओर जातीय भावों की वलवृद्धि ऐसी शक्तिया हैं, जो अन्त में दोनों जातियों की पुरानी दुखमयी स्मृति को भी धीरे धीरे बिलकुल लोप कर देंगी, निस्सन्देह उन्नति धीरे-धीरे होगी। और वभी २ आगे बढ़ कर पीछे भी हटना पड़ेगा परन्तु हमें अपनी भारी सफलता का पूर्ण विश्वास रखना चाहिये। ओर सब प्रकार की कठिनाइया पडने पर भी हम को दृढ़ रहना चाहिये। हमारी राजनीति की यह साधारण कहावत है कि भारतीय जाति का भविष्य उस समय तक अधकारमय रहेगा जब तक दोनों जातियों के सार्वजनिक मामलों में एकना ओर मेल के भाव दृढ़ न हो जाय। आप एक दूसरे से जितने ही अप्रसन्न क्यों नहीं, पर उपर्युक्त कथन की सत्यता से

कभी इन्कार नहीं कर सकते । हम में से कुछ लोग हिन्दू और मुसलमानों में मेल कराना अपना कर्तव्य समझते हैं उनके लिए इसके सिवाय और कोई ढंग नहीं है कि वे यथा शक्ति ऐसी झगड़ालू बहसों से बिल्कुल दूर रहें, जो दोनों जातियों में द्वेष पैदा करती हैं । उन्हें स्वयं भी सहनशीलता की भावना डालना चाहिये और दूसरों को भी ऐसी ही सम्मति देना चाहिये ।

माननीय गोखले ने कहा कि इस मामले में हिन्दुओं पर विशेष दायित्व है, क्योंकि शिक्षा के विचार से यह दूसरी जाति से आगे बढ़े हुए हैं । और इसी कारण से ये जातीयता को बढ़ती हुई आग्रह्यकताओं को ज़ियादा अच्छी तरह समझ सकते हैं । यदि कुछ संज्ञा मुसलमानों की शिक्षा तथा, उन्हीं के हितार्थ अन्य कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें, तो सन्देह नहीं कि दोनों जातियों में मेल की मात्रा बढ़ने लगेगी । सम्भव नहीं कि धीरे-२ इस कार्य का आवरण न हो, बरन् वर्तमान अविश्वास और पापकर्म की जगह पर परस्पर सहनशीलता और विश्वास के प्रचार होने में भी उपयुक्त कार्य से बहुत कुछ सहायता मिलेगी—

इस प्रकार विषय के सामान्य अंश पर विचारों को प्रगट करने के बाद माननीय गोखले ने उस बहस के सम्यन्ध में कथन आरम्भ किया जो पिछले ६ महीने से चल रही थी । आपने कहा कि उत्तेजना का एक बड़ा कारण तो यह है कि जन साधारण ने नये सुधारों की असलियत और विस्तार के समझने में भूल की है । आपने इस विषय में अपनी सम्मति का स्पष्ट वर्णन किया । उन्होंने कहा कि कम संख्या वाली

जातियों को प्रतिनिधि भेजने और पृथक् निर्वाचन करने के अधिकार देने के पक्ष में मैं सदा रहा हूँ। परन्तु मेरी सम्मति है कि जिन स्थानों की कोई विशेष जाति अधिकारिणी हो, उनकी पूर्ण अलग चुनाव से न होना चाहिये बल्कि पृथक् निर्वाचन में केवल वह कमी पूरी होनी चाहिये जो समाधारण द्वारा चुनाव में गयी रह गई है। अर्थात् यदि किसी जाति के प्रतिनिधियों की एक विशेष सख्या नियत हो, तो पहले सर्वसाधारण द्वारा चुनाव हो। इस चुनाव में उस जाति का भाग होगा ही। यदि पूरा चुनाव हो चुकने पर प्रतिनिधियों की नियत सख्या उस जाति की नहीं है तब विशेष अधिकार मिले हैं, तो इस कमी को केवल वह जाति ही प्रतिनिधि चुन कर पूरा करेगी। इसी के साथ ही मैं मुसलमानों के सिवाय अन्य छोटी सख्या वाली जातियों को भी आवश्यकता पड़ने पर यही अधिकार मिलने के पक्ष में रहा हूँ। देश की भाषा भला और सार्वजनिक जीवन के विकास के लिये परम आवश्यक है कि पहले सर्वसाधारण द्वारा चुनाव हुआ करे, जिसमें धर्म और मजहब का विचार छोड़ सब जातियाँ एक ही प्रकार से भाग लें। पर यदि कोई छोटी सख्या वाली जाति ऐसी रह जाय जिसे सर्वसाधारण के चुनाव में अपना उचित और पूरा हिस्सा न मिल सका हो, तो उसे अपने प्रतिनिधियों की सख्या पूरी करने के लिये अलग और विशेष चुनाव करने का अधिकार होना चाहिये। मैंने पिछले मार्च के महीने में यही विचार बड़ी व्यवस्थापक सभा में प्रकट किये थे। यद्यपि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ने मुझे बुरा मला कहा तो भी मैं अभी तक अपनी पहिली सम्मति पर स्थिर हूँ। अर्थात् देश की

मैं उस समय जब मैं इस पदार्थ नियुक्त हुआ था मदगास
 आसका। परन्तु यह अन्त्रा ही हुआ क्योंकि उस समय क
 पेसी न थी कि जो लोग बाहर से आते, ने कुछ परिचित
 अनुभव करते। अतः मैं उस परिवर्तन पर लक्ष्य रख न
 आया हूँ और आशा करना हूँ कि यहाँ मैं अपने मित्रों से पर
 मर्श कर सकूँगा। मुझे गेड है कि मैं अत्रकाश की स्थूलता के
 कारण उन स्थानों पर न जा सकूँगा, जहाँ पर लोगों ने घड़ी
 रूपापूर्वक मुझे निमन्त्रण दिया है और जहाँ मैं स्वयम् जाना
 पसन्द करता हूँ। परन्तु मैं आशा करता हूँ कि ऐसा अवसर
 फिर मिलेगा, जब मैं इस प्रान्त में लम्बा प्रवास कर सकूँगा।
 बहुरि यों कहिये कि मैं नेशनल कांग्रेस के भाग्य के साथ
 ही साथ डोलता फिरता हूँ। मेरे सार्वजनिक जीवन और
 कांग्रेस की आयु एक ही साथ आरम्भ होती है। गत कुछ
 वर्षों में मुझे भारतवर्ष के भिन्न-७ प्रान्तों की गटनाओं और
 विचारों से परिचित होने का सुअवसर मिला है और मैंने
 एक बात निश्चय रूप से देगी है, वह यह है कि भिन्न-७ प्रां
 और नेताओं के व्याख्याना में तथा राजनेतिक आन्दोलन
 विषयक साधारण बातचीत में मैं निराशा की एक सूक्ष्म रेखा
 बराबर देखता हूँ। ऐसा बोलना होता है कि राष्ट्रीय विचारकों
 के विभाग में एक प्रकार की निराशा घुसनी जाती है। जनता
 खुले गजाने अथ पृष्ठने लगी है कि कांग्रेस ने इन उन्नीस वर्षों
 में क्या किया? कोई इसी प्रश्न को फेर कर यों पृष्ठते है कि
 क्या कांग्रेस इसी प्रकार काम करके कुछ वास्तविक लाभ
 पहुँचा सकेगी? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो और भी बढ़कर
 उस राजनेतिक आन्दोलन को जिसमें हमलोग लगे हुए हैं,
 निरर्थक बतलाने का उद्योग करते हैं। उनका कथन है कि

ससार के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण देने में नहीं आता जिसमें हम लोगों के राजनैतिक आन्दोलन के समान कोई भी उद्योग, आन्दोलनकारियों को कुछ भी लाभ पहुँचा सका हो, उन लोगों का यह उद्देश है कि राजनैतिक भ्रष्टों को डोढ़ यदि आयोगिक आन्दोलन किया जाय तो देश को विशेष लाभ होने का सम्भावना है। इन बातों से आप कुछ भी परिणाम निकालें, पर इतना निश्चय है कि हमलोगों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास शन २ परन्तु निश्चय रूप से राजनैतिक आन्दोलनों की ओर से पिच रहा है।

अब यदि इस नेराण्य का कोई वास्तविक कारण है तब तो भविष्य अवश्य ही अन्धकारमय समझना चाहिये। परन्तु मैं प्रश्न करता हूँ कि क्या सचमुच ही यह न्यायसंगत है ? यह प्रश्न मैं आप लोगों से उसी प्रकार करता हूँ जैसे मैं कभी अपने आप से हताश होने पर किया करता हूँ। यह प्रश्न अभी हल होगा जब आप गीर और निरद्वेग होकर इसकी भीमासा करेंगे। इसमें आपको दो तीन बातें अपने आप से पूछनी होंगी। पहिली बात यह है कि राजनैतिक चर्चा चलानेवाले जन्मदानाओं का क्या विचार और मन्तव्य था ? उनके हृदय को उथल पुथल करनेवाली आशाएँ और लालसाएँ कौन २ सी थीं ? दूसरी बात विचार करने के योग्य उस समय की अवस्था है जिस समय इन राजनैतिक विचारों का जन्म हुआ था, तथा अन्त में यह देखना होगा कि इस समय कैसी अवस्था में इस काम को करना होगा तथा उस समय से आज की अवस्था में क्या २ फेर बदल हुआ है। इन प्रश्नों को आप पहले हल कर लें, इन्हीं के द्वारा आप अपनी राजनैतिक स्थिति का ज्ञान भी प्राप्त कर सवेंगे।

पहले प्रश्न, अर्थात् राजनेतिक विचारों के जन्मदाताओं के क्या २ विचार थे ? उनकी आशाएं और लालसाएं क्या थीं ?- का उत्तर अधिक नहीं दूना होगा । उन महापुरुषों का उद्देश्य शासकों और प्रजा के बीच में बराबरी करने का था अर्थात् शासकों के विचारों को प्रजा पर विहित कर देने तथा प्रजा के कष्टों की पुकार को शासकों के कानों तक पहुंचा देने ही का था ? राजनेतिक आन्दोलन का यह पहिला भाग है और यह व्यूनाधिक सकलता के साथ सम्पादित भी हो रहा है तथापि मैं यह अवश्य ही कहूंगा कि इसमें अभी उन्नति करने का मैदान खाली है । परन्तु इससे भी ऊपर उनका उद्देश्य उन जटिल प्रश्नों को हल करने का था जिस पर हम लोगों के देश का भविष्य निर्भर है । उनकी लालसाएं थीं कि वह हाजिकारक नीति और कायदे कानून जिनके कारण हमारी पूरी उन्नति नहीं होने पाती, दूर करें और ब्रिटिश प्रजा के पूरे स्वत्वों को जो इस समय केवल नाम के लिये हमें मिले हैं, प्राप्त करें । यही हमारे राजनेतिक आन्दोलन का दूसरा परन्तु सर्वश्रेष्ठ भाग है । इसी प्रश्न के साथ अद्वन्द्वन खड़ी होती है, और वे विचार जो प्रायः राजनेतिक सकलता के विषय में सुनने में आते हैं, इसी प्रश्न के अन्तर्गत हैं ।

। सज्जनों ! अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर विचार करें, जिस समय यह कार्य आरम्भ होनेवाला था उस समय की अवस्था क्या थी और हमारे पूर्व कार्यकर्त्ताओं को किन २ अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ा था और हम लोगों को, जो उनके कार्य को आज कर रहे हैं क्या अनुभव करना है ? हम लोगों की एक ओर जाति उन्नति, अनन्य अधिकार और सच्चा, दूसरी ओर भयानक अज्ञानता, भ्रम, और प्रजिघ्रता का

दलदल है। इन दोनों असमान शक्तियों के बीच में हम लोगों का कार्य करना है, हमें इन शक्तियों का सामना करना है और उन शक्तियों को जो हम लोगों के विरुद्ध जमी है, दबा कर विजय पाना है तथा जल्दी-जल्दी किसी प्रकार उस बड़े जन समूह को आ सो रहा है, जागृत करके कार्यक्षेत्र में उत्साह पूर्णक प्रवृत्त कराना है। सज्जना ! आप स्वयं विचारें कि यह कैसा दुष्कर काम है। हम लोगों को इस बात की आशा करने का कोई कारण नहीं कि एकाधिकार या दुर्गम दुर्ग पहले ही हमारे में टूट जायगा। अथ यदि इस द्वार ने हम लोग निराश हो बैठें तो यह हमारा ही दोष है और किसी का नहीं। सज्जना ! स्मरण रहे कि जिन लोगों से हमें सामना करना है, आर जिनके हाथ में अधिकार की अविच्छिन्न धार-डोर है, शासन की पूरी शक्ति उनकी सहायक है। अस्तु, इसके स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं कि हमारा सामना करनेवाले चुने हुए विश्व पुरुष हैं, और उन लोगों के व्यक्तिगत गुण हमसे कहीं बड़े चढ़े हैं, उनका वर्तव्य, देशप्रेम, राज भक्ति, सम्मिलित होकर कार्य करने की शक्ति और कानून की पारन्दी इत्यादि गुण अनुलनीय हैं। वे जानते हैं कि अपने स्वार्थों का प्राप्त करने के लिए किस प्रकार उद्योग करना चाहिये। हम उनके वास्तविक गुणों के स्वीकार करने में लज्जा नहीं। बल्कि यदि हम लोग राजनैतिक कार्यों के सच्च सद्गुणों को जानते हैं तो आज ऐसे प्रतिरोधियों को पाकर हम अपने को अन्य मानते हैं। हम लोगोंको इस बात पर प्रसन्नता प्रगट करनी चाहिये कि हमारे सामना करनेवाले ऐसे गुणों से भर पूरे हैं। निराश होने के बूले हम लोगों को अपनी द्वार पर प्रसन्न होना चाहिये और सोभाग्य समझना चाहिये

कि हमें ऐसे विराधिया से सामना करना है, और ईश्वर की कृपा समझना चाहिये कि हम लोगों को सामना करने के लिए ऐसे शक्तिवानों से काम पड़ा जिनसे सामना बर्क हम भविष्य में दृढ़ और बलवान बन सकते हैं। उस बड़ी जनता को जिसका जिक्र मने ऊपर किया है और जो दूसरे दल में शामिल है, उत्तेजित करना, जीवन देना और अपने साथ ले चलना अत्यन्त कठिन काम है। अतएव यह काम निःसंशय होने ७ होगा ही, और ऐसा ही हो भी रहा है। मेरा असल मतलब इन दो दलों के वर्णन करने से यह है कि जिसमें आप लोग इस कार्य की गुम्ता और दुःसाध्यता को समझ लें और देख लें कि हम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कठिनता का भली प्रकार अनुभव कर लें, और अपने उद्योग की माप करें कि कितना कार्य करने पर कितनी सफलता प्राप्त होती है, तब मैं विश्वास करता हूँ कि आप निराश न होकर कार्य करेंगे और उन बातों पर जो आप इसके विषय में सुना करते हैं, ध्यान न देकर कार्य-साधन में तत्पर रहेंगे।

महाशयो ! ध्यान रहे कि कांग्रेस कैबल गत उन्नीस वर्षों से ही काम कर रही है। परन्तु यदि आप अपने कामों की गणना करेंगे, जो मेरे समझ में अपेक्षित दर्जे से कहीं कम है और साथ ही उनके फलों का विचार करेंगे तो मुझे आशा है कि आपको हताश होने का कोई कारण नहीं रह जायगा। प्रश्न यह है कि इन १६ वर्षों में क्या सफलता हुई? यदि आप अपने नेत्रों को अपनी सफलता की ओर फरेंगे तो देखेंगे कि कुछ सफलता तो ऐसी हुई है, जिसको भूल जाना अममकाय है। हम

लोगों का पहला आन्दोलन सिविल-मर्चिस की परीक्षा में उमर को बढ़ाने के विषय में था और हम लोग के प्रयत्नों से उमर १६ वर्ष के बजाय २३ वर्ष की गई। हम लोगों का दूसरा आन्दोलन लेजिस्लेटिव कांसिल के हकों को बढ़ाने का था, और हम लोग इसमें भी सफलमनोरथ हुए। हम लोगों की कौन्सिलें अब १६, १७ वर्ष पूर्व की कौन्सिलें नहीं रहीं। अब इन के विचार परिपक्व और पूर्णरूप से होते हैं, हा इसमें सन्देह नहीं कि अभी बहुत कुछ उन्नति इसमें हो सकती है और हम लोग को काम करने की जगह भी है परन्तु कुछ नहीं से कुछ होता ही अच्छा है।

महाशयो, यह काम बिलकुल ऐसे नहीं कि जो गिनती के योग्य न हों। दूसरी बात देखिये कि हम १५ या २० वर्षों के भीतर देश के प्रेसों की उन्नति के दृढ़ कारण हो रहे हैं, ये बातें पहले कदापि नहीं थीं। आज एक समाचारपत्र दूसरे के साथ मिलकर देश की उन्नति में भारी सहायता पहुँचा रहा है। आपके प्रस्ताव जो कांग्रेस में पाम होते ह, जनता के हाथों में पहुँचकर निरन्तर शासकों पर दबाव डाला करते हैं और सर्वसाधारण भी उन्हें इन समाचारपत्रों के कालमों में पढ़ कर समझ लेते ह। कांग्रेस के राजनैतिक आन्दोलन प्रतिदिन इन प्रेसों के द्वारा चारों ओर फैला जा रहे ह। प्रेसों को यह स्वत्व भी कांग्रेस के द्वारा ही मिला है। और भी देखिये कि देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों के मनुष्य एक दूसरे से मिलेजुले मालूम होते ह। अब हम लोग पन्द्रही राष्ट्रीय विचारों से भरे दीख पड़ते ह। पन्द्रही निराशा और सफलता अब हम लोगों को एकही राग रलाती और हसाती है। सक्षेप में इन लक्षणों का अर्थ यह है कि अब राष्ट्रीयता बढ़ रही है। इन कुल बातों

का श्रेय कांग्रेस को ही है। पन्द्रह सोलह वर्षों में इतने कम ङयोग पर भी इतना काम करना क्या कम है ? भाइयो ! मेरे विचार से नौ राजनैतिक विषय में निगूण होने की कोई बात ही नहीं।

परन्तु मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि इधर कुछ दिनों से राजनैतिक आन्दोलनों में अटकने बढ़ गई है। कांग्रेस की नींव जमजमाने के कारण प्रान्तिक राजनैतिक सम्मेलनों पर धक्का पड़ रहा है। कांग्रेस होने के कारण अनेक सार्वजनिक गूढ़ समस्याएँ भी प्रान्तिक हो चली हैं। राजनीतिज्ञ लोग पहले के समान प्रान्तिक विषयों में ध्यान नहीं देते। इन बातों को मैं मुक्तकण्ठ से अवश्य स्वीकार करूँगा। और साथ ही साथ एक बात और देखने में आती है यह है कि हमारे प्रतिरोधियों में एकता और भी बढ़ गई है और हमारी बातों का प्रतिवाद अब और जोरों से होने लगा है। कांग्रेस के पहले अंग्रेज लोग प्रायः हमारी लालमाओं के साथ चाह्य सहानुभूति दिग्वला दिया करते थे परन्तु अब, जब उन लोगों ने देखा है कि हम लोग मिलजुल कर अपने अभीष्ट के लिये उद्योग कर रहे हैं, तब से कुछ इने गिने ही अंग्रेज हम लोगों का हाथ बढ़ाया चाहते हैं। इसके अतिरिक्त शासकों की जाति में शासन का कुछ अभिमान सा पैदा हो गया है, जिससे हमारी कठिनाइयाँ और बढ़ रही हैं।

हम लोगों की कठिनता इस सर्कीर्ण सामाजिक जोश के कारण और भी बढ़ गई है। यह वह सार्वभौमिक साम्राजिकता नहीं, जिसमें साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिये काम होता था बल्कि इससे केवल जाति विशेष के लिये ही हक माने जाते हैं। मैं गुल कर इसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, महाशयगण स्वयं समझ लेंगे। इसी सर्कीर्णता के

कारण हमारे कामों में अनेक विघ्न पड़ते जाते हैं। परन्तु य अडचनों कुछ ऐसी नहीं, जिन्हें लिये अधिक चिन्ता की कुछ बात हो। इन सबों का आशय केवल इतना ही है कि हम लोग अपने परिश्रम को छिगुण कर दें और अपने कामों में अधिक जीवन प्रदान करें और आक्रमणों का सामना करें।

बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो बहस करते हैं कि राजनीति आन्दोलन से कुछ लाभ नहीं, और इतिहास में कोई घटना इस प्रकार की नहीं जिसमें यह दिगदर्श पड़े कि किसी ने कभी ऐसे आन्दोलनों से कुछ भी लाभ उठाया है, तथा व्यवसायिक आन्दोलन ही सब कुछ है। 'मेरे मित्र मिस्टर चौधरी ने प्रगल्भ प्रान्तिक कांग्रेस के समापति के आला से जो व्याख्यान दिया है उसके कुछ अंश की तो मैं गुले दिल से प्रशंसा करता हूँ, परन्तु उसका कुछ अंश मेरी समझ में नहीं आता। उक्त कथन है कि शासित प्रजा को राजनीतिक विषयों में कोई अधिकार नहीं। ये उन अर्ध-सत्य बातों में से हैं, जो भूढ़ से भी बढ़ कर भयानक हैं। यदि 'राजनीति' का सङ्कुचित अर्थ देशों के परस्पर व्यवहार सम्बन्धी राजनीति से ही हो, तब तो मि० चौधरी की बात अवश्य ठीक है, नहीं तो यदि राजनीति का विस्तृत अर्थ देश-सम्बन्धी राजनीति से है, जिसे अर्थ में मैं राजनीति शब्द को जानता हूँ—तब तो प्रजा राष्ट्रों को अपने राजनीतिक विषयों में शासक राष्ट्रों के समान ही, बरिष्ठ अधिकार अधिकार है। तुमको एक प्रगल्भ जाति की उन्नति के विरुद्ध लड़ना है, तुम्हें उन अधिकारों में भाग लेना है, जिन्हें उन लोगों ने एकदम अपना रक्खा है, और जो तुम्हारे लिये बढ़ हैं। ये सब कार्य राजनीतिक हैं। अतएव आप लोगों को इस प्रकार के पक्षपात में पड़ कर भूल कर बैठना ठीक नहीं। अब रही

का श्रेय कांग्रेस को ही है। पन्द्रह सोलह वर्षों में इतने कम ढ़ागों पर भी इतना काम करना क्या कम है ? भाइयो ! मेरे विचार में तो राजनैतिक विषय में निराश होने की कोई बात ही नहीं।

परन्तु मैं इस बात को भी नहीं भूला सकता कि इधर कुछ दिनों से राजनैतिक आन्दोलनों में अडचन बढ़ गई है। कांग्रेस की नींव जमजाने के कारण प्रान्तिक राजनैतिक सम्मेलनों पर उधा पड़ चुका है। कांग्रेस होने के कारण अनेक सार्वजनिक गृह समस्याएँ भी प्रान्तिक हो चली हैं। राजनीतिज्ञ लोग पहले के समान प्रान्तिक विषयों में ध्यान नहीं देते। इन बातों को मैं मुक्तकण्ठ से अग्रय्य स्वीकार करूँगा। और साथ ही साथ एक बात और देखने में आती है वह यह है कि हमारे प्रतिरोधियों में एकता और भी बढ़ गई है और हमारे यानों का प्रतिघाट अब और जोरों से होने लगा है। कांग्रेस के पहले अंग्रेज लोग प्रायः हमारी लालसाओं के साथ बाह्य सहानुभूति दिखला दिया करते थे परन्तु अब, जब उन लोगों ने देखा है कि हम लोग मिलजुल कर अपने अभीष्ट के लिये उद्योग कर रहे हैं, तब से कुछ इने गिने ही अंग्रेज हम लोगों का हाथ बढ़ाया चाहते हैं। इसके अतिरिक्त शासकों की जाति में शासन का कुछ अभिमान सा पैदा हो गया है, जिससे हमारी कठिनाइयाँ और बढ़ रही हैं।

हम लोगों की कठिनाता इधर संकीर्ण सामाजिक जोश के कारण और भी बढ़ गई है। यह वह सार्वलौकिक साम्राज्यवाद नहीं, जिसमें साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिये काम होता था, बल्कि इससे केवल जाति विशेष के लिये ही हक माँगे जाते हैं। मैं खुल कर इसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, महाशयगण स्वयं समझ लेंगे। इसी संकीर्णता के

कारण हमारे कामों में अनेक विघ्न पड़ते जाते हैं। परन्तु य अडचनों कुछ ऐसी नहीं, जिनके लिये अधिक चिन्ता की कुछ बात हो। इन भयों का आशय केवल इतना ही है कि हम लोग अपने परिश्रम को द्विगुण कर दें और अपने कामों में अधिक जीवन प्रदान करें और आक्रमणों का सामना करें।

बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो बहा करते हैं कि राजनैतिक आन्दोलन से कुछ लाभ नहीं, और इतिहास में कोई घटना इस प्रकार की नहीं जिसमें यह दिखलाई पड़े कि किन्नी ने कभी ऐसे आन्दोलनों से कुछ भी लाभ उठाया है, तथा व्यवसायिक आन्दोलन ही सब कुछ है। मेरे मित्र मिस्टर चौधरी ने बंगाल प्रान्तिक कान्फरेन्स के सभापति के आसन से जो व्याख्यान दिया है उसके कुछ अंश की तो मैं खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ, परन्तु उसका कुछ अंश मेरी समझ में नहीं आता। उनका कथन है कि शासित प्रजा को राजनैतिक विषयों में कोई अधिकार नहीं। ये उन अर्थ सत्य बातों में से हैं, जो भूठ से भी बढ कर भयानक हैं। यदि 'राजनीति' का सङ्क्षिप्त अर्थ देशों के परस्पर व्यवहार सम्बन्धी राजनीति से ही हो, तब तो मि० चौधरी की बात अग्रगण्य ठीक है, नहीं तो यदि राजनीति का विस्तृत अर्थ देश सम्बन्धी राजनीति से है, जिस अर्थ में मैं राजनीति शब्द को जानता हूँ—तब तो प्रजा राष्ट्रों को अपने राजनैतिक विषयों में शामक राष्ट्रों के समान ही, बल्कि अधिकार है। तुमको एक प्रधान जाति की उन्नति के विरुद्ध लड़ना है, तुम्हें उन अधिकारों में भाग लेना है, जिन्हें उन लोगों ने एकादम अपना रक्खा है, और जो तुम्हारे लिये बढ है। ये सब कार्य राजनैतिक हैं। अतएव आप लोगों को इस प्रकार के पक्षाभास में पड कर भूल कर बैठना ठीक नहीं। अब रही

औद्योगिक उन्नति की बात, सो मुझे इसके साथ पूरी सहानुभूति है परन्तु मैं यह जानता हूँ और आप लोगों को स्मरण भी दिला देता हूँ कि इस प्रकार के आन्दोलन की एक सीमा है, जिसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। आप विश्वास करें कि जब तक आपको अपने देश के शासन में अधिकार नहीं होगा, आप व्यय के विषय में चोल नहीं सकेंगे, तब तक आप उस ओर कोई उन्नति नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूँ कि जहाँ महाशय आप को आज केवल औद्योगिक उन्नति के लिये बहका रहे हैं, ओर राजनैतिक आन्दोलन से एकदम हटाना चाहते हैं वेही दस धर्य के बाद हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायेंगे और कहेंगे कि 'दुविधा में दोनों गये माया मिले न राम'। मैं यह नहीं कहता कि देश में इतने ही राजनैतिक कार्यों से काम चल जायगा, बल्कि मेरा कहना यह है कि परिश्रम प्रतिदिन बढ़ाते जाना चाहिये। पिछले कार्य घृणा करने के योग्य नहीं और न उनकी प्रणाली ही दोषयुक्त है। मैं यह नहीं कहता कि हमको राजनैतिक आन्दोलन की वर्तमान अवस्था पर ही सतोष करना चाहिये। मुझे स्वयम् वर्तमान दशा पर असतोष है। परन्तु इसके लिये हमें उद्योग करना चाहिये। हम लोगों का कर्तव्य यह है कि वर्तमान मार्गों को सुनें, और अपने कार्य में नवजीवन और ओज की वृद्धि कर उसे पूरा करें। हम लोगों का सार्वजनिक जीवन शक्तिहीन और निर्जीव है क्योंकि यह ओजहीन है। बहुत ही कम लोगों को अपने कार्यों में विश्वास है, और जिसका परिणाम यह होता है कि मनोवाछित सफलता प्राप्त नहीं होती। हम लोग सभी कोई जापान की सफलता की प्रशंसा करते हैं, और बहुतेरे उसका इतिहास भी पढ़ते हैं। मैं खुद ही उसकी

बहानियों को आदर्श धमाना चाहता हूँ। मैं उस में क्या पाता हूँ। अच्छा सुनिये, प्रथम तो उस देश में अति यत्नान जाती यता पाई जाती है, यह जापान की अपनी वस्तु है, यह पाश्चात्य देशों से उधार नहीं लाई गई है। ऐसा राष्ट्रीय प्रेम शनै २ उन्नति का अङ्कुर है, इसके अतिरिक्त एक बात और भी मेरे देखने में आती है और वह वहा के नेताओं का सम्मान है। वहा नेताओं की बातें जनता बड़े दृढ़ भाव से धारण करती है। मेरे विचार से जापान की उन्नति के मूलमंत्र यही दोनों हैं। नेता लोग काम करने का मार्ग बतला देते हैं और सर्व साधारण धैर्य के साथ उस काम को करते चले जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग की एकाग्रता का महत्त्व समझ कर सब जातियाँ ने मिल कर काम किया और यही कारण है कि वहा के लोगों ने अपने पुराने बख्यों को छोड़ कर शीघ्र ही नये परिधान को ग्रहण कर लिया।

यह एक भारी उपदेश हम लोग जापान से ग्रहण करने हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप सफलमोर्ख हों तो आप एकत्र होकर कार्य करें। हिन्दुस्तान में जापानी नेताओं के जोड़ के एकही आदमी फीरोजशाह मेहता हूँ, परन्तु ऐसे लोगों की आशाएँ शिक्षित जनता को आर मूढ़ पर माननी चाहिये बिना इसके नेता योग्य होते भी कुछ कर नहीं सकेंगे। विविध प्रश्नों पर स्वयम् विचार करना भी घुरा नहीं परन्तु जहा उद्योग की एकाग्रता आवश्यक है वहा अपने को उस मनुष्य के आधीन किये जिना जिमकी योग्यता सर्वमान्य हो, काम चलने का नहीं। सार्वजनिक जीवन में नियमों की पाबन्दी और भी आवश्यक है। अतएव नेताओं को भी अपने उत्तर दायित्व का विचार सदा ही करते रहना जरूरी है।

महाशयो, अथ वे दिन गये, जय राजनीति एक मन पर लाने की सज्ज थी, अथ इस देश का राजनैतिक प्रयत्न प्रति दिन बढ़ता जाता है अतएव इस मैदान में आनेवालों को केवल इसका ही व्यवसाय करना होगा, जैसे मनुष्य अपनी जीविका निर्दिष्ट करके उसी में अपनी सारी शक्ति लगा देता है वैसेही अब राजनैतिक विषय को भी अपनी जीविका समझ कर पूर्ण उद्योग करना होगा। इस काम के लिए हम लोगों को उस समाज की ओर देखना पड़ता है, जहाँ से लेजिसलेटिव कांसिल के मेम्बर लोग चुने जाते हैं। मैं इन सदस्यों में से प्रत्येक से यह आशा नहीं रखता कि वे लोग अपना व्यवसाय एक डम छान्दकर इस काम को उठाएँ, परन्तु प्रत्येक प्रान्त से एक-एक ऐसे मनुष्यों का निकाल लेना जो अपना कुल समय नहीं तो कुछ समय तो अवश्य राजनैतिक विचारों के पुष्ट करने में बितावें, उचित है। इन्हीं मनुष्यों को राजनैतिक केन्द्र बना कर हमारे नवयुवकगण कार्य आरम्भ करेंगे और नवीन राजनैतिक जीवन का उच्चतम आदर्श तैयार होने की सम्भावना है। मैं अथ नर दो तीन बातें टीक कर सका हूँ। हम लोगों की स्थिति में कहीं भी बातें ऐसी नहीं, जिससे निराशा हो। जैसा मनुष्य जो दूसरों को हताश करने के उद्योग में लगे है या इन प्रकार के शत्रु जैसा हमने ऊपर कहा है, प्रयोग करने है वे देश के शत्रु हैं, स्वयम् को कुछ करते नहीं चित्त। दूसरा के उत्साह का भी भग्न करते हैं।

जैसा कहा जाता है कि इतिहास में शासित जातियों की उन्नति इस प्रकार होती नहीं चुनी गई है। परन्तु महाशयो! मैंने स्वयम् इतिहास का अध्ययन किया है और जो कुछ मैंने

देखा है, वह यह है कि तुम किसी भी घटना से ठीक ठीक मेल खानेवाली कोई दूसरी घटना इतिहास में नहीं पा सकने ।

लोग कहते हैं कि इतिहास बारम्बार अपनी घटनाओं को दुहराता है परन्तु शायद कोई भी घटना ऐसी नहीं, जो वास्तव में फिर कभी उसी रूप में घटित हो । ऐसा सम्भव है कि कोई शासित जाति आन्दोलन से उन्नत न हुई हो परन्तु इससे क्या ? हम लोगों का ही उदाहरण सब से प्रथम ससार के इतिहास में दर्ज होगा । ससार के इतिहास का तो अभी अन्त नहीं हुआ है, कितने ही परिच्छेद इसमें अभी जोड़े जायेंगे । अतएव हम लोगों को हताश कदापि न होना चाहिये ।

मैं आप लोगों को अधिक देर तक ठहराना नहीं चाहता । इस समय की सब से आवश्यक बात यह है कि आप लोग अपने कार्य में विश्वास रखें और अधिक आत्मत्याग करने को भी प्रस्तुत रहें । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ दिनों से प्रति प्रातः शक्तियों का जोर कुछ बढ़ गया है । कई प्रतिघातक कानून जिनके पास न होने के लिये देश भर ने सम्मिलित होकर प्रयत्न किया था, पास हो गये । बहुत से भारी पदाधिकारियों के सम्भाषण कुछ ऐसे हुए हैं, जिनसे देश में अशान्ति सी फट गई है । मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब बिगड़ पाधाएँ शीघ्र दूर हो जायगी और जितना काम करेंगे उसके अनुसार फल भी अवश्य ही पावेंगे । हम लोगों का आन्दोलन ऐसा है, जिसमें सभी कोई कुछ न कुछ काम अवश्य कर सकते हैं । जिनके पास धन है वह धन से, जिन्हें अवकाश है वे समय से और जिनमें योग्यता है वे अपने परिश्रम के द्वारा सार्वजनिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं । नवयुवकगण परिश्रम

करके उपदेशकों का काम कर सकते हैं। मैं इन कामों के लिए युवकों को ही चाहता हूँ जो अपने धृष्टों से उपदेश ग्रहण कर सकें। और बिना किसी ठाटबाट के जनता के सम्मुख जाकर काम करें। अगर हम लोग सभी को ई अलग अलग अपना काम करें तो हम लोगों का यह उद्योग एक न एक दिन राज नैतिक स्वतन्त्रता पाकर ही बंद होगा। इस ओजपूर्ण आन्दोलन के सम्मुख हम लोगों की साधारण और तुच्छ विभिन्नता और मतभेद सब अवश्य ही लोप हो जायेंगे। सब कगड़े मिट जायेंगे। हम लोगों का विश्वास सूर्य की तरह चमक उठेगा। आत्मत्याग के लिए हम कटिबद्ध हो जायेंगे। देश और जाति के कदम आगे की बढ़ेंगे और उस अभीष्ट फल को हम हस्तामलक कर लेंगे जो हम लोगों का दिवा मनन और रात्रि स्वप्न रहा है।

भारतवर्ष के प्रति-इंगलैण्ड का कर्तव्य ।



१५वीं नवम्बर १९०५ को इंगलैण्ड के 'नेशनल लिबरल क्लब' में मि० गोखले ने यों कहा था .—श्रीमन् महानुभावों तथा महिलाओं ।

आज इस सभा ने मुझे भारतवर्ष के विषय में कुछ सुनाने के लिये निमन्त्रित कर अनुगृहीत किया । भारतवर्ष के राज-नैतिक सुधारक एक प्रकार आपके लिबरल दल के सहयोगी हैं क्योंकि हमलोग हिन्दुस्तानमें जिन सत्ताओं की अभिलाषा करते हैं, वेही आप लोगों के दल को भी स्वीकृत है । शान्ति, सुधार और मित्रव्ययिता ही हम लोगों का मूल मन्त्र है, हम लोग भी आप लोगों के ही तरह उन हकों का द्वार जो आज कुछ इने गिने लोगों ने हथिया रखा है, सर्वसाधारण के लिये खोल देने तथा सर्वसाधारण के ऊपर एक समाज विशेष के प्राबल्य को उठा देने के उद्योग को ही अपना प्रधान कर्तव्य मानते हैं ।

महाशयगण ! मैंने सहयोगी शब्द का व्यवहार सकुचित रूप से यहा किया है, उसका अर्थ यहां एक ही कार्यक्षेत्र में कार्य करनेवाले से है, एक ही साधना के लिये अनेक काम करनेवालों से नहीं । हम लोग वस्तुतः आपके दल के सहयोगी कहे जाने के योग्य नहीं क्योंकि हम नि सहायों के पास हूत

जता तथा प्रेम के अतिरिक्त और क्या है, जिसका भेंट आप लोगों की कृपा के बदले दिया जाय। और यह प्रतिफल बहुतों को आपसों में अत्यन्त तुच्छ भी जेंचेगा तथापि मुझे आशा है, नहीं, नहीं, विश्वास है कि और कुछ नहीं तो कम से कम हमलोग स्वराज्य का अपील सुनाते समय आपके दिल से सहानुभूति की भिक्षा तो अवश्य पा सकेंगे।

सभ्य महिलाओं और महाशयों! प्रायः एक सौ वर्ष से 'इंग्लैण्ड' ओर भारतवर्ष का भाग्य एक सूत्र में गुंथा हुआ है, आप लोगों ने क्योंकर भारतवर्ष को अपने शासन में सम्मिलित किया है, इसकी विवेचना करने का समय और आवश्यकता यहाँ नहीं, परन्तु मैं अपने देश की ओर से दो बातें निवेदन करूँगा, जिनमें पहली तो यह है कि यद्यपि हमलोग विदेशियों के आधीन हैं तथापि केवल परतंत्रता के कारण ही हम लोग उन अर्धशिक्षित वा अशिक्षित जातियों की नाईं जिन्हें आप लोगों ने जीता है, स्पर्धा किये जाने के योग्य नहीं। भारतीय राष्ट्रप्राचीनतम है जिसकी सभ्यता यूरोपियनों की सभ्यता शब्द के अर्थ समझने के बहुत पहले ही चर्मसीमा तक पहुँच चुकी थी। मेरा भारतवर्ष ससार के बड़े २ वर्गों की जन्मभूमि है। साहित्य, साख्य, विज्ञान, शिल्प इत्यादिने इसकी भूमि को बहुत दिनों तक अपना क्रीड़ा स्थल बना रखा था, परन्तु ईश्वर सारी निधि एक ही को नहीं देता, और भारतवर्ष भी पुरातन समय में स्वतन्त्रता देवी के प्रेम से, जिसके लिए पाश्चात्य देश जिब्बात है, चञ्चित रखा गया। तथा इसने अचेतनिक सत्ताओं की भलाइयों को नहीं समझा। दूसरी बात यह है कि केवल इन्हीं कारण से कि भारतवासी विदेशियों के आधीन हैं, सिद्ध नहीं होता कि इनमें सामरिक भाव की न्यूनता है। आप स्वयं

ही नैय लेवें कि आज दिन आपकी नैतिक शक्ति का मुख्याश भारतवर्ष के बीरों से ही बलवान है। मैं इन दोनों बातों को इसलिए कह रहा हूँ, जिसमें आप लोग इस बात को स्वीकार करें कि यद्यपि भारतवर्षासी परतन्त्र है तथापि सभ्य जातियों में सम्मान पाने के योग्य है। आपके भूतपूर्व राजनैतिक नेतागण इस बात का कर्मा अस्वीकार नहीं करते थे। वे सदा इस बात को, कि समार के एक कोने में स्थित एक छोटा सा द्वीप दूसरे कोने पर के एक महादेश को शासित करे, एक दैवयोग ही मानते थे। वे यह कहते थे कि भारत वर्ष हम लोगों को सौंपी हुई एक पवित्र धरोहर है और इसकी रक्षा और पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, उनके अन्तःकरण की सच्चाई प्रशंसनीय थी। आप लोगों को शासन करते हुए करीब सौ वर्ष होते हैं और अब यदि हम लोग आप लोगों के शासन की आलोचना करें तो शायद ही कोई ऐसा कहेगा कि भारतवासियों को अभी इतनी जल्दी आलोचना करना ठीक नहीं। भारतवर्ष में सब से पहला काम जिसने आपके शासकों का ध्यान आकर्षित किया था वह अंग्रेजी बल का स्थापन करना था और यह उन लोगों ने अपने नवीन आविष्कारों के द्वारा तथा पाश्चात्य शासन प्रथा को चलाकर पूरी भी कर डाला। यह काम हुआ भी पड़ी, सूची के साथ। सारे देश में रेल, तार और पोस्टऑफिसों का जाल बिछ गया, शान्ति और शृङ्खला का राज्य हो गया, न्याय महंगा होते हुए भी देशियों के बीच पूरे तौर से होने लगा। हा अब प्रश्न देशी और विलायतियों के बीच का होता तब तो बात कुछ अवश्य ही बदल जाती। इसमें सन्देह नहीं कि जो शासन पद्धति यहाँ फैलाई गई है वह किसी प्रकार परिपूर्ण नहीं कही

जा सकते तथापि मैं यह अवश्य कहूँगा कि यह ऐसी है, जिस पर आप सन्तोष प्रकाश कर सकते हैं। वल एकत्र करने के अतिरिक्त आप लोगों के राजनीतिज्ञों ने सामो-पचार नीति का अवलम्बन किया और आपके कार्य का यह भाग भी सन्तोषजनक है क्योंकि हिन्दुस्तानी परदेशियों के शासन से सन्तुष्ट रहने लगे। यह परिणाम आप लोगों के पार्लामेन्ट और सम्राटों की उदार-नीति तथा अंग्रेजी शिक्षा के फैलने के कारण सुगम हो गया। इस पाश्चात्य विद्या के प्रादुर्भाव होने के कारण देश में स्वतन्त्र सस्थाओं का प्रेम जम गया। करीब पचहत्तर वर्ष के होता है जब आपके पार्लामेन्ट ने १८३३ का चार्टर एक्ट पास किया, जिसमें भारत के शासन के मूलतत्त्वों का समावेश था। और पच्चीस वर्ष के बाद महारानी ने उन्हीं तत्त्वों का अनुमोदन अपने चार्टर में किया। १८३३ और १८५८ की घोषणाएँ ही आपके पार्लामेन्ट और राजा की प्रतिज्ञाएँ हिन्दुस्तानियों के सम्मुख पेश करती हैं और यही दो प्रतिज्ञाएँ आपके भारतीय शासन की नींव हैं।

ब्रिटिशराज्य का प्रधान लक्ष्य, हिन्दुस्तानियों की उन्नति करना, राज्य कार्य में दोनों जातियों के बीच तुल्यता प्रदान करना तथा जाति पाति और रंग रूप के भेदों को दूर कर देना ही कहा जाता है। इन प्रतिज्ञाओं के सन्मुख सभी हिन्दुस्तानी शिर नम्रा कर परदेशियों की शासन-युक्ति में योग देने लगे। चार्टर के बाद ही हिन्दुस्तान में तीन पुराने विश्वविद्यालयों की नींव पड़ गई, स्कूल कालेज खुल चले और इङ्ग्लैण्ड के ढंग पर विद्याध्ययन का काम भी आरम्भ हो गया। स्मरण रहे कि पाश्चात्य विद्या का द्वार हम लोगों के लिए खोल कर

भविष्य फल का विचार भी आप लोगों ने कर लिया था क्योंकि मैकाले ने अपने एक प्रसिद्ध सभाषण में कहा था कि पाश्चात्य विद्या के रंग में रंगे जाकर हिन्दुस्तानी एक न एक दिन अपनी राजनीति को यूरोप के ढंग में ढालना चाहेंगे। उनका कथन है "मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा दिन कभी आसकता है कि नहीं, परन्तु मैं ऐसे सुदिन को रोकने का उद्योग नहीं करूंगा, उलिक ऐसे समय को मैं इङ्गलैण्ड के सीभाग्य का दिन कह कर अभिनन्दन ही करूंगा"।

इस प्रकार आपलोगों की की हुई प्रतिज्ञाएँ तथा पाश्चात्य विद्या का आरम्भ उच्चतम शासन प्राणाली के साथ मिलकर आपके चिरमिलपित सामोपचार कार्य को सन्तोषजनक रूप में सफल करने लगा। बीस वर्ष पहले एक इङ्गलैण्ड लौटनेवाले अंगरेज को यह विश्वास होता था कि देशभर में अंग्रेजी शासन को सभी प्रसन्नतापूर्वक अङ्गीकार किये हुए हैं, और यह बात थी भी, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि इस शासन में अपनी उन्नति करने का अवकाश मिलेगा और प्रजा होते हुए भी अन्य उपनिवेशों की तरह हम अपनी मर्यादा रख सकेंगे। महाशयो ! आज यदि वह विश्वास अति क्षीण हो गया तो इसके एकमात्र कारण आपके राजनीतिक लोग हैं, जो दो सीढ़ी चढ़ा कर अब तीसरे पर पैर नहीं देने देते। अर्थात् सस्थापन और सामोपचार के पश्चात् पुनर्सृष्टि करना नहीं चाहते। जिस समय आप लोगों ने भारतवर्ष में कार्य आरम्भ किया था और जिस समय आपको पाश्चात्य शासन नीति वहाँ फेलानी थी उस समय हिन्दुस्तानियों के नीतिनिपुण न होने के कारण कुछ नीतिविद्व अंग्रेजों के हाथ में कार्य सौंप देना अनुचित नहीं था परन्तु आज जब आपके

कालेज और स्कूलों को, कृपा से बहुतेरे काम करने, वाले तैयार हो गये हैं और शासन में हाथ बटाने को, भी, प्रस्तुत हैं तब आप लोग क्यों अपनी नीति का जीर्णोद्धार नहीं करते ? क्यों मूलतत्त्वों को पुनरावलोकन कर अपनी की हुई, प्रतिज्ञाओं की पूर्ति नहीं करते ? दुर्भाग्यवश आपके-राजनीतिज्ञ लोग इसी समय आनाकानी करते हैं जिसका परिणाम प्रायः भयानक होने की वमकी दे रहा है। पच्चीस वर्ष पूर्व एक बड़े न्यायी अग्रज लार्ड रिपन ने भारी उद्योग इस शुभ काम को आरम्भ करने का किया था। भारतवासियों के उस शुभेच्छु ने पांच वर्ष तक ब्रिटिश राज्य के शासन के मूल तत्त्वों को विस्तृत करने में जो तोड़ परिश्रम किया था, और उन कुछ स्वत्यों को, जिनके लिए शिक्षित भारतवासियों का हृदय लालायित हो रहा था, दिया भी। उस महापुरुष ने स्वराज्य की वर्षामाला सिखलाने का उद्योग किया, शिक्षा के लिए उत्तेजना दी, और अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों के बीच की भागी असमानता, जो आज दिन देश भर में व्याप्त है दूर करने की चेष्टा की। इसका परिणाम क्या हुआ ? विचारों अपने देशवासियों के हाथ से पूरे रूप से फटकारा गया और उसके बाद से किसी वाय सराय की हिम्मत उस महापुरुष के चलाये मार्ग को अग्रतः ध्यान करने की नहीं हुई। इतना ही नहीं गत कुछ वर्षों में शिक्षित जनता के विरुद्ध प्रतिघातक उपायों का जोर बढ़ चला, फिर लार्ड कर्जन के शासन काल में इसका रूप और भयानक हो उठा। मैं केवल यही जनलाना चाहना हूँ कि ये उपाय कभी सफल होने के नहीं हैं। अन्तिम गिन्ती से चिदित होता है कि वर्गीय दस लाख मनुष्य अंग्रेजी पढ़े सिके हैं। आप इस सख्या को एकदम आज दिन एक इंच जगह में रक नहीं रख

सकते। और यदि यह सम्भव भी हो तो आप लोगों को ऐसा करना उचित नहीं। मैं तो कहता हूँ कि यह असम्भव है और असम्भव को सम्भव करने का उद्योग सदा ही भयावह होता है। बहुत कुछ बुराईया हो चुकीं। अब मेरे देश घामिशों का विश्वास ब्रिटिश शासन से एकदम हिल उठा है, यहाँ तक कि कुछ युवकों को तो एक दम कुछ है ही नहीं। यह समस्या अब भयावह हो रही है। इस समय सभी बुद्धिमानों को भविष्य के विषय में भय हो रहा है। और यदि आप लोग इसे अब भी अनुभव नहीं करेंगे तो पीछे इसका इलाज कठिन हो जायगा।

महाशय और महिलाओं! मैंने इसे स्वीकार किया है कि पुराने देश में नई रीशनी फैलाने का श्रेय आप लोगों को ही है। अब इस देश का, आपके सौ धर्म के शासन में जितना कल्याण हुआ है, विचारणीय है। यही असल जान है। अगर इस जात्र का फल सन्तोषप्रद हुआ तब तो सब किसी के आपत्ति करते रहने पर भी मैं इस शासन के तत्वों को अच्छा ही कहूँगा।

अच्छा अब हमें पहले मानसोन्नति के विषय को लेना चाहिये। यह दोष गुण मिश्रित है। हममें बहुत सी बातें नैराश्या हैं, जिस पर आप पूरे तौर से सन्तोष प्रकट कर सकते हैं। आपके शासन के गुणों से हम लोगों में शान्ति, न्याय और श्रद्धा की उन्नति, पाश्चात्य शिक्षा का फैलाव, भाषण व्यवस्था, सार्वलौकिक सभा की श्रेष्ठता इत्यादि का आ जाना सर्वप्रधान और अभिमान करने योग्य है। इसके साथ ही साथ बुराईया भी हैं जिनमें मैं हम लोगों के राष्ट्र की अव्यवस्था सबसे बढ़कर और प्रथम रखने योग्य है आप लोग हम लोगों

को विश्वासपात्र नहीं समझते यह दूसरी बात है। साबूत में देखिये, १८६२ के पार्लामेंट के एक सम्भाषण से ज्ञान होता है कि २४०० अफसर सिविल-सर्विस के हिन्दुस्तान में है जिनमें से सिर्फ ६० हिन्दुस्तानी है और वे भी कुछ ऊँचे दर्जे के नहीं। तीसरी बात यह है कि इंग्लैंड के पार्लामेंट के एक व्यक्ति को शासन में जितना अधिकार है उतना हमारे ३३ करोड़ भारतवासियों को इकट्ठे होने पर भी नहीं। चौथी बात हम लोगों का निःशस्त्र होना है। इत्यादि। भारतवासियों की वास्तविक स्थिति तो यही है। बाहर यदि हम लोग आपके उपनिवेशों में जाते हैं, जैसे नेशल इत्यादि देशों में, तब तो हमारा अपमान और भी बढ़ जाता है, हम लोग असम्य समझे जाकर फूट-पाथ पर भी चलने नहीं पाते। अब यदि सौ वर्ष तक आपकी प्रजा रहकर हम लोगों के हक यों ही रहे तो फिर कौन कहेगा कि आपके शासन का फल हम लोगों पर बहुत अच्छा हुआ?

अब यदि हमलोग आर्थिक विषय की ओर मुँह तो मुँह और भी शोक के साथ कहना पड़ेगा कि भारतवर्ष की आर्थिक अवस्था आपके शासन से अत्यन्त भयानक होगई है। यह बात मैं बीस वर्ष में पूर्ण विज्ञता प्राप्त करने पर कहने को समर्थ हुआ हूँ। भारतवासी आज दिन दीनता के घोर गड्ढे में गिरे पड़े हैं, यह बात मैं दो एक उदाहरणों से सिद्ध कर दूँगा। आपकी वार्षिक आय ४२ पौण्ड अर्थात् ६३०) रुपया की आदमी है परन्तु हमलोगों की सिर्फ ३०)। आप लोगों की रक़नी की आमदनी १३ पौण्ड अर्थात् १६५) है और मेरे यहाँ केवल ३॥) है। आपके सेविगर्वेकों में २ अरब २२ करोड़ रुपये हैं और हम लोगों के यहाँ आप से सतगुनी जनता के रहते भी सिर्फ पस ही करोड़ हैं, जिसमें से भी अधिक रुपया गुरो

पियनों का ही है। आपके यहां की सम्मिलित मूलधन वाली कम्पनियों का प्रस्तुत मूलधन १,६००००००००० पौण्ड है और हम लोगों का केवल २ ही करोड है उसमें से भी अधिकतर अगरेजों का ही है।

हमारे देश का ३ हिस्सा कृषिव्यवसायी है परन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि कुछ दिनों से इनकी दशा भी शोचनीय हो रही है। भारतवर्ष के कृषक एकदम दरिद्र और अज्ञ से चूर हैं अतएव उन लोगों के पास इतना काफी धन नहीं कि अपने व्यवसाय में कुछ रुपये लगा सकें, जिसका परिणाम यह है कि अधिकतर कृषकों का परिश्रम एकदम निष्फल जाता है। भारतवर्ष के एक एकड़ जमीन में ५ मन के करीब गल्ला पैदा होता है और आपलोगों के यहां १५ मन। और गी सुनिष्ट गत आठ वर्षों के अकाल से भारतवर्ष में कृषकों को करीब ३० करोड रुपयों की घटी हुई है। एक विज्ञ, (मिस्टर हट्टर) के कथनानुसार ४ करोड मनुष्य केवल एक घंटा भोजन कर जीवन यापन करते हैं, और ७ करोड मनुष्य ऐसे हैं जो एक शामको खा कर भी यह नहीं जानते कि खाधा की वृत्ति कौन सी चिड़िया का नाम है। सज्जनों ! एक महादेश की यह दुरावस्था किस हृदय को नहीं पिघलाएगी। यदि आपके सौ वर्ष के शासन के बाद भी हमलोगों की यही दशा रही तो आप किस मुख से कह सकते हैं कि आप लोगों का शासन सतोपजनक हुआ ? इतना ही फ्यों, यह भली भांति दिखलाया जा सकता है कि यह दुरावस्था भी प्रतिदिन घोरतर होती जाती है। अकाल पर अकाल पड़ते जाते हैं, कष्ट प्रति समय बढ़ता जाता है, इस पर भी गत सात वर्षों से भोग प्रजा को निगले जाता है। हाय !!

अब जनता की ओर चलिये तो देखा जायगा कि भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में जनता बढ़ने के बदले गत बीस वर्षों में घटती जाती है या ज्यों की त्यों बनी है। इसका मुख्य कारण अकाल मृत्यु ही है। इंग्लैण्ड और भारतवर्ष की मृत्युसंख्या मित्र कर देखने से पता होगा कि इन वर्षों की पहले चौथाई भाग में भारतवर्ष में मृत्युसंख्या २४ या २५ की हजार थी और इंग्लैण्ड में २० थी। दूसरे चौथाई में हम लोगों की मृत्युसंख्या २४ से २८ होगई और आप लोगों की २० से १८ रह गई। तीसरे चौथाई में हम लोगों की ३० और आप लोगों की १७ रही। और चौथे चौथाई अर्थात् गत पांच वर्षों में हमारी मृत्युसंख्या बढ़ कर ३२ पहुच गई और आप लोगों की १६ स भी नीचे रसक गई। क्या ? महाशय ! इसका कारण यह है कि आप लोग अपने मजदूरों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते हैं और उनके खाने पीने का इन्तजाम स्वयं सरकार से करते हैं। और हम लोगों के साथ वे बातें नहीं। अब आप विचार सकते हैं कि जनता के इस घोर कष्ट के लिए कौन उत्तर दायी है ?

चालीस वर्षों से हम लोगों के यहां आय में व्यय की संख्या बढ़ती जाती है, वह आज १५ अरब रुपया अधिक हो गई है। कोई भी देश इतना हास सह कर जीता रह सकता है ? इसका कोई प्रतिकार नहीं। सिवा इसके कि भारतवर्ष को अपना काम करने का अधिकार देकर उपनिवेशों के दर्जे तक पहुंचा दिया जाय, दूसरा कोई उपाय हम लोगों की दृष्टि उन्नत नहीं कर सकता। मैं स्पष्ट रूप से यह देता हू कि वर्तमान शासन-पद्धति में आप लोग हम लोगों की 'भलाई का नम्बर' अपने स्लेट पर पटले और दूसरे दर्जे में तो

[illegible]

महाराज ! जब तक मैं इस सेंद्र के लिए
कर सकूँगा कि महाराज के महाराज के महाराज
को लो लो ! महाराज के महाराज के महाराज के महाराज
यह लो लो महाराज के महाराज के महाराज के महाराज
महाराज, महाराज के महाराज के महाराज के महाराज

नरिताओं और सजनों ! मैं जन्म करता हूँ कि मैं जन्म
 तोनों की शास्त्र-पद्धति के पुनः सञ्चार करने —
 शस्त्र के दिव्यता के लिए अपने सर्वेष्ट
 इस समय मेरा ही अनिर्वाचित शास्त्र-धर्म
 भी वास्तविक विरोध नहीं । हम लोग न ११
 कोई अधिकार ही नहीं रखते हमारे नाश

अब जनता की ओर चलिए तो देखा जायगा कि भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में जनता बढ़ने के बदले गत बीस वर्षों से घटती जाती है या ज्यों-की-त्यों पड़ी है। इसका मुख्य कारण अशाल मृत्यु ही है। इंग्लैण्ड और भारतवर्ष की मृत्युसंख्या मिला कर देखने से बात होगी कि इन वर्षों की पहले तीसरा भाग में भारतवर्ष में मृत्युसंख्या २४ या २५ फी हजार थी और इंग्लैण्ड में २० थी। दूसरे चौथाई में हम लोगों की मृत्युसंख्या २४ से २८ होगई और आप लोगों की २० से १८ रह गई। तीसरे चौथाई में हम लोगों की ३० और आप लोगों की १७ रही। और चौथे चौथाई अर्थात् गत पांच वर्षों में हमारी मृत्युसंख्या बढ़ कर ३२ पहुच गई और आप लोगों की १६ से भी नीचे रख कर गई। क्यों ? महाशय ! इसका कारण यह है कि आप लोग अपने मजदूरों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने हैं और उनके खाने पीने का इन्तजाम स्वयं सरकार से करने हैं। और हम लोगों के साथ वे बातें नहीं। अब आप विचार सकते हैं कि जनता के इस घोर कष्ट के लिए कौन उत्तर दायी है ?

चालीस वर्षों से हम लोगों के यहाँ आय से व्यय की सख्या बढ़ती जाती है, यह आज १५ अरब रुपया अधिक हो गई है। कोई भी देश इतना हानि सह कर जीता रह सकता है ? इसका कोई प्रतिकार नहीं। सिवा इसके कि भारतवर्ष को अपना काम करने का अधिकार देकर उपनिवेशों के दर्जे तक पहुँचा दिया जाय, दूसरा कोई उपाय हम लोगों की दशा उन्नत नहीं कर सकता। मैं स्पष्ट रूप से कहे देता हूँ कि वर्तमान शासन पद्धति में आप लोग हम लोगों की भलाई का नम्बर अपने स्लोट पर पहले और दूसरे दर्जे में तो

क्या तीसरे दर्जे में भी नहीं रखते और न उस पर विचार ही करते हैं। अंग्रेजों को पूरी तनखाह मिलती है। उनका बोझ हम लोगों पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। भारतवर्ष की आमदनी का तीसरा हिस्सा गवर्नमेण्ट के खर्चों के लिए प्रति वर्ष यहाँ चला आता है। नहरों का इन्तजाम करने के पहले आप लोग रेल की लाईनों का विचार करते हैं क्योंकि रेल कम्पनियों में मूल धन अंग्रेजों का है। प्रजाप्रा की उन्नति प्राथमिक शिक्षा पर कितनी निर्भर है किसी से छिपा नहीं, परन्तु इस शोर सफ़ार ने कितना ध्यान दिया है, इसका गता इतने ही से लग जायगा कि प्रत्येक पाँच गावों में से चार गाव बिना स्कूल के हैं और प्रत्येक आठ लड़कों में से सात निरे, मूर्ख हैं। वर्तमान समय में भारतवर्ष में शिल्प की शिक्षा की कितनी आवश्यकता है सभी जानते हैं परन्तु समूचे देश भर में एक नाम के लिए भी कोई ऐसी संस्था नहीं, जहाँ कुछ शिल्प धाणिज्यादि की शिक्षा दी जा सके।

--- महाशयो ! जब तक यह दशा रहेगी, कोई विश्वास कर सकता है कि भारतवर्ष की भलाई की बातें आप कभी सोचते हैं ? बहुतसी बातें ऐसी हैं जिसमें आप की सहायता तत्काल आवश्यक है जैसे प्राथमिक शिक्षा, शिल्प की शिक्षा, छपकों की कीमती इत्यादि।

- महिलाओं और सज्जनों ! मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों की शासन-प्रवृत्ति के पुनः संस्कार करने की आवश्यकता को दिखलाने के लिए यथेष्ट बातें कह डालीं।

इस समय आपकी अनियंत्रित शासन प्रणाली से किसी का भी वास्तविक विरोध नहीं। हम लोग भारतवासियों को तो कोई अधिकार ही नहीं परन्तु हमारे भारतीय, मंत्री महाशय

जिनका काम निरीक्षण करने का कहा जाता है, इस काम को कर ही नहीं सकते क्योंकि वे विचारे मेरे देश में कभी गये नहीं, अतएव उन्हें इस विषय का कोई सच्चा ज्ञान हो नहीं सकता। पार्लामेंट ने इस अनर्थ को समझ कर मंत्री को एक सदस्यों की सभा सहायता करने के लिये दी ! परन्तु शोक है कि इन सदस्यों में से एक भी हिन्दुस्तानी नहीं सब के सब पेशनयाफ़ा एंग्लो इन्डियन ही हैं। इन एंग्लो इन्डियनों के विचार एकदम पक्षपातपूर्ण हैं और सभा में शासकों के ही मतलब की बातें होती हैं। यद्यपि पार्लामेंट कहने को तो अवश्य निरीक्षण करने वाली संस्था है परन्तु स्टेट सेक्रेटरी के सम्राट की सभा के सदस्य होने के कारण, और अधिकांश जनता के द्वारा अनुमोदित होने के कारण पार्लामेंट का निरीक्षण भी केवल नाममात्र का रह जाता है। अतएव यदि सच्ची बात पूछी जाय तो यह है कि कहीं भी किसी का अधिकार नहीं, कोई निरीक्षक नहीं। मैं आशा करता हू कि लिबरल पार्टी इस अनर्थ को खूब समझती है। इस समय हम लोगों की केवल इतनीही मांग है कि राजकार्य में हम लोगों को भी कुछ निरीक्षण का अधिकार दिया जाय। मैं गवर्नमेंट की कठिनाइयों को पूरा समझता हूँ, अतएव मैं तत्काल प्रजातन्त्र नहीं मांगता। हम लोगों की मांग एक दम साधारण है। उसकी साधारणता ऐसी है कि जिसे सुन कर आप लोग आश्चर्य में पड़ जायेंगे।

पहले वाइसराय की लेजिसलेटिव कौंसिल की ओर चेलिये इसमें केवल ४ सभासद हिन्दुस्तानी हैं बाकी २१ सरकारी। वर्ष भर में केवल एक दिन आय धन्य के विषय पर कुछ बातें होती हैं। इस एक दिन में भी कुछ किया नहीं जाता

और न किसी को उस विषय पर चादविवाद करने का पूरा अधिकार दिया गया है, न किसी बात में अलग अलग राय ही ली जाती है। हम लोग चाहते हैं कि दोनों दल की संख्या कौंसिल में बराबर रहती, चाइसराय को थोड़ा अधिकार रहे, इस में कुछ आपत्ति नहीं। आयव्यय के लेखे में टिप्पणी करने का अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिये। प्रान्तिक शासन में देशियों को आय व्यय विषयक प्रश्नों में हस्ताक्षेप करने का अधिकार मिलना चाहिये और गवर्नमेंट को अन्य अन्तर्विषयों का इन्तज़ाम सौंपना चाहिये। इन सबों के बाद स्टेट सेफ्टरी की कौंसिल में भी हम लोग तीन देशी मेम्बर चाहते हैं। जिसमें किसी प्रश्न की मीमांसा होने के पहले भारतीय अपनी राय देमकें और किसी विषय पर देशी मत प्रकाशित कर सकें। और अन्त में पार्लामेंट के कामन्स में कम से कम बारह प्रतिनिधियों का चुनाव हिन्दुस्मान से होना चाहिये। ६७० मेम्बरों के बीच में केवल बारह कुछ गड़ बड़ नहीं मचा सकेंगे और न मंत्रियों के भाग्य ही बदल सकेंगे। मैं इतना कुछ जो चाहता हूँ वह प्रथम तो राज्यकार्य में योग देकर अपनी स्थिति को उच्च रखने के लिये ही है, दूसरे इसके द्वारा पार्लामेंट को भारतीय विचारों को भारतीयों के मुख से सुनने का सुअवसर देने के लिये है। इससे जब हम लोग पार्लामेंट में एकमत हो कर किसी बात का विरोध करेंगे उस समय कम होते हुए भी हम आप लोगों से विस्मरण किये जाने के योग्य नहीं रहेंगे।

आप लोग कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान को यह अधिकार देने पर उपनिवेशों को भी यह अधिकार देना होगा, परन्तु यह तो कोई दलील ही नहीं क्योंकि उन उपनिवेशों का

कल उस देश से आ रहे हैं उनको ठीक मानने और मतलब समझने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये। भारत एक बड़ा देश है और यह बहुत संभव है कि हजारों कोस दूर दूसरे देश में भेजी हुई लडीबंद पत्रों कभी २ जन साधारण पर गलत प्रभाव डालें। इसके सिवाय ऐंग्लोइंडियन समाज का एक ढल, विशेष कर उत्तर में, भारत के सुधारों के ढंग और विस्तार से भयभीत हो रहा है, और उन तारों में, जो यहाँ रोज २ आते हैं, इस भय के चिह्नों का पता लगाना कुछ बहुत कठिन नहीं है।

अन्त में मुझे भय है कि अशान्ति की घकालत करने वाले तथा उनके सहायक, महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा से कुछ बहुत प्रसन्न नहीं हैं (अर्थात् अप्रसन्न हैं) और आज फल उनकी नई तेजी का प्रायः यही कारण है। परन्तु यह सब कुछ होने पर भी, और इन सब बातों के सम्मिलित प्रभाव को छोड़ करके भी यह निश्चित है कि आज भारत में बहुत ही कठिन स्थिति है, उस देश की दशा बड़ी सकटमय है, और यथार्थ में अगले दो या तीन साल में यह निश्चित हो जावेगा कि इंग्लैंड और भारत के बीच भावी सम्बन्ध क्यों और कैसा रहेगा। मुझे आशा है कि वे सब लोग जो ऐसी अवस्था में हैं, कि भारत के मामलों पर उनका असर पड़ सकता है, इन बातों को भली भाँति समझ लेंगे। केवल यही नहीं है कि कुछ उग्र-स्वभाव के मनुष्य आपे से बाहर हो सब उचित बंधनों को तोड़ जान बूझकर अशान्ति फैला रहे हैं, परन्तु बात यह है कि जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पाई है, या जो अंग्रेजी शिक्षा पा रहे हैं, उनके विचार अंग्रेजी राज्य की

घोर से घड़ी शीघ्रता से बढ़ल रहे हैं, और भारत के अच्छे-से अच्छे दिमाग वाले मनुष्य इन लोगों के साथ हैं।

नये भावों का इतिहास।

इन परिवर्तनों का परिणाम क्या होगा और सरकार उनके सवन्ध में किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये इतने कठिन मामले हैं, कि जिनके निश्चय करने के लिए भारत वर्ष या इस देश के सब शासकों और आन्दोलन करनेवालों को कुछ समय तक अपना पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इस परिवर्तन, इस अशांति—अथवा और जिस किसी नाम से आप इसे पुकारें—के मूल तथा विस्तार को ठीक रीति से समझने के लिये आपको ब्रिटिश भारत के इतिहास के ७५ साल पीछे, अर्थात् स १८३३ में जाना पड़ेगा। इसी साल इस्ट इन्डिया कंपनी का व्यापारी रूप बदल गया और उसने शासकों, अर्थात् फेवल शासकों, का ही रूप धारण किया। उसी साल पार्लामेंट ने यह प्रसिद्ध आज्ञापन पास किया, कि भारत के शासन में जाति अथवा धर्म का भेदभाव न रक्खा जायगा, और सभी सरकारी नौकरियों के द्वार सभी के लिये एक से खुले रहेंगे। उस समय लार्ड विलियम बेंटिंज भारत के बड़े लाट थे, और स्वर्गीय सर विलियम हंटर ने ठीक ही कहा है कि वह पहिले ही बड़े लाट थे जिन्होंने भारतवासियों का हित ही अपने कार्यों का मुख्य उद्देश्य रक्खा था। (जय भवनि ।)

वह समय प्रथम रिफार्म बिल* (सुधार करने वाले कानून)

* सन् १८३२ में इंग्लैण्ड का पहिला सुधारक कानून पास हुआ था। यही अंग्रेज जनता की स्वाधीनता का शीर्षक था। इसके पहिले सब अधिकार बड़े जमींदारों के ही हाथों में थे। पृष्ठ ०।

और गुलामों को स्वतन्त्रता दिये जाने का था। और इस देश (इंग्लैण्ड) के नीतिज्ञों तथा मंत्रियों ने भारत के साथ भी उसी उदार नीति का व्यवहार करना निश्चित किया था जो इंग्लैण्ड के इतिहास का सर्वोत्तम भूषण है। (जय ध्वनि ।) उन्होंने उन विचित्र घटनाओं को, जिनके कारण मुझे भर अंग्रेज एक उहुन बड़ी और सभ्य जाति पर अपना राज्य स्थापित कर सके, ईश्वर की ही महिमा का प्रकाश समझा। उनके हृदय पसोज गए और उन्होंने सच्चे दिल से प्रकाशित किया कि वे भारत पर इस प्रकार से राज्य करेंगे, मानों वह उनको एक धरोहर की भांति सौंपा गया हो। और राज्य का नीज अंग्रेज तथा भारतीय दोनों जातियों की परास्त्री के आधार पर रखी जायगी।

उपर्युक्त-वादों को पूरा करने के लिए २५ वर्ष तक बहुत कम उद्योग हुआ, क्योंकि इस काल में सरकार की सारी शक्ति राज्य को बढ़ाने और दृढ़ करने में खर्च होती रही थी। सरकार इस समय शासन की एक पेसी मशीन तैयार करने में लगी हुई थी, जो पश्चिमी ढंग की हो और जो पश्चिम के आदर्शों को व्यक्त कर सके। इस समय तक भारतवर्ष में शिक्षित लोगों के समुदाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो अंग्रेजी नीतिज्ञों के वादों के लाभों का आदर करना और सार्वजनिक सम्मतियों के दबाव से उन वादों को पूरा कराने का उद्योग करता।

२५ वर्ष पूरे होने के बाद एक मारके को उन्नति हुई, यद्यपि सिपाही विद्रोह की काली घटा अभी भारत के आकाश से छोप नहीं हुई थी। इस उन्नति, अर्थात् भारत के

भिन्न भिन्न प्रान्तों में विश्वविद्यालयों की स्थापना, से उन पुराने वादों का पूरा होना संभव हुआ। उसी समय राजराजेश्वरी की ओर से एक घोषणा भी प्रकाशित हुई, जिसमें १८३३ के वादों को फिर से दुहराया गया। फिर २५ वर्ष और गीते। इस काल में शिक्षित लोगों को एक ऐसा समुदाय उत्पन्न हुआ, जिसके मंत्र में स्वाधीनता की ध्वनि भरी हुई थी। और इसी समय, सन् १८५८ से २५ साल बाद सन् १८८३ के लगभग, एक और मंत्र की उन्नति हुई, अर्थात् स्थानिक स्वराज्य प्रदान किया गया।

पैर पीछे हटाने का फल ।

द्वैतयोग से लार्ड रिपन के स्थानिक स्वराज्य वाले कानून पास होने के २५ वर्ष बाद अब फिर नए सुधार होंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो सुधार अब प्रकाशित किए जाएंगे वे हमारी उन्नति की तीसरी सीढ़ी होंगे, और उनके द्वारा वर्तमान प्रगथ में ऐसा परिवर्तन होगा, जिस प्रकार १८८३ में स्थानिक स्वराज्य का आरम्भ हुआ था, अब प्रान्तिक स्वराज्य का श्री गणेश होगा। पिछले २५ साल का समय भारतवासियों के लिए बड़ी कठिनाई का समय था। यह समय हमारे लिए भी वैसा ही पीछे हटने (अवनति करने) का था जैसा अभी हाल ही में समाप्त होने वाला युग आप के लिए था। ग्लैडस्टन के प्रथम होम रूल बिल के अस्वीकार होने की तिथि से आरंभ

१९१५ में १८८६ में २५ साल का नेता मोहम्मद मोमरो वार १९१६ का प्रधान मंत्री हुआ। इसने ग्लैडस्टन की होमरूल प्रदान करने

होकर आप के देश में अनुदार शासन चोखरों से युद्ध समाप्त होने तक रहा । हमारे बुरे दिन भी उसी-समय से आए और लार्ड कर्जन के शासन काल के अंत तक रहे । इसी अनुदार युग के साथ २ एक महान् जातीय चेष्टा भी अपना प्रभाव दिखाने लगी । इस चेष्टा का उद्देश्य यह था कि भारत की राजनैतिक स्थिति को उच्च कोटि का बनाये । इंग्लैंड के उदार दल के सिद्धान्तों तथा ब्रिटिश राज्य के उच्च आदर्शों में विश्वास ही इस चेष्टा की आरम्भिक अवस्था में हमारा आधार था । कुछ नवयुवकों ने जिन्होंने १८६० से प्रायः १८७५ तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई थी, और उन लोगों ने, जो इसके पूर्व ही अपना शिक्षा-काल समाप्त कर चुके थे, पुराने उदार दल की सर्वोत्तम युग अवस्था देखी थी । यही सज्जन कांग्रेस के आरम्भ होने के समय उसके नेता बने । मेरे देशवासियों ने उदार दल के प्रसिद्ध पुरुषों को जैसे ब्राइट, ब्रैडला और फासेट को, अत्याचार के विरुद्ध और कैबल न्याय की दृष्टि से ही भारत धर्म का पक्ष लेते देखा था । इसके अतिरिक्त लार्ड रिपन के शासन ने हमारी कृतज्ञता और उत्साह को बढ़ा दिया था । इस लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस ने अपना कार्य आरम्भ करते समय उदार दल पर बहुत कुछ विश्वास और भरोसा रक्खा था । परंतु धीरे धीरे यह विश्वास और भरोसा कम होने लगा और उदार दल के भारत में

के लिए एक महीना बिल पार्लियामेंट में पेश किया पर उदार दल में फूट पड़ जाने से बिल पास न हुआ । उदार दल के मन्त्रिमण्डल ने पद त्याग दिया । प्रायः २० वर्ष तक अनुदार दल का प्रभुत्व रहा ।

हेनरी फाउलर* तथा उदार दल के वायसराय लार्ड यलगिन ने अधिकांश कांग्रेस वालों के हृदय से उसे बिलकुल नष्ट कर दिया। उदार दल का विश्वास हटते ही ब्रिटिश राज्य के उच्च उद्देश्य में भी लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। और लार्ड कर्जन के अंतिम ६ साल के शासन ने इस श्रद्धा की भी इतिश्री कर दी। आप सब लोगों को मालूम है कि लार्ड कर्जन बहुत ही योग्य पुरुष हैं और उन्होंने भारत के शासन की मशीन को बढ़िया बनाने के लिये बड़ा परिश्रम किया और अपना समय लगाया, परन्तु उन्हें शिक्षित भारतवासियों की इच्छाओं और अभिलाषाओं के साथ कुछ भी सहानुभूति न थी। यहां तक कि उन्होंने अपने शासन के अंतिम ३ वर्षों में शिक्षित समुदाय के बढ़ते हुए प्रभाव और गौरव के नष्ट करने तथा भारतवासियों के पैरों में गुलामी की वेडियों को अधिक कड़ा और पुष्ट बनाने में अपनी शक्ति भर कोई कसर नहीं की। इसी अभिप्राय से उन्होंने विश्वविद्यालय, छापेखाने और समाचार-पत्र तथा सरकारी नौकरियों के सम्यन्ध में बहुत कड़ी आशाप प्रकाशित कीं। यहां तक कि महारानी विक्टोरिया की मन् १८५८ वाली प्रसिद्ध घोषणा को भी एक प्रकार से ख करने का उद्योग किया। फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कानयोक्शन (उपाधि वितरण के लिये उच्च कोटिके सफल विद्यार्थियों आदि के जमाव) में एक ध्यायान दिया, जिसमें बड़ी बुद्धिहीनता से भारतवासियों और उनके पूर्वजों तथा उनके जातीय उच्च आदर्शों की निन्दा की,। इस व्याख्यान को

* सर हेनरी फाउलर और लार्ड यलगिन ने उदार हो कर भी भारत के साथ अनुदारों का नाती बनाव किया। इस लिए उदार दल में भारत का विश्वास छीन हो गया। अनु० ।

कोई भारतवासी कभी भी सरलता से भूल न सकेगा और न कदाचित् कभी व्याख्यान को क्षमा ही प्रदान कर सकेगा । इन सब के ऊपर तुरा यह हुआ कि चलते चलते उन्होंने वगमग कर के बड़ी भारी भूल की । ३ वर्षों तक भारत सताप और क्रोध की ज्वाला को सहता रहा, यहा तक कि सतोष और सहनशीलता की सीमा टूट गई । लोग बैठे बैठे अपनी निपट शक्तिहीनता का चिन्तन करने लगे । नए नए विचार और भाव उनके हृदय में लहर मारने लगे । कुछ ने तो धायाकाटे और सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयत्न किया, कुछ इससे भी आगे उठ गए और शारीरिक बल प्रयोग का अवलम्बन करने लगे ।

अन्य बातों का प्रभाव ।

सन् १८०५ के अंत में जब लार्ड कर्जन भारत से निधारे तब देश की उपर्युक्त दशा थी । उनके स्थान में लार्ड मिन्टो धायसराय हुए । यह दयालु और नम्र स्वभाव के पुरुष और सहानुभूति रखने वाले शायक हैं, पर एक असाधारण कठिनाई का काम इनके हिस्से में आया था, कुछ तो स्थानिक शासकों (भारतीय सिविलियनों) के दबाव के कारण और कुछ तत्कालीन दशा से विवश हाकर, इन्हें गत तीन वर्षों में बड़ी कड़ी नीति बरतनी पड़ी । और विधि की विटवना देसिए, कि लार्ड मार्ल को, जिन्हें भारतीय शिक्षित समुदाय चिरकाल से अपना शुरू कर्क मानता था भारत मर्जी होने के कारण, इस कड़ी और द्रमाने वाली नीति का-पार्लामेंट में पक्ष लेकर समर्थन करना पड़ा इन सब बातों से भारत और भी क्षुभित और दुःखित होगया ।

और भी कुछ कारण ऐसे उपस्थित हुए जिन से पिछले कई साल में ब्रिटिश राज्य की ओर से हमारे प्राचीन विचार बहुत कुछ बदल गए। एशिया महाद्वीप में एक नवीन भाव की वायु बह रही है। यह नवीन भाव जातीयता और चेष्टा संगठनात्मक शासन के हैं। यह उसी प्रकार के भाव हैं जैसे कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के अधिकांश भाग में फैले थे। सारांश यह है कि हम पूरब के वासी इस मामले में यूरोप वालों से ५० वर्ष पीछे हैं। यदि आप उन घटनाओं और परिवर्तनों पर विचार कर जो टर्की, मिश्र, ईरान, और चीन में हो रहे हैं—जापान की तो बात ही क्या है—तो आप इस नई भारतीय चेष्टा को समझ सकेंगे। फिर रूस पर जापान के विजय पाने से पूरब को एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। अन्त में उस व्यवहार का जिक्र करना भी आवश्यक है जो अंगरेजी उपनिवेशों में भारतवासियों के साथ किया जाता है। इस व्यवहार ने हमारी आँखें खोल दी हैं और अब हम यह समझने लगे हैं कि हम को भी कभी २ ब्रिटिश राज्य की अन्य अंगरेज प्रजा के समान कहना मिलेगी या मुंह बिढाता मात्र है। हमें यह भी मालूम और निश्चय होने लगा है कि जब तक हमारी भ्रियति अपनेही देश में अच्छी न होगी, तब तक कहीं भी हमारा साथ उचित और बराबरी का वर्तन नहीं हो सकता। लार्ड कार्न का यह उद्योग, कि शिक्षित भारतवासियों का प्रभाव नष्ट हो जाय, पिछले २० वर्षों में हर समय ही दुःखदायी होता, पर इस समय, जब उपर्युक्त सब प्रभाव अपना काम कर रहे हैं, और भी अधिक हानिकारक हुआ है।

भी पहुँचाए जायें क्योंकि इनका सिद्धान्त है कि सब तान की गड़गड़ और कष्ट यहाँ तक कि अराजकता भी, देश विदेशियों के अधिकार से अच्छी है।

अंग्रेजी राज्य का उच्च उद्देश्य ।

यदि वे सुधार, जो अभी हाल ही में प्रकाशित होने वाले हैं, कुछ वास्तविक महत्व के हुए, तो यह सुधार चाहने वाला शिक्षित समुदाय का प्रसन्न होना असंभव नहीं है। और यदि ये लोग सतुष्ट हो गए तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भाव आज फैले हुए हैं, और जो वर्तमान स्थिति के सब से अधिक भयंकरक अंग हैं, वे बहुत कुछ लोप हो जायेंगे। फिर अशांति फैलाने वालों और उनके सहायकों के साथ देश में बहुत कम सहानुभूति रहे जायगी, और अशांति को मिटाने का काम आजकल की अपेक्षा बहुत सरल हो जायगा।

मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि आरम्भिक अवस्था में काँग्रेस को ब्रिटिश सरकार के उच्च उद्देश्य में बड़ी धृष्टता थी। यह उच्च उद्देश्य क्या है? अर्थात् शिक्षित भारतवासियों की पीढ़ी दरपीढ़ी उस उच्च उद्देश्य का क्या अर्थ समझती है। इनका यह अभिप्राय नहीं है कि कुछ अंग्रेजों को भारतवर्ष में सदा ऊँची नौकरियाँ मिलती रहें। या अंग्रेजी धन सदा भारतवर्ष के बड़े बड़े लाभदायक व्यापारों में लगा रहे। या लार्ड कर्जन और रीडयार्डकिपलिंग के से मनुष्य अंग्रेजों अफसरों के निस्वार्थ कर्तव्यपालन और सफेद चमड़े के पुरुषों के दायित्व के राग अलापा करें। नहीं, महिलाओं और महाशयों! मेरा अभिप्राय इन सब ऊपर लिखी बातों से नहीं है। हम ब्रिटिश शासन का उच्च उद्देश्य यह समझते हैं कि

पहिले तो पश्चिम, और विशेष कर इंग्लैंड, की शासन प्रणाली के जो उच्च आदर्श हैं वे भारत में स्थापित किए जायें, और फिर जनता को स्वराज्य की ओर धीरे धीरे उन्नति करने में उस समय तक सहायता दी जाय जब तक यह काम पूरा न हो जाय ।

इसके विरुद्ध, यदि ब्रिटिश सरकार भारत में पश्चिमी आदर्श को स्थापित करके भी अनियंत्रित और अत्रिकारी तत्त्व के दग पर शासन करती रही, तो हमारे विचार में यह अपने उच्च उद्देश्य के सिद्ध करने में विलगुल असफल रही । और यदि पश्चिमी आदर्श भारत से लोप हो गए और फिर वही पुराने देशी दग व्यवहार किए जाने लगे, तो भी हम यही कहेंगे कि अंग्रेजी सरकार अपने उच्च उद्देश्य को पूरा न कर सकती । जहां तक पश्चिमी आदर्शों का संबंध है, ब्रिटिश सरकार अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है अर्थात् वे आदर्श स्थापित हो गए हैं, परंतु दूसरे अभिप्राय के संबंध में कहना पड़ता है, कि लार्ड रिपन के दिष्ट हुए स्थानिक स्वराज्य के आरम्भिक अंश को छोड़ कर, इस ओर बहुत ही कम उन्नति हुई है । और यद्यपि यह दूसरा अंग पहिले पश्चिमी आदर्श को स्थापित करने की अपेक्षा अधिक आवश्यक और महत्व का है, तथापि अत्रिकारी इस के खूब ही विरुद्ध रहे हैं । यह नहीं कहा जा सकता, कि जब अंग्रेजी शिक्का का देश में प्रचार किया गया था, उस समय यह अनुमान नहीं था कि जनता स्वराज्य मांगेगी, क्योंकि आप सब को मालूम है कि सन् १८२३ में भी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसिद्ध आज्ञापन मिला था, लार्ड मैकाले ने बड़े ललित और मधुर शब्दों में इस अंग भविष्य का दृश्य वर्णन किया था ।

अन्य नीतिशैलियों ने भी समय समय पर ऐसे ही विचार और भाव प्रगट किये हैं, और कुछ दिन पहिले तो भारतवर्ष में किसी को यह मन्त्रेह भी न था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य सिवाय भारतवासियों को स्वराज्य देने के कुछ और भी हो सकता है। इसके अनिर्गुण आप का साहित्य, जो हम ५० वर्ष से बराबर पढ़ रहे हैं, स्वाधीनता और वैयक्तिक शासन के विचारों से भरा पड़ा है, इतनाही नहीं बरन् उन लोगों के लिए, जो दूसरों के द्वारा शासित होने रहने हों, आपके साहित्य में एक प्रकार की घृणा प्रकट की गई है। ऐसी अवस्था में यह आशा कोई कैसे कर सकता है कि भारतवासी, ५० वर्ष तक आपका साहित्य और इतिहास पढ़ कर सी, रार्ड कर्जन के मुख से अपने प्रायः सदैव के दासत्व की घोषणा सुनने पर, चुपचाप बैठे रहेंगे।

विलकुल नए प्रबंध की आवश्यकता है। भारतवर्ष को स्वराज्य मिलना केवल ब्रिटिश राज्य के उच्च उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही आवश्यक नहीं है, बरन् हमारे आत्म सम्मान की रक्षा के लिए भी उसकी बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के सर्वोच्च हित के लिए भी उसकी जरूरत है। (जय ध्वनि।) सभा है कि वर्तमान शासन प्रणाली उम्र परिवर्तन काल के लिए, जय एक देश के विचार और शासन पद्धति दूसरे देश में प्रचलित की जा रही हो, उचित कही जा सके, परन्तु वह शासित जाति के स्थायी लाभ और भावी भलाई के लिए तो विलकुल ही अनुचित है। जब तक सरकार अपना पूरा उद्योग और अपनी सारी शक्ति शान्ति स्थापन करने तथा तार, रेल आदि बनाने में मग्न करती थी, उस समय तक वर्तमान शासन के दोषों पर ध्यान नहीं गया।

परन्तु वह अवस्था अव्यवस्थित हो गई। और नये सिरे से शासन के प्रयत्न करने की अब बहुत आवश्यकता है।

आज कल शासन ऐसे चलायमान विदेशी अफसरों के हाथ में है जो केवल उतने समय तक देश में हैं, जितना उनकी नारुरी का काल समाप्त करने और पेनशन लेने के लिए काफी हो। उन्हें देश से स्थायी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि यह भाग तो केवल देश के निवासियों में ही हो सकते हैं। जब वे भारतवर्ष से बाहर जाते हैं, सारी योग्यता और विद्या, ज्ञान और अनुभव जो उन्होंने उस देश में रहकर और उस देश के मध्ये उपार्जित किया है, अपने साथ बाहर ले जाते हैं, और फिर हमको उनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचता। इन लिये शासन का कार्य ऐसे लोगों के हाथ में रहता है, जा या तो जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों, जैसे सर्वसाधारण की शिक्षा, किसानों की ऋण से मुक्ति इत्यादि, जिनपर बराबर ओर निरन्तर बहस, विचार तथा उद्योग होना चाहिये, स्वाभाविक रीति से ही उन विदेशी अफसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करते। शासन का वर्तमान कोशल केवल एक मशीन के पुरजों की सी निपुणता हो सकती है क्योंकि वह अफसरों की योग्यता और अपने पद के कर्त्तव्यपालन आदि के भाव का फल हाती है। परन्तु उसमें उश्कोटि की वह पटुता कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। जो केवल स्वराज्य से ही प्राप्त होती है।

सुधारों का ढंग ।

मैं अभी कह चुका हूँ यदि सुधारों में, जो हाल ही में प्रकाशित होने वाले हैं, कुछ सार हुआ तो शिक्षित भारत

वासियों के बहुत बड़े भाग का सतुष्ट होना असम्भव नहीं है । अब से १५ दिन के भीतर ही हमको मालूम हो जायगा कि यह सुधार क्या है, और तब हम कह सकेंगे कि उनसे जनता को कहीं तक सतोष होगा । यदि उनसे समझदार लोगों को संताप न हो सके तो फल बड़ा आपत्ति जनक होगा ।

मेरी हार्दिक आशा है कि ब्रिटिश शासन की उन्नति में यह सुधार तीसरी महत्वपूर्ण सीढ़ी होने में यह भी आशा करता हूँ कि वे स्थानिक स्वराज्य के मन्दिर निर्माण को पूर्ण कर देंगे । उनसे प्रान्तिक मामलों का पुनः संगठन होगा, और उन कौंसिलों में गैर सरकारी मेम्बरों का बहुपक्ष होगा, जिन्हें शासन और अर्थ संबंधी मामलों पर उचित अधिकार प्राप्त रहेंगे, यद्यपि रुढ़ करने की शक्ति सरकार के हाथ में रहेगी । फिर अब भाग्यवासियों की नियुक्ति कार्यकारिणी कौंसिलों में भी होनी चाहिये और जाति के भेद मिटाने के जो वादे अभी हाल ही में महाराज की ओर से किये गये हैं उन्हें ऊँची नीयतियों पर भाग्यवानियों को नियुक्त करके पूरा किया जाना चाहिये । मन्त्रालय के इन नये वादों की पूर्ति बेसी नहीं होनी चाहिये उसी 'सन १८५८' की प्रोपणा की हुई है । अतः मैं, जिला शासन के भी अधिकार विभाजित होना चाहिये, और जनता के प्रतिनिधियों की जिला शासन के काम में सहायता ली जानी चाहिये ।

मेरा विचार है कि यदि यह सुधार कर दिये जायेंगे तो जनता को प्रान्तिक, जिला और, स्थानिक शासन में वास्तविक दिलचस्पी पड़ा हो जायगी । और इन्हीं के साथ २ यदि दो और महत्वपूर्ण मामलों का उचित और सतोषजनक निपटारा हो जाय तो मेरा विश्वास है कि वर्त-

मान स्थिति सभल जायगी। वे दो मामले बगभग को रद्द करके बंगाल प्रान्तों को सम्मिलित करना और राजनैतिक अपराधियों को क्षमा प्रदान करना ह। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब तक बगभग में किसी प्रकार परिवर्तन न होगा, बंगाल में शान्ति न हो सकेगी और सार भारतवर्ष में उस समय तक अशान्ति फैली रहेगी जब तक बंगाल में शान्ति न हो जाय। हाल में विद्रोह के मुकद्दमों से लोगों के दिलों में बहुत कुछ मनमुटाव, उत्तेजना और सत्तोभ उत्पन्न हो गया ह। और जब तक यह मनमुटाव उन अभियुक्तों और दंडित मनुष्यों को जिनको केवल मतभेद रखन के कारण ही ठड मिला है, क्षमा प्रदान करके मेट न दिया जायगा, तब तक नए सुधारों में बहुत कुछ सार होने पर भी उनका काफी प्रभाव न पड सकेगा। मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार सच्चे और स्थायी सतोष उत्पन्न करने का केवल यही एक ढंग ह और यदि लार्ड माले और लार्ड मिंटो ने उसे स्वीकार किया और बिना विलम्ब किए ही स्वीकार किया, तो अग्रगण्य ही इसका बड़ा अच्छा परिणाम होगा, तथा उन दोनों लार्डों के नाम लार्ड कैनिंग और लार्ड रिपन के नामों के साथ भारी पीढ़िया बड़े आदर से याद करेंगी।

परन्तु यदि यह अवसर हाथ से गवा दिया गया, यदि सुधारों में उतना सार न हुआ जितना होना चाहिए, या उनके साथ साथ उन दो मामलों का जिनका अभी मैंने जिक्र किया ह, सतोषजनक निपटारा न हुआ, तो फिर मुझे भय है कि सरकार को भारतवर्ष के कुछ भागों में फौजी कानून जारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि एक क्का फौजी कानून जारी हो गया तो ब्रिटिश सरकार का जो

वासियों के बहुत बड़े भाग का सन्तुष्ट होना असम्भव नहीं है। अब मे १५ दिन के भीतर ही हमको मालम हो जायगा कि यह मुद्धार क्या है, और तब हम कह सकेंगे कि उनसे जनता को 'कहाँ तक मनोप' होगा। यदि उनसे समझदार लोगों को सतोप न हो सका तो फल बड़ा आपत्ति जनक होगा।

मेरी हार्दिक आशा है कि ब्रिटिश शासन की उन्नति में यह सुधार तीसरी महत्वपूर्ण सीढ़ी होगे, म' यह भी आशा करता हूँ कि ये स्थानिक स्वराज्य के मन्दिर निर्माण को पूर्ण कर देंगे। उनमें प्रान्तिक कांसिलों का पुनः संगठन होगा, और उन कांसिलों में गैर सरकारी मेम्बरों का बहुपक्ष होगा, जिन्हें शासन और अर्थ-सम्बन्धी मामलों पर उचित अधिकार प्राप्त रहेंगे, यद्यपि रद्द करने की शक्ति सरकार के हाथ में रहेगी। फिर अब भारतवासियों की नियुक्ति कार्यकारिणी कौंसिलों में भी होनी चाहिये और जाति के भेद मिटान के जो चाहे अभी हात ही में महाराज की ओर से किये गये हैं उन्हें उन्हीं नौकरियों पर भारतवासियों को नियुक्त करके परा किया जाना चाहिये। सम्राट् के इन नये वादों की पूर्ति वैसी नहीं होनी चाहिये जैसी सन १८५८ की घोषणा की हुई है। अतः मैं, जिला शासन के भी अधिकार विभाजित होना चाहिये, और जनता के प्रतिनिधियों की जिला शासन के काम में सहायता ली जानी चाहिये।

मेरा विचार है कि यदि यह सुधार कर दिये जायेंगे तो जनता का प्रान्तिक, जिला और स्थानिक शासन में वास्तविक दिलचस्पी पदा हो जायगी। और इन्हीं के साथ २ यदि दो और महत्वपूर्ण मामलों का उचित और सतोप जनक निपटारा हो जाय तो मेरा विश्वास है कि उत्तम

मान स्थिति सम्बल जायगी। वे दो मामले बगभग को रद्द करके बंगाल प्रान्तों को सम्मिलित करना और राजनैतिक अपराधियों को क्षमा प्रदान करना है। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जब तक बगभग में किसी प्रकार परिवर्तन न होगा, बंगाल में शान्ति न हो सकेगी और सारे भारतवर्ष में उस समय तक अशान्ति फैली रहेगी जब तक बंगाल में शान्ति न हो जाय। हाल में विद्रोह के मुकद्दमों से लोगों के ठिला में बहुत कुछ मनमुटाव, उत्तेजना और सन्नोभ उत्पन्न हो गया है। और जब तक यह मनमुटाव उन अभियुक्तों और दंडित मनुष्यों को जिनमें केवल मतभेद रखन के कारण ही दंड मिला है, क्षमा प्रदान करके मेट न दिया जायगा, तब तक नए सुधारों में बहुत कुछ सार होने पर भी उनका काफी प्रभाव न पड़ सकेगा। मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार सच्चे और स्थायी सतोष उत्पन्न करने का केवल यही एक ढंग है और यदि लार्ड मार्ले और लार्ड मिटो ने उसे स्वीकार किया और बिना विलम्ब किए ही स्वीकार किया, तो अग्रज ही इसका बड़ा अच्छा परिणाम होगा, तथा उन दोनों लार्डों के नाम लार्ड केनिंग और लार्ड रिपन के नामों के साथ भावी पीढ़िया बड़े आदर से याद करेंगी।

परन्तु यदि यह अग्रसर हाथ से री दिया गया, यदि सुधारों में उतना सार न हुआ जितना होना चाहिए, या उनके साथ साथ उन दो मामलों का जिनका अभी मतं जिक्र किया है, सतोषजनक निपटारा न हुआ, तो फिर मुझे भय है कि सरकार को भारतवर्ष के कुछ भागों में फौजी कानून जारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि एक दफा फौजी कानून जारी हो गया तो ब्रिटिश सरकार का जो

भैतिक प्रभाव है, और जिसके बल पर राज्य स्थित है, उसका सारे देश में अन्त हो जायगा। और फिर इसका फल क्या होगा ? यह विचार करते हुए सिर चाकर जाने लगता है।

तीसरा भाग



शिक्षा-सम्बन्धी

फरगुसन कालेज से बिदाई



१६ सितम्बर सन् १९०२ ई० को शुक्रवार के दिन फरगुसन कालेज से अपना सम्बन्ध छोड़ते हुए मिस्टर गोखले को 'कालेज के विद्यार्थियों ने एक अभिनन्दनपत्र दिया था। उसके उत्तर में मिस्टर गोखले ने निम्न लिखित वक्तुता दी।

प्रिन्सिपल महोदय, अध्यापको तथा विद्यार्थियों, जो अभिनन्दनपत्र आप लोगों ने इस समय दिया है उसके उत्तर में मेरा हृदय बिना कणार्द्र हुए नहीं रह सकता और न मैं उस बड़ी कृपा के लिये, जो आपने आज मेरे ऊपर की है, धन्यवाद ही देने में समर्थ हूँ। ससार की सब वस्तुओं से अलग होने में दुःख होता है, परन्तु जिससे घनिष्ट सम्बन्ध है उससे पुराना रिस्ता तोड़ने और बिदाई लेने में उस दुःख से कहीं बड़कर क्लेश होता है जो किसी दूसरी वस्तु से नाता साँझने में हुआ करता है। अठारह वर्ष पर्यन्त अपनी शक्तयानुसार जो कुछ मुझसे हो सका मैंने इस संस्था की वृद्धि के लिये प्रयत्न किया। भलाइयों में, बुराइयों में, धूप में और आँधी में, मैंने इस पाठशाले के लिये कोशिश की और मेरा एक मात्र उद्देश्य यही रहा कि इसकी बेहतरों किस प्रकार से हो। अन्त में, इस कालेज से अपने को अलग समझना मेरे लिये असम्भव हो गया। इस समय जब इस पाठशाले के सम्पूर्ण कार्यों से हाथ खींचने का समय आया है तो मेरा हृदय सम्मनित धन्यवाद और अतीव शोक से पूरित हो गया है।

मैं परमात्मा को कोटिश धन्यवाद देता हूँ जिनेकी कृपा
 ने मैं उस सकल को भलीभांति पूरा कर सका, जिसको
 इतने वर्ष पूर्व युवावस्था के जोश में आकर मैंने किया था ।
 मुझे इस बातकी परवाह नहीं कि भविष्य में क्या हो ; परन्तु
 अपने जीवन के इस अंश को मे यही प्रसन्नता और घमड़ के
 साथ अवलोकन करूंगा । और अपने दिल में कहूंगा कि पर
 मात्मा का धन्यवाद है, जिसने मुझे अपने प्रण के पालन करने में
 सहायता दी । परन्तु सज्जनो ! धन्यवाद देने के साथ ही
 साथ मुझे इस बात का बड़ा शोक भी है कि इस पाठशाला के
 लिये जी तोड़ कर काम करने की इतिथी हो रही है । आप
 लोग भली प्रकार समझ सकते हैं कि इस पाठशाला से सम्बन्ध
 छोड़ने में मुझे कितना शोक है जिसके लिये मैंने फोड़ बात
 उठा नहीं रखी । चाहे जिस क्षेत्र में मुझे काम करना पड़ा हो,
 परन्तु वह सदैव मेरी आँखों के सामने नाचता रहा । आप
 लोगों में से कुछ पूछेंगे, जैसा मेरे दूसरे मित्रों ने पूछा है, कि इस
 समय अलग होते हुए जय तुम्हें इतना शोक है तो तुम अपना
 सम्बन्ध कालेज में क्यों छाँड़ रहे हो । इस प्रश्नका मेरा उत्तर
 यह है कि मैंने चिरकाल पर्यन्त भीरु स्वरानतया सत्र यात्रों
 की समालोचना किये बिना इस पाठशाला को छोड़ने का
 निश्चय नहीं किया है । पहिली बात तो यह है कि मेरा स्वास्थ्य
 इस समय अब वैसा नहीं रहा जैसा पहिले था । गत वर्ष दिन
 प्रतिदिन, सप्ताह पतिमप्ताह, मुझे इस बात की चिन्ता लगी
 रही कि बीच में बिना विश्राम लिये मैं अपने कार्य को
 किस प्रकार समाप्त कर सकूंगा । उस समय भी जैसा
 आप लोगों में से बहुतों को मालूम है, मैं कालेज में अपने
 भर्तृव्यों को उतनी उत्तमता के साथ नहीं पालन कर सका

जितनी उम्मीदी के साथ मेरे सहकारियों ने किया था। यह एक बड़े अंशमजस का स्थान है कि मेरे सहकारियों ने मेरे विरुद्ध एक बात भी नहीं कही और मुझे उनकी इस कृपा का इस प्रकार घेजा लाम उठाने का कोई अधिकार भी नहीं है। आप लोगों को यह सर्वश्रेष्ठ नियम भली भाँति मालूम है कि जब कोई भोजन करने के लिये बैठे तो कुछ भूखा ही उसे उठ आना चाहिए अथवा जब मिन के मकान जाय तो दिन भर अतिथि मन्कार कराने के बजाय कुछ समय पूर्व ही उनसे विदाई ले ले। मैं मानता हूँ कि मेरे सहकारियों की राय में यह उदाहरण उपयुक्त नहीं है तथापि बलात् अटारह वर्ष पयन्त काम कर के मैंने सोचा कि मेरे लिये इस काम को दूसरे लोगों के लिये छोड़ कर इस पाठशाले से सम्बन्ध छोड़ना ही अच्छा है। परन्तु इस पाठशाले से सम्बन्ध ताड़ने का कारण केवल यही नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि यह प्रधान कारण नहीं है। मैं आप लोगों से साफ साफ कहता हूँ कि इसी तरह के दूसरे कारणों ने भी ऐसा करने के लिये मुझे विवश किया है। बहुत दिन हुये, मैंने एक मनुष्य की कहानी पढ़ी थी, जो समुद्र के किनारे रहता था। उसके साथ उसके प्रिय घरवाले भी थे। वह एक अच्छे श्रोपडे और खेतों का मालिक था, जिनसे उसको धन धान्य मिला करता था। लोगों ने समझा कि वह बहुत ही खुश है। परन्तु समुद्र उसके हृदय में एक विचित्र भावना उत्पन्न करता था। जब कि वह शान्त होता और एक सोते हुये लडके की तरह भन्दे सास लेता था, तो वह उसके हृदय पर नये भाव उत्पन्न करता था, और जब वह एक क्रोधित सिंह की तरह दहाड़ने लगता तो उसके हृदय में वह और ही भाव उत्पन्न करता

था। अन्ततोगत्वा, इस प्राणघातक आनन्द को बहुत दिन तक वह न लूट सका। उसने अपनी सब चीजें बाँध कर एक नाँव में रक्की, और उसी में बैठ कर उसने समुद्र का आश्रय लिया। लहरों ने दो मर्तवा टक्कर मारी, परन्तु उसने इस सूचना को कुछ भी परवाह न की। उसने तीसरी मर्तवा प्रयत्न किया, और निर्दयी समुद्र ने उसे डुबो दिया। किसी न किसी रूप में आज मेरी भी अगस्था ठोक उसी प्रकार है। यहाँ पर, इस कालेज में, मैं पूर्णरूप से कर रहा हूँ और अपने सहकारियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपना कर्तव्य पालन करता हूँ। वे मेरे दोषों पर कुछ भी ध्यान नहीं देने और मेरे छोटे से छोटे कामों की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उनकी इस उदारता ने मेरे हृदयतलपर बड़ा असर डाला है। इन बातों के होते हुये भी मैं इस काम को छोड़ कर सार्वजनिक के तूफानी, अनिश्चित और भयानक समुद्र पर जा रहा हूँ। और मेरे हृदय के अन्दर एक आवाज मुझे ऐसा करने के लिये बाधित भी करती है। मैं आप से सच सच कहता हूँ, और आप मुझ पर पूर्ण विश्वास भी रखिये, कि देश के विस्तोर्ण और उठने ही उत्तरदायित्व के काम करने के लिये मैं उस स्वच्छन्दकार्य में हाथ लगाता हूँ जो उससे कहीं अधिक कठिन है। इस देश के सार्वजनिक जीवन में इनाम तो बहुत थोड़े हैं, परन्तु कठिनाइयाँ और निराशायी बहुत हैं। करने के लिये काम बहुत है, और कोई नहीं कह सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। परन्तु एक बात स्पष्ट है। वे लोग, जिन्हें इस काम करने की आन्तरिक इच्छा है, अपने जीवन को ऐसे काम में आशा और धन्य के साथ समर्पण कर देते हैं, और

मिर्फ उसी आनन्द के इच्छुक होते हैं, जो नि स्वार्थ काम करने से प्राप्त होती है। यह पेना स्थान नहीं है जहाँ मैं अपनी भविष्य आशाओं अथवा कामों को बताऊँ। परन्तु एक बात मैं जानता हूँ, और वह यह है, कि चाहे मैं आगे आगे काम करता चला जाऊँ, और किसी रूप में सर्वसाधारण को लाभ पहुँचाऊँ, अथवा तूफान से पीड़ित ओर नौकाविहीन मत्ताह की भाँति मुझे लौटना पड़े, परन्तु, जैसा आप लोगों ने अपने अभिनन्दनपत्र में कहा है, मेरा ध्यान सर्वदा इस पाठशाले की ओर रहेगा और जब कभी मैं यहाँ आऊँगा तो मेरा इस पाठशाला में सच्चा स्वागत किया जायगा। इसके पृथक् कि मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँ, मैं एक बात फालेज के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि उनको इस पाठशाले का घमंड सदैव रहेगा। मैं आप लोगों से निदा होने वाला हूँ, और इसलिये इस विषय पर विस्तार पूर्वक नहीं कह सकता। मैंने भारतवर्षभर का भ्रमण किया है, और भिन्न भिन्न स्थानों के शिक्षा सम्बन्धी पाठशालाओं को देखने की स्वभावतः मेरी रुचि भी रही है। परन्तु देश भर में कोई ऐसा विद्यालय हमारे विद्यालय के सदृश नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिन में बहुत सामान है, और जो अपने इतिहास के लिये विख्यात हैं। परन्तु हमारी पाठशाला मेरे मित्र, मिस्टर पराजपे और मिस्टर राजराडे इत्यादि सज्जनों के सदृश मनुष्यों के आत्म त्याग से बड़ा हुआ है। इस विद्यालय का एक मुख्य उद्देश और एक मुख्य लक्ष्य है। उद्देश यह है कि आजकल के भाग्यवासी नैसर्गिक भाग्यताओं को छोड़ कर धार्मिक जोश और उन्माह से देश के एक ही काम के लिये एक सूत्र में रंध जायँ। लक्ष्य

इसका यह है कि हम लोग मदद करना स्वयं सीखें, दूसरों पर भरोसा न करें और अपना घोड़ा अपने ही पत्थरों पर ले लें। इस कालेज के विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस शिक्षा को सदैव अपने सामने रखेंगे और उस समय जब तुम उसकी घुराइयाँ करने में प्रवृत्त हो तब भी अपने पिता के दीपों की तरह उसकी शमा कर श्रद्धा, उत्साह और उदारता के साथ उसके लिये काम करोगे और यथाशक्ति उसको अधिक प्रसिद्ध करने और लाभकारी बनाने का प्रयत्न करोगे। अब सिधाय विदाई लेने के और कुछ कहना मेरे लिये शेष नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ इस समय मेरे दिमाग में नाच रहा है उसका बहुत थोड़ा भाग मैंने इस समय कहा। परन्तु चाहे मैं जितना कहूँ मेरे विचार भलीभाँति प्रकाशित नहीं हो सकते। मेरी इच्छा है कि आप लोग सकुशल रहें। आप लोगों से इस समय विलग होने में मैं समझता हूँ कि मैं अपने जीवन का अच्छा काम अपने पीछे छोड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों में से कुछ दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिये मेरे सहकारी हों ताकि हम लोग कभी कभी कालेज की दीवारों के अन्दर मिल जुल सकें। परमात्मा आपका और इस कालेज का कल्याण करे।

अवनत जातियों की उन्नति



(१९०३ ई० की २७ वीं अप्रैल को मिरर गोपाले ने धारवाड की प्रान्तीय सोशल कान्फरेन्स में अवनत जातियों की उन्नति के विषय का प्रस्ताव पेश करते हुए यह वक्तृता दी थी —)

समापति और तन्मय महोदय !

आज जो प्रस्ताव मुझे सौंपा गया है वह यह है — यह कान्फरेंस समझती है कि नीच जातियों की वर्तमान शोचनीय और गिरी दशा स्वयमेव और राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यन्त असन्तोषजनक है, और आशा करती है कि देश के सभी शुभचिन्तक अछूत जातियों की उन्नति में दत्तचित्त होना, उनमें आत्माभिमान भर देना तथा विद्या दान देने का उत्तम विधान करना अपना परम धर्म समझेंगे।

महाशयो ! मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुधा बिना कारण कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, परन्तु इस प्रस्ताव के शब्द इतने जोरदार नहीं जितने उनको होना उचित और अत्युचित है। इन नीच जातियों की दशा (इन्हें नीच जाति कहना दुःख है) केवल असन्तोषजनक ही नहीं, जैसा इस प्रस्ताव में दर्ज है, बल्कि सहृदयों के हृदय पर घोर धक्का पहुँचाने वाली, समाज की पैठड़ी रचना और सब से अधिक हमारी विज्ञान बुद्धिमान जनता के अन्यायपूर्ण व्यवहार को सूचिन करने वाली है।

मैं आज के विषय को पीराणिकी दृष्टि से देखने नहीं आया हूँ बल्कि न्याय, मनुष्यत्व तथा राष्ट्रीय स्वार्थ के नाते से अपने विचार प्रकट करने को। महाशयो ! मैं आश्चर्य करता हूँ कि कैसे कोई न्यायशील व्यक्ति यह देख सकता है कि एक ऐसे जीव पर जिनकी युधि, अययन, समझने की शक्ति, इत्यादि प्रायः मेरे और आपके से हैं, और जिसमें अनुभव करने की शक्ति की भी कमी नहीं, ऐसा पैशाचिक व्यवहार, फटकार, मानसिक और दैहिक अत्याचार, किया जाय, और सदा के लिए उनकी उन्नति के पथ के बाधक उपायों का प्रयोग कैसे होता है ? हम लोगों की न्याय बुद्धि के लिए यह असह्य है। यदि आप इस घोर अन्याय का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने को उनके स्थान में रखें और विचारें कि आप एक कुत्ते को, बिल्ली को और, तो क्या, अपने पालतू सुभर के बच्चे को झू सकते हैं, परन्तु इन मनुष्यों का, परमात्मा के इन तेज पूर्ण अंशों का, स्पर्श तक घृणारूप है। सदा से छाछित, इन मनुष्यों की यहाँ तक मानसिक अपनति हो गई है कि जब तो वे तुम्हारे व्यवहारों से असन्तोष भी प्रकट नहीं करते और समझते हैं कि इनसे अधिक और कुछ उनके भाग्य में बढ़ा ही नहीं।

मुझे आज से सात, आठ वर्ष हुए महात्मा रानाडे का एक व्याख्यान का स्मरण है। यह वह समय था जब मेरे भारतीय भाई अपने अफ्रीका प्रवासित भाइयों पर किये गए अत्याचारों की बात सुन सुन कर आठ, आठ आँसू रो और उन व्यवहारों का घोर विरोध कर रहे थे। हम लोगों के परम हितैषी महात्मा गान्धी अफ्रीका से कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर अपने भाइयों की दुर्दशा की बातें,—जैसे, वे नेटाल तथा अफ्रीका के अन्य प्रान्तों में 'फुट पाथ' पर तथा रेल

की प्रथम भेणी की गाड़ियों में नहीं चलने पाते हैं, पद पद पर धक्के खाते और होटलों में भाकने नहीं पाते हैं, इत्यादि—सुना रहे थे। हम लोगों के जातीय सम्मान में बड़े वेग से ज्वार आया था और बृटिश प्रजा कहला कर बृटिश उपनिवेशों में इस तरह फटकारा जाना सह्य नहीं जाता था। ऐसे सुसमय में महात्मा रानाडे ने हिन्दु क्लब में कुछ कहा था। महात्मा रानाडे में एक यह अपूर्व गुण था कि जब कभी उन्हें मालूम होता कि जनता इस समय जोश में है, वे तुरन्त उस सुभयसर को हाथ में ले, जातीय विचारों को ऐसा मरोड़ते कि जाति अपने जोश को ठीक मार्ग में ढगा देती और इधर उधर भटकने से बच जाती। जब सभी लोग अपने प्रवासी भाइयों पर किये गए अत्याचारों पर असन्तोष प्रकट कर रहे थे तब रानाडे ने उनके सम्मुख जाकर पूछा, “भाइयो, जरा विचार कर देखो तो सही कि तुम्हारे अपने ही पाप तो कोई ऐसे नहीं, जिनका यह प्रायश्चित्त हो रहा है।” मुझे उनके ठीक शब्द स्मरण नहीं। वे शब्द ये थे—“गपनी अन्तर्ज्योति का मानस मन्दिर में प्रकाश डालो, जो प्रकाश चाहते हो उसे दिल में खोजो।” रानाडे ने अपने साधारण ढङ्ग में अफ्रीका वासी भाइयों के कठिन उद्योग पर सहानुभूति प्रकाशित करते हुए कहना प्रारम्भ किया। उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि भारतवासी अपने प्रवासी भाइयों की स्थिति पर शोक प्रकट कर रहे हैं, उनका विश्वास था कि यह जागृति इस जाति की सूखी हड्डियों में एक बार पुनर्जीवन सञ्चार का निश्चयात्मक चिन्ह है। रानाडे ने पूछा, “भाइयो! क्या पद्दलित और पीड़ित प्रवासी भाइयों के साथ ही मापकी सहानुभूति का अन्त हो जाता है? अथवा यह सर्वसाधारण

को और प्रत्येक अन्याय और अत्याचार की ओर दिखलाई जाती है। विदेशियों पर आक्षेप करना बहुत सहज है परन्तु छिद्रान्त्रियों को न्याय से अपनी ओर भी देखना चाहिए और विचारना चाहिए कि वे लोग स्वयम् कहीं तक निर्दोष हैं।" रानाडे ने इतना कह कर अपने देश की नीच जातियों के साथ भिन्न भिन्न प्रान्तों में किये जाने वाले व्यवहारों का दिग्दर्शन कराया। इसका वर्णन ऐसे करुण शब्दों में किया गया कि सुनने वाले लज्जा, दुःख और श्लानि से पानी पानी हो गए। महात्मा ने ठोक ही पूछा कि उन लोगों के लिये जो स्वदेश में ऐसे घृणित अन्याय और अत्याचार को बिना जिह्वा हिलाए सह लेते हैं, विदेशियों पर सब प्रकार का बोपा रोपण करना कहीं तक न्याय-सङ्गत है? अतएव यह प्रश्न पहले तो सब प्रकार से न्याय की दृष्टि से देखने योग्य है, फिर मनुष्यत्व की दृष्टि से।

प्रायः प्रतिवादियों का कहना है कि यदि हमारे देश में जातिपाति के भेद हैं तो पाश्चात्य देशों में भी अनेक दल-बन्धियाँ हैं। इस विषय में दोनों देशों में बहुधा बहुत कम विभिन्नता है। परन्तु थोड़े विचार ही से मालूम हो जायगा कि यह सादृश्य बिल्कुल भूल है। पाश्चात्य दलों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हमारी जातियों की तरह उनके बीच में लोहे की मजबूत दीवारें नहीं गड़ी की गई हैं। मिस्टर चेम्बरलेन जो आज दिन ब्रिटिश सम्राज्य के गण्यमान्य व्यक्ति हैं एक दिन चमार का और फाटा उतारने वाले का काम करते थे। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि चेम्बरलेन स्वयं चमार का काम करते थे, परन्तु वह चमड़े के व्यवसाय से रुपया पैदा करते थे। आज चेम्बरलेन सम्राट के साथ भोजन करते

हैं, और देश के सर्वप्रधान व्यक्तियों के मंग पूर्णरूप से घरा-घरी का दर्जा रखकर व्यवहार करते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या कभी कोई भी मास्त्री घमार भारतवर्ष में इसी प्रकार सामाजिक समानता का दावा कर सकता है ? एक बड़े लेखक का कथन है कि जातिभेद समाज की रक्षा के लिये अत्यावश्यक है, परन्तु उसी भाति अभ्युदय के पथ का बाधक भी है। और मैं भी इस बातका अनुमोदन करता हूँ। आप यदि हजार वर्ष पहले घाले स्थान पर ही जमे रहना चाहते हैं तब तो अब श्व ही जाति भेद के उठाने की आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि आप उस फौचड से जिस में फंसे आपको इतने दिन हुए अब निकलने के इच्छुक हों तब तो आपका पुराने लफ्कीर के फकीर बनने में निस्तार नहीं। वर्तमान सभ्यता ने समानता को अपना मूल मंत्र समझा है और उँचाई निचोई के पुराने जमाने के व्यापक विचारों का यहिष्कार होने लगा है। आजकल मनुष्यत्व का उद्देश्य यही माना जाता है कि हम लोग पर्वदलित स्वदेशवासियों की अवस्था को उन्नत करके उनके स्वर्गों का सम्मान करें।

अन्त में, सज्जनों ! यह राष्ट्रीय स्वार्थ का प्रश्न है। यदि स्वदेशवासियों के अधिकारों को अधिष्ठा, भूर्यता और अन्धकार के गड्ढे में पड़ा हुआ छोड़ दें तो किस प्रकार हम लोग अपने राष्ट्रीय लालसाओं को पूरा कर सकेंगे ? कैसे विश्व के उन्नत राष्ट्रों के बीच हम लोगों का नाम गिना जायगा ? जब तक हमारे ये देशवासी नैतिक तथा मानसिक उन्नति के द्वारा शनैः २ उच्च स्थान पर नहीं उठाये जायेंगे तब तक यह कब सम्भव है कि वे लोग हम लोगों के विचारों और आशाओं में योग देकर हम लोगों के उद्योग में हाथ उठावें। आप विचार

नहीं करते हैं कि राष्ट्रीय उन्नति के कामों में इन अधिकांश भाइयों का जोश हम लोगों को बिना उनकी सहायता किये कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं समझता हूँ कि विचारणीय और विवेचक महात्मा विवेकानन्द ने इस मत को पूरे तौर से ग्रहण किया था। मेरा विचार है कि जब तक नीच जातियाँ हम लोगों का काम में हाथ नहीं बँटाती तब तक हम लोग एक राष्ट्र के नाम से कहे जाने के योग्य हो ही नहीं सकते।

मैं पूछता हूँ कि क्या यह आत्म गौरव की बात है कि ये नीच जातियाँ, जब तक अभागी हिन्दू जाति के विद्वान पक्षों के नीचे पड़ी हैं, हमारे द्वार से दुतकारी जायँ, धक्के खायँ और ईसाइयत के शुभ नाम के स्पर्शमात्र ही से, कोट, पैन्ट और हेट के धारण करते ही, हम से हाथ मिलाने के योग्य हो जायँ और सभी प्रकार सम्भव कहे जाने लगें ? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य इस अवस्था को सन्तोषजनक न कहेगा। मैं यह नहीं कहता कि ये जातियाँ एकवारगी उन्नत हो कर देश की उच्च जातियों के तुल्य हो जायँ, और ऐसी किसी की आशा भी नहीं। यह काम अवश्य शनैः २ होगा और यह हो भी नहीं सकता है जब इनको पूरा विद्यादान दिया जाय और उनकी स्थिति अच्छी बनाई जाय। मेरा विश्वास है कि भारत वर्ष की वर्तमान अवस्था में इस काम से बढ़ कर पथित्र और उच्च कार्य नहीं हो सकता। यदि विद्वान युवकों के लिए इस समय कोई सामाजिक सुधार का सर्वोच्च कार्य ऐसा है जिस में उन लोगों को अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए तो वह यही है, यही है। उन सौ, सौ प्रेज्युपेंटों के बीच जिन्हें प्रति वर्ष युनिवर्सिटी उत्पन्न है क्या कुछ मनुष्य, पांच सैकड़े, चार सैकड़े, तीन सैकड़े, अजी, एक सैकड़े भी ऐसे नहीं जो

इस पवित्र कार्य में अपने को सवया समर्पण करने के लिये तैयार हों? मेरी यह प्रार्थना प्रौढ़ों और वृद्धों से नहीं है जिनका जीवन एक न एक प्रकार से किसी काम के साथ लग गया है बल्कि मैं उन नवयुवकों से अपील करता हूँ जिन्होंने अभी तक यह निश्चय नहीं कर लिया है कि उनका भविष्य क्या होगा और जिनको अपनी प्राप्त विद्या को योग्यकार्य में लगाने की वास्तविक अभिलाषा है। वर्तमान समय में देश की सब से बड़ी आवश्यकता शिक्षित युवकों में आत्मत्याग का उत्पन्न होना है, और ये लोग मेरी बातों का विश्वास करें कि इन नीच जातियों की मानसिक और चरित्र सम्बन्धी उन्नति और उनके हितसाधन से बढ़ कर और कोई ऐसा शुभकार्य नहीं जिस में ये लोग अपने बहुमूल्य जीवन को समर्पित करें।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कानून का मसौदा

(१६ मार्च सन् १९११ ई० को माननीय मि० गोखले ने यडी व्यवस्थापक सभा में प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कानून का मसौदा पेश करते हुए निम्न लिपित वक्तृता दी थी —)

श्रीमन् महोदय ! मैं आप की आशा चाहता हूँ कि एक कानून का मसौदा कौंसिल के समक्ष पेश करूँ, जिस का उद्देश्य यह है कि सारे भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार का परमोत्तम प्रयत्न किया जाय ।

कौंसिल के सदस्य महानुभावों को विदित होगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों मैंने एक प्रस्ताव पेश करने का सहास किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा सारे भारतवर्ष में मुफ्त और अनिवार्य कर दी जाय, और शासकों का एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो इसके सम्बन्ध में उचित मन्तव्य सोचे । उस अवसर पर जो विवाद हुआ था उसमें होम सदस्य, होम मंत्री और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल को सम्मिलित करके कौंसिल के १५ सदस्यों ने यहस की थी । उस समय तक शिक्षा के लिए कोई मुख्य विभाग इस कौंसिल में न था और शिक्षा विभाग पुलिस और जेल विभागों के साथ साथ होम डिपार्टमेन्ट ही में शामिल था । विवाद के अनंतर जब होम सदस्य ने इस बात का विश्वास दिलाया कि इस प्रश्न पर गवर्नमेन्ट भली भाँति विचार करेगी तो प्रस्ताव उस समय घापस ले लिया गया ।

महाशय ! अब इस बात को १२ महीने से अधिक समय बीत चुका और इतने अर्से में इस मामले में पूरी उन्नति हुई

है। और एक तरह से तो इस मामले ने आशा से अधिक तरकी की है, अर्थात् मेरे अनुमान से भी अधिक। इस विषय में मेरा एक प्रस्ताव यह था कि इस कौंसिल में शिक्षा विभाग का एक मंत्री रहना चाहिये और क्रमशः फिर एक सदस्य भी रखवा जाय, जिसके सिपुर्द केवल शिक्षा सम्बन्धी काम हो। सन्तोष की बात है कि गवर्नमेन्ट ने एक साथ ही शिक्षा विभाग को पृथक् कर दिया और माननीय मिस्टर बटलर साहब उस शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी नियुक्त किये गये। इनकी नियुक्ति पर सब ने सन्तोष प्रकट किया है और सब लोग इनसे सहमत हैं कि बटलर साहब वास्तव में बड़े निपुण और कार्यशील हैं। परन्तु कार्य शीलता से भी अधिक जिस बात की आवश्यकता थी और जिसका मैं सम्मान करता हूँ वह यह है कि भारतवर्ष की उन्नता से उनकी उदारता और सहानुभूति के जोश को धारा मभी राक तनिक भी शुष्क नहीं हुई है। यह जोश वह चीज है जो आरम्भ में थोड़ा बहुत सभी में होती है और जिसके बिना मनुष्य का उन्नति सम्बन्धी कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता।

महोदय ! मेरा अनुमान है कि शिक्षा विभाग के स्थापित होने से हमको यह आशा रखना चाहिए कि वह समय जब समस्त भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार हो जायगा, अब निकट आता जाता है। और देश में शिक्षा को व्यापक बनाने के विषय में लोगों की राय शक्तिशाली होती जा रही है। इससे स्पष्ट है कि गत वर्ष के विचार के अनंतर इस मामले पर समाचार पत्रों में अधिक जोर दिया गया है और गत दिसम्बर में केवल भारतवर्ष की जातीय कांग्रेस ही ने प्रयाग में इसके अनुकूल प्रस्ताव नहीं पास किया, बल्कि

मुसलिम लीग ने भी, जिसका वार्षिकोत्सव नागपुर में हुआ था इसके पक्ष में राय दी। इसी तरह गवर्नमेन्ट की ओर से भी उक्त प्रोपणा-पत्र में, जो गत जूलोई में हीम जाफ कामन्स में नये शिक्षा विभाग के स्थापित होने पर प्रकाशित किया गया था, यही प्रकट होता है। अटर सेक्रेटरी महोदय ने कहा था कि शिक्षा-विभाग के स्थापित करने का एक उद्देश्य यह भी है कि भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार अच्छी तरह हो। और उ। महत्त्वपूर्ण शब्दों से, जो श्रीमान् ने जातीय कांग्रेस के अभिनन्दन पत्र के उत्तर में शिक्षा के सम्बन्ध में कहे थे, यही प्रकट होता है। गङ्गार साहय की शिक्षा सम्बन्धी कान्फरेंस से भी यही बात होता है कि गवर्नमेन्ट अब इस बात की आवश्यकता को भली प्रकार अनुभव करने लगी है कि शिक्षा सम्बन्धी मामलों में उसको अपनी चाल अच्छी तरह तैयार करनी चाहिये।

इन सब बातों पर लक्ष्य रखते हुए, मेरी राय में यह अवसर इस काम के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ता है कि हम कौंसिल और देण के सामने शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रस्ताव पेश करें, जो इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य है। और मैं जाशा करता हूँ कि कौंसिल इस मसौदे को पेश करने की बात स्वीकार करेगी।

श्रीमन्महोदय। मैं विश्वास करता हूँ कि गवर्नमेन्ट ने मेरे उक्त प्रस्तावों पर, जो मैंने गत वर्ष इस विषय में पेश किये थे अच्छी तरह विचार कर लिया होगा। और मैं जाशा करता हूँ कि माननीय मेम्बर महोदय मुझे सूचित करेंगे कि उन्होंने ने उससे क्या, क्या परिणाम निकाले हैं।

जिस यान पर मैंने अधिक ध्यान दिनाया है वह यह है कि नारे भारतवर्ष में, जहां तक प्राथमिक शिक्षा का जिद्द है, गवर्नमेन्ट उसको धीरे धीरे अनिवार्य और मुक्त कर देने की चेष्टा आरम्भ करे। और यही प्रस्ताव इस मसाले में भी है जिसे मैं पेश कर रहा हूँ। श्रीमन्, अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय व्यतीत हुआ, एक विद्वान अमेरिकन ने अपनी वक्तृता में अपने देशवासियों से कहा था कि यदि उसमें कोई ऐसी अद्भुत शक्ति होती कि वह अपनी वक्तृता से सत्तार की सारी जातियों को होशियार कर सकता तो उसे प्येबल यही कहना था कि तुम "अपने बालकों को शिखा दो, अपने सब बालकों को शिखा दो, अपने बालकों में से प्रत्येक को शिक्षा दो।" वक्ता की इस सिद्धान्त से प्रकट होने वाली असाधारण बुद्धि मता और मनुष्योचित सहायभूति के प्रभाव को सारा देश अनुभव कर चुका है। और अब लगभग प्रत्येक सभ्य देश में वक्ता की गवर्नमेन्ट इस कर्त्तव्य को अपना मुख्य कर्त्तव्य मानने लगी है। यदि प्राथमिक शिक्षा का लाभ सिर्फ इतना ही समझा जाय कि हम जे हम लिखना पढ़ना सीख जायगे, तो भी इनका प्रचार सारे देश में करना कोई टोटी बात नहीं है। नितान्त निरक्षरता की अपेक्षा थोड़े बहुत लिखने पढ़ने का भी यदि देश में प्रचार हो जाय तो बहुत बड़ी बात होगी। परन्तु सर्वसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का फलतः यही अर्थ नहीं कि लिखने पढ़ने की चीजों को योग्यता जिन लोगों को हो जाती है बल्कि इसका यह अर्थ है कि वे मनुष्य जीवन का महत्व समझने लगते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है और वे अच्छे रास्ते पर आजाते हैं। इसका यह परिणाम होता है कि हर मनुष्य की सभ्यता और शिक्षा का मूल्य बढ़

मुसलिम लीग ने भी, जिसका धार्मिकोत्सव नागपुर में हुआ था इसके पक्ष में राय दी। इसी तरह गवर्नमेन्ट की ओर से भी उच्च प्रोपणा-पत्र से, जो गत जीलार्ड में होन आफ कामन्स में गये शिक्षा विभाग के स्थापित होने पर प्रकाशित किया गया था, यही प्रकट होता है। अंडर-सेक्रेटरी महोदय ने कहा था कि शिक्षा-विभाग के स्थापित करने का एक उद्देश्य यह भी है कि भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार अच्छी तरह हो। और उन महत्वपूर्ण शब्दों से, जो श्रीमान् ने जातीय कांग्रेस के अभिनन्दन पत्र के उत्तर में शिक्षा के सम्बन्ध में कहे थे, यही प्रकट होता है। गडलर साहब की शिक्षा सम्बन्धी कान्फरेंस से भी यही घात होता है कि गवर्नमेन्ट अब इस घात की आवश्यकता को भली प्रकार अनुभव करने लगी है कि शिक्षा सम्बन्धी मामलों में उसको अपनी चाल अच्छी तरह तैयार करनी चाहिये।

इन सब बातों पर लक्ष्य रखते हुए, मेरी राय में यह अवसर इस काम के लिए बहुत उपयुक्त जान पड़ता है कि हम कॉन्सिल और देश के सामने शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रस्ताव पेश करें, जो इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य है। और मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सिल इस मसौदे को पेश करने की बात स्वीकार करेगी।

श्रीमन्महोदय ! मैं विश्वास करता हूँ कि गवर्नमेन्ट ने मेरे उन प्रस्तावों पर, जो मैंने गतवर्ष इस विषय में पेश किये थे अच्छी तरह विचार कर लिया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मेम्बर महोदय मुझे सूचित करेंगे कि उन्होंने ने उससे क्या, क्या परिणाम निकाले हैं।

जिस बात पर मैंने अधिक ध्यान दिलाया है वह यह है कि सारे भारतवर्ष में, जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का जिक्र है, गवर्नमेन्ट उसको धीरे धीरे अनिवार्य और मुरू कर देने की चेष्टा आरम्भ करे। और यही प्रस्ताव इन्म मसादे में भी है जिसे मैं पेश कर रहा हूँ। श्रीमन्, अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय व्यतीत हुआ, एक विद्वान अमेरिकन ने अपनी वक्तृता में अने देशवासियों से कहा था कि यदि उसमें कोई ऐसी अद्भुत शक्ति होती कि वह अपनी वक्तृता से ससार की सारी जातियों को होशियार कर सकता तो उसे फेरल यही कहना था कि तुम "अपने बालकों को शिक्षा दो, अपने सब बालकों को शिक्षा दो, अपने बालकों में से प्रत्येक को शिक्षा दो।" यत्ना की इन सिद्धान्त से प्रकट होने वाली अन्नाधारण बुद्धि मता और मनुष्योचित सहायभूति के प्रभाव को सारा देश अनुभव कर चुका है। और अब लगभग प्रत्येक सभ्य देश में वहाँ की गवर्नमेन्ट इस कर्त्तव्य को अपना मुख्य कर्त्तव्य मानने लगी है। यदि प्राथमिक शिक्षा का लाभ सिर्फ इतना ही समझा जाय कि इस से हम लिखना पढ़ना सीख जायगे, तो भी इसका प्रचार सारे देश में करना कोई टोटी बात नहीं है। नितान्त निरक्षरता की अपेक्षा थोड़े बहुत लिखने पढ़ने का भी यदि देश में प्रचार हो जाय तो बहुत बड़ी बात होगी। परन्तु सर्वसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का फेरल यही अर्थ नहीं कि लिखने पढ़ने की थोड़ी सी योग्यता जिन लोगों को हो जाती है वलिक इसका यह अर्थ है कि वे मनुष्य जीवन का महत्व समझने लगते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है और वे अच्छे रास्ते पर आजाते हैं। इसका यह परिणाम होता है कि हर मनुष्य की सभ्यता और शिष्टता का मूल्य बढ़

जाता है, और जाति में ज्ञान और बुद्धि की पूजा में वृद्धि हो जाती है। जो आदमी इन बातों के महत्त्व को नहीं समझता उसके लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं कि वह आरोग्यता पर उत्तम जल वायु से पडने वाले प्रभाव को भी मिथ्या समझे। मैं अनुमान करता हूँ कि किसी गवर्नमेन्ट के प्रजावात्सल्य का अंदाजा इस बात से भलीभांति लगाया जा सकता है कि वह अपनी प्रजा में सर्व साधारण की शिक्षा के सम्यग्ध में अपना कर्त्तव्य फंदा तक पालन करती है। अतएव यदि हम इसी खयाल से इस देश की गवर्नमेन्ट के गुणों का अंदाजा करें तो हमको अवश्य यह कहना पड़ेगा कि यहाँ की गवर्नमेन्ट को अब जागना चाहिये और पहले की अपेक्षा अपने कर्त्तव्य-पालन की ओर अधिक ध्यान देना और उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिये। इसके पहले कि इसकी गणना उचित रीति से ससार के अन्य सम्यग् राज्यों के साथ की जाय, यह देखना जरूरी है कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार कितना है। कितने लोग लिख पढ़ सकते हैं या इस समय कुल जनसंख्या में से पाठशालाओं में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा के लिए कितना धन व्यय किया जाता है। और किन सिद्धान्तों पर शिक्षा दी जा रही है। इन में से किसी बात पर लक्ष्य रख कर देखा जाय तो विदित होगा कि ससार के अन्य सम्यग् देशों की अपेक्षा अभी भारत वर्ष बहुत पीछे घसित रहा है। यदि केवल पढ़े लिखे की संख्या के हिसाब से देखिये तो १९०१ ई० की जनसंख्या से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में केवल ६ फी सैकड़ा आदमी लिख पढ़ सकते थे। उसके विरुद्ध योरूप के सब से पिछड़े हुए देश, रूस, में २० फी सैकड़ा मनुष्य ऐसे हैं जो लिख

पढ़े कहे जा सकते हैं। और उन्नत जातियों में तो योरूप, अमेरिका, आस्ट्रिया इत्यादि में ऐसे अनेक देश हैं जिनमें लगभग समस्त जन संख्या लिखना पढ़ना जानती है। उन यशों की संख्याओं को जो इस समय पाठशालाओं में प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं, मैं अपनी गत वर्ष की वक्तृता में से एकबार फिर उद्धृत करूँगा --

संयुक्त प्रदेश अमेरिका में कुल जन संख्या में से ११ फी सैकड़ा इस समय पाठशालाओं में प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं। केनाडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, सुइजरलैंड में यह संख्या १० से २० प्रति सैकड़ा तक पाई जाती है। आस्ट्रिया, नार्वे, नीदरलैंड में १५ और १७ के मध्य में, फ्रान्स में १४ प्रति सैकड़ा से कुछ अधिक, डेन्मार्क में १३ फी सैकड़ा, स्वीडन में १४ फी सदी, बेल्जियम में १२, जापान में ११ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं। इटली, ग्रीस और स्पेन में यह संख्या ८ और १ के बीच में है और पुर्तगाल और रूस में ४-५ के दमियान। इसके विपरीत भारतवर्ष में केवल १.५ ।

शिक्षा पद्धति पर ध्यान दीजिये तो विदित होगा कि अधिकांश देशों में प्राथमिक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य है और किसी किसी में अनिवार्य है, पर इस विषय में अधिक सख्ती बहा नहीं की जाती है। परन्तु यदि भारतवर्ष की ओर दृष्टिपात कीजिये तो यहाँ न मुक्त है, न अनिवार्य। इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, सुइजरलैंड, आस्ट्रिया, हंगरी इटली, बेल्जियम, डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन, अमेरिका आस्ट्रेलिया, केनाडा और जापान में मुक्त और अनिवार्य दोनों ही हैं, और सामान्यतः ६ वर्ष के लिए, बल्कि कई दशाओं में नौवय

तक के लिए, अनिवार्य कर दी गई है। एंग्लैंड में अनिवार्य है, परन्तु मुक्त नहीं है। स्पेन, पुर्तगाल, - ग्रीस, बल्गारिया, सर्बिया और रूमानिया में मुक्त है और यद्यपि कानूनन अनिवार्य भी है, परन्तु इनके लिए कोई सख्ती नहीं की जाती। टर्की में भी मुक्त है और नाममात्र के लिए अनिवार्य है। रूस में अनिवार्य नहीं है तथापि एक नियत सीमा तक मुक्त है।

अब यदि समस्त देशों के फी आदमी के व्यय का हिस्सा लगा कर देखा जाय तो भी यही प्रकट होता है, कि भारत वर्ष ही सबसे पीछे है। संयुक्त प्रदेश, अमेरिका, में सब से अधिक, अर्थात् फी आदमी की शिक्षा के लिये १६ शिलिङ्ग व्यय किये जाते हैं। स्वीटजरलैंड १३ शि० ८ पेंस, आस्ट्रेलिया ११ शि० ३ पेंस, इंग्लैंड और वेल्स १० शिलिङ्ग, केनाडा ६ शि० ८ पेंस, स्कॉटलैंड ६ शिलिङ्ग ७ पेंस, जर्मनी ६ शिलिङ्ग १० पे०, आयरलैंड ६ शि० ५ पेंस, नीदरलैंड ६ शिलिङ्ग ४ १/२ पेंस, स्वीडन ५ शि० ७ पे०, बेलजियम ५ शि० ४ पे०, नार्वे ५ शि० १ पे०, फ्रांस ४ शिलिङ्ग १ पेंस, आस्ट्रिया ३ शिलिङ्ग १ १/२ पेंस, स्पेन १ शिलिङ्ग १ १/२ पेंस, इटाली १ शिलिङ्ग ७ १/२ पेंस, सर्बिया और जापान में एक शिलिङ्ग २ पेंस, रूस में ७ १/२ पेंस और दौर्भाग्य भारत वर्ष में केवल १ पेंस। श्री मन्महोदय। उत्तर में शायद यह कहा जा सकता है कि माध्यामिक शिक्षा का प्रचार पाश्चात्य देशों का मुख्य उद्देश्य है और पाश्चात्य सभ्यता को भारत में आये अभी केवल एक शताब्दी हुई है। अतएव पाश्चात्य देशों से उसका मुकाबिला करना थोड़ासा अन्याय है परन्तु मेरी राय में यह विवाद मानने के योग्य नहीं, क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी तो शिक्षा का प्रचार थोड़े ही दिन से हुआ है। इसके अतिरिक्त जापान में भी जहां पाश्चात्य सभ्यता

का विकास हुए ४० साल में अधिक समय नहीं हुआ, सामान्य शिक्षा अनिवार्य रीति से प्रचलित की गई है। और यदि फर्राग कीजाय कि पाश्चात्य देशों से इसका मुकाबला करना उचित नहीं तो भी इसका क्या जवाब है कि सीलोन, फिलपाइन और बरौदे की अपक्षा भी भारतवर्ष क्यों बहुत पीछे पड़ा हुआ है ? फिलपाइन को अमेरिका के हाथ में गये हुए अभी केवल १३ वर्ष व्यतीत हुए हैं। यह तो फर्क नहीं जा सकता कि फिलपाइन के निवासी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता अथवा शिक्षा के उत्साह में हिन्दुओं से बड़े चढ़े हैं। तो भी इन द्वीपों में सर्व सामान्य शिक्षा विभाग में ऐसी आश्चर्यजनक उन्नति हुई है कि अमेरिका के निदानों और उसके साहस पर हम मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं। जब तक इन द्वीपों पर रपेन का अधिकार था, वहाँ कोई शिक्षा उन्नति प्रचलित थी ही नहीं, जयसे अमेरिका ने उन पर अधिकार जमाया, सामान्य शिक्षा का पूरा पूरा प्रयत्न किया गया है। शिक्षा वहाँ मुक्त दी जाती है पर कानून अभी अनिवार्य नहीं है, तथापि इसके प्रस्ताव वहाँ पेश हो रहे हैं। वहाँ तक उत्साह उठा हुआ है कि बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों ने अपनी आन्ना से शिक्षा अनिवार्य कर दी है और यद्यपि वह उचित नहीं तथापि कोई उसमें कुछ विवाद नहीं करता और प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करते हैं। वहाँ शिक्षा वहाँ किन्तनी जल्दी उन्नति कर रही है, इनका अनुमान इससे किया जा सकता है कि पाँच बरस में १६०३ से १६०८ तक में वहाँ विद्यार्थियों की संख्या दूनी होगई अर्थात् २५०००० से ३६०००० पर पहुँची। यदि इस संख्या का अनुमान जनसंख्या के हिसाब से किया जाय तो भी प्रति सैकड़ा ६ लड़के वहाँ

शिक्षा पाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में केवल २ प्रति सैकड़ा सीलोन की अवस्था दक्षिण-भारत से बहुत कुछ मिलती हुई है, तथापि शिक्षा के विषय में सीलोन भारतवर्ष से कहीं अच्छा है। वहाँ प्राथमिक-शिक्षा का प्रबन्ध दो प्रकार से है। एक तो सरकारी स्कूलों के द्वारा और दूसरे इम्दादी पाठशालाओं के द्वारा। $\frac{1}{3}$ के लगभग तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और $\frac{2}{3}$ इम्दादी पाठशालाओं में। सरकारी स्कूलों में बहुत असें से शिक्षा अनिवार्य है, और यदि इसमें माता पिता कुछ विवाद करें तो स्थानीय अदालत के समक्ष वे उत्तरदाता होते हैं और उन पर जुर्माना भी हो सकता है। सं० १९०१ में एक कमेटी नियुक्त की गई थी जो गवर्नमेन्ट की ओर से शिक्षा प्रचार के उपाय सोचे। उसने राय दी कि गवर्नमेन्ट मा बाप को बाध्य करे कि वह अपने लड़के को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलावे। १९०५ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसने निम्न लिखित प्रस्ताव पेश किये थे जिन्हें उपनि चेशमन्त्री ने स्वीकार कर लिया। (१) यह कि उन भागों में जहाँ गवर्नर जनरल का शासन है, ६ बरस तक के लड़के पाठशालाओं में उपस्थित होने पर बाध्य किये जायें। (२) फीस न ली जाय। (३) बालको की शिक्षा का प्रबन्ध अधिक ध्यान देकर किया जाय। (४) हर जिले में पृथक् पृथक् कमेटियाँ नियुक्त की जायें जो शिक्षा का निरीक्षण करें। (५) सड़को के महसूल जो आमदनी होती है वह इन कमेटियों को सौंप दी जाय जिससे वह एक शिक्षा फंड स्थापित करें। पहली बार १९०८ ई० में इन नियमों के अनुसार १६ जिलों में काररवाई की गई। और १९०६ ई० की सरकारी रिपोर्ट में निम्नलिखित वाक्यों का उल्लेख है — “अब तक कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित

महोँ हुई और इम्दादी पाठशालाओं के प्रयन्धको को जिन फठिनाइयो का भय था वे सब निमल होंगी । और आशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक सब जिलों में भली भाति उक्त काररवाई प्रचलित होजायगी" । १९०१ में उन विद्याधियों की कुल सख्या जो प्राथमिक शिक्षा पा रहे थे, २३७००० थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल जन संख्या में से ६१/१०० प्रति सैकड़ा शिक्षा पा रहे हैं ।

- भारतवर्ष की सीमा के भीतर महाराज गायकवाड ने शिक्षा-प्रचार के लिये जिस तल्लीनता के साथ उद्योग किया है उसके लिये वे हम सब से फोटिश धन्यवाद के भाजन हैं । १८ वर्ष हुए जब महाराजा साहब ने अपने राज्य के अमरैली तालुके के देहातों में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल स्थापित किया और कमरा आठ वर्ष के भीतर पूरे तालुके में शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर दी गई । अन्त में सन् १९०७ ई० में प्राथमिक शिक्षा १२ बरस के लड़कों और ६ से १० साल तक की लड़कियों के लिए सारे राज्य में मुक्त और अनिवार्य हो गई । अब लड़कियों की अग्रस्था १० से ११ साल कर दी गई है । गत दो बरस की बड़ीदा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट बड़ी चित्ताकर्षक है, जिससे प्रकट होता है कि १९०६ में विद्यार्थियों की सख्या १६५,००० थी जिससे ज्ञात होता है कि आठ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में शिक्षा पा रहे थे । यदि पाठशालाओं में जाने वाले लड़कों का हिसाब लगाया जाय तो ७६१/१०० प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में पढ़ते थे । इसके विरुद्ध ब्रिटिश भारत में केवल २११/१०० प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में हैं । पाठशालाओं में जाने वाली लड़कियों की सख्या उक्त राज्य में ४७ और ब्रिटिश भारत में ४

शिक्षा पाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में केवल २ प्रति सैकड़ा! सीलोन की अवस्था दक्षिण-भारत से बहुत कुछ मिलती हुई है, तथापि शिक्षा के विषय में सीलोन भारतवर्ष से कहीं अच्छा है। वहाँ प्राथमिक-शिक्षा का प्रबन्ध दो प्रकार से है। एक तो सरकारी स्कूलों के द्वारा और दूसरे इम्दादी पाठशालाओं के द्वारा। $\frac{1}{2}$ के लगभग तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और $\frac{1}{2}$ इम्दादी पाठशालाओं में। सरकारी स्कूलों में बहुत अर्से से शिक्षा अनिवार्य है, और यदि इसमें माता-पिता कुछ विवाद करें तो स्थानीय अदालत के समक्ष वे उत्तरदाता होते हैं और उन पर जुर्माना भी हो सकता है। सन् १९०१ में एक कमेटी नियुक्त की गई थी जो गवर्नमेन्ट की ओर से शिक्षा प्रचार के उपाय सोचे। उसने राय दी कि गवर्नमेन्ट मा बाप को बाध्य करे कि वह अपने लड़के को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलाये। १९०५ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसने निम्न लिखित प्रस्ताव पेश किये थे जिन्हें उपनिवेशमन्त्री ने स्वीकार कर लिया। (१) यह कि उन भागों में जहाँ गवर्नर जनरल का शासन है, ६ बरस तक के लड़के पाठशालाओं में उपस्थित होने पर बाध्य किये जायें। (२) फीस न ली जाय। (३) बालको की शिक्षा का प्रबन्ध अधिक ध्यान देकर किया जाय। (४) हर जिले में पृथक् पृथक् कमेटियाँ नियुक्त की जायें जो शिक्षा का निरीक्षण करें। (५) सड़को के महसूल जो आमदनी होती है वह इन कमेटियों को सौंप दी जाय जिससे वह एक शिक्षा फंड स्थापित करें। पहली बार १९०८ ई० में इन नियमों के अनुसार १६ जिलों में काररवाई की गई। और १९०९ ई० की सरकारी रिपोर्ट में निम्नलिखित वाक्यों का उल्लेख है — "अब तक कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित

महों हुई और इम्दादी पाठशालाओं के प्रधानों को जिन कठिनाइयों का भय था वे सब निर्मूल होंगी । और आशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक सब जिलों में भली भाँति उक्त काररवाई प्रचलित होजायगी" । १९०१ में उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जो प्राथमिक शिक्षा पा रहे थे, २३७००० थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल जन संख्या में से $\frac{६१}{१००}$ प्रति सैकड़ा शिक्षा पा रहे हैं ।

- भारतवर्ष की सीमा के भीतर महाराज गायकवाड़ ने शिक्षा-प्रचार के लिये जिस तल्लीनता के साथ उद्योग किया है उसके लिये ये हम सब से कोटिश धन्यवाद के भाजन हैं । १८ वर्ष हुए जब महाराजा साहब ने अपने राज्य के अमरौली तालुके के देहातों में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल स्थापित किया और क्रमशः आठ वर्ष के भीतर पूरे तालुके में शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर दी गई । अन्त में सन् १९०७ ई० में प्राथमिक शिक्षा १० बरस के लड़कों और ६ से १० साल तक की लड़कियों के लिए सारे राज्य में मुक्त और अनिवार्य हो गई । अब लड़कियों की अवस्था १० से ११ साल कर दी गई है । गत दो बरस की बड़ीदा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट बड़ी चिन्ताकर्षक है, जिससे प्रकट होता है कि १९०६ में विद्यार्थियों की संख्या १९५,००० थी जिससे ज्ञात होता है कि आठ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में शिक्षा पा रहे थे । यदि पाठशालाओं में जाने वाले लड़कों का हिसाब लगाया जाय तो $\frac{७६१}{१०००}$ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में पढ़ते थे । इसके विरुद्ध ब्रिटिश भारत में केवल $\frac{२११}{१०००}$ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में हैं । पाठशालाओं में जाने वाली लड़कियों की संख्या उक्त राज्य में ४७ और ब्रिटिश भारत में ४

शिक्षा पाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में केवल २ प्रति सैकड़ा सीलोन की अवस्था दक्षिण-भारत से बहुत कुछ मिलती हुई है, तथापि शिक्षा के विषय में सीलोन भारतवर्ष से कहीं अच्छा है। वहाँ प्राथमिक-शिक्षा का प्रबन्ध दो प्रकार से है। एक तो सरकारी स्कूलों के द्वारा और दूसरे इम्दादी पाठशालाओं के द्वारा। $\frac{1}{4}$ के लगभग तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और $\frac{3}{4}$ इम्दादी पाठशालाओं में। सरकारी स्कूलों में बहुत अर्से से शिक्षा अनिवार्य है, और यदि इसमें माता पिता कुछ विवाद करें तो स्थानीय अदालत के समक्ष वे उत्तरदाता होते हैं और उन पर जुर्माना भी हो सकता है। सन् १९०१ में एक कमेटी नियुक्त की गई थी जो गवर्नमेन्ट की ओर से शिक्षा प्रचार के उपाय सोचे। उसने राय दी कि गवर्नमेन्ट मा बाप को बाध्य करे कि वह अपने लड़के को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलावे। १९०५ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसने निम्न लिखित प्रस्ताव पेश किये थे जिन्हें उपनिवेशमन्त्री ने स्वीकार कर लिया। (१) यह कि उन भागों में जहाँ गवर्नर जनरल का शासन है, ६ बरस तक के लड़के पाठशालाओं में उपस्थित होने पर बाध्य किये जायें। (२) फीस न ली जाय। (३) बालको की शिक्षा का प्रबन्ध अधिक ध्यान देकर किया जाय। (४) हर जिले में पृथक् पृथक् कमेटियाँ नियुक्त की जायें जो शिक्षा का निरीक्षण करें। (५) सड़को के महसूल जो आमदनी होती है वह इन कमेटियों को सौंप दी जाय जिससे वह एक शिक्षा फंड स्थापित करें। पहली बार १९०८ ई० में इन नियमों के अनुसार १६ जिलों में काररवाई की गई। और १९०६ ई० की सरकारी रिपोर्ट में निम्नलिखित वाक्यों का उल्लेख है — “अब तक कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित

गर्हीं हुई और इम्दादी पाठशालाओं के प्रबन्धकों को जिन कठिनाइयों का भय था वे सब निमूल होंगी । और आशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक सब जिलों में भली भाँति उक्त काररवाई प्रचलित होजायगी" । १९०१ में उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जो प्राथमिक शिक्षा पा रहे थे, २३७००० थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल जन संख्या में से $\frac{१}{१५}$ प्रति सैकड़ा शिक्षा पा रहे हैं ।

- भारतवर्ष की सीमा के भीतर महाराज गायकवाड ने शिक्षा-प्रचार के लिये जिस तल्लोतता के साथ उद्योग किया है उसके लिये वे हम सब से कोटिश धन्यवाद के भाजन हैं । १८ वर्ष हुए जब महाराजा साहब ने अपने राज्य के अमरैली तालुके के देहातों में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का मूल स्थापित किया और क्रमशः आठ वर्ष के भीतर पूरे तालुके में शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर दी गई । अन्त में सन् १९०७ ई० में प्राथमिक शिक्षा १० बरस के लड़कों और ६ से १० साल तक की लड़कियों के लिये सारे राज्य में मुक्त और अनिवार्य हो गई । अब लड़कियों की अवस्था १० से ११ साल कर दी गई है । गत दो बरस की बड़ीदा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट यही चित्ताकर्षक है, जिससे प्रकट होता है कि १९०८ में विद्यार्थियों की संख्या १६५,००० थी जिससे ज्ञात होता है कि आठ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में शिक्षा पा रहे थे । यदि पाठशालाओं में जाने वाले लड़कों का हिसाब लगाया जाय तो $\frac{७६}{१००}$ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में पढ़ते थे । इसके विरुद्ध ब्रिटिश भारत में केवल $\frac{२१}{१००}$ प्रति सैकड़ा पाठशालाओं में हैं । पाठशालाओं में जाने वाली लड़कियों की संख्या उक्त राज्य में ४७ और ब्रिटिश भारत में ४

प्रति सेकंडा है। १९०६ में प्राथमिक शिक्षा के लिए बड़ीदा राज्य में कुल ६१ लाख रुपया खर्च किया गया जो ६१ पेन्स प्रति गनुष्य पड़ता है। परन्तु ब्रिटिश भारत में प्रति मनुष्य केवल १ पेन्स खर्च होता है, यद्यपि रकबे की दृष्टि से बड़ीदा की जन संख्या का भी सामान्यतः वही औसत है, जो ब्रिटिश भारत का।

शिक्षा को अनिवार्य करने की आवश्यकता और मसौदे की कुछ शर्तों के विषय में कथन करते हुए मि० गोखले ने कहा—कि यह उस जीने की पहली सीढ़ी की ओर एक छोटासा प्रयत्न है जो बहुत बड़ा और जिसके पार करने में कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी। परन्तु यदि सर्वसाधारण की दशा को उन्नत करने की आवश्यकता है तो इस जीने को अग्रसर पार करना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि इस मसौदे की सभी शर्तें एकसौ अनिवार्य हों। यदि मेरे मित्र इसमें कुछ संशोधन और फाट छाट करेंगे तो उस पर भी अवश्य ध्यान दिया जायगा।

श्रीमन्, यदि यह मसौदा विशेष चाद विवाद के लिए स्वीकार किया गया तो शायद एक साल के बाद यह कौंसिल के समक्ष फिर उपस्थित होगा। इस बीच में देशवासियों, सभासमितियों को इस पर राय देने और नुक्ताचोनी करने का अवसर मिलेगा। श्रीमन्, यह सर्वसाधारण शिक्षा के पूरे प्रचार का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो प्रजा के नेताओं और गवर्नमेन्ट के सहानुभूति पूर्ण सम्मिलन के बिना हल नहीं हो सकता है। प्रथम तो गवर्नमेन्ट को इस प्रस्ताव को अपना समर्थक प्रयत्न करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जितना उपया इसे पूरा करने के लिए आवश्यक हो वह गिना किसी

सोच विचार के एकत्रित करना उचित है, जैसा अन्य देश की सभ्य गवर्नमेंटों ने किया है। हमारी यह प्रार्थना परमावश्यक है और इसके साथ गवर्नमेंट की कीर्ति और प्रशंसा तथा प्रजा की भलाई पूरा रूप से लगी हुई है। साथ ही साथ प्रजा के नेताओं को भी बड़े उत्साह से इन काम में भरपूर भाग लेना उचित है, यदि धन या समय देने की आवश्यकता हो तो इसके लिए वे प्रस्तुत रहें। यदि थोड़ी सी अप्रसन्नता या असंतुष्टता का मौका आ जाय तो वे न क्षमिकों और ऐसे धीय और साहस से काम करें कि अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी पैर पीछे न हटावें। थोमन्, मेरा अनुमान है कि यह मसौदा सौभाग्य से यदि कानून के रूप में परिणत होगया तो प्रजा के नेताओं के लिए परीक्षा का अवसर आयेगा। और मेरी अभिलाषा है कि गवर्नमेंट और वह दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकलें। एक और बड़ी जरूरत जिस पर मैं कईवार कौंसिल का ध्यान आकर्षित करा चुका हूँ इस समय यह है कि गवर्नमेंट हमको यह अनुभव करा दे कि यद्यपि किसी सीमा तक यह एक विजातीय गवर्नमेंट है तथापि इच्छा, उद्देश्य और सहानुभूति की दृष्टि से यह जातीय गवर्नमेंट से कुछ भी कम नहीं। और यह उसी दशा में सम्भव है, जब गवर्नमेंट अपने उन सारे उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को जान ले जो अन्य देशों में उनकी गवर्नमेंट अपनी प्रजा के साथ पालन करती हैं। हम भी इसी के साथ इस गवर्नमेंट को जातीय गवर्नमेंट समझने के लिये तैयार हैं। मेरी राय में कोई जातीय आवश्यकता इस समय इतने महत्व की नहीं जितनी प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार की है, जिसके द्वारा इस निर्जोष

ढाँचे में सजीवता का सञ्चार हो, निराशा की काली निशा
 में आशा का प्रकाश हो और जो उदास बैठे हैं उन्हें सन्तोष
 हो। इसमें गवर्नमेन्ट और प्रजा अपने सम्मिलित प्रयत्न
 से देश को पर्याप्त लाभ पहुँचा सकते हैं। यदि बिन
 किसी आना कानी के इसका आरम्भ कर दिया जाय और
 सरकार और प्रजा दोनों ही अपने प्रयत्नों से सच्चाई का प्रमाण
 दें तो मुझे पूर्ण आशा है कि यह कठिन मार्ग आगामी पीढ़ी
 के आने तक अवश्य तै हो जायगा और वे लोग अपने उद्देश्यों
 और कामों को नवीन उत्साह के साथ पूरा करने में छग
 जायेंगे। हमारे लिये केवल यही सन्तोष काफी होगा कि
 हमने उस मार्ग को पार करने में जिसमें अभी अभीष्ट स्थान
 कहीं नजर नहीं आता, कुछ आगे कदम बढ़ाने की चेष्टा की।

प्रारम्भिक शिक्षा-१९१०

(१८ मार्च, १९१०, को वाइसरॉय की कौंसिल में माननीय मि० गोखले ने प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में एक बड़े ही महत्त्व की वक्तृता दी थी । उस वक्तृता का अनुवाद नीचे दिया जाता है —)

मार्ड लाई, — मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह कौंसिल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले कि — 'यह कौंसिल सम्मति देती है कि सारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर देना प्रारम्भ कर दिया जाय और इस विषय पर विचार करने और पूर्णरूप से सम्मति देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का एक कमीशन नियत किया जाय ।'

मैं विश्वास करता हूँ कि कौंसिल इस बात का अच्छी तरह विचार करेगी कि इस प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य क्या है । इस प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया कि सारे भारतवर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा एकदम अनिवार्य कर दी जाय । यह भी नहीं कहा गया कि सारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा एक दम मुक्त कर दी जाय, यद्यपि तीन वर्ष हुए कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने निश्चित रूप से इस मत का समर्थन किया था । इस प्रस्ताव का केवल यही आशय है कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर देना प्रारम्भ कर दिया जाय और इस विषय पर विचार करने और मसौदा बनाने के लिये सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का एक कमीशन नियत किया जाय । अन्य शब्दों में अब गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को जनसमूह को शिक्षा देने के सम्बन्ध में पूरी तरह अपनी घड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए जिसका अधिकांश समय

गवर्नमेण्टें पालन कर रही हैं और इस नीति को सफल बनाने के लिए अच्छी तरह सांच बिचार कर एक कार्यविवरणी तैयार होनी चाहिए जिसमें इस बात का प्रबंध रहे कि यह शिक्षा का काम उचित समय में पूरा किया जायगा।

माई लार्ड, आज कल के समय में जनसमूह में शिक्षा प्रचार करने की नीति की आवश्यकता, बुद्धिमत्ता, मनुष्यता और देशभक्ति दिखाना सर्वथा अनावश्यक है। एक फ्रेंच लेखक ने उन्नीसवीं शताब्दी को उचित हो शिक्षा की शताब्दी बताया है। इसी शताब्दी में पश्चिमीय देशों में लोगों में बहुत अधिक शिक्षा का प्रचार हुआ और साथ ही और तीन बातों में बड़ी उन्नति हुई (१) शिल्प के कार्यों में विज्ञान का उपयोग (२) दूरी को मिटाने के लिए रेल और तार का प्रचार (३) और प्रजातंत्र राज्यों की उत्पत्ति। तीन बातों ने मिल कर जनसमूह की शिक्षा को राजा के कर्तव्यों में वर्तमान स्थान दिलाया है, (१) मनुष्यदया का कार्य जिसने जेलघानों की दशा सुधारी और दासों को मुक्त कराया, (२) प्रजातंत्र शासनप्रणाली जिसने शासनप्रबंध में लोगों को अधिक अधिकार दिया, और (३) व्यवसाय जिसने सब देशों को अच्छी तरह बता दिया कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा देने से भी उस देश के व्यवसायी बड़े कुशल होंगे। माई लार्ड, अब यह समय बहुत दूर गया जब कि कोई सोच समझ कर यह कहे कि अधिकांश पुरुष शारीरिक परिश्रम करने ही के लिए बनाए गए हैं और उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा देना भी उचित नहीं है। इसके विपरीत अब सब लोग यह स्वीकार करते हैं कि समाज का यह कर्तव्य है कि यह भविष्य में सब लोगों को थोड़ी बहुत साधारण शिक्षा अवश्य दे। और सारे संसार में

इस कर्तव्य को अच्छी तरह पालन करना केवल एक ही तरह यानी प्रारम्भिक शिक्षा को मुख्य और अनिवार्य बनाकर उचित, समझा गया है। सब से पहले जर्मनी ने यह कार्य आरम्भ किया और गत शताब्दी में योरोपीय देशों, अमरीका और जापान ने अपने यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा को मुख्य और अनिवार्य बनाने का नियम प्रचार किया और आज हम देखते हैं कि एशिया और टर्की को छोड़ कर यह नियम सब योरोपीय देशों में प्रचलित हैं यद्यपि कुछ छोटे छोटे राज्यों में अनिवार्य शिक्षा पूरी तरह प्रचलित नहीं है। युनाइटेड स्टेट्स, केनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रजातन्त्र राज्यों में भी अनिवार्य और मुख्य प्रारम्भिक शिक्षा पूरी तरह प्रचलित है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष में भी बड़ोदा के सुशिक्षित और दूरदर्शी महाराज ने अमरेली तालुका में इस नियम की १५ वर्ष परीक्षा करने के बाद उसे सारे राज्य में प्रचलित कर दिया। जब दो वर्ष पूर्व टर्की में राष्ट्र-चिह्न हुआ और जब वहाँ का अधिकार 'कमिटी आफ यूनियन और प्रोग्रेस' नामक समाज के हाथ में आया तो उसने पहिले ही पहिले घोषणा की कि यह समाज शिक्षा को मुख्य और अनिवार्य करने का बहुत शीघ्र प्रयत्न करेगा। एशिया में यद्यपि शिक्षा अनिवार्य नहीं है किन्तु अधिकांश शिक्षा मुख्य दी जाती है। सब देशों में जहाँ का हिसाब किताब मिलता है केवल ब्रिटिश इंडिया ही ऐसा है जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा मुख्य और अनिवार्य नहीं है।

भिन्न भिन्न देशों के प्राइमरी स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या पर दृष्टि डालने से बड़ी शिक्षा मिल सकती है। विद्यार्थियों की संख्याओं को ठीक ठीक समझने के लिये

स्मरण रखना आवश्यक है कि भिन्न भिन्न देशों में अनिवार्य शिक्षा का समय समान नहीं है। जैसे कि इंग्लैण्ड में अनिवार्य शिक्षा देने का समय ६ से ७ वर्ष तक है, यूरोप के अन्य देशों में और अमरीका में ८ वर्ष है, जापान में ४ वर्ष है और इटली में केवल ३ ही वर्ष है। अंग्रेजों के हिसाब से सब लोगों में से १५ फी सैकडे ऐसे हैं जिन्हें प्रारम्भिक शिक्षा देना उचित है। अतएव यह प्रत्यक्ष है कि जहाँ इंग्लैण्ड की अपेक्षा अधिक समय तक शिक्षा दी जाती है वहाँ के लड़कों की सराया उसी हिसाब से बढ़ेगी और जहाँ शिक्षा देने का समय कम है, वहाँ का औसत कम पड़ेगा। युनाइटेड स्टेट्स में सब से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। वहाँ उनकी सराया सत्र जनसंख्या में २१ फी सदी है। केनाडा, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड, ग्रेट ब्रिटन और आयरलैंड की सराया १७ से लेकर २० फी सदी तक है। जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगेरी, नार्वे, और नेदरलैंड्स की सराया १५ और १७ फी सदी के बीच में है। फ्रांस में १४ से कुछ अधिक है, स्वीडन में १४ और डेन्मार्क में १३ है। बेलजियम में १२ और जापान में ११ है। इटली, ग्रीस और स्पेन में ८ और ६ के बीच में है। पोर्चुगाल और रशिया में ४ और पाँच के बीच में है। फिलीपाइन्स द्वीप में ५ है। बङ्गोदा में ५ है और ब्रिटिश इंडिया में केवल १.६ है।

अब मैं कौंसिल का ध्यान संक्षेप से इस देश में जो प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति हुई है उस ओर आकर्षित करता हूँ। हमारी प्रारम्भिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली १८५४ से आरम्भ हुई है जब कि कोर्ट आफ् डिरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल के नाम प्रसिद्ध डिस्पैच (राजपत्र) भेजा था। उस समय के पहले प्रारम्भिक शिक्षा देशीय पाठशालाओं में दी जाती थी। ये

पाठशालाएँ अत्यन्त प्राचीन प्रथा के अनुसार लोगो द्वारा चलाई जाती थीं और इनमें न गवर्नमेन्ट कुछ सहायता देती थी और न गवर्नमेन्ट का कुछ अधिकार था। सन् १८८२ के शिक्षा कमीशन के कथनानुसार उन दिनों (१८५४) कोई ५०००० पाठशालाएँ थी और उनमें ६ लाख लड़के पढ़ते थे। जन संख्या और उस समय की देश की दशा देखने से यह संख्या कुछ मिलक्षण है। १८५४ के डिस्पैच के आरम्भ में लिखा था कि 'यह हमारा एक अत्यन्त पवित्र कर्तव्य है कि हम यथा शक्ति भारतवासियों को वे नैतिक और सांसारिक लाभ पहुँचावें जो उत्तम विद्या के प्रचार से प्राप्त होते हैं और ईश्वर की कृपा से भारतवर्ष इङ्ग्लैंड के सम्बन्ध से वह उत्तम विद्या प्राप्त करे।' अन्य शब्दों में जैसे कि १८८२ का शिक्षा कमीशन कहता है कि, '१८५४ में भारतवर्ष के सब निवासियों को शिक्षा देना पूरी तरह गवर्नमेन्ट का एक कर्तव्य स्वीकार किया गया था।' उस डिस्पैच में साफ साफ लिखा था कि 'ऐसी शिक्षा पर भूतकाल में बहुत कम ध्यान दिया गया था।' इसमें गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को विचार करने के लिए परामर्श दिया गया था कि 'किस तरह सब श्रेणी के लोगो के उपयुक्त लाभकारी और व्यावहारिक विद्या का बहुत से ऐसे लोगो में जो स्वयं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं पूरी तरह प्रचार किया जाय' और इसमें गवर्नर जनरल से यह भी कहा गया था कि 'डिरेक्टस चाहते हैं कि भविष्य में गवर्नमेन्ट विशेष रूप से शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से दृढता से कार्य करे।'।

प्रारम्भिक शिक्षा के इतिहास में दूसरा महत्त्व का समय सन् १८८२ है। उस वर्ष गवर्नमेन्ट आफ् इन्डिया ने इस देश

मं, शिक्षा की साधारण अवस्था की जांच करने के लिये एक कमिशन नियत किया और जांच करने का एक मुख्य विषय यह भी था कि प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में १८५४ के टिस्लेच की नीति कहा तक काम में लाई गई है। कमिशन को माहूर हुआ कि उस समय देश में प्रारम्भिक शिक्षा के ८५००० स्कूल हैं जिन्हें गवर्नमेन्ट ने स्वीकार किया है जिनमें २१॥ लाख लड़के पढ़ते हैं और ३॥ लाख लड़के देशी स्कूलों में पढ़ते हैं जिन पर शिक्षाविभाग का कोई अधिकार नहीं है। अतएव १८८२ में कोई २५ लाख यानी ब्रिटिश इंडिया की सारी जनसंख्या के १२ फीसदी लड़के प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस कमिशन ने यह दिखाया था कि अभी बहुत से स्थानों में बहुत सी शिक्षा देने की आवश्यकता है और उसने अन्य बातों के अतिरिक्त दो बातों की सम्मति दी थी। एक तो यह कि 'यद्यपि हर तरह की शिक्षा का प्रचार करना गवर्नमेन्ट का कर्तव्य है, किन्तु देश की वर्तमान अवस्था में गवर्नमेन्ट को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार और उसकी उन्नति में पहले अब से बहुत अधिक उद्योग करना चाहिए।' और दूसरे यह कि, 'हर प्रान्त के अनुकूल कानून बना कर प्रारम्भिक शिक्षा को यथा सम्भव सब से अधिक प्रचार बढ़ाने का उद्योग होना चाहिए।'

तीसरी शताब्दी बीत गई है कि प्रारम्भिक शिक्षा का अधिक प्रचार करने के लिए निश्चय किया गया था। तब से अब तक वास्तव में बहुत ही कम और निराशाजनक उन्नति हुई है। हम देखते हैं कि १९०६-०७ में गवर्नमेन्ट द्वारा स्वीकार किए हुए ११३००० प्राइमरी स्कूल थे और उनमें ३६ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त लोगों के निज के स्कूलों में ५॥ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे यानी उस समय कुल ४५ लाख

विद्यार्थी या ब्रिटिश इण्डिया की कुल जनसंख्या के १६ फी सदी आदमी प्रारम्भिक शिक्षा पा रहे थे। इन अङ्कों में ब्रह्मदेश भी सम्मिलित है किन्तु १८८२ के अङ्कों में ब्रह्मदेश नहीं लिया गया था। गत २५ वर्षों में कुल उन्नति सारी जनसंख्या की १२ फी सदी से केवल १६ फी सदी हुई है। यह जो बहुत ही थोड़ी सी उन्नति हुई है, उसमें अधिकांश उन्नति केवल गत ६ या ७ वर्षों ही में हुई है। भारतीय शिक्षा के डिरेक्टर जनरल माननीय मि० आर्नेज सब यातें बहुत अच्छी तरह कह सकते हैं जैसा कि उन्होंने गत पञ्चवार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि — 'गत २५ वर्षों या गत ५ वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा की बहुत ही कम उन्नति हुई है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि सर्पसाधारण में प्रारम्भिक शिक्षा का पूरी तरह प्रचार करने के लिए हमें कितना अधिक रास्ता तैयार करना है। गत ५ वर्षों में विद्यार्थियों की जो संख्या बढ़ी है यदि उसी हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाय और देश की जनसंख्या बिल्कुल न बढ़े तो भी स्कूल में पढ़ने योग्य उम्र के लड़कों को स्कूल में भेजने में कितनी ही पीढ़ियाँ लगी जायँगी।' प्रान्तीय, म्युनिसिपल और लोकल फण्डों से प्रारम्भिक शिक्षा का वार्षिक व्यय केवल ७ लाख बढ़ा है यानि १६०६-०७ में ६३ ३ लाख व्यय था और १८८२ में ३६ २ लाख व्यय। इसी अर्थ में देश में भूमि कर ८ करोड़ अधिक बढ़ गया है। १८८२ में भूमि कर २१ ८ करोड़ था, १६०६-०७ में २६ ७ करोड़ हो गया। सेना का खर्च ६३ करोड़ बढ़ गया है १८८२ में १६ ३ करोड़ का १६०६-०७ में ३२ ४ करोड़ हो गया और सिविल विभागों का खर्च ११ करोड़ से १६ करोड़ या तो ५ करोड़ बढ़ गया। रेलों के बनाने में पहले ४ करोड़ वार्षिक

ध्वंश होता था, अब १५ करोड़ घाघि क होने लगा । इन प्रश्नों को आपस में मिलान कर आलोचना करना ध्यर्थ है ।

गत चौथाई शताब्दी में भारतवर्ष में जो उन्नति हुई है उसका उसी समय की अन्य देशों की उन्नति से मिलान करने से बड़ा लाभ होगा । मैं आशा करता हूँ कि कौंसिल मुझे भारतवर्ष के साथ अन्य देशों की बातें मिलान करने की आज्ञा देगी । इस काव्य के लिए मैं दो पश्चिमीय और दो पूर्वीय देशों को लेता हूँ—पश्चिमीय देशों में इंग्लैंड और रशिया को, और पूर्वीय देशों में जापान और फिलिपाइन्स को । इंग्लैंड पहिले सर्वसाधारण में शिक्षा प्रचार करने का विरोधी था । उसने पहिले ही पहिले १८७० में प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयत्न आरम्भ किया । १८७० के कानून के अनुसार गवर्नमेन्ट ने जनसमूह में शिक्षा प्रचार करने की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर ली । इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही था कि उचित रूप से शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय । इस कानून द्वारा स्कूल बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि वे लड़कों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए बाध्य करें । इसके बाद १८७६ और १८८० में दो कानून और बने । १८७६ के कानून ने माता पिताओं को अपने लड़कों को स्कूल में भेजने में बाध्य किया और जहाँ पर स्कूल बोल नहीं थे, वहाँ स्कूलों में लड़कों को भेजने के लिए कमेटियाँ बनाई गई । १८८० के कानून ने स्कूल बोर्डों और उक्त कमेटियों को बाध्य किया कि वे अपने अलग नियम बनावें और उन्हें अमल में लावें । और १८८२ में सारे देश में शिक्षा अनिवार्य हो गई । सन् १८७१ से लेकर १८८२ तक विद्यार्थियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उस विषय में

सर हेनरी फोर्ब ने अपनी 'The State in its relation to Education' नामक पुस्तक में बड़ी विस्तारपूर्वक बातें लिखी हैं। १८७७ में इंग्लैंड और वेल्स की सारी जनसंख्या २ करोड़ २७ लाख थी और यह हिसाब लगाया गया था कि साधारण रीति पर कम से कम ३२ लाख लड़कों का स्कूलों में जाना चाहिए। किन्तु उस समय केवल १३ लाख लड़के यानी स्कूलों में जाने योग्य लड़कों में केवल ४३.३ फी सदी स्कूलों में जाते थे। १८७६ में २० लाख लड़के यानी स्कूलों में जाने योग्य लड़कों में ६६ फी सदी से भी अधिक स्कूलों में जाने लगे। अंतमें १८८२ में स्कूल में जाने वाले लड़कों की संख्या ३० लाख से भी बढ़ गई और एक एक लड़का जिसे स्कूल में जाना चाहिए था स्कूल में जाने लगा। इंग्लैंड में प्रारम्भिक शिक्षा १८६० में मुक्त-बिना फीस लिए-दी जाने लगी।

जापान में जहां पश्चिमीय उद्योग पूर्वीय व्यवस्था के धनुकुल बड़ी सफलाता के साथ काम में लागू हुए हैं शिक्षा का सुधार अन्य महत्व की बातों के साथ १८७१ में आरम्भ हुआ। उस वर्ष एक राजपत्र निकाला गया जिसमें शिक्षा प्रचार के सम्बन्ध में नई नीति अवलम्बन करने की सूचना दी गई। उस राजपत्र में यह घोषित किया गया कि 'अब से यह विचार किया गया है कि शिक्षा का इस तरह प्रचार किया जायगा कि किसी गांव में कोई कुटुम्ब मूर्ख न रहे और किसी कुटुम्ब में कोई मनुष्य मूर्ख न रहे'। बम्बई के मि० शाप ने इन शब्दों को ठीक ही 'बड़ी ऊंची आकांक्षा' वाले शब्द कहा है, किन्तु जापान ने ३० वर्ष में अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। जिस समय उक्त राजपत्र जारी किया गया उस

समय हिमाय लगाया गया कि स्कूल में जाने योग्य लड़कों में २८ फी सदी लड़के स्कूल जाते थे। इस समय ६० फी सदी से भी अधिक औसत है। जापान एक दूरिद्र देश और फिर भी उसने इतना अधिक काम कर के दिखा दिया है। इसके साथ ही जापान ने अपनी सेना और सामुद्रिक बल बढ़ाने में भी बड़ा स्वार्थत्याग किया है जिसकी सलाह चारो ओर दुन्दुभि घज रही है। जापान में पहले यद्यपि अनिवार्य शिक्षा का नाम को प्रचार हो गया था किन्तु वह पूर्ण तरह काम में नहीं लाई गई। १८६० में लड़कों को स्कूलों में जाने का पूरा प्रयत्न किया गया और अलग अलग अवस्था के अनुसार अनिवार्य शिक्षा देने का समय ३ से ४ वर्ष तक कर दिया गया। १९०० में अनिवार्य शिक्षा का समय ४ जगह ४ वर्ष कर दिया गया और यथा समय प्रारम्भिक शिक्षा शुरू की जाने लगी।

रशिया में जहा की शिक्षा सर्वोत्तम बातें कुछ अंशो में भारतवर्ष से मिलती जुलती हैं वहा प्रारम्भिक शिक्षा परिष्कृत मीय दृष्टि से देखने पर बहुत ही बुरी दशा में है। गवर्नमेन्ट १८६४ और १८७१ में कानून बना कर शिक्षा की उन्नति करने की चाही, किन्तु अधिक सफलता नहीं हुई। फिर भी वहा गत २५ वर्षों में जनसमूह की शिक्षा की भारतवर्ष की अपेक्षा अधिक उन्नति हुई है। १८८० में रशिया में कोई २३००० प्राथमिक स्कूल थे। १९०६ में उनकी संख्या ६० हजार से भी अधिक हो गई। १८८० में स्कूल में जाने वाले लड़कों की संख्या ११-४ लाख यानी सारी जनसंख्या की १२ फी सदी थी। ठीक इतने ही फी सदी लोगो को १८८२ में भारत वर्ष में शिक्षा दी जाती थी। गत २५ वर्षों में रशिया में

विद्यार्थियों की संख्या ११ ४ लाख से ५७ लाख-होगई है। अर्थात् इस समय सारी जनसंख्या के ४५ फी सदी लोग प्रारम्भिक शिक्षा पा रहे हैं। इस तरह रशिया में १२ फी सदी से ४५ फी सदी उन्नति हुई है, किन्तु उतने ही समय में भारतवर्ष में १२ फी सदी से केवल १६ फी सदी उन्नति हुई है। रशिया में प्रारम्भिक शिक्षा यद्यपि अनिवार्य नहीं किन्तु प्रायः मुक्त दी जाती है।

अब मैं फिलिपाइन्स देश की बात कहता हूँ। यह देश बहुत से टापुओं का बना है और विदेशियों के अधीन है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तमें यह देश स्पेन के अधिकार में से निकल कर युनाइटेड स्टेट्स के हाथ में आया। इतने ही थोड़े दिनों में यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा की बहुत अधिक उन्नति हुई है। स्पेन के अधिकार में भी फिलीपाइन वालों में शिक्षा का अच्छा प्रचार था। १६०३ में यहाँ २००० प्राइमरी स्कूल थे और १॥ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। पाच वर्ष में स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई है और विद्यार्थियों की संख्या ३ लाख ६० हजार है। उस देश की जनसंख्या लगभग ७० लाख है। इस जनसंख्या के हिसाब से १६०३ में २ फी सदी लोगों को शिक्षा दी जाती थी, ५ वर्ष बाद वही २ फी सदी से ५ फी सदी से भी अधिक हो गई, किन्तु भारतवर्ष में इन पाच वर्षों में केवल १६ फी सदी से १६ उन्नति हुई है। फिलीपाइन्स देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है, किन्तु वह पूरी तरह अमल में नहीं लाई जाती। जहाँ अध्यापकों का वेतन पब्लिक फंड से दिया जाता है, वहाँ शिक्षा मुक्त दी जाती है।

माई लार्ड, मैंने इन सब बातों की आलोचना कर कॉन्सिल को इसलिए रुकट नहीं दिया कि मैं बीती हुई बातों के लिए

समय हिमाय लगाया गया कि स्कूल में जाने योग्य लड़कों में २८ फी सदी लड़के स्कूल जाते थे। इस समय ६० फी सदी से भी अधिक औसत है। जापान एक दरिद्र देश है और फिर भी उसने इतना अधिक काम कर के दिखा दिया है। इसके साथ ही जापान ने अपनी सेना और सामुद्रिक यत्न बढ़ाने में भी बड़ा स्वार्थत्याग किया है जिसकी सत्तार में चारों ओर दुन्दुभि बज रही है। जापान में पहले यद्यपि अनिवार्य शिक्षा का नाम को प्रचार हो गया था किन्तु वह पूरी तरह काम में नहीं लाई गई। १८६० में लड़कों को स्कूलों में भेजने का पूरा प्रयत्न किया गया और अलग अलग अवस्था के अनुसार अनिवार्य शिक्षा देने का समय ३ से ४ वर्ष तक कर दिया गया। १६०० में अनिवार्य शिक्षा का समय हर जगह ४ वर्ष कर दिया गया और यथा समय प्रारम्भिक शिक्षा शुरू हो जाने लगी।

रशिया में जहा की शिक्षा संधीरी बातें कुछ अंशों में भारतवर्ष से मिलती जुलती हैं वहा प्रारम्भिक शिक्षा पश्चिमीय दृष्टि से देखने पर बहुत ही बुरी दशा में है। गवर्नमेन्ट ने १८६४ और १८७१ में कानून बना कर शिक्षा की उन्नति करनी चाही, किन्तु अधिक सफलता नहीं हुई। फिर भी वहा गत २५ वर्षों में जनसमूह की शिक्षा की भारतवर्ष की अपेक्षा अधिक उन्नति हुई है। १८८० में रशिया में कोई २३००० प्राथमरी स्कूल थे। १६०६ में उनकी संख्या ६० हजार से भी अधिक हो गई। १८८० में स्कूल में जाने वाले लड़कों की संख्या ११ ४ लाख यानी सारी-जनसंख्या की १२ फी सदी थी। ठीक इतने ही फी सदी लेगो को १८८२ में भारत वर्ष में शिक्षा दी जाती थी। गत २५ वर्षों में रशिया में

विद्यार्थियों की संख्या ११ ४ लाख से ५७ लाख हो गई है। अर्थात् इस समय सारी जनसंख्या के ४५ फी सदी लोग प्रारम्भिक शिक्षा पा रहे हैं। इस तरह रशिया में १२ फी सदी से ४५ फी सदी उन्नति हुई है, किन्तु उतने ही समय में भारतवर्ष में १० फी सदी से केवल १६ फी सदी उन्नति हुई है। रशिया में प्रारम्भिक शिक्षा यद्यपि अनिवार्य नहीं किन्तु प्रायः मुक्त दी जाती है।

अब मैं फिलिपाइन्स देश की बात कहता हूँ। यह देश बहुत से टापुओं का बना है और विदेशियों के अधीन है। उन्नोन्नी शताब्दी के अन्तमें यह देश स्पेन के अधिकार में से निकल कर युनाइटेड स्टेट्स के हाथ में आया। इतने ही थोड़े दिनों में वहाँ प्रारम्भिक शिक्षा की बहुत अधिक उन्नति हुई है। स्पेन के अधिकार में भी फिलीपाइन वालों में शिक्षा का अच्छा प्रचार था। १६०३ में वहाँ २००० प्राइमरी स्कूल थे और १॥ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे। पाच वर्ष में स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई है और विद्यार्थियों की संख्या ३ लाख ६० हजार है। उस देश की जनसंख्या लगभग ७० लाख है। इस जनसंख्या के हिसाब से १६०३ में २ फी सदी लोगों की शिक्षा दी जाती थी, ५ वर्ष बाद वही २ फी सदी से ५ फी सदी से भी अधिक हो गई, किन्तु भारतवर्ष में इन पाच वर्षों में केवल १६ फी सदी से १६ उन्नति हुई है। फिलीपाइन्स देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है, किन्तु वह पूरी तरह अमल में नहीं लाई जाती। जहाँ अध्यापकों का वेतन पब्लिक फंड से दिया जाता है, वहाँ शिक्षा मुक्त दी जाती है।

माइ लार्ड, मैंने इन सब बातों की आलोचना कर कॉमिल को इसलिए कष्ट नहीं दिया कि मैं बीती हुई घातों के लिए

पश्चात्ताप करना उचित समझता हूँ, किन्तु इसलिए कि वर्तमान और भविष्य घातों भूतकाल की घातों के साथ मिलान करने से बड़ी अच्छी तरह छल की जा सकती है 'पीती ताहि बिसारि दे' यह कहावत निस्संदेह बड़ी अच्छी है किन्तु कभी भविष्य की घातों को अच्छी तरह समझने के लिए पुरानी घातों को याद करना आवश्यक होता है। माई लार्ड, मैं इस घात के विश्वास करने का साहस करता हूँ कि इस कौंसिल में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो सारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता या महत्व को स्वीकार नहीं करता। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र महाराज वर्दमान भी इस देश के लोगों को सर्वथा मूर्खता और अन्धकार में पड़े रहना अच्छा नहीं समझेंगे। अभी तक ससार भर में जनसाधारण में पूरी तरह शिक्षा प्रचार करने के लिए एक ही सिद्धान्त अविवेकार हुआ है अर्थात् शिक्षा को अनिवार्य करना। और मेरी समझ में यदि हमारी यह पलवती इच्छा है कि इस देश के लोगों को भी शिक्षा के बीसे ही लाभ प्राप्त हों जैसे अन्य देश के लोगों को मिल रहे हैं तो हमें उन देशों का अनुकरण करना चाहिये। फिर अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ शिक्षा मुक्त देनी चाहिये क्योंकि बिना ऐसा किये बेचारे गरीब लोगों को अधिक फट्ट होगा। निस्संदेह इस शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पर वादानुवाद करते समय हमसे कहा जायगा कि अनिवार्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए अभी देश तैयार नहीं है। जब जब किसी तरह के सुधार करने का प्रस्ताव किया जाता है तब तब उसके विपक्ष में सदा यही बात कही जाती है कि अभी देश तैयार नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस विषय का

साधना और बड़े विचार के साथ होना चाहिये किन्तु मुझे इस बात का भी पूरी तरह निश्चय है कि अब इस कार्य के आरम्भ करने में अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए।

अब मैं निश्चित रूप से इस विषय पर अपने विचारों को कौंसिल के सामने उपस्थित करूँगा। और मैं आरम्भ ही में बताएँ देता हूँ कि मैं केवल लड़कों को अनिवार्य शिक्षा देने का पक्षपाती हूँ, लड़कियों को नहीं। आज कल भारतवर्ष में कुछ अशों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को शिक्षा देने की अधिक आवश्यकता है किन्तु इस काम को पूरी तरह करने में इतनी अधिक कठिनाइयाँ हैं कि देश में लोग अपनी इच्छा से लड़कियों को जो शिक्षा दे रहे हैं उन्हीं से हमें कुछ काल तक सन्तोष करना चाहिए। हा, हमें लोगों की लैंगिक शिक्षा देने के लिए पहिले से अधिक उत्तेजित करना चाहिए। अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि हम लड़कों को अनिवार्य शिक्षा किस तरह दे सकते हैं। मैं यह बतला चुका हूँ कि इंग्लैंड की सारी जासूरियाँ के १५ की सदी लोगों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ शिक्षा देने का समय ६ से ७ वर्ष तक है। मेरी समझ में यहाँ जापान की तरह अनिवार्य शिक्षा देने के लिए केवल ८ वर्ष का समय नियत होना चाहिए यानी ६ वर्ष की उम्र से लेकर १० वर्ष की उम्र तक। हमारे देश की सारी पुरुषसंख्या में ऐसे लड़कों का औसत ११ और १२ की सदी के बीच में है। यानी जब हमारे देश में लड़कों को अनिवार्य शिक्षा देने का पूरी तरह प्रचार हो जायगा तो उस समय देश की सारी पुरुषसंख्या के लगभग १२ वीं सदी लड़के प्रारम्भिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा सम्बन्धी गत पञ्चवार्षिक रिपोर्ट के

की जरूरत हो तो मैं कहूँगा कि १८६० और १८७० में बाहरी माल पर ७½ फी सदी कर (इम्पोर्ट ड्यूटी) लगता था। इस समय ५ फी सदी लगता है। जब ७½ फी सदी कर लगता था तो उस समय भी वह आय बढ़ाने के लिए कर लगता था और अब भी ऐसा ही समझा जायगा। अब बाहर के माल पर ५ फी सदी की जगह ७½ फी सदी कर लगाने पर गवर्नमेन्ट को २॥ करोड़ की आमदनी अधिक होगी। पाचवें यदि सन (जूर) पर ५ फी सदी कर लगाया जाय तो इससे हर साल १ करोड़ की आमदनी होगी और यह हर तरह से एक आदर्श कर होगा क्योंकि इसे विदेशियों को देना पड़ेगा इस लिए कि सन समार भर में और कहीं उत्पन्न नहीं होता। बाहर नाने वाली चीजों पर कर लगाने के लिए और भी चीजें बताई जा सकती हैं। अन्त में जब दशा बहुत ही खराब हो जाय और कहीं से भी रुपया न मिले और किसी तरह काम न चले (किन्तु मेरी समझ में ऐसा होना सर्वथा असम्भव है) तो उस समय मैं नमक पर ॥॥ और अधिक टैक्स लगाने का परामर्श दूँगा और इससे १॥॥ करोड़ से भी अधिक आय होगी, क्योंकि मैं इसे अधिक दु खदाई नहीं समझता कि मेरे देशवासी कुछ कम नमक खाय, किन्तु मैं इसे यही भारी विपत्ति समझता हूँ कि मेरे देशवासी सबथा-मूर्ख बने रह कर अधिकार में पड़े रहें और लौकिक और पार लौकिक उन्नति से वञ्चित रहें।

मार्ड लार्ड, मैं नाफ साफ कहता हूँ कि इस प्रस्ताव को मैंने इस आशा से उपस्थित नहीं किया कि कौंसिल इसे स्वीकार कर लेगी। जिस तरह कि यह कौंसिल बनी हुई है उससे यह आशा नहीं है कि इसमें कोई प्रस्ताव जब तक

उसे गवर्नमेन्ट पहले से पसन्द न कर ले स्वीकार किया जा सके और वतमान विषय पर तो मैं स्वीकार करता हूँ कि गवर्नमेन्ट से यह प्रार्थना करना युक्तियुक्त नहीं है कि वह बिना अच्छी तरह विचार किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। इसके अतिरिक्त यदि गवर्नमेन्ट इस प्रस्ताव के पक्ष में होतो तो इस विषय में बिना सेक्रेटरी आफ स्टेट से परामर्श किए वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकती थी। इस लिए मुझे जरा भी आशा नहीं है कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा। किन्तु चाहे गवर्नमेन्ट इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो किन्तु वह सब बातों पर शीघ्र अच्छी तरह विचार करने का वादा कर सकती है। हर दशा में मैं हृदय से आशा करता हूँ कि गवर्नमेन्ट दो बातें नहीं करेगी एक तो यह कि अनिवार्य और मुख्य प्रारम्भिक शिक्षा देने के सिद्धान्त के विरुद्ध निश्चित रूप से अपना मत प्रकाश नहीं करेगी और दूसरे यह कि इस प्रस्ताव को यह कह कर अस्वीकार नहीं करेगी कि आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

माई लाई, इस उक्ति में बहुत कुछ सत्य भरा पड़ा है कि जब इच्छा होती है तो फायदा करने का साधन भी मिल जाता है। मेरी समझ में यह अनिवार्य और मुख्य शिक्षा का प्रश्न सब से अधिक महत्व का प्रश्न है। इसी प्रश्न पर लाखों लड़कों का जो शिक्षा का सुन्दर फल चयना चाहते हैं घुरा भला निभर है। सुन्दर प्रतिभा, अच्छी योग्यता और ऊँचा चरित्र कुछ भी बिना शिक्षा के नहीं प्राप्त होता। वास्तव में यहाँ एक ऐसा प्रश्न है जिससे भविष्य में हमारे एक राष्ट्र होने का घनिष्ट सम्बन्ध है। माई लाई, चाहे आज का

प्रस्ताव उठा कर यहाँ अलग रखा दो किन्तु मुझे विश्वास है कि यह एक पेमा विषय है जिसमें अवश्य हमारी जीत होगी। सारे सभ्य ससार की व्यवस्था, ब्रिटिश प्रजातन्त्र राज्य की सहानुभूति और हमारी स्वाभाविक आकांक्षाएँ जिन्हें श्रीमान् ने एक से अधिक बार ठीक बतलाया है—ये सब बातें इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। यह प्रश्न कौंसिल के सामने बार बार उपस्थित किया जायगा जब तक कि पूरी तरह से हल न हो जाय। माई लाडं, मैं सच्चे मन से आशा करता हूँ कि गवर्नमेन्ट वर्तमान अवस्था को ठीक ठीक समझेगी और समय के अनुसार चलेगी। मेरी छोटी समझ में इस समय गवर्नमेन्ट को अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक है। उसे राजनीतिज्ञता भी दीयानी चाहिए, ऐसी राजनीतिज्ञता जो धीरे धीरे किन्तु बिना चूके अपनी प्रजा का नय नै बड़ा हित साधन करने में तत्पर रहती है।

चतुर्थ भाग



फुटकर

श्रीमान् दादा भाई नौरोजी

[सन् १६०५ ई० के मितम्बर मास म मिस्टर दादा भाई नौरोजीकी ८१वीं वर्षगांठ मनाई जाने के समय दम्बई में एक सभामाधारण सभा के सभापति का आसन ग्रहण करत हुये लोक मान्य मिस्टर गोखले ने निम्न लिखित वक्तृता दी]

भद्र श्री और पुरुषो! आप लोगोंन मुझे इस समय सभा का सभापति बनाया है। इस सत्कार के लिये मैं सन्ध हृदय से आप लोगों को अन्यावाद देता हूँ। इस महात्सव म इतने भारी गद् ग्रहण करने से मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। किसी देश म एक साधारण व्यक्ति की घण्टा के उत्सव का जय इस प्रकार जनता मनाये तो यह उत्सव उस देश के लिये अपूय उत्सव है। और उस उत्सव की शोभा सांगुती बढ़ जाती है जय प्रत्येक मतावलम्बी अपना सत्कार दिखलाने के लिये उसमें सम्मिलित हो। मिस्टर दादाभाई का अपने दीर्घ और यशस्वी जीवन में उस प्रेम के बहुत स-सकृत मिले हांगे जिस प्रेम की दृष्टि से इस देश के हरएक मजहब के लोग उन्हें देखा करते हैं परन्तु मुझे खन्नेह है कि उनके सत्कार के उपलक्ष में चाहे बड़ी से बड़ी खुशी क्यों न मनाई गई हो परन्तु क्या वह खुशी उनके चर्प गाँठ के इस वापिक उत्सव की खुशी का मुकाबला कर सकती है जा केवल दम्बई ही में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सा में भी मनाई जा रही है। सज्जनो इस महती सभा का क्या प्रयोजन है? इसका क्या कारण है कि मिस्टर दादाभाई ने थोड़े ही

समय में बिना किसी जाति पाति के झगड़े के अपने लाखों देशवासियों के हृदयों में वह स्थान जमा लिया है जो राजा और महाराजाओं को भी दुर्लभ है। हम उनका मान इसलिये नहीं करते कि वे हमारे समय के अथवा ५० वर्ष पूर्व से सब से बड़े राजनीतिज्ञ हैं बल्कि इसलिये कि उनमें हमारे देश के उच्च और उत्तम विचार विद्यमान हैं और इसलिये कि वे भविष्य में जानीय उद्देश्यों के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने इस अवस्था को उसी समयसे प्राप्त कर लिया है जब हम में से बहुत तो पैदा भी न हुये होंगे और हममें से कोई भी ऐसा न मिलेगा जिसपर जातीयता के नामों में उनकी शिक्षा और उदाहरण का प्रभाव न पड़ा हो। सन् १८५० वर्ष पूर्व जब मिस्टर दादाभाई का जन्म हुआ था, किसको मालूम था कि वह सयुक्त भारतवर्ष के सब से बड़े और विश्वस्त नेता (मुखिया) निकलेंगे। उस समय ऐसी भविष्य बाणी करना वाला मनुष्य पागल समझा जाता।

सन् १८२५ ई० में मरहटों के राज्य का अंत हुआ था। यह वह समय था जब कि अंग्रेजी शासकों ने जिनके अग्रसर पल फिन्स्टन साहब सदा माने जायेंगे, पहिले ही पहिल अपनी बुद्धिमत्ता और उदार राजनीति से राज्य स्थापित करने का काम अपने हाथ में लिया था। और इस ओर के लोगों के दिल स्वभावतः गुस्से और असंतोष से भरे हुये थे और उनको इस बात की व्यर्थ आशा भी थी कि हमारी गवर्मेन्ट किसी न किसी दिन फिर स्थापित होगी। इस समय पश्चिमीय शिक्षा

*उनका प्रभाव अपने देशवासियों पर ऐसा ही है जैसा कि स. म. व. महाराजा का उन लोगों पर है जिनके जीवन की आशाएं उनकी शिक्षाओं से बढ़ गई हैं।

प्रणाली का प्रादुर्भाव मुश्किल से हुआ था। और १८३३ के चार्टर एक्ट का कुछ नाम या निशान भी नहीं था और जिस प्रकार इस यात का किसी को ख्याल भी नहीं हो सकता कि एशिया के सब प्रदेश एक दूसरे से संगठित हो जायेंगे उसी प्रकार उस समय किसी को भी पता नहीं था इस बड़े देश के इतने सूरे होते हुये भी सब लोगों के एकही उद्देश और एक ही भाव होंगे। मेरी समझ में यह अंग्रेजी शासकों की बुद्धिमत्ता और उदार राजनीतिका परिणाम है कि जो यात पहिले ख्याल में भी नहीं आती थी वह प्रत्यक्ष मूर्तिमान् देख पड़ती है। मिस्टर दादाभाई और उनके साथ के काम करनेवाले पुराने सुधारकों को ही गौरव प्राप्त होना चाहिये कि उन लोगों ने देश की अवस्था को खूब समझा और अपने देश भाइयों की आवश्यकताओं पर विचार किया और दिज्ञोज्ञान से परिश्रम करके उनको पूरा दिग्मा दिया।

उस समय के कार्यकर्त्ताओं का एक समुदाय इस कार्यक्षेत्र से ऊभल हो गया और हमारे में से थोड़े से अब भी, हमें रास्ता दिखलाने के लिये जीवित हैं। परमात्मा उन्हें दीर्घायु करे। परन्तु इन सब वर्षों में दादाभाई हरेक कामों में, अग्रसर रहे हैं और न तो अवस्था और निराशा ने उनके उत्साहों पर धक्का पड़ुवाया और न उन लोगों की अनउपस्थिति ही ने देशवासियों के प्रति उनके प्रेम को कम कर दिया। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार, उन्होंने इस राजनैतिक आन्दोलन की खबरदारी की जिसकी शुरुआत छोदी थी और जिसने अब विशाल रूप धारण किया है। उसी की विजय और हार पर उनके जीवन की विजय और हार थी और उन्होंने इस आन्दोलन के प्रत्येक रूप को

देखा है। वे उस समय भी इस आन्दोलन के परिपोषक थे जिस समय उसके लिये लोगों को आशा और दृढ़ विश्वास था और उन्होंने उस समय भी आन्दोलन से अपने को अलग नहीं किया जिस समय उनके लिये निराशा ही निराशा दिखलाई पड़ती थी। इसलिये आज दादाभाई को जन्मगांठ मनाते समय हम उस महान व्यक्ति के प्रति अपना संस्कार प्रगट करते हैं जो ५० वर्ष से भी अधिक से हमारे भगड़े और उद्देशों की साक्षात् मूर्ति रहे हैं और उस मंगलदाता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं जिसने इस महान पुरुष को इतने दिनों तक जीवित रखा है जिसने अपना सब कुछ मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर दिया है।

सज्जनो ! दादाभाई में कितनी मधुरता, सादापन, सहज शीलता, आत्मसयम, देशानुराग, प्रेम और उच्च उद्देशों की पूर्ति की आकांक्षाएँ भरी हैं। ज्योंही कोई इन गुणों का स्मरण करता है त्योंही उसे मालूम होता है कि वह गाया एक महान व्यक्ति के सामने खड़ा है। निस्सन्देह मिस्टर रानाडे के कथनानुसार तीस करोड़ पुरुषों में से यदि एक भी ऐसा महान पुरुष उत्पन्न हो तो उसे जाति को पड़ी आशा रखनी चाहिये।

सज्जनो ! धर्म के इतनी भारी जैनसंख्या के समुख मिस्टर दादाभाई नौरोजी के व्यक्तिगत गुणों का चर्चन करना मुझे निरर्थक मालूम होता है। अपने समय को उनकी मुख्य शिक्षाओं के कहने में खर्च करूँगा जिनके विषय में थोड़े दिनों से तेरफ वितर्क किया जा रहा है। जो रत्नाम्र अंगरेजी शासन से हम लोग को प्राप्त हुये हैं उनको पूर्ण रीति से मानने के

लिये मिस्टर दादाभाई से बढकर कोई दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं है।

प्रथम २ उन्हीं को यह यात जँची और अपने दीर्घ जीवन में बराबर आप अपने शासकों को सूचना देते चले आये हैं कि अंगरेजी शासन के लाभ को दो बड़ी बुराइया तदृश नदृश करे डालती है एक तो द्रव्य सम्यन्धी और दूसरी नीति सम्यन्धी। द्रव्य सम्यन्धी बुराई यह है कि बिना किसी लाभ के प्रत्येक वर्ष बहुतसा धन यहां से बाहर चला-जाता है और नीति सम्यन्धी बुराई यह है कि बड़े और उत्तर दायित्व के ओहदों में शामिल न किये जाने के कारण जाति की शक्ति क्षीण होती जा रही है। मैं समझता हू कि इन दोनों धानों में मिस्टर दादाभाई का कथन अखण्डनीय है। जो मिस्टर दादाभाई इन वर्षों में बराबर आन्दोलन करते चले आये हैं कि बिना किसी लाभ के बहुत सा धन प्रतिवर्ष देश के बाहर जा रहा है इसमें केवल यूरोपियन अफसरों की पेन्शन और अंगरेजी सेना का खर्चा या और दूसरे खर्च जो इंग्लैण्ड में इण्डियन गवर्मेन्ट के नाम पर किये जाते हैं शामिल नहीं हैं बल्कि वह लाभ जो यूरोपियन व्यापारी पैदा करके इंग्लैण्ड देश के लिए बाहर भेजत हैं, और अंगरेजी बगीलों-डाकूतों और कर्मचारियों को पचता भी शामिल है, उनका कथन है कि कमसे कम तास करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बाहर चला जाता है। इंग्लैण्ड का हिन्दुस्तान के साथ राजनैतिक सम्बन्ध होने की वजह से लोग भले ही कहें कि इतना रुपया जाना उचित है परन्तु अथशास्त्र की दृष्टि से देखने पर मालूम होता है बिना किसी फायदे के इतना धन देश से निकल जाता है। अंगरेज कर्मचारियों की जगहों पर हिन्दुस्तानी कर्मचारी साधारणतः नियुक्त किये जा सकते हैं

परन्तु ऐसा नहीं किया जाता परिणाम यह होता है कि प्रचुर धन इस देश का बिना किसी लाभ के बाहर चला जाता है। हिन्दुस्तान यदि बनी भी होता तो भी इस प्रकार प्रतिवर्ष इतने द्रव्य का बाहर जाना बड़े ध्वरादृष्ट की बात थी। परन्तु सब इस बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान ससार के दगिर् देशों में न एक है और इसी लिये मिस्टर दादाभाई का कहना है कि इतने धन के चले जाने से देश में बचत नहीं हो सकती। और चूँकि कारीगरी धन पर बड़ है और धन बचत से एकत्रित होता है अतः इतने रुपये प्रतिवर्ष बाहर चले जाने की वजह से देश की कारीगरी नहीं बढ़ सकती। अब रही बात हम लोगों के बड़े और उत्तरदायित्व के उद्देश में न लिये जाने की इस विषय में उनका कहना गिल्कुल साफ है। जब कि हम भिन्न २ ऊँचे पदों में नियत किये जाने का आन्दोलन करते हैं तो इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि 'थोड़ी' सी जगह हमारे देश भाइयों को और मिल जाय-यदि ऐसा भी होता तो भी नाक भी सिकोड़ने की कोई बात नहीं। बल्कि वस्तुतः हमारी इच्छा है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में हम भी सम्मिलित किये जायें। हम चाहते हैं कि हम अपने ही देश में ऐसी २ जगहों में काम करें जिस से हमारी शक्ति और आचरण की वृद्धि हो और कार्य को आरम्भ करने की योग्यता आवे और सचमुच इसी से उन लोगों की भिन्नता मालूम होती है जो शासन करते और जो केवल आशा का प्रतिपालन करते हैं। तब भी बहुत से छिद्रान्वेषी कहते हैं कि मिस्टर दादाभाई जोड़े दिनों से अति कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो अगरेजी कर्मचारियों को उत्तेजित करनेवाले हैं। सज्जनों! मेरी इच्छा है कि वे सभ्य जो इस बात की शिकायत

कहते हैं एक या दो बातों पर ध्यान दें। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि मि० दादाभाई ससार के शांतिप्रिय मनुष्यों में से एक हैं और जब ऐसे शांति प्रिय पुष्प को बड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो यह समझना चाहिये कि सचमुच कुछ ऐसी अवस्थायें आ पड़ी हैं कि जिनकी वजह से उन्हें कड़े शब्दों से काम लेना पड़ा है। और उनके कड़े शब्दों का दोष उन पर नहीं है बल्कि उन पुरुषों पर है जो उन्हें ऐसा करने के लिये विवश करते हैं। मिस्टर दादाभाई के आत्मिक और बीचवाले लेखों को देखिये। मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि कोई एक भी शब्द नहीं निकाल सकता जो फेंका कहा जा सके। यदि हाल में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कुछ लोगों को बड़े प्रतीत होते हैं तो इसका यही कारण है कि इतने वर्षों के उनके लेखों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया दूसरे उन्हें मालूम होगया है कि कुछ वर्षों से अंगरेजी शासन प्रणाली क्रमशः गिरती जा रही है। यहिनो य सउजनों—दसके अलावा दादाभाई ऐसे वृद्ध और देश के लाभ के लिये तन मन धन अर्पण करने वाले मनुष्य को तो सब बातें सच २ कह देना चाहिये और बग़ावटी लच्छेदार बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जिनके करने की आशा आप से और हम से कभी २ की जा सकती है। मेरी समझ में मिस्टर दादाभाई केवल अपने देशवासियों ही के नहीं बल्कि शासकों के भी पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। और यदि गुरु सच्चाई को सुन्दर प्रेमल शब्दों से ढकने का कुछ भी चिन्तन करें तो उनपर कोन दोषारोपण कर सकता है। सउजनों ? अंगरेजों के शिकायत करने की मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे परवाह उन अपने

परन्तु ऐसा नहीं किया जाता परिणाम यह होता है कि प्रचुर
 धन इस देश का बिना किसी लाभ के बाहर चला जाता है।
 हिन्दुस्तान यदि बनी भी होता तो भी इस प्रकार प्रतिवर्ष इतने
 द्रव्य का बाहर जाना बड़े ध्वराहट की बात थी। परन्तु सब इस
 बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान ससार के दग्ध देशों में से
 एक है और इसी लिये मिस्टर दादाभाई का कहना है कि इतने
 धन के चले जाने से देश में वृद्धि नहीं हो सकती। और चूंकि
 कारीगरी धन पर बद्ध है और धन वृद्धि से एकत्रित होता है
 अतः इतने रुपये प्रतिवर्ष बाहर चले जाने की वजह से देश
 की कारीगरी नहीं बढ़ सकती। अब रही बात हम लोगों के यहाँ
 और उत्तरदायित्व के 'उन्हें' में न लिये जाने की इस विषय
 में उनका कहना बिल्कुल साफ है। जब कि हम भिन्न २
 ऊँचे पदों में नियत किये जाने का आन्दोलन करते हैं तो
 इसमें हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि 'थोड़ी' सी जगह
 हमारे देश भाइयों को और मिल जाय—यदि ऐसा भी होता
 तो भी नाफा भी सिकोड़ने की कोई बात नहीं। बल्कि वस्तुतः
 हमारी इच्छा है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में हम भी
 सम्मिलित किये जायें। हम चाहते हैं कि हम अपने ही देश
 में ऐसी २ जगहों में काम करें जिस से हमारी शक्ति और
 आचरण की वृद्धि हो और कार्य को आरम्भ करने की योग्यता
 आवे और सचमुच इसी से उन लोगों की भिक्षता मालूम
 होती है जो शासन करते और जो केवल आज्ञा का प्रतिपालन
 करते हैं। तब भी बहुत से छिद्रान्वेयी कहते हैं कि मिस्टर
 दादाभाई थोड़े दिनों से अति कटु शब्दों का प्रयोग कर
 रहे हैं जो अंगरेजी 'कर्मचारियों' को उत्तेजित करनेवाले हैं।
 सचनों! मेरी इच्छा है कि वे सभ्य जो इस बात की शिकायत

करते हैं एक या दो बातों पर ध्यान दें। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि मि० दादाभाई ससार के शांतिप्रिय मनुष्यों में से एक हैं और जब ऐसे शांति प्रिय पुरुष को कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो यह समझना चाहिये कि सचमुच कुछ ऐसी अवस्थायें आ पड़ी हैं कि जिनकी वजह से उन्हें कड़े शब्दों से काम लेना पड़ा है। और उनके कड़े शब्दों का दोष उन पर नहीं है बल्कि उन पुरुषों पर है जो उन्हें ऐसा करने के लिये विवश करते हैं। मिस्टर दादाभाई के आरम्भिक और बीचवाले लेखों को देखिये। मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि कोई एक भी शब्द नहीं निकाल सकता जो रूढ़ा कर्हा जा सके। यदि हाल में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कुछ लोगों को बड़े प्रतीत होते हों तो इसका यही कारण है कि इतने वर्षों के उनके लेखों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया दूसरे उन्हें मालूम होगया है कि कुछ वर्षों से अंगरेजी शासन प्रणाली क्रमशः गिरनी जा रही है। यहिनो व सज्जनों—इसके अलावा दादाभाई ऐसे वृद्ध और देश के लाभ के लिये तन मन धन अर्पण करने वाले मनुष्य को तो सच बातें सच २ कह देना चाहिये और धनायदी लच्छेदार बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जिनके करने की आशा आप से और हम से कभी २ की जा सकती है। मेरी समझ में मिस्टर दादाभाई केवल अपने देशवासियों ही के नहीं बल्कि शासकों के भी पथ प्रदर्शक बंधे जा सकते हैं। और यदि गुरु सदाई को सुन्दर कोमल शब्दों से ढकने की कुछ भी चिन्ता न रहे तो उनपर कोन दोषा-रोपण कर सकता है। सज्जनों ? अंगरेजों के शिकायत करने की मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे परवाह उन अपने

परन्तु ऐसा नहीं किया जाता परिणाम यह होता है कि प्रचुर धन इस देश का बिना किसी लाभ के बाहर चला जाता है। हिन्दुस्तान यदि धनी भी होता तो भी इस प्रकार प्रतिवर्ष इतने द्रव्य का बाहर जाना बड़े घबराहट की बात थी। परन्तु सब इस बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान ससार के दग्ध देशों में से एक है और इसी लिये मिस्टर दादाभाई का कहना है कि इतने धन के चले जाने से देश में वचत नहीं हो सकती। और चूँकि कारीगरी धन पर बढ़ है और धन वचत से एकरूत होता है अतः इतने रुपये प्रतिवर्ष बाहर चले जाने की वजह से देश की कारीगरी नहीं बढ़ सकती। अब रही धान हम लोगों के गड़े और उत्तरदायित्व के उद्देश में न लिये जाने की इस विषय में उनका कहना बिल्कुल साफ है। जब कि हम भिन्न २ ऊँचे पदों में नियत किये जाने का आन्दोलन करते हैं तो इससे हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि थोड़ी सी जगह हमारे देश भाइयों को और मिल जाय—यदि ऐसा भी होता तो भी नाक भों सिकोड़ने की कोई बात नहीं। बरिक्त वस्तुतः हमारी इच्छा है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में हम भी सम्मिलित किये जायें। हम चाहते हैं कि हम अपने ही देश में ऐसी २ जगहों में काम करें जिस से हमारी शक्ति और आचरण की वृद्धि हो और कार्य को आरंभ करने की योग्यता आवे और सचेतम इसी से उन लोगों की भिन्नता मालूम होती है जो शासन करते और जो केवल आशा का प्रतिपालन करते हैं। नये भी बहून से छिद्रान्वेषी कहते हैं कि मिस्टर दादाभाई थोड़े दिनों से अति कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो अंगरेजी कर्मचारियों को उत्तेजित करनेवाले हैं। संगतों! मेरी इच्छा है कि वे सम्यक् जो इस बात की शिकायत

करते हैं एक या दो बातों पर ध्यान दें। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि मि० दादाभाई ससार के शांतिप्रिय मनुष्यों में से एक हैं और जब ऐसे शांति प्रिय पुरुष को कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो यह समझना चाहिये कि सचमुच कुछ ऐसी अवस्थायें आ पड़ी हैं कि जिनकी वजह से उन्हें कड़े शब्दों से काम लेना पड़ा है। और उनके कड़े शब्दों का दोष उन पर नहीं है बल्कि उन पुरुषों पर है जो उन्हें ऐसा करने के लिये विवश करते हैं। मिस्टर दादाभाई के आगमिक और बीचघाले लोगों को देखिये। मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि कोई एक भी शब्द नहीं निकाल सकता जो बड़ा कहा जा सके। यदि हाल में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कुछ लोगों को बड़े प्रतीत होते हैं तो इसका यही कारण है कि इतने वर्षों के उनके लेखों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया दूसरे उन्हें मालूम होगया है कि कुछ वर्षों से अंगरेजी शासन प्रणाली क्रमशः गिरती जा रही है। यहिनो व मज्जनो—इसके अलावा दादाभाई ऐसे बृद्ध और देश के लाभ के लिये तन मन धन अर्पण करने वाले मनुष्य थे तो सब बातें सच २ कह देना चाहिये और यावद्दी लब्धेदार बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जिनके करने की आशा आप से ओर हम से कभी २ की जा सकती है। मेरी समझ में मिस्टर दादाभाई केवल अपने देशवासियों ही के नहीं बल्कि शासकों के भी पथ प्रदर्शक बने जा सकते हैं। और यदि गुरु सच्चाई को सुन्दर क्रोमल शब्दों से ढरने की कुछ भी चिन्ता करें तो उनपर कौन टोपा-रोपण कर सकता है। सज्जनो? अंगरेजों के शिकायत करने की मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे परवाह, उन अपने

देशवासियों के कहने की है जो देश के लिये कुछ भी न करते हुये बिना किसी हिचक के कह डालते हैं कि कडे शब्दों का प्रयोग करके मिस्टर दादाभाई नौरोजी दश के हित की हत्या कर रहे हैं। सज्जनों मिस्टर दादाभाई चाहे मृदु शब्दों का प्रयोग करके चाहे कठिन शब्दों का प्रयोग करें, जो दादाभाई को नहीं सुनता उसे हम अपना नहीं कह सकते। जो उद्दटता से उनपर घृणा करके अपना हाथ साफ करत हैं वे एक तरह से उनका बध करते हैं।

भद्र स्त्री और पुरुषों ! मैं आप लोगों को ब्रह्म रोकना नहीं चाहता। प्रथम इसके कि मैं अपने वक्तव्यको समाप्त करूँ मेरी इच्छा है कि उपदेशके दो एक शब्द अपने नवयुवक, भ्रातागणों के सामने रखूँ। मेरे प्यारे नवयुवक! विचारिए, तो, सही कि मिस्टर दादाभाई को पैदा कर परमात्मा ने कसा सुन्दर आदर्श आपके सामने रखा है। इस महान व्यक्ति के प्रति हृदय में उत्पन्न हुआ आप लोगों का जोश यदि उसके नाम पर तालियों के पीटने ही पर सीमा बद्ध रहा तो (स्मरण रखिये) आज के बत्सव के उद्देश की पूर्ति मुश्किल से होगी। मेरी इच्छा है कि उनके जीवन से लभ्य शिक्षाओं, पर विचार, कीजिये और यथाशक्ति उन्हें कार्यरूप में परिणित करने का प्रयत्न कीजिये ताकि एक-न एक दिन वे आप में सलग्न हो जाय। सज्जनों सिध्द २ समय में सिध्द २ जानियों में सब को प्यार करने वाले और बुद्धिमान परमात्मा आवश्यकतानुसार निद्राल और बुरे साग पर जाते हुये मनुष्या को रास्ता, बिखलाने के लिये महान पुरुष प्रदान किया करते हैं। इसमें कुछ भी शका नहीं है कि इन्हीं महान पुरुषों में से दादाभाई को परमात्मा ने हमारे देश वाशियों के मध्य भेजा है। मेरी समझ में ऐसा बड़ा देशभक्त

कदाचित् ही किसी दूसरे देश में पैदा हुआ हो ।

यद्यपि हममें से कोई भी उनके गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता है और उनका ऐसा अर्द्धम्य सर्वरूप, परिश्रम करने की प्रचंड शक्ति, और मस्तिष्क हममें से बहुत थोड़ाको सुलभ हो सकता है परन्तु उनकी तरह हमलोग बिना किसी जाति पाति के टूटे के अपने देश को तो प्यार कर सकते हैं और उस बड़े उद्देश के लिये जिसकी पूर्ति के लिये वे चिरकाल से इतनी दृढ़ता के साथ परिश्रम करते चले आये हैं हम लोग भी कुछ बलिदान अग्रण्य कर सकते हैं । नतीनाथह निकला कि अपनी मातृभूमि के लिये बलिदान करने की जिज्ञा मिस्टर दादाभाई के जीवन से प्राप्त की जा सकती है । और यदि ये हमारे नए युवक इन (महाभारत) का अपने जीवनो में कुछ भी परिशिष्ट करना प्रारम्भ करदे तो देखने से भविष्य चाहे अधिकार मय ही मालूम पड़ता हो किन्तु उससे अवश्य ही भला होगा ।

भद्र स्त्री और पुरुषो । आपने बड़ी धीरता से मेरे व्याख्यान को सुना इसके लिये मैं आप लोगों को हृदय से अग्यवाद देता हूँ ।

मि० महादेव गोविन्द रानाडे

(६ मूलाद सन् १९०१ ई० को बम्बई के तत्कालीन गवर्नर श्रीमान् साहेबार्थकोट की अध्यक्षता में बम्बई की स्मारक सभा में मिस्टर गोरेले ने मिस्टर महादेव गोविन्द रानाडे पर निम्न लिखित वक्तृता दी ।)

श्रीमान् इन दिनों यदि किसी हिन्दुस्तानी को उसके प्रिय कृतज्ञ और दुःखपीडित देशवासियों से स्मारक मिलना चाहिये तो वह हिन्दुस्तानी परलोकवासी नि सन्देह रानाडे ही है । ४० वर्ष तक उन्होंने अपूर्वश्रद्धा और दृढता के साथ हम लोगों के लिये केवल एक ही क्षेत्र में नहीं बरन् सब कार्य क्षेत्रों में परिश्रम किया और कठिन से कठिन निराशाओं में भी अपने सिद्धान्त पर अटल रहे । जो काम उन्होंने हमारे लिये किये हैं जो आदर्श व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के लिये उन्होंने हमारे सम्मुख रखे हैं और मातृभूमि के लिये मंगले प्रकार जीवन अर्पण करने का जो उच्च उदाहरण उन्होंने हमें दिखलाया है । इन सब की गणना हमारे देशवासियों के अमृत्य वस्तुओं में सदा की जायगी ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मिस्टर रानाडे ने अपने काम के अधिकतर भाग को उस प्रचण्ड बुद्धि से किया है जिसे परमात्मा ने उन्हें पूरे तोर पर दी थी । परन्तु अकेले इस प्रचण्ड बुद्धि से काम न चलता यदि साथ ही साथ उनमें धीरता के साथ अपूर्ण परिश्रम, कठोर आत्म-सयम और नैतिक शक्ति न होती । यदि किसी व्यक्ति में केवल येही शक्तियाँ विद्यमान हों तो भी वह अपने देशभाव्यों में वडामान प्राप्त कर सकता है ।

इस प्रस्तावना का अभिप्राय यह है कि मिस्टर रानाडे के स्मारक चिन्ह बनाने के लिये सब लोगों से चढ़ा इकट्ठा करना चाहिये। मेरी समझ में ऐसा ठीक भी है क्योंकि रानाडे में जाति पक्षपात नहीं था, वे दूसरे समाजों की अच्छी बातों को मानने के लिये उद्यत थे और उनसे मिलजुल कर एक ही उद्देश की पूर्ति के लिये काम करते थे। उनके जीवन में एक यह भी उद्देश था कि भिन्न-२ समुदायों के लोग जातीयता के ध्याल से एक ही स्टेडफार्म पर खड़े हों और यह कहें कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई कहलाना हमारा गौड़ उद्देश है। मिस्टर रानाडे के विचार-सम्प्रदायी और संकीर्ण नहीं थे।

उनकी यह इच्छा थी कि मनुष्य के प्रत्येक कामो में उत्पत्ति हो और सब समुदायों का भला हो। सर्वोपरि जो बात वे हमें सिखलाना चाहते थे वह यह थी कि हम मनुष्य का गोण्य उसके मनुष्य होने के कारण करें।

हम सब लोगों को मालम है कि कितनी दृढ़ता के साथ मिस्टर रानाडे उस सिद्धान्त पर काम करते रहे जिस उन्होंने अपने संमुख रक्खा था। उनके जीवन का यह एक उच्च मिशन था परन्तु उसकी पूर्ति के लिये जो २ आपत्तियाँ उन्हें उठानी पड़ीं वे कम नहीं थी। उन्हें शारीरिक कष्ट तो उठाना ही पड़ा इसके अतिरिक्त उन्हें मानसिक कष्ट भी भेलने पड़े। उन्होंने इतने बड़े बोझ को सहन किया। चूँ तक भी नहीं किया और न कभी आराम की इच्छा की, ८० वर्ष पूर्व इसी स्थान में मिस्टर तेलंग के विषय में कहते हुये मिस्टर रानाडे ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन के समय सुधारकों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मिस्टर रानाडे को भिन्न २ कार्य क्षेत्रों में--इस प्रकार के दृष्टों का सामना करना, पडा-और उससे जो दुख, उन्हें पैदा हुआ उसे सहन किया। सामाजिक और धार्मिक विषयों के अलावा राजनैतिक विषयों में भी दुख उठाना, पडा। एक ओर तो शासक के उदार कामों और कठिनाइयों का विचार था और दूसरी ओर देश के फायदे का खयाल था। वे ऐसे प्रयत्न करने थे जिन्होंने किसी को क्षति न पहुँचे और ऐसा करने में उन्हें बड़ी चिन्ता और दुख का सामना करना, पडता था। परन्तु मिस्टर रानाडे ऐसी २ सफलताओं को खुशी से सह लेते थे और कहते थे कि भविष्य में इनसे अच्छा, फल निकलेगा। एक समय उन्होंने कहा था कि हमें अपने को सहन करना चाहिये इसलिये नहीं कि यह सहन में स्वाद मालूम होता है बल्कि इस कारण से कि इसके अन्तर्गत नतीजों का गौरव इन दुखों और कठिनाइयों से, कहीं बढ़ कर है। मिस्टर रानाडे में दूसरा बड़ा गुण जिसका उल्लेख मैं यहाँ, पर करना चाहना हूँ यह था कि इन्होंने सदैव अपने आचरण का विचार रक्खा और जो नियम, एक मरनवा, स्थिर कर लिया उस पर जीवन पर्यन्त अटल रहे। मिस्टर रानाडे से बढ़कर और किसी दूसरे पुरुष को अपने आचरण का इतना न्याय नहीं था। दहदहें का आत्म सत्य जो उनमें था कोई परमात्मा का देन नहीं था बल्कि उन्हीं कठिन नियमों का नतीजा था जिन को वे सदैव अपने जीवन में परिणित करत जाते थे। मैंने प्रायः देखा है कि वे सावधानतया उन असहनीय दोषों को सुना करत थे जो उनके विरुद्ध लगाये जाते थे और अपनी प्रशंसाओं की कुछ प्रशंसा भी नहीं करते थे। यह एक भूल की बात है कि उनका स्वभाव ऐसा था कि उन पर कुछ भी

प्रभाव नहीं पड़ता था। यह सत्य है कि उनके रहने और काम का ढंग साधारण मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल भिन्न था परन्तु मस्तिष्क अतीव कोमल था और उस पर हर प्रकार के अन्याय का बड़ा भारी असर पड़ता था। परन्तु उन्हें यह सब स्वीकृत था। वे कहते थे कि इससे मेरे आचरण को बड़ा लाभ होगा और इसकी कभी शिकायत उन लोगों से भी कभी नहीं किया जो उनके पास रहते थे। मेरे मित्र सर वालचन्द्र जी ने उनकी उस अपूर्व फुर्ती का उत्तरण पहिले ही कर दिया है। जिससे वे देश के सब काम करनेवालों को जान जाते थे और उन्हें काम करने का उत्साह देते थे। इस विषय में डाक्री बुद्धि बड़ी काम करती थी। परिणाम यह था कि जिस प्रकार ग्रह अपनी २ जगह पर घूमते हुये सूरज से रोशनी और चमक प्राप्त करते हैं उसी प्रकार इस देश के भिन्न २ स्थानों में रहते हुये लाभ करनेवाले मिस्टर रानाडे से शिक्षा और उत्साह प्राप्त करते थे।

उनमें प्रत्येक काम के करने की श्रद्धा भी बड़ी प्रचंड थी। जिसे वे नवयुवकों में हम २ कर भरने का प्रयत्न करते थे। जिन नवयुवकों को उनसे घना सम्बन्ध था उनके लिये उनके शब्द ही कानून थे और उनकी प्रसन्नता ही सत्कार में सब से बड़ा पारलौकिक था। मिस्टर रानाडे में सचमुच एक बड़े गुरु के गुण विद्यमान थे। और जब कि ऐसा बड़ा गुरु हमारे बीच से चल बसा तो क्या हमारे लिये यह सोचना आश्चर्य की बात है जो रोशनी भूलते हुये पद चिन्हों को अभी तक मार्ग दिखाता थी वह बुझ गई और एकाएक अकस्मात् हमारे जीवन में अन्धेरा छा गया। तथापि हम लोग तब्रता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मन् जिस

प्रकार आपने हमारे देश के लिये मिस्टर रानाडे को दिया था उसी प्रकार समय पर उन्हीं के सदृश दूसरे पुरुष को उत्पन्न कर। इस समय हमारा कर्तव्य यह है कि हम उनके नामकी उपासना कर, उनके उदाहरणों को प्रकटित करें उनकी शिक्षाओं पर दृढ़ रहें और इस बात का विश्वास रखें कि उन ज्ञानि को अपने भविष्य पर निगाह नहीं होना चाहिये जिसने एक रानाडे को उत्पन्न किया है।

(सन् १८८३, १० को रानाडे की मृत्यु सम्बन्धी सभा में श्रीमान् गोखले ने निम्न लिखित प्रकृति सम्बन्ध के हिन्दू यूनियन क्लब में दी थी।)

श्रीमान् सभापति महोदय, महिलाओं और सख्तों, शत जनवरो में मेरे मित्र मिस्टर पाखे ने हिन्दू यूनियन क्लब की ओर से मुझे लिखा था कि मैं मिस्टर रानाडे की मृत्यु पर इस घर्ष की सभा में उपस्थित होकर व्याख्यान दूँ। जिस समय मुझे उनका पत्र मिला तो मैंने विचार किया कि उनकी इस आज्ञा का प्रतिपालन करना मेरा कर्तव्य है परन्तु उस समय मैं कलकत्ते में था और मार्च के अन्त के पहिले में लौटने की कोई आशा नहीं थी। मैंने अपनी स्थिति लिख भेजी और कहा कि मैं क्लब की सेवा कर सकता हूँ यदि सभा की तिथि यदि किसी प्रकार टाल देना उचित समझा जाय। कमेटी ने यड़े आग्रहपूर्वक मेरे कहनेका मान लिया और एक दिन ऐसा निश्चित कर दिया जिस समय में आराम के साथ उपस्थित हो सकूँ। यही कारण है कि इस समय मुझे उस घटना को देने के लिये खड़ा हुआ देखते हैं जो सर्वमुच धर्मास पूर्वहीं वेदी गई होती।

भट्ट स्त्री और पुरुषों ।

मिस्टर पाण्डे के पत्रों के उत्तर में—“जो दा” कह देना बड़ी सुगम बात है परन्तु मैं अपने वक्तव्यमें क्या कहूँगा? इस विषय पर विचार करना कोई सरल बात नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि मिस्टर रानाडे बड़े कृशाय बुद्धि के थे, बड़े परिश्रमी थे और उनकी विवेचन शक्ति बड़ी प्रगट थी महान आत्मा लगातार दिना एक दिन ठहरे ३५ वर्ष पर्यंत लगातार प्रवृत्ता, मोक्षता लिखता, बोलता और काम करता रहा। उनके विषयमें चर्चा करने के लिये सामिग्रियों का थड़ा ढेर है। वे वक्ता का घण्टा देनवाली हैं। मिस्टर रानाडे के जीवन की भिन्न-२ अवस्थाओं पर एक दरजा लेखकों का देना सुगम है परन्तु इस समय उनके विषय में एक आम स्पीच देना सुगम नहीं है। अतएव हम कह सकते हैं कि मिस्टर रानाडे हमारे समय के बड़े सचरित्र महात्मा और उनके साथ का रहना बड़ा पवित्र और आचरण पर प्रभाव डालनेवाला था, अथवा यह कहिये कि वे एक बड़े देश भक्त थे। उनके हृदय में देश-प्रेम उमड़ा पड़ता था। वे बिना थकावट के हिन्दुस्तान की भलाई के लिये प्रयत्न करते जाते थे।

वे एक बड़ा उदाहरण हैं जिसका इस देश के लोगों को अनुकरण करना चाहिये, अथवा यह कहिये कि वे एक बड़े सुधारक थे जिनकी सर्वव्यापिनी दृष्टि हमारे समय के ऊपर से नीचे तक के कुल अंग पर पड़ती थी और उससे न तो राजनीतिक न सामाजिक, न धार्मिक, न शैक्षणिक, न आध्यात्मिक और न शिल्पा, सबन्धी कोई बात छूटने पाती थी। अथवा यह कहिये कि वे बड़े विद्वान् गुरु या एक हमारे समय के एक बड़े कार्यकर्त्ता थे। हम उनकी सन्मति

और जिज्ञाओं को और उन कार्य पद्धतियों को एकत्रित कर सकते हैं जो भिन्न २ कार्यक्षेत्रों में प्रिय थीं और उन पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक दरजन वक्तृताय दे सकते हैं और तब भी हमारे विषय की समाप्ति नहीं हो सकती। मिस्टर रानाडे के इन सय गुणों को लेते हुये और उनको साधारण तौर से वर्णन करते हुये एक शाम स्पीच का देना मेरी सम्मति में बड़ा कठिन काम है। जो कुछ मैं आज कहना चाहता हूँ उसमें मैं धीयुत रानाडे की जीवन्मयी घटनाओं या उनके कार्यों की आलोचना करने का उद्योग न करूँगा।

- प्रथम तो यह हमारा समय उनके समय से बहुत दूर नहीं है और दूसरे में विलकुल समीप ही रहता था। अतः मुझ में यह अलहदगी नहीं जिसके बिना आलोचनात्मक विचार नहीं किय जा सकता है। परन्तु इस सामीप्य के कारण जिसको मैं वर्णन करने में अनमर्थ हूँ मुझे अच्छे २ अक्षर हाथ लगे और मैं उनके भीतरी विचार, आशाओं और बहेशों और उनके उन आकर्षक प्रभाव के उद्गम से भिन्न होगया जो उनसे मिलने वाले लोगों पर पड़ता था इन्हीं बातों पर आज मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे उनके माथ १४ वर्ष तक रहने का सोभाव्य प्राप्त हुआ। इस बीच मैं जिन २ गुणों के कारण मैं आश्चर्य में पड़ जाता था उन्होंने २ गुणों को यथाशक्ति सक्षिप्त रूपमें बयान करूँगा। यह बताऊँगा कि उनका दृढ सकटप क्या था, और कठिनाइयों और निराशाओं में वह दृढ सकटप किस प्रकार अटल रहा। और अन्त में यह बताऊँगा कि उन्होंने अपने देश के दोनदार बच्चों के लिये क्या सदेश छोड़ा है ताकि वह फल जिम्मे लिये

उन्होंने इतना परिश्रम किया काटी जा सके और उपयुक्त समय पर आत्मा से दूर न हो जाये ।

मिस्टर रानाडे से मिलने पर पहिली बात जो देखने में आती थी, उनकी स्पष्ट, तीव्र और गहरी देशभक्ति थी, जो उनके विशाल शरीर के भीतर भरी हुई थी । मेरा अनुभव है कि यदि दूसरा और कोई पुरुष इस प्रकार दिन रात अपने देश की भलाई के लिये विचारों में डगा हुआ मुझे मिला है तो वे मिस्टर दादाभाई नौरोजी हैं । वे भारत के प्राचीन समय को उड़े गौरव और घमड़ की दृष्टि से देखते थे । परन्तु वर्तमान और भविष्य में उनकी दृष्टि विशेषरूप से रहा करती थी और यही कारण था कि उन्होंने सुधार के भिन्न २ कार्यक्रमों में अनुर्य और आश्चर्यजनक काम कर दिखाया । मिस्टर रानाडे का पूर्ण स्पष्ट रूप से मालूम हो गया था कि किन ० बड़े २ नामों ने हम भारतवर्ष के निरामी अंग्रेजी शासन में कर सकते हैं, वे उन कमाउटों से भी परिचित थे जिनका सामना करते हुए ही देश के लिये वर्तमान अवस्थाओं में काम किया जा सकता है । मने सुना है कि जब ये कालिज में थे तब उनके विचार बड़े उद्दण्ड थे । स्वर्गदासी जवेरी-लाल भाई नएक दफा मुझ से कहा था कि मिस्टर रानाडे ने उन दिनों एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने मराठा गवर्नमेन्ट के मुखामिले में अंग्रेजी गवर्नमेन्ट की खूबरी धूल उड़ाई थी, उस समय के प्रिंसिपल (इलफिस्टन कालिज के) मिस्टर रानाडे को उड़े मान और प्रेमकी दृष्टिसे देखते थे । प्रिंसिपल साहय ने उन्हें पुनानर उनके विचारों की गतिधिया समझाई और कहा, "दे नवयुवक जो गवर्नमेंट तुम्हें शिक्षा दे रही है और तुम्हारे देश के लिये इतना कर रही है, तुम्हें उसका

इस प्रकार का अनादर नहीं करना चाहिये । यह कह कर उन्होंने क्रोध में आकर मिस्टर रानाडे की ६ मासकी छात्रवृत्ति बढ़ कर दी । इस भर्त्सना से मिस्टर रानाडे के चित्तपर बुरा प्रभाव पड़ा । वे जीवन पर्यन्त ग़ड़ी श्रद्धा और प्रेम से दखते रहे अधिक पढ़ने और गुनने से उनका विचार विस्तृत हुये । चिरकाल पश्चात् वे अपना जीवनोद्देश्य समझ सके और उसे प्राप्त किया । कोई अन्याय, कोई निराशा उनके मार्ग को नहीं रोक सकी । उनके जीवन का केवल मात्र उद्देश्य यही था कि हिन्दुस्तान इतनी शताब्दियों को सुन्ती से उठे और यहाँके लोग सच्चे, न्यायी, स्वाभिमानी बने और उनमें उच्चविचार और जातीयता के लिये काम करने के विचार उत्पन्न हों । उन्होंने मान लिया कि हिन्दुस्तान और इङ्गलैंडका पारस्परिक सम्बन्ध परमात्मा की कृपा से हुआ है और इसी सत्य से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी । उनका यह सिद्धान्त विघ्नों के पड़ने पर भी नहीं ढिगा । यहाँ तक कि वे उस समय भी इस पर दृढ़ थे जब कि लोग उनके उद्देश्यों के तात्पर्य को उल्टा समझ रहे थे वे सदा अपने उद्देश्यों पर दृढ़ रहे । जो उनके समीपस्थ थे उनसे वे प्रायः कहा करते थे इस वर्तमान शासन पद्धति में यद्यपि व्यक्तिगत उन्नति करने तथा व्यक्तिगत योग्यता दिखाने के लिये कार्य करने का सर्वांग क्षेत्र है तब भी हमारे देशवासियों का बहुत कुछ भला हो सकता है और यदि अपनी स्थिति पर विचार करके अवसरों को हाथ से न जाने दें तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है ।

और उनका यह प्रखर और उत्साहपूर्ण विश्वास ही था जिसके कारण वे सुधार के कार्यक्षेत्र में काम करने गये ।

वे सत्य को चाहनेवाले और असत्य के विरोधी थे परन्तु इन्हीं दो के कारण वे सुधारक नहीं कहलाये । वे स्वभाव में बड़े सहनशील थे और जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक दूसरों की धार्मिक और सामाजिक बातों का खडन करके उनकी आत्मा को दुःख नहीं पहुँचाते थे । ससार और भारत वर्ष के इतिहास में बड़े २ सुधारक हो गये जिन्होंने अपने अदर परमात्मा की आवाज से सत्य बात कहने को प्रेरित होकर अपने अतःकरण के अनुसार काम करते, द्रुपे शरीर की आहुति दी है । मेरी राय में ऐसे लोगों का स्थान निराळा ही होता है और मनुष्य को शील से जो स्थान लाभ किया जा सकता है वह उन सब में उच्च है ।

उन्होंने सुधार इस मन्त्र से नहीं किये कि उनके अतःकरण ने उन्हें ऐसा करने के लिये कहा बल्कि उन्हें बड़ विश्वास था कि बिना सुधार के हमारी जाति सगठन नहीं की जा सकती थी । वे पुरुष जो सच्चाई की शिक्षा सच्चाई ही के लिये देते हैं यद्यपि एकही स्थान में एक समय के लोगों के सम्मुख भाषण करते हैं परन्तु सचमुच वे मनुष्यमात्र का भला करते हैं । राजा के अपा ही देश में जीवित रहने और इसी के लिये लाभ करने में सन्तोष था । वे इतिहास और दूसरी जातियों के आचार व व्यवहार के पूर्ण पंडित थे और इनको पढ़कर अपने देश के हित के लिये उनसे शिक्षा ले ली जाती थी । मिस्टर राजा के काम और शिक्षाओं को समझने के लिये मेरी सम्मति में उनके और दूसरे सुधारकों में अंतर जान लेना बड़ा जरूरी है । पंडित राजाराम मोहन, राय मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे क्योंकि उनकी समझ में, मूर्तिपूजा निरर्थक है, झूठी है और इन्हीं कारणों से वे मूर्तियों

की इतनी घुराई करते थे, मिस्टर रानाडे ने भी मूर्तिपूजा गड़न की है। क्योंकि लोगों के नीच और वृथा विश्वास में पड़ जाने का भय है और यह जाति के धार्मिक और मानसिक उन्नति में एक प्रकार का कांटा है। मेरी इच्छा है कि इसको आप लोग इस बात को अच्छे प्रकार नोट कर लें 'क्योंकि इसे से और मिस्टर रानाडे के आचरण से बहुत कुछ सम्बन्ध है और कभी २ इससे उनका मित्र आश्चर्य में पड़े जाया करते हैं। आप लोगों को भली भाँति स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थना समाज के कतिपय सभासद मिस्टर रानाडे से अप्रसन्न होगये थे क्योंकि वे ठाकुर द्वारे के मन्दिर में तुकाराम, रामदास और एकनाथ महात्माओं की जीवनि पर व्याख्यान देने के लिये गये थे। यद्यपि उनकी बातें और समाज की शिक्षाएँ बिल्कुल मिलती जुलती थीं परन्तु चूंकि वे समाज के एक विख्यात सभासद थे अतः मूर्तिपूजा के स्थान में जाने और वहाँ व्याख्यान देने के कारण कुछ लोग बिगड़ गये (एक तरह से) उस समय उनको ऐसा सोचना गलत नहीं था, ममवत उनकी जगह मैं भी यही ख्याल करता। परन्तु रानाडे कहते थे कि हमें तो वक्तवाओं से काम है जगह की कुछ परवाह नहीं वे चाहते थे कि मेरे विचार मेरे देशवासियों तक पहुँच जायें। मुझे उनके मध्य बोलने का अवसर चाहिये इस बात की कुछ भी परवाह नहीं है कि वे कदा एकत्रित हुये हैं।

दूसरी बात जो मिस्टर रानाडे में पाई जाती थी वह यह थी कि वे हमारे समय के हिन्दुस्तानियों से विचार शक्ति में सबसे बढ़े चढ़े थे। उनका दिमाग अच्छे प्रकार खुला हुआ था। व एक बात को समझ धूमकर और न्याय की दृष्टि से देख

कर प्रहण करते थे। नतीजा निकालने में कभी भी जल्दी नहीं करते थे। वे शनैः तक घुस जाते और और नतीजे निकालते थे। उनके सिद्धान्त अधिक पाठन, आलोचन और पूरी मीमांसा पर निर्धारित थे। जब यह एक मरतवा था जाते थे तो विश्वमनीय होने के कारण सर्वसाधारण पर उनके मानने के लिये बड़ा जोर डाला जाता था। उनकी पुशाम बुद्धि जातीयता के सब कामों में दौड़ती थी। उन्हें क्या था कि देश की प्रत्येक आवश्यकताओं पर एकसा आग देना चाहिये।

इसी कारण से सभी कामों की ओर उनकी विशेष रुचि थी। जितना परिश्रम उन्होंने राजनैतिक कमजोरियों का दूर करना में, शासकों के अत्याचारों को दूर करने में किया उतनाही परिश्रम उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने, घातविषाद का रोकने, विधवाओं की शारी करने, शहूँ जातियों का उच्चार करने, देश की आर्थिकस्थिति बदलाने और पूजा विभाग का अधिक पवित्र और मरल और आध्यात्मिक बनाने में किया। इन सब आवश्यकताओं को निपटण करते हुए उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि नवयुवकों को काम करने का उत्साह अधिक बढ़े ताकि उनके काम पवित्र हों, विचार ऊँच हों, और उनका जीवन पराक्रम और अच्छे उद्देश्यों से पूर्ण हो। उनके विचार बड़े माहस सरगरी और आमत पूरक लोगों के काल तक पहुँचाये गये। वे इतने प्रौढ़ थे कि कोई अगमोत प्रलाप और विचार उनको गेक नहीं सकते थे उनपर धर्मगत चाहे कितने ही अन्याय और आक्षेप किये जाते थे परन्तु उनके सिद्धान्त पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं पाती थी।

की इतनी बुराई करते थे, मिस्टर रानाडे ने भी मूर्तिपूजा
 गड़बड़ की है। क्योंकि लोगों के नीचे और बुराई विश्वास में पड़
 जाने का भय है और यह जाति के धार्मिक और मानसिक
 उन्नति में एक प्रकार का काटा है। मेरी इच्छा है कि इसको
 आप लोग इस बात को अच्छे प्रकार नोट कर लें क्योंकि इस
 से और मिस्टर रानाडे के आचरण से बहुत कुछ सम्बन्ध है
 और कभी २ इससे उनके मित्र आश्चर्य में पड़ जाया
 करते हैं। आप लोगों को भली भाँति स्मरण होगा कि कुछ
 वर्ष पूर्व प्रार्थना समाज के केतिपय सभासद मिस्टर रानाडे
 से अप्रसन्न होगये थे क्योंकि वे ठाकुर द्वारे के मन्दिर में
 तुकाराम, रामदास और एकनाथ महात्माओं की जीवनियों
 पर व्याख्यान देने के लिये गये थे। यद्यपि उनकी बातें और
 समाज की शिक्षाएँ बिल्कुल मिलती जुलती थीं परन्तु चूंकि
 वे समाज के एक विख्यात सभासद थे अतः मूर्तिपूजा के स्थान
 में जाने और वहाँ व्याख्यान देने के कारण कुछ लोग विगड़
 गये (एक तरह से) उस समय उनका ऐसा सोचना गलत
 नहीं था, सम्भवतः उनकी जगह में भी यही रयाँल करता।
 परन्तु रानाडे कहते थे कि हमें तो ब्रह्माचारियों से काम है जगह
 की कुछ परवाह नहीं वे चाहते थे कि मेरे विचार मेरे देशवा
 सियों तक पहुँच जायें। मुझे उनके मध्य बोलने का अवसर
 चाहिये इस बात की कुछ भी परवाह नहीं है कि वे कहाँ पर-
 चित हुये हैं।

दूसरी बात जो मिस्टर रानाडे में पाई जाती थी वह यह थी
 कि वे हमारे समय के हिन्दुस्तानियों से विचार शक्ति में सबसे
 चढ़े चढ़े थे। उनका दिमाग अच्छे प्रकार तुला हुआ था। वे
 हर एक बात को समझ बूझकर और न्याय की दृष्टि से देख

धर प्रहण करते थे। नतीजा निकालने में कभी भी जल्दी नहीं करते थे। वे अन्दर तक घुस जाते और और नतीजे ढूँढ निकालते थे। उनके सिद्धान्त अधिक पाठन, आलोचन और पूरी मीमांसा पर निर्धारित थे। जब यह एक मरतमा बन जाते थे तो विश्वसनीय होने के कारण सर्वसाधारण पर उनके मानने के लिये बड़ा जोर डाला जाता था। उनकी पुशाम्र बुद्धि जातीयता के सब कामों में डोड़ती थी। उन्हें प्याज था कि देश की प्रत्येक आवश्यकताओं पर एकसा ध्यान देना चाहिये।

इसी कारण से सभी कामों की ओर उनकी विशेष रुचि थी। जितना परिश्रम उन्होंने राजनैतिक कमजोरियों को दूर करने में, शासकों के अन्याचारों को दूर करने में किया उतनाही परिश्रम उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने, बालविवाह को रोकने, विधवाओं की शादी करने, अछूत जातियों का उद्धार करने, देश की आर्थिकस्थिति बदलने और पूजा विज्ञान को अधिक पवित्र और सरल और आध्यात्मिक बनाने में किया। इन सब आवश्यकताओं को निपटार करते हुये उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि नवयुवकों को काम करने का उत्साह अधिक बढ़े ताकि उनके काम पवित्र हों, विचार ऊँचे हों, और उनका जीवन पराक्रम और अच्छे उद्देश्यों से पूर्ण हो। उनके विचार उड़े साहस सरगामी और आग्रह पूर्वक लोगों के कालों तक पहुँचाये गये। वे इतने प्रोढ़ थे, कि कोई अनर्गल प्रलाप और विचार उनको रोक नहीं सकते थे उनपर व्यक्तिगत चाहे कितने ही अन्याय और आक्षेप किये जाते थे परन्तु उनके सिद्धान्तों पर किसी प्रकार की खराबिया नहीं पड़ने पाती थी।

आप लोगों में से कदाचित् जानते होंगे कि २५ वर्ष हुए दक्षिण में बड़ी अशान्ति थी। पासुदेव बलवन्त नाम का एक पूनानिवासी गृह से उजड़ लोगों को लेकर गुलाम खुल्ला गवर्नमेंट के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और वह निरपराधी लोगों को लुटने लगा। सर-रिचर्ड टेमपिल को गवर्नमेंट ने स्याल किया कि पूना के बड़े २ लोग भी इसमें सहायुभूति प्रगट करते और सहायता देते हैं क्योंकि पासुदेव बलवन्त पूना का रहने वाला एक ब्राह्मण है। उन्होंने मिस्टर रानाडे पर भी सन्देह किया। अवश्य ही यह सन्देह बड़ा ही भयानक था और नितान्त अनुचित था क्योंकि रानाडे पूना के समर्थीद आन्दोलन के घे माने हुये मुखिया थे और यह सब को मालूम था कि पासुदेव बलवन्त के भीरण उपायों के सर्वथा विरुद्ध थे। तब भी मई सन् १८७६ ई० में किमी बदमाश ने पूना के दो स्थानों में आग लगा दी। गवर्नमेंट ने एकदम मिस्टर रानाडे का तबादला धूलिया में कर दिया। उनका तबादला पहिले ही से नामिक को हो चुका था परन्तु पूना से अधिक दूर होने के कारण धूलिया अधिक सुरक्षित स्थान किया गया। यद्यपि अभी ब्रिटिशों के दिन बाकी थे तब भी उनके पास हुकुम भेजा गया कि पूना को छोड़कर एकदम धूलिया को स्थाना हो जाय। गवर्नमेंट को यह कारगरवाद इतनी विचित्र थी कि हाईकोर्ट ने भी अन्त में इस तबादले का विरोध किया।

यान तो यह थी कि मिस्टर रानाडे ने स्वयं को गिरफ्तार किया और उस का बयान लिया। पहचाने पर उनके सानगी जातीय पत्र व्यवहार एक ल तक बड़ी खबरदारी के साथ देखे गये आश्चर्य की तो यह थी कि उनके पास पूनावालों की ओर से

ऐसे पत्र आने लगे जिसमें बड़े २ डाकुओं के होनेवाले अपराचारों की रिपोर्ट थी। मिस्टर रानाड़े को फौरन मालूम हो गया पुलिसवाले पेमे २ पत्र यह जानने के लिये भजते हैं आया मुझ से यामुदेव से कोई सम्बन्ध है या नहीं है परन्तु निर्भीक होकर उन्होंने ऐसे पत्रों को घुलिया पुलिस के हवाले कर दिया। एक मास के पश्चात् जो बर्ताव उनके साथ किया जाता था उसमें ऊब गये और उन्होंने इस विषय में, एक अहमदाबादी अफसर से यान चीत की। वे मिडिल सर्जिस के पर सद्बन्ध और भवसाधारण के साथ पूरी सहायुभूति प्रगट करने के लिये वे इस प्रान्त में प्रसिद्ध हैं।

उस अफसर ने इन कृत्य पर शोक प्रगट किया और मिस्टर रानाड़े को भरासा दिया कि गवर्नमेन्ट की अप पूरा विश्वास हो गया है कि जो शका तुम पर की गई थी वह सर्वथा निर्मूल है। यदि मिस्टर रानाड़े की जगह हमरा मनुष्य होता तो जब फमा उसे इस घटना के विषय में बात चीत करने का समय मिलता तो वह कुछ न कुछ बुरे शब्द अवश्य प्रयोग में लाता। परन्तु मुझे स्मरण है उस घटना को मुझ से पयान करते हुये उन्होंने सावधानी से कहा "वर्तमान अवस्थाओं में ऐसे मत भेद पडहा जाया करते हैं" और फिर हमें यह बात भी भूल जानी चाहिये कि यदि हम उनके स्थान पर होते हो कदाचित् हमसे और भी बड़ी भूल हो जाती।

उनके न्याय का एक ठडा उदाहरण है और इस बात पर पूरा सबूत है कि चाह उनके साथ कितनी बुराई क्यो न की जाय परन्तु अंग्रेजी शासन से उनका विश्वास विचलित नहीं हो सकता था। हमारे प्रकार की एक और घटना है जो सिद्ध करती है कि हरेक प्रश्न की अन्तर्गूढ बातों को सोचने का

उनका वैसे अच्छा अभ्यास था यह घटिना नो वर्ष पूर्व हुई थी जब कि हम लोग कांग्रेस कान्फ्रेंस में सम्मिलित होकर लौट रहे थे। उस समय रानाडे की अनुपस्थिति में अवसर पाकर एक अंगरेज ने सोलापुर स्टेशन में उनके विस्तरे को सेकन्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में फेरकर उनकी जगह पर अपना अधिकार जमा लिया और इस प्रकार उनका अपमान किया था।

मिस्टर रानाडे को जब यह सूचना मिली तो वह चुपके से अपनी गाड़ी में गये और कुछ भी बिना बुरा भला कहे डाक्टर भण्डारकर के साथ जो हम लोगों के साथ थे दूसरी जगह पर बंठ गये। जब कि सोने का समय आया तो डाक्टर भण्डारकर—जो दोनों में हटके थे—ऊपर वाले सन्दूक में में चले गये और अपनी जगह मिस्टर रानाडे को दे दी। पूना पहुँचकर उन अंग्रेज बहादुर को जो असिस्टेन्ट जज थे पता चला वेमद्र पुरुष जिनका अपमान उन्होंने किया था हाई कोर्ट के जज रानाडे थे और ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने मुआफी मांगनी चाही। उन को अपने पास आता हुआ देखकर मिस्टर रानाडे अपनी पीठ फेर ली और लम्बे धुये। दूसरे दिन सुने पूछा कि क्या अब इस मामले में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा विश्वास ऐसे बपायों में भिराकुल नहीं है। यह तो केवल बात की बात है और कुछ भी हो यह मामला ऐसा नहीं है कि जिसने लिये लड़ा जाय। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुझ से प्रश्न किया “इन मामलों में क्या हमारे अन्तःकरण शुद्ध हैं। इन दिनों हम लोग अछूत जातियों के साथ जो हमारे देशवासी हैं कैसा वर्ताव करते हैं इस समय जब कि उन्हें और हम मिलजुल कर देश के लिये

काम करना चाहिये हम लोग अपने प्राचीन बड़प्पन को तिलांजुली देकर उनको नीचे ही नीचे गिराते जा रहे हैं।

यदि शामकों के भाई बिरादरी हमारे साथ हम प्रकार पेश आयें तो उन्हें हम शुद्ध अन्तःकरण से किस प्रकार दोषी ठहरा सकते हैं। उन्होंने आगे चलकर कहा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि ऐसी २ घटनायें बड़ी दुःख-उत्पादक और लज्जास्पद हैं परन्तु यदि हम इन असहनीय घटनाओं से भी कुछ लाभ उठा सकते हैं तो यह है कि हम उस काम में सच्चे हृदय से और भी लग जाय जो हमारे सामने उपस्थित है।

मिस्टर रानाडे में दूसरा गुण यह था कि वे बड़े धुरन्धर काम करने वाले थे। यदि कोई पुरुष उन कामों की समालोचना करने बैठे जो इस महान् आत्मा ने अपने जीवन में किये थे—तो उसे बड़ा आश्चर्य और डर मालूम होने लगेगा। उनका दिमाग बराबर शिक्षा प्राप्त करने में लगा रहता और वे बड़े जोश और उत्साह के साथ जो इस देश में देखी नहीं गई दूसरों को यही शिक्षा प्रदान करते थे। उामें करने की शक्ति केवल प्रयत्न ही नहीं थी बल्कि उन्हें उसमें आनन्द आता था और उन्नी में वे डूबे रहा करते थे। उसी पर वे जोधित थे और घूमते फिरते और उसी पर उनका जीवन निर्भर था।

वे हमेशा यही कहा करते थे कि इन दिनों निरत्साहपन हममें मय से बड़ी बुराई है। विरुद्ध रायों और निरर्थक दूसरे विषयों में लगी हुई शक्तियों को तो वे सह लेते थे परन्तु निरत्साहता उनके लिये असहनीय थी और इससे उन्हें बड़ा शोक होता था। वे धार्मिक उत्तरदायित्व के साथ प्रायः ये सभी काम में हाथ डालते थे। विचारकरके देखिये कि जीवन

में उन्होंने कितना काम किया। आफिस का काम करने के लिये उनके पास उद्युत था। परन्तु इससे उनके दूसरे कामों में बाधा नहीं पड़ी। दूसरे काम तो उन्होंने इतने किये जितने ६ आदमी कर सकते थे। दर्शन, अध्यात्मविद्या, समाज शास्त्र इतिहास राजनीति और अर्थशास्त्र में उनकी समान रुचि थी। ये इन विषयों के पूर्ण परिणित थे और समय २ हर विषय का अध्ययन भी करते जाते थे। यह बात सभी, फां, मालूम है कि उन्होंने राजनीति में सार्वजनिक सभा पूना के नेता बनकर २५ वर्ष तक काम किया। उन्नति की दृशा में जितने अच्छे २ काम सभा क या तो रानाडे ने स्वयं अपने हाथों से किये या उनकी सम्मति से किये गये। सभा का त्रिमासिक पत्र १७ वर्ष निकला। उसके दो तिहाई सफा में रानाडे ही के लेख रत्न करते थे। उनकी निगरानी में सभा देश की राजनीतिक और संस्थाओं से बढ़ी बढ़ी थी और कई वर्षों, म. गवर्नमेन्ट में उसकी ख्याति भी विशेष रही।

मुधार के कामों में उस दिन से लेकर जिस दिन उन्होंने फालिज ब्रौडा मृत्युपर्यन्त बड़ी कोशिश की। लिखने में, बोलने में, मुद्रादिमें में, सलाह-देन में सहायता दन में और अन्य मुधार सम्बन्धी कामों में बराबर भाग लेते रहे। सोशल का फ्रेस के वे जन्मदाता थे और गार्मिक कामों में भी उनकी लगाना रुचि रहा करती थी उनके गोडे से धर्मोपदेश ऐसे अच्छे थे कि उनसे अच्छे दूसरे धर्मोपदेश-मुझे सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ।

वे विचारशील भी करें थे। और अर्थशास्त्र सम्बन्धी विषयों पर कभी २ लिखा करते थे। भारतवर्ष सम्बन्धी अर्थशास्त्र के उनके लेख उन लोगों के बड़े लाभ के हैं जो इस विद्या को

नमस्ती रूप में भारतवर्ष में लगाना चाहते हैं। इन्डस्ट्रियल कॉन्ग्रेस बुल धरों तब पूना में होती रही। चार इन्डस्ट्रियल प्रदर्शनी जार्डों के समय में हुई थी। आप दोनों के सम्बन्धों में से एक थे। बहुत शोधोगिक और व्यापारिक सन्धायें जो पूना में गत २० वर्षों में स्थापित की गई अश्विभूत उनक वरसाद, शिक्षा और सहायता से हुई। उन्होंने मरहूँ का प्रतिष्ठान भी सिरा है यद्यपि यह अमम्पूर्ण है।

जब पर्यटन में थे तो युनिवर्सिटी सम्बन्धी मामलों में भी आप अधिक भाग लेते थे। भूतपूर्व चेम्बरलैन मि. ममलिस फेन्डी ने उनके सिन्डीकेट के कामों की प्रशंसा बड़े लोगों से की है। इन कामों के अलावा मिस्टर रानाडे का पत्र व्यवहार भी हिन्दुस्तान भर में उनके उद्युत से मित्रों और अनुयायियों से खूब था। कई वर्षों तक तो छोटे २ घरेलू मामलों से लेकर राजनीति सम्बन्धी आदि विषयों में एक दिन में २० से भी अधिक पत्रों का उत्तर देना पड़ता था। हिन्दुस्तान के प्रत्येक काम करनेवाले से उनका लगाव था। जब कभी ऐसे भले आदमी से भेंट होती तो वे फूलें न समाते, उनके कामों की प्रशंसा करते और उसके बाद उनसे सदैव पत्र व्यवहार किया करते थे। हम केवल उनके किये हुए कामों को देखकर इतने आश्चर्य युक्त नहीं होत कि उनके उत्साह को देखकर होते, वह जिससे वे काम करते थे।

वक्ता और लेखकों ने महात्मा रानाडे के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि वे बड़े प्रबल आशावादी थे जिसका लोग उनकी मानसिक शक्ति का एक अङ्ग बताते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि थोड़ा बहुत यह ठीक भी है। उनका स्वभाव सचमुच आशापूर्ण था। यही कारण था कि

यदि हिन्दुस्तान के किसी भाग में कुछ भी उन्नति दिखलाई पड़ती थी तो उसे भट्ट इस्तेमाल के लिये नोट कर लिया करते थे। उनके आगायादी होने का कारण कुछ तो यह भी था कि वे हमारे पुरुषों की अपेक्षा दूर तक की गत देखते थे। उनका देखना पहाड़ पर से चीजों के देखने के समान था और अन्य पुरुषों का देखना घरांतल ही में घड़े होकर वस्तुआ का देखना था। परन्तु मेरा तो यह विश्वास है कि मिस्टर रानाडे ने बड़े आगायादी होन का कारण यही था कि वे बड़े काम करने वाले थे। वेही लोग निराशा का पाठ पढ़ाने लगते हैं निहं काम करना नहीं आता था- जिन्हें काम करने की शक्ति और गौरव नहीं मालूम है। मिस्टर रानाडे का दृढ़ विश्वास था कि यदि हमारे देश वासी सग्नदमों से काम करें तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में है उनका विचार था कि काम करना जातीय उत्थान का कारण है और जब तक जीवित रहें तब तक खूबी से काम करते रहें। यदि उन्हें कहीं निराशा दिखलाई पड़ती तो वे हताश हिम्मत कभी नहीं होते थे। १२ वर्ष व्यतीत हुये सोशल कानफ्रेंस और उनकी अग्रियता के विषय में बातचीत करते हुये मने एक ठप्पा उनसे पूछा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी २ निर्जीव और थोड़ी सभाओं को करना 'और' प्रस्तावों को पास करने से कुछ नतीजा नहीं है इसीलिये वे अपना सम्बन्ध इससे तोड़ते जाने हे परन्तु आप इसमें इतने दृढचित्त क्यों हैं।" इस पर मेरी ओर घूम कर मिस्टर रानाडे ने कहा "यह काम निर्जीव नहीं है बल्कि उनका उद्माह निर्जीव है।" थोड़ी देर रुक कर उन्होंने मुझसे फिर कहा कुछ वर्षों तक ठहरो, समय आ रहा है कि यही प्रश्न ने लोग कांग्रेस के विषय में भी करेंगे

जिसके लिये ठाको इतना उत्साह है हमारे देशवासियों में यह घुराई है कि वे एक ही कार्य में बहुत दिनों तक एकत्र चित्त से किसी कार्य में नहीं लगे रह सकते। स्वयं तो मिस्टर रानाडे का यह अनुभव था कि फल मिलने के पहिले धैर्य और अध्ययनाय आवश्यक है। सन् १८६१ ई० में जो बात उन्होंने मुझ से कही थी वह मेरे दिमाग में गड़ गई है। उस वर्ष सोलापुर और बीजापुर के प्रांतों में अकाल पड़ गया था। सार्वजनिक सभा में जिवरा में मंत्री था, उन जिलों की हालतों पर बहुत से समाचार एकत्रित किये गये थे और घटा की हातत गवर्नमेंट के सन्मुख भी उपस्थित की गई। वह एक प्रकार स्मारक था जिसके लिये हम लोगों ने बड़ा दिमाग और परि धम रच किया था। गवर्नमेंट ने कैबल दा सतर का उत्तर लिख भेजा कि पत्र के समाचार मालूम हुये। जब हमलोगों का इस प्रकार का उत्तर मिला तो मुझे बड़ी निराशा हुई। दूसरे दिन सायंकाल में मिस्टर रानाडे के साथ घूमन के लिये गया और पूछा "इतने परिश्रम करने और प्रार्थना भेजने की कोनसी आवश्यकता है जब गवर्नमेंट इससे अधिक और नहीं कहना चाहती कि पत्र के समाचार छात हुये।" उन्होंने उत्तर दिया हमारे देश के इतिहास में हमारे स्थान को तुम लोग निरूपण नहीं करते। वे गवर्नमेंट के पास नाम मात्र को भेजे जाते हैं। वे एक प्रकार से सबसाधारण के सन्मुख उपस्थित किये जाते हैं ताकि उनके मालूम होजाय कि इस समय क्या करना चाहिये। तीजे की कुछ भी परवाह न करके ऐसा काम कई वर्ष किया जाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार की राजनीति हमारे देश के लिये विलुप्त नहीं है। इसके अति रिक्त यदि गवर्नमेंट इन बातों को नोट करले जो हम कहते

हैं तो भी यही समझना चाहिये कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया ।

दूसरी विचित्र बात उनके कार्य में यह थी कि वे छोटे से छोटे परन्तु जरूरी काम करने के लिये सदैव तैयार रहा करते थे । शिवालय बनान में उन्होंने राज के काम करने का कभी भी हठ नहीं किया, वे मन्दिर को तैयार करने के लिये ईंट और पत्थरों को कंधे पर ढोने के लिये उद्यत थे । सर्व साधारण के लाभ के कर्त्तव्य पालन में यदि उन्हें नीचा भी देखना पड़े तो उसमें लिये तैयार थे । सन् १८८५ ई० को पूना जाने के कुछ महीने पीछे मुझे एक ऐसी विचित्र घटना देखने में आई उस वर्ष म्यूनिसिपल बोर्डों में लार्ड रिपन की गवर्नमेंट के उद्देश कानून के अनुकूल नवीन परिवर्तन हुये थे । चुनाव की प्रथा पहिले पहिल प्रचलित की गई थी । पूना के लोग इस से बड़े प्रसन्न थे । उस वर्ष से पहिले म्यूनिसिपलटी का काम अफसरों के हाथ में था । मिस्टर गनाडे की इच्छा थी कि अपने शहर के मामलोंके बेराभाल में थोड़ा काम सर्वसाधारण कर । अभान्यवश पूना के एक बड़े रईस स्वर्गवासी मिस्टर कुन्टे ने बड़े जोरों के साथ अफसर घाती प्राचीन प्रथा का समर्थन किया । मिस्टर गनाडे और मिस्टर कुन्टे में सदृष्टांश होने की वजह से बड़ी मित्रता थी, मिस्टर कुन्टे के प्राचीन प्रथा के समर्थन करने ने गनाडे ने उन्हें एक अच्छी फटकार जमाई थी मिस्टर कुन्टे एक बड़े बका थे । उन्होंने जीघ ही स्वर्गवासी गण के खिलाफ बहुतसी समायों की । थोड़ी देरके लिये लोगों में बड़ा जोश उमड़ा और ऐसा मालूम होता था कि गवर्नमेंट इस मगड़े से कुछ और ही क्या करेगी । इसलिये

मिस्टर रानाडे ने मिस्टर कुन्टे को राजामद कर लेने की चेष्टा की। इस अभिप्रायसे वे मिस्टर कुन्टे की एक सभा में गये यद्यपि उन्हें मालुम था कि मिस्टर कुन्टे प्रत्येक सभा में मिस्टर रानाडे की धूल उड़ाया करते हैं। यह सभा जिसमें मिस्टर रानाडे गये रास्ते पथ में की गई थी। यह एक मक्का मक्का हाल (बड़ा घ भरा) था। हम सब लोग फर्श पर बैठे थे। और मिस्टर कुन्टे हाल के एक कोने से बोल रहे थे। दरवाजा दूसरे सिरे में था। मिस्टर कुन्टे थोड़े हाँ देर बोले थे कि मिस्टर रानाडे कमरे के भीतर आते हुये दिगम्बर पड़े। वे अदर आकर हम सब लोगों की तरह दरवाजे के समीप फर्श पर बैठ गये। मिस्टर कुन्टे ने उनकी ओरसे और घास्तघ में सब की ओर से मुँह फेर लिया। थोड़ी देर दीगता की ओर मुँह करके बोलन रहे और फिर एक ठम से चुप हो गये। उनके बैठने पर मिस्टर रानाडे अपनी अगह छोड़कर उनके पास जा बैठे। जब सभा विलजित हुई तो मिस्टर रानाडे ने मिस्टर कुन्टे से उनकी गाड़ी पर बैठकर बाहर घूमने की आज्ञा की। मिस्टर कुन्टे ने इस पर नाफ भा बढ़ाकर कहा "मैं तुम्हारी गाड़ी पर नहीं जाना चाहता"। ऐसा कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठ गये। मिस्टर रानाडे चुपके २ उनके पास गये और कहा "यदि आप मेरी गाड़ी में बैठकर नहीं जाना चाहते हों तो मैं आपका गाड़ी में बैठकर आपही के साथ चलूँगा"। ऐसा कहकर वे मिस्टर कुन्टे की गाड़ी में बैठ गये। अब मिस्टर रानाडे से आप बरकाना मिस्टर कुन्टे के लिये असंभव होगया। वे दोनों बड़ी देर तक गाड़ी में बैठ बटे इधर उधर घूमा किये और लोटनेके पहले दरेक घातें पूर्णरूपसे निपट गईं। मिस्टर कुन्टे

का क्रोध शत हो गया और उन्होंने सर्वसाधारण को मुक्त, लफत करना छोड़ दिया ।

अभी तक तो मैंने मिस्टर रानाडे को सर्वव्यापिनी मोक्ष गति देशप्रेम और कार्यान्तराग के त्रिपय में कहा है । अब मैं दो चार शब्दों में उनके स्वभाव की उत्कृष्टता अथवा उनका पवित्र स्वभाव वर्णन करूँगा जो उनकी मस्तिष्क शक्तियों से भी बढ़कर था और जिसकी वजह से भारतवर्ष भर में उनके देशवासी उन्हें प्रेम भाव से देखते थे और उन पर, अनुराग रखते थे । नवयुवक यदि उनके सम्मुख आ जाते तो यह समझते कि हम साक्षान्-परमात्मा के सामने आये, एक शब्द भी गुरु उच्चारण करने की कौन कहे जब तक साध रहते बुरे विचार मनमें नहीं आने देते थे । इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है । मेरे अनुभव में आज भी यदि कोई पुरुष उन्हीं के सदृश प्रभाव डालनेवाला है तो वह मिस्टर दादा भाई नौरोजी है । मिस्टर रानाडे के बड़े गुणों में सर्वोच्च गुण यह था कि उनमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं था । मैं कह चुका हूँ कि उन्होंने बराबर भिन्न-कार्य क्षेत्रों में काम किया परन्तु न तो उन्होंने नेक नामी की कुछ परवाह की और न इस बात का विचार किया कि मुझे इस या उस काम में शायसी मिलनी चाहिये या नहीं । प्रत्येक काम में चाहे वह राजनैतिक हो अथवा किसी प्रकार का हो उनको किसी को आगे करके करने में ही आनन्द आता था, उनकी हार्दिक इच्छा यह थी कि काम करनेवालों का नपर बढ़ता जाय । मैं समझता हूँ कि मैंने कभी किसी से मिस्टर रानाडे को यह कहते नहीं सुना कि मैंने यह काम अथवा वह काम किया है । ऐसा मालूम होता था उत्तम पुरुष एक वचन उनके शब्द कोप में

था ही नहीं, नम्रता पूर्वक अपने जीवन के अतः दिन तक अपने को शिक्षित करना भी उनका दूसरा बड़ा गुण है। स्वभाव ही से उनका हृदय बड़ा कोमल था और किसी प्रकार के अन्याय या कमीनेपन का असर उनके हृदयपर नहीं पड़ता था। परन्तु उन्होंने अपने को इतना शिक्षित कर लिया था कि हर एक शक्ति को धारण करने में सक्षम थे। उनकी स्वाभाविक मानसिक वृत्ति शान्ति तथा प्रफुल्लित थी और इसका एक कारण तो यह था कि उन्हें यह बात ज्ञात थी कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक ही है और दूसरे परमात्मा की इच्छा पर उसको अद्वैत विज्यास था।

तब भी यदि वे किसी से बहुत अप्रसन्न हो जाते, उसको किसी में निराशा होती या और दूसरे कारणोंसे उनका भीतरी खेद होता तो वे लोग जो उनका अच्छी प्रकार नहीं जानते थे उनसे चेहरे से उनके दुःख का नहीं मालूम कर सकते थे। उनका अन्य पुरुष को जाने दीजिये उनका पार्श्ववर्तीने भी उन लोगों के प्रति शिकायत नहीं सुनी जिन्होंने उनसे हानि पहुँचाई हो। वे चाहते थे कि यदि समाचार पत्रों में मेरी ख़ुशख़बरी निकले तो लोग उसे मुझे अवश्य सुनायें। किसी ७ किसी रूप में वे लगातार सर्वसाधारण के सामने रहे अतः प्रत्येक दिन प्रायः उनके कामों की समालोचनाये होती थीं चाहे वे भली हवा अथवा बुरी हों। मुझे ज्ञात है कि यदि कोई समाचार उनकी प्रशंसा में होते हों तो पूरा न पढ़ते परन्तु अपने विरुद्ध समालोचनाओं को अवश्य सुनते। चूँकि उनकी आखे कम जोर थीं इसलिये कभी २ समाचार पत्र में ही उन्हें सुनाता था। वे देखते थे कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस में ग्रहण कर सकूँ। यदि जो कुछ उनके प्रति कहा गया था

उससे उन्हें दुःख होता तो वह दुःख एक प्रकार से उनके 'आधरण' उच्च धनाता था। उनके एक गुण को मैं उरलें। इस समय मैं और करना चाहता हूँ। वे सर्वसाधारण की विशेषता: नियंत्रित और पंडित लोगों की सहायता के लिये उद्यत रहा करते थे। नीच से नीच आदमी दिन में किसी समय उनसे मिल सकता था। ऐसा कोई नहीं था जिसके पत्र का उत्तर उसे न मिला हो। वे सब की बातों को ध्यान से सुनते चाहे उसकी सहायता वे कर सकें अथवा न कर सकें। इसको वे धर्म का एक अंग समझते थे।

सन् १८६७ ई० की अमरावती कांग्रेस होजाने पर इस ओर लोटते समय उस रात को गाडीमें केवल हमी दो आदमी थे। प्रातः ४ बजे गाडीमें किसी को गाता हुआ सुनकर मैं एक दम चौंकर उठ बैठा। ओंख खोलने पर मैंने देखा कि मिस्टर रानाडे तुकाराम के दो अभग बार बार गा रहे हैं और हाथों की ताल दे रहे हैं। 'आवाज तो स्त्रीली नहीं थी परन्तु जिस जोश से वे गा रहे थे वह इतना उत्तेजक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गये और मैं भी बैठकर सुनने लगा।

जे का रजले गाजले । त्यासी हण्णे जों आपुले ।

तोचि साधू ओतयावा । देव तेथेंचि जाणावा ॥

करि मस्तक ठेंगणा लागे सताच्या चरणा ।

जरि हावा तुम देव । तरि हा सुलभ उपाय ॥

वही सच्चा साधू है और परमात्मा भी उसी में मिलता है जो दोन दुखियों की सहायता करता है इसलिये यदि तुम परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो उसका सुगम मार्ग यही है कि तुम नम्र हो और साधुओं की सगत करो।

जब कि मैं इन पदों को सुन रहा था तो मैं अपने दिल में

यह कहे बिना न रह सका कि मिस्टर रानाडे इसी शिक्षा को आदर्श मानकर उसका अनुशीलन करते हैं। यह देखने में तो सीधी सार्दी है परन्तु इसका तत्त्व जीवन के लिये बड़ा गौरव प्रद है। यह घड़ी मेरे जीवन की अमृत्य घड़ी थी और यह दृश्य सचमुच मुझे कभी भी विस्मरण नहीं होगा।

भद्र श्री शार पुरुषों ! रानाडे के जिन गुणों से मुझे बड़ा आश्चर्य होता था उन गुणों को मने पयान किया। मेरी समझ से ३० वर्ष तक उन्होंने हमारे उच्च विचार और उच्च अकांक्षाएँ सामने रखीं और चिरकाल तक ऐसा महात्मा मिलना कठिन है। इस नवीन शताब्दी के प्रारम्भ में मिस्टर रानाडे का इस प्रकार मरना हमारे लिये बड़े रोद का विषय है इसका प्रारम्भ निराशा और दुःख की जगह आशा और दिलासा से पूर्ण होना चाहिये था। वह आयाज जो इतनी गंभीर, इतनी उदार और इतनी आशा पूर्ण थी लुप्त हो गई। सच पूछिये तो उसकी बड़ी आवश्यकता अब इस समय थी। एक प्रकार की निराशा हमारे वर्तमान बड़े २ काम करने वालों के मस्तिष्कों में घुनघुना रही है म इससे माता भी पू कि वर्तमान समय की दशा ऐसी है जिसे देखकर हमारा विश्वास टूट जाय और निराशा करना उचित जान पड़े मध्य और नीच जातियों के लोग भारतवर्ष भर में क्रमशः पतित होते जा रहे हैं और जिस भारी सग्राम में हम लोग इस समय सलग्न हैं उसमें भी कई स्थानों में हम हार रहे हैं। परन्तु मेरी समझ में इससे क्या होता है यदि हम इन निराशाओं के बशीभूत होते हैं तो हम उस काम के योग्य नहीं जिसे मिस्टर रानाडे ने किया और उस सपत्ति के अधिकारी नहीं है जो वे लिये छोड़ गये हैं। आप लोगों को स्मरण होगा ७१

हम लोग किस प्रकार रोये। इस देश में हमके पहिले इतना सर्वव्यापी दुःख कभी नहीं देखा गया। ऐसा मालूम होता था कि शोक की एक विशाल लहर देशभर में फैल गई और उसका अन्तर ऊँच नीच धनी ग़ारें दरिद्र लोगों पर एकसा पड़ा। परन्तु यदि हम उनकी मृत्यु पर शोक ही शोक प्रगट करते हैं तो उनके प्रति हमारे कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती। हमें विशेषतः नवयुवकों को उनके जीवन के पवित्र और हम पर बड़ा सन्देशों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिये, जिन सिद्धान्तों के लिये जीवन पर्यन्त उन्होंने काम लिया वे ये हैं—सब के लिये समानता, और मनुष्य का गौरव मनुष्य होने के कारण मानना—

इन सिद्धान्तों की पूर्ति अतः में अवश्य होगी चाहे उसकी वर्तमान दशा कैसी ही खराब क्यों हो। हम सब उनकी पूर्ति के लिये प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु जीवन का सच्चा गौरव तो 'मातृभूमि के लिये काम करने और उस पर सब कुछ न्योत्रा घर करने पर निर्भर है'। यही सन्देश है जो मिस्टर रानाडे हमारे लिये छोड़े गये हैं। मेरे मित्रो! हमारी मातृभूमि की आधुनिक दशा चाहे जैसी हो परन्तु उसके लिये सब से अच्छा काम और उल्लिखित जिन्हें हम कर सकते हैं उसके लिये करें। एक समय था जब वह उत्कृष्ट धर्म, विज्ञान, भाषा कलाकौशल और दूसरी वस्तुओं का जो एक जाति में बड़े महत्व का है—मिटार थी।

यह बड़ी पेन के सपत्ति हमारी है, यदि हम इस बात को स्मरण रखें यदि हम उस उत्तरदायित्व को समझें जो हम पर है, यदि हम सच्चे हों और अपने स्वर्गवासी नेता के उद्देश्य के साथ उसके लिये जीवित रहना और कार्य करना

अपना उद्देश समझें तो कोई समय नहीं जान पड़ता कि इसका भविष्य उसके भूत के सदृश क्यों न हो जाय ।

। ।

२४ जुलाई सन् १९०४ में रानाडे पुस्तकालय और साज्ज इन्डियन एसोसिएशन मिल पुर की आधार शिला रखने के समय गोखले की रक्तता ।

श्रीमान् सभापति महाशय आगे भद्र पुरुषो—पहिले पाहिल मुझे इस स्मारक के सचालकों को हार्दिक प्रणाम देना चाहिये जिन्होंने इसकी नींव डालने के लिये मुझे बुलाकर मेरा बड़ा आदर किया है । जब कि मुझे यह मालूम हुआ कि आप लोगों की यही इच्छा है कि इस काम को मंफरु में आपसे सचसच कहता हूँ उम समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सोचने लगा कि आप लोग मुझ पर इतने दयालु क्यों हैं । किसी बात पर विचार न करके यह काम मुझे ही सौंपा है यद्यपि इस काम के करने के लिये मुझमें अधिक योग्य पुरुष वर्तमान हैं जिनके घाल देश की सेवा करते २ सफेद हो गये हैं और जिनके लिये यह काम बाट जोह रहा था ।

मैंने देखा कि आप लोगों के प्रबन्ध में चलगली डालने और आप लोगों को प्रचण्ड दुख में डाले बिना इस काम से मुझे छुटकारा मिलना असंभव है यही कारण है कि इस समय आप लोग मुझे अपने मध्य में देख रहे हैं । यदि इसमें केवल मेरी ही बात होती तो मैं न आता । सज्जनों चकि मैं एक मर-हठा हूँ और १२ वर्ष तक जो इस देश के विद्याध्ययन करने के लिये आवश्यक हैं—नम्रता और आदरपूर्वक शिष्टा मने उनके पास रहकर प्रदण की है दक्षिण प्रान्त की इस राजधानी में उनके स्मारक को देखकर मुझे वाग्ने की तरफ गले हम लोग भी

रहे हैं। पहिले बम्बई में २००००) रुपया इकट्ठा हो गया है और वहमेरी समझ में उनकी एक मूर्ति बनाने में लगाया जायगा। पूना में एक लाख से भी अधिक रुपया जमा हुआ है जिससे हम लोग अर्थशास्त्र की शिक्षा सम्बन्धी एक पाठशाला खोलने वाले हैं। लोगों को अर्थशास्त्र की शिक्षा देना और देश की शिष्टपंथालों को उन्नति देना, इसके उद्देश्य दानों। इसके अलावा सोशल कान्फ्रेंस मेमोरियल अहमदाबाद में है जो दो वर्ष पूर्व ही बन चुका है। उसका उद्देश्य मिस्टर रानाडे के सामाजिक सुधारों को करते रहना है। इस प्रकार हम लोग मिस्टर रानाडे के प्रति अपनी बड़ी और अमर कृतज्ञता को प्रकाशित करने के लिये जो कुछ थोड़ा बहुत हम से होसकता है कर रहे हैं।

हम पर उनके कार्य तथा विचारों का प्रभाव पड़ा यह दिखता है हमारा कर्तव्य है कि उनकी स्मृति हमारे विचारों के लिये नएसे मूल्यमानि वेस्तु है।

परन्तु सज्जनों आप लोगों को इस प्रकार मिस्टर रानाडे के स्मरणार्थ यदि एक स्मारक का बनवाना आवश्यक समझना मेरी समझ में एक महत्वपूर्ण बात है। यह इस बात को सूचित करता है कि एक नया उत्साह नवीन जीवन के पानी की सतह पर तैर रहा है और घाटी में मुर्दा हड्डियों में धीरे-धीरे जान डाल रहा है। आज इस स्मारक के उठाने का क्या मतलब है ? मेरी राय में तो इसका यही कारण है कि मिस्टर रानाडे का नाना एक सूत्र या एक ही जाति से नहीं था बल्कि सारे देश और भारतवर्ष की सत्र जातियों से था, जो काम उन्होंने देश के लिये किया उसमें स्थान या भाषा की भिन्नता की वृत्तक नहीं है और वह प्रेम और आदर की दृष्टि से देखा जाता

है मिस्टर रानाडे को इतना-गौरव कैसे मिला ? उनके काम करने का ढंग यों था कि उनके देशवासी उन्हें इतना चाहने लगे । निस्सन्देह हम सब जानते हैं कि मिस्टर रानाडे बड़े योग्य, बड़े मज्जन, बड़े सोचनेवाले, बड़े पंडित और बड़े काम करनेवाले थे और उनका घरेलू जीवन बड़ा परिश्रम था । ~ ~

केवल इन्हीं कारणों से वे अपने देशवासियों के इतने प्यारे हो सकते थे जैसाकि इस इकथित समाज से मालूम पड़ रहा है और यदि किसी मनुष्य के मरने के बाद भी लोग उसकी स्मृति रक्षा तथा आदर करने के लिये एकत्रित हों तो हमें मान लेना पड़ेगा कि वह व्यक्ति अवश्य ही उच्च जीवन का रहा होगा और उसने हमारे हृदय में बहुत ही उंचा स्थान प्राप्त कर लिया मैं कह चुका हूँ कि मिस्टर रानाडे बड़े योग्य और सज्जन पुरुष थे । परन्तु वे इससे भी अधिक थे । वे उन मनुष्यों में थे जो निबल और भूल करनेवाले मनुष्यों को रास्ता दिखाने के लिये समय समय पर भिन्न २ देशों में जन्म लिया करते हैं । वे एक काम करनेवाले पुरुष थे— नवीन धर्म पुस्तक के सिखलानेवाले थे उन्होंने हमारे विचारों में जान डाल दी और हमारे दिलों को आशा से भर दिया । उन्होंने हमारे ध्यान को उन नवीन बातों की ओर आकर्षित किया जो परमात्मा की कृपा से आविर्भूत हुई । उन्होंने उनके मतलय बतलाये । इस बात की सूचना दी कि हम क्या लाभ उठा सकते हैं उनका हमारा उत्तरदायित्व समझाया और बतलाया कि जो काम हमें करना चाहिये यदि हम उससे नें भागें तो हमारे सामने एक बड़ी अच्छी फसल आनेवाली है । उन्होंने यही सदेश हमारे पास तक पहुँचाया । उनमें बड़े २ गुण थे । उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, उनके दिलमें सदैव देश-

प्रेम तरंग मार रहा था, उनकी 'आत्मा शुद्ध' और प्रगल्भी, उनमें काम करने की बड़ी शक्ति थी, उनमें बड़ा धैर्य था और कामसे कभी नहीं थकते थे, और परमात्मा ने जिस उद्देश के लिये उन्हें पैदा किया उसमें उनका अटल विश्वास था। इन गुणों से, भूपिन मिस्टर रानाडे ने अपने देशवासियों के विचार, आशाओं और उद्देश्यों को नवीन करने का भार अपने सिर पर लिया। ३५ वर्ष पर्यन्त वे एकही कार्यक्षेत्र नहीं बदलें देश के हर एक कामों में कार्य करते रहे। उनके हृदय की एक मात्र अभिलाषा यही जीवन भर रही कि हिन्दुस्तान की भी गणना सत्कार की अन्य जातियों में होने लगे और पैना होना चाहिये भी था क्योंकि प्राचीन समयमें उसका बड़ा गौरव था। उसके स्त्री पुरुषों के रहन सहन और विचार उच्च हों और वे जातीयता के बड़े २ काम करने लगे। मेरी समझ में हमारे सामने उपस्थित काम को तथा उन हालातों को जिनमें उसे किया जाना चाहिये मिस्टर रानाडे से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति रपट रूप से नहीं जान सका।

एक पुरातन राष्ट्र का स्पष्ट दुसरी पुरातन जाति से हुआ है जिसकी सभ्यता यद्यपि जड़वाद पर निर्भर है तथापि अधिक उद्योगशील है और यदि हम अपना पतन नहीं चाहते तो यह आवश्यक है कि अपने चार्ज और की अच्छाईया को ग्रहण करें परन्तु साथही साथ अपनी अच्छी बातों को न भूल लें। मेरी समझ में मिस्टर रानाडे से बढ़कर किसी अन्य पुरुष को प्राचीन समय के लिये न विशेष प्रेम ही था और न आदर ही था। उन्होंने एक दफा कहा था कि हम यदि चाहें तो भी हमारा नाता प्राचीन काल से नहीं टूट सकता। यदि हम तोड़ भी सकें, तो भी हमें नहीं तोड़ना

चारिये । ॥ परन्तु ये केवल प्राचीन ही से नहीं सन्तुष्ट थे । उनके लिये देशकी घतमान और भविष्य अग्रसर्यें भूत स अधिक महत्त्व वाली थीं । और यद्यपि देशका घीना हुआ इतिहास हमें हमारी कमजोरियों को दिग्गलकर कमियोंको घतल कर तथा शक्तियों की असपूर्णता और उद्यति के इतिहास से प्रमाणित नियमों को प्रकाशित कर हमारे कतव्य पथपर हमें सहायता देता है तथा जीवन सप्राम में डटे रहने का हमें उत्साहित करता है तथापि जीवन का मुख्य लाभ घतमान कर्तव्यों को पूरा करने से भविष्य के लिये क्षेत्र तय्यार करने पर निर्भर है । -

इसी जोश में ये लगातार पढाकिये, लगातार सोचा किये, लगातार विचारा किये, अपने पढा को असरी रूप में लगाने को लगातार प्रयत्न करते रहे और लगातार उन प्रश्नों के हल करने पर ध्यान डटाये रहे जो उनके देशवासियों के सन्मुख उपस्थित थे । यदिकिसी दूसरे को भी उसी उत्साह से काम करते देखते तो फले न समाते । ऐसे आदमी को चाहे वह कहीं हो वे नोट कर लेते थे, उससे सम्बन्ध रखते, हरएक बात से उसे दिलासा देते और पश्चात् उसे कभी नहीं भूलते थे । यही कारण था कि हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों के काम करनेवाले उनकी सलाह लेने और ऐसे २ स्थान नियत कर लिये जहा उनके विचारों का प्रचार हो सके और वे उनको सफलता और निराशा में शान्तिना देते थे । इन सब गुणों के साथ ही साथ उनकी शरीर-कान्ति भी यही मोहनी थी जिसके बिना कोई मनुष्य बड़ा नेता या बड़ा शिक्षक नहीं हो सकता । जो उनके सन्मुख आता वही उनकी आत्मा के पड़प्पन और उदारता से भर जाता । लोग समझते कि हम

पवित्रता, प्रेम और भक्ति के मैदान में और एक प्रकार से साक्षात् परमात्मा के सामने आ गये हैं अतः उनके विचार-धुरे विषयों की ओर नही प्रवृत्ति होने पाते, थे ।

सज्जनों ! ऐसे २ मनुष्य परमात्मा के चुने हुये मनुष्य जिनको वह इस ससार में अपने उत्तम उद्देश की पूर्ति के लिये भेजते है और जय ये मरजाते है तो दुःख का अनुमान कोई नहीं कर सकता । यही कारण था तीन वर्ष से ज्यादा 'हुये' जय मिस्टर रानाडे का देहान्त हुआ तो हम में से बहुतों का ऐसा मालूम होता था कि हमारे जीवना पर एकबारगी अधेरा छा गया त आर दुःख वेश भर में छा गया और और ऊँचे नीचे, धनी और दरिद्र सब प्राणों और सब जातिओं पर इसका भयकर असर पड़ता पड़ा । और हमारे देश की उस वृत्तवृत्ता को प्रकाशित करने के लिये और यह दिखलाने के लिये ये हमारी मलाई के लिये जीवित और काम करते रहे मिश्र २ स्थानों में स्मारक बनवाने के प्रयत्न होने लगे ।

सज्जनों ! मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता है कि मद्रास का स्मारक पुस्तकालय के रूप में होगा । उनके स्मरणार्थ इससे बढ़कर और कोई दूसरा स्मारक आप लोग निश्चित नहीं कर सकते थे । जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे समय के लोगों ने ज्यादाही मिस्टर रानाडे का समय पुस्तकों में फटा । यह बात मानी हुई है कि रानाडे से बढ़कर किसी दूसरे ने न तो पढ़ने में इतना लाभ ही उठाया और न पढ़े हुये को असली काम ही में पूर्ण रूप से लगाया ।

जो विषय इस पुस्तकालय से सुगम किये जाने का विचार हो रहा है उन विषयों की ओर अपने को लगाते हुये नवयुवकों को देखकर जो सतोष और आशा होती वह दूसरी बातों में

उन्हें नहीं हो सकती थी। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों का पुस्तकालय साउथ इन्डियन एसोसियेशन के सयन्ध में है और पात्र भिन्न २ विषयों में यानी इतिहास अर्थशास्त्र, राजनीति, शिल्पकला और विज्ञान में उन्नति देना इसका उद्देश है। इनमें से तीन विषयों में तो वे म्यं बढ़े बढ़े थे और जरूरत है कि नवयुवक उनका अध्ययन करें। शिल्पकला और विज्ञान में शिक्षित समुदाय के अग्रिम भाग को सतोऽजनक सफलता मिलना असंभव है। इसके लिये उस विषय की ऊँचे दर्जे की विशेष योग्यता की आवश्यकता है और ऐसी विशेष योग्यता केवल बहुतही बड़े व्यक्तियों में पाई जाती है।

मुझे पूर्ण आशा है कि जब इसका काम पूर्णरूप से प्रारम्भ होजायगा तो इसमें कुछ ऐसे निम्लेंगे जो इन विषयों का अध्ययन जीवन पर्यन्त करेंगे। इतिहास अर्थशास्त्र राजनीति की ओर तो नवयुवकों में से बहुतों का ध्यान आकर्षित होगा। आप लोगों ने भाषा, धर्म और तब शास्त्र के अध्ययन को छोड़ दिया है। यह ठाक नहीं है मेरा मतलब यह नहीं है कि आप लोग इन विषयों की ओर घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल नहीं—परिह्र आपकी राय में जिन विषयों के अध्ययन का प्रबन्ध आप लोग कर रहे हैं उनकी ओर कुछ भी तवज्जह नहीं की गई इसलिये उनकी उन्नति विशेष रूप से होनी चाहिये। सज्जनों, हम लोग खुलमुखुला इस बात को मानते हैं कि उस पुरुष को घड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आजकल सब समाचारों का पता लगाना चाहता है। आजकल एक विषय पर इतनी पुस्तकें निकलती हैं और उन का समुदाय इतना बढ़ना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के

सर जी० एम० मेहता

४ मई सन् १९६५ ई० की प्रान्तीय आठवों कान्फ्रेंस में जिसकी बैठक बेलगाव में हुई थी यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था कि जो काम मि० मेहता ने बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करके गत सुप्रीम कौन्सिल में अपने देश के लिये किया था उसके लिये वे इस कान्फ्रेंस के इतिहास में विरस्मरणीय रहेंगे यह कान्फ्रेंस सभापति को इस बात का अधिकार देती है कि वे इस भाव का एक मानपत्र तैयार कर और उनकी सलाह से समय और स्थान निश्चय कर उसे उन्हें समर्पण करें।

(ऊपर लिखित प्रस्ताव उपस्थित करते हुये प्रोफेसर जी० के० गोखले ने निम्नलिखित वक्तृता दी थी)

सभापति महोदय और भद्र पुरुषों ! जो प्रस्ताव में आप लोगों के सन्मुख अगीकारार्थ उपस्थित करनेवाला है, उसके पेश करने में मुझे केवल प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मेरा हक भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द यह सभापति की ओर से आपके खामने रक्षित जायगा तो आप लोग उत्साह और एक स्वरसे इसका अनुमोदन करेंगे।

भद्रपुरुषों ! मिस्टर मेहता की कुशाग्र बुद्धि और उनके वे काम जो उन्होंने २५ वर्ष सार्वजनिक जीवन में अपने प्रान्त के लिये ही नहीं सारे देश के लिये किये हैं। इतने विख्यात हैं कि उनके नाम से सचमुच घर-घर का गच्चा भली भाँति भिन्न है। उनकी प्रबल बुद्धि, निर्भीक स्वतन्त्रता, गौरव और

विवेचन शक्ति ने उनको प्रेसीडन्सी के सार्वजनिक जीवन का नेता और बम्बई के सार्वजनिक जीवन का एक अपूर्व अगुआ बना रक्खा है ।

सज्जनो ! जब किसी व्यक्तिको इतना उच्च सम्मान मिल जाता है तो स्वर्गधाम्नी लारियट के शब्दों में उसपर तुलनाओं की भरमार होने लगती है, मेरी समझ में मि० मेहता की कौन कहे यही हाल सचका होना है । मनुष्य और वस्तुओं की आलोचना करने में पूर्ण पंडित मेरे एक मित्र ने बम्बई में मि० तेलग, मि० मेहता और मि० रानाडे के त्रिषय में कहा था कि मि० तेलग स्पष्टवादी और सुशिक्षित, मि० मेहता प्रबल कुशाग्र बुद्धि और मि० रानाडे अति गम्भीर और नवीन बातों के निकालने वाले थे । सज्जनो, मेरी समझ में तुम मुझसे सहमत होगे कि यह आलोचना सत्य है । परन्तु यदि कुछ लोग यह कह कि मि० मेहता बड़े बुद्धिमान और तेज हैं तो इससे यह नतीजा निकालना चाहिये कि अन्य गुणों की उनमें कुछ न कुछ कमी है । मुझे तो ऐसा मालूम होता चला आया है कि उनमें मि० मडलीक की स्वतन्त्रता और आचरणशक्ति, मि० टोलगड का स्पष्टार्थ और विद्या और मिस्टर रानाडे की अच्छी समझ और नवीन बातों का निकालना ये सभी गुण विद्यमान थे । इन गुणों का परिचय सदा मिलता रहा परन्तु जैसा गत सुप्रीम कौन्सिल में मिला वैसा कभी नहीं मिला । सज्जनो, गत कौन्सिल में मिस्टर मेहता द्वारा संपादित कार्यों का सविस्तार निरूपण मैं नहीं करूँगा । पहिली बात तो यह है कि वे अभी तक हमारी आँखोंके सामने धूम रहे हैं और दूसरी बात आने बम्बई की सार्वजनिक सभा में उनकी व्याख्या स्पष्टतया कर दी है, एक बात तब भी मैं अग्रगण्य दूँगा कि उन्होंने गत

मुवाहर्सा म सिद्ध कर दिया कि वे कौंसिल और इमर
सस्थाओं में अंग्रेजों का मुकाबिला कर सकते हैं। जिन लोगों
ने उन मुवाहर्सा को पढ़ा है वे मुझसे सहमत होंगे कि मिस्टर
मेहता की दलीला ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें निपुण तार्किक सिद्ध
कर दिया है और वज्रदासी स्पीच से मालूम होता है कि वे
अपने सिद्धान्त के बड़े पक्के थे और उनकी, वक्तृताओं में बड़ा
मसाला भरा हुआ करता है। उस समय गवर्नमेंट की ओर से
एक के बाद दूसरे मेम्बर मिस्टर मेहता का पछाड़ने के लिये
उठे। फौजी सभासद सर चार्ल्स इलियट, सर एनटनी मेक
डानेल, सर जेम्स लेस्ट वेन्ड हरएक ने बारी बारीसे मिस्टर
मेहता का सामना किया। यह इस बात को सिद्ध करता है कि
जिस पक्ष को मिस्टर मेहता ने पकड़ो वह पक्ष गवर्नमेंट की
दृष्टि में कितना मजबूत था। सर जेम्स वेस्टलडने मिस्टर मेहता
को पछाड़ने की कोशिश में अपने को लादित किया। जब
मिस्टर मेहताने उड़े जोरों से सिविल सर्विस की बुराईया की तो
वे बिठ गये और खिमिया कर कहने लगे कि मिस्टर मेहता
एक नवीन ओश कौंसिल में पैदा कर रहे हैं उनपर कटु शब्दों का
प्रयोग का लाज्जत लगाया। जब दोनों की वक्तृताये छप गईं तो
सर्व साधारण मजूर देख सकते थे कि किसके वचन कठोर थे
जिस धीरता से मिस्टर मेहताने उस समय काम लिया उसकी
प्रशंसा बलकत्ता के स्टेट्समेन ने भी मुक्तकण्ठ से की है। मुवाहर्से
भर में अपने को अपने विरोधियों का मुकाबिला करने वाले
सिद्ध किया है। मद्रास समाचार पत्र के एक सम्पाददाता
क्या ही खूब कहा है कि मिस्टर मेहताने दलील का उत्तम
दलील में, किडक का जयाब किडक में, मजाक का मजाक
और हँसी का उत्तर हँसी में दिया। सज्जनों, हम यह सुनकर

बड़ा अहंकार है कि हमारे प्रतिनिधि ने इतनी सफलता प्राप्त की। हमें यह भी देखकर अमड है कि हमारे मित्रों ने कलकत्ते में इंग्लैंड सी अनर्जी की अध्यक्षता में कामिल ने अपना सभा सत्र रखते हुए भी अपनी कृतज्ञता प्रगट करने के लिये उन्हें एक मानपत्र दिया। हममें से जो मिस्टर मेहता से परिचित हैं वे इस बातको जानते हैं कि वे इन मानपत्रों की कुछ भी परवाह नहीं करने। हम जानते हैं कि जिन काया को उन्होंने सम्पादन किया है वे स्वयं पुरस्कार रूप हैं। तब भी उनका प्रति इस समय हमारा कर्तव्य है शीघ्र उन कर्तव्य की पूर्ति इसी प्रकार हो सकती है कि हम सभापति महोदय को इस बात का अधिकार दें कि वे हम लोगों की कृतज्ञता मिस्टर मेहता को सन्मुख उसी प्रकार से प्रकाशित करें जसा इस प्रस्तावना में लिखा है।

विद्यार्थी और राजनीति ।



(माननीय मि० गोखले ने उम्मीद विद्यार्थी-भ्रातृमण्डल के सामने ६ अक्टूबर १९०६ को यह व्याख्यान दिया था —)
सज्जनों,

इस समय हमारे सामने अत्यंत चिन्ताजनक और महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या यह है कि हम अपने नव युवकों को किस प्रकार ऐसी उद्दिमत्तापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण सलाह दें कि उनका जीवन उत्कृष्ट उद्देश्यों की पूति में और मातृभूमि की सेवा के लिये घोर गम्भीर परिभ्रम करने में बीते । एक ओर तो हमें चाहिये कि उन विशुद्ध आयेगों और उदार जोशों को, जो नवयुवकों के हृदय ही में उत्पन्न होते हैं, निर्मल न होने दें किन्तु ज्यों का त्यों प्रबल बनाये रखें । दूसरी ओर हमें चाहिये कि उनके मनमें सत्र घातों के उचित परिमाण में देखने का उत्तरदायित्व का, और देश की वास्तविक आवश्यकताओं को ठीक २ समझने का भाव उत्पन्न करें । यह दुहरा काम यो तो सदा ही और सर्वत्र ही कठिन होता है पर हमारे देश की वर्तमान अवस्था अन्नाधारण त्रिषम कठिनाइयों से परिपूर्ण है । हमारे चारों ओर ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो हम सब से यही कहती हैं कि "अब न तो बैठने का, और न खड़े रहने का

किन्तु आगे बढ़ने का समय है"। जिस हवा में हम साँस लेते हैं वह स्वयं परिवर्तन की अभिलाषा से भरी हुई है। पुराने विश्वास विध्वंस हो रहे हैं। परिस्थिति के अनुसार विचारों में नये २ परिवर्तन आवश्यक हो गये हैं। जरा चारों ओर यह हलचल मच रही है जिसे लोग 'अशान्ति' के नाम से ठीक ही सम्बोधन करने हैं तब यह आशा नहीं की जा सकती थी कि हमारे विद्यार्थी अपने पुराने स्थान पर खड़े रहेंगे जरा भी आगे न बढ़ेंगे।

उनका आगे बढ़ना तो साधारण बात है परन्तु जिस मार्ग पर उनमें से बहुत से लोग चल रहे हैं उस पर हमें अन्यतन्त्र गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये और उसकी खूब कड़ी परीक्षा करनी चाहिये। यह तो एक साधारण स्वयंसिद्ध बात है कि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक होंगे। इसलिये जो विचार और आकाङ्क्षा उनके मन को निश्चयपूर्वक किसी ओर झुकाव दे देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हम सबको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि यह विचार और आकाङ्क्षा उनको अपने भविष्य दायित्वों के लिये कदा तक योग्य बना सकती है।

एक शिकायत जो इतनी पोच है कि उसपर विचार करने की त्रिलकुल आवश्यकता नहीं है बहुधा सुनने में आती है। लोग निन्दा के तौर पर कहते हैं कि भारतीय विद्यार्थी अपने उचित समय से पहिले ही राजनीति में अनुराग करने लगते हैं और इस स्थिति को मिटा देना परमावश्यक है। हम मानते हैं कि भारतीय विद्यार्थी बहुत जल्दी राजनैतिक प्रश्नों में दिनचर्या लेने लगते हैं पर जो लोग इसको युग

समझते हैं और इसको मिटा देना आवश्यक या सम्भव समझते हैं वह यह भूल जाते हैं कि यह अवस्था इस देश की आन्ध्रधारण राजनैतिक स्थिति का अग्रगण्य परिणाम है और जब तक राजनैतिक स्थिति ऐसी ही है तब तक यह अवस्था कभी मिट नहीं सकती। आन्ध्रशासित जातियों की राजनीति क्षेत्र में देशभक्ति से ही नहीं किन्तु उत्तरदायित्व से भी काम लेना पड़ता है। वहाँ जिन नवयुवकों में देशभक्ति का भाव होता है पर दायित्व का भाव नहीं होता वह व्यावहारिक राजनीति से दूर रहने हैं। इसके विपरीत भारतीय विद्यार्थी के लिये राजनीति एक सग्राममात्र है जिसमें उसके देशभाई अपनी मातृभूमि का पक्ष लेकर विदेशी शासन के प्रतिनिधि विदेशी अफसरों से जुझ रहे हैं। यहाँ पर देश के शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में बड़ों के लिये भी उत्तरदायित्व के भाव के लिये कोई स्थान नहीं है। जब हमारे नवयुवकों के निग्रह के लिये दायित्व इत्यादि के कोई भाव ही नहीं है तो उनके समीप राजनीति केवल देशप्रेम की बात है और राजनीति में अनुगम देशानुराग ही है। विद्यार्थियों की सारी गम्भीरता, आत्ममर्यादा, धीरता और देशभक्ति का चरित्र तकाजा है कि वह राजनीति से अर्थात् देश के मामलों से अनुराग रखें। स्वयं इटालिस्तान ने हमारे देश में वह विचार प्रचलित किये हैं जो हमें देशभक्ति, स्वतन्त्रता, स्वराज्य की महिमा और उपयोगिता बतलाते हैं और जो यह भी बतलाते हैं कि मत्र स्वराज्य प्राप्त जातियाँ गुलामी से सन्तुष्ट रहनेवाली जातियों को पूर्ण अपमान की दृष्टि से देखती हैं। हमारी वर्तमान राजनीति केवल यही है कि साधारण जनता में इन विचारों का प्रचार करें और अपनी वर्तमान अवस्था को,

विचारों के अनुसार परिवर्तन करने का प्रयत्न करें । यह अवश्यम्भावी है कि देश की अत्यन्त भावुक जान्माओं पर इन विचारों का अत्यन्त अधिक प्रभाव पड़े ।

दायित्व के पद प्राप्त करने से ही हमारी राजनैतिक सम्मतियों और निर्णयों में अधिक स्थिरता आ सकती है और हमारी देशभक्ति की चञ्चलता रुक सकती है जिन मामलों में, जैसे म्युनिस्सिपैलिटियों के मामलों में जनता को उत्तरदायित्व के अधिकार मिल चुके हैं उनसे विद्यार्थियों को उचित समय के पूर्व कोई अनुमान नहीं होता । आजकल तो हम शासन के कोरे समालोचक मात्र हैं, शासन के कार्य में हमारा कोई भाग नहीं है । पर जैसे-यह अवस्था बदलेगी और प्रभु शासन में हमें अधिकाधिक भाग मिलेगा तैसे तैसे हमारी राजनीति भावुकता की दशा से आगे बढ़कर दायित्व की अवस्था को पहुँचेगी और राजनीति में विद्यार्थियों का वर्तमान असमर्थ चित्त अनुराग कम हो जायगा ।

पर वर्तमान अवस्था में यह अवश्यम्भावी है कि वह अपने समय के पहिले ही राजनैतिक मामलों में दिलचस्पी लेने लेंगे, आप उन्हें किसी तरह रोक ही नहीं सकते । पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह चाहे जिस स्थान से और चाहे जिस प्रकार से राजनैतिक विचार ग्रहण कर लें । धर्म मेरा दृढ़ है कि वर्तमान समय की एक बड़ी भारी आवश्यकता है कि हमारे कालेजों में नवयुवकों की राजनैतिक शिक्षा का सुप्रबन्ध हो । राजनीति को और विशेषतः सामयिक राजनीति को भयकर और कुछ अशोभनीय में, निषिद्ध विषय मानने की वर्तमान नीति का परिणाम यह हुआ है कि विद्यार्थी

थियों को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सम्मति स्थिर करने में अपने शिक्षकों से कुछ सहायता नहीं मिलनी। इस विषय स्थिति में नि सहाय होकर उनको जैसे तैसे सम्मति स्थिर करनी पड़ती है। इस विषय में उनके जीवन के नाजुक समय में उनकी ओर हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं। हमारी इस कर्तव्यविमुखता के परिणाम यह ओर और महत्वपूर्ण हुए हैं और होने ही चाहिये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय विद्यार्थियों और भारतीय आकांक्षाओं के सर्वोत्तम मित्र और हितैषी, दिल्ली का पादरी मि० पण्डित ने हाल में समाचारपत्रों को एक पत्र भेज कर मेरे विचारों का समर्थन किया है। वह कहते हैं कि "आजकल के भारतीय विद्यार्थी की राजनीति का तीन चौथाई भाग ऐतिहासिक और आर्थिक प्रश्नों का बना हुआ है। इतिहास और अर्थशास्त्र ने अध्यापकों का कर्तव्य है कि अपने विषय पढ़ाते समय इन प्रश्नों को सहानुभूति और बुद्धिमानी से समझाएँ। इस तरह कालेजों में ही अच्छी राजनीति सम्मतियाँ बन जायेंगी।" इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न भिन्न अध्यापकों की सम्मतियाँ भिन्न भिन्न होंगी पर वास्तविक महत्व की बात यह नहीं है कि विद्यार्थियों के सामने ही सम्मतियाँ पेश की जाती हैं किन्तु यह है कि उनके नैतिक भावों को शिक्षा मिले और उनको पर साधनो और दीर्घदृष्टि से विचार करने की यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और राजनैतिक शिक्षा मुख्य लाभ है। विद्यार्थियों के लिये राजनीति सम्मानना यही सिद्ध करती है। नैतिक शिक्षा परमावश्यक है। मेरी।

विद्यार्थियों को और विशेषतः कालेज के विद्यार्थियों को राजनैतिक मामलों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की और उनपर ठीक सम्मति स्थिर करने की सब सुविधाएँ होनी चाहिये। उनको इन सब मामलों पर कालेज में स्वतंत्रतापूर्वक वादविवाद करने का प्रोत्साहन देना चाहिये। सार्वजनिक पुरुषों को जिनकी सम्मति आन्दर के योग्य है वादविवादों में सम्मिलित होने के लिये कभी कभी बुलाना चाहिये। राजनैतिक विषयों पर व्याख्यान सुनने के लिये और दर्शक की हैसियत से राजनैतिक सभाओं में जाकर लाभ उठाने के लिये उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये।

यह तो हुई राजनैतिक शिक्षा की बात पर मेरी सम्मति है कि विद्यार्थियों को राजनैतिक आन्दोलन में व्यावहारिक भाग न लेना चाहिये। राजनैतिक आन्दोलन के दो भाग हैं; एक का सम्बन्ध जनता से है और दूसरे का सरकार से। जनता की ओर राजनैतिक आन्दोलन का उद्देश्य विस्तीर्ण और सुव्यवस्थित सार्वजनिक सम्मति और भाव उत्पन्न करना है। सरकार की ओर उसका उद्देश्य उस सम्मति या भाव के बल से शासन में वांछित परिवर्तन कराना है। हर दशा में यह अत्यन्त उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है और विद्यार्थी लोग जिनकी बुद्धि अपरिपक्व होती है इस कार्य में भाग लेने के अयोग्य हैं। राजनैतिक आन्दोलन में विद्यार्थियों के भाग लेने से सार्वजनिक जीवन की गंभीरता और उत्तरदायित्व कम हो जाता है। और उसकी सच्ची उपयोगिता में भी अन्तर आ जाता है। इससे विद्यार्थियों के मन अहिनकर आवेश में भर जाते हैं और बहुधा कठोर पक्षपात का भाव उत्पन्न हो जाता है जिससे उनके अध्ययन में बाधा पड़ती है और जो उनकी मानसिक

और नैतिक वृद्धि के लिये भी हानिकार है। कालेज के जीवन का वास्तविक कार्य यह है कि आनोपार्जन और चरित्रसंगठन के द्वारा भविष्य जीवन के कर्तव्यों के लिये तैयारी की जाय। जो चार या पांच वर्ष अधिकांश नवयुवक कालेज में प्रितति हैं वह इस कार्य के लिये ही कम है। मुझे निश्चय है कि नव युवकों से यह कहना बेजा न होगा कि "जब तक आप अपना अध्ययन समाप्त न कर लें और देश के सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान न ग्रहण कर लें तब तक जग धैर्य और आत्म निग्रह से काम लीजिये और राजनीति में कोई व्यावहारिक भाग न लीजिये"।

मैं समझता हूँ कि अब हमारी ऐसी अवस्था हो गई है कि हमें इस मामले में दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्य का सामना करना चाहिये। सब को विदित है कि हाल में देश में एक नये राजनैतिक पथ का प्रचार हुआ है जिसने समस्त भारत के नवयुवकों के मन पर प्रबल अधिकार जमा लिया है। नये पथ की बहुत सी शिक्षाएँ तो सवमान्य हैं, जैसे कि देशानुगता हमारे जीवन का मूलमंत्र होना चाहिये, देश के लिये स्वाध त्याग करने में हमें परम आनन्द मनाना चाहिये जहा तक हो सके अपने पैरों खडे होना चाहिये, दूसरों का मुह न नाफना चाहिये। इन सिद्धान्तों का उपदेश पहिले भी दिया गया था पर नये पथ ने सैकड़ों सभाओं और सैकड़ों पत्रों के द्वारा ऐसे तीव्र आवेश के साथ उपदेश दिया कि चारों तरफ जोश फैल गया। पर जहा नये पथ ने यह बहुमूल्य कार्य किया वहा साथ साथ देश में बहुत सी अहितकर राजनैतिक शिक्षा भी फैलाई। पहिले पहिल इस शिक्षा का प्रयोग देश के पुगने सार्वजनिक जीवन की जट यादने के लिये किया गया।

जब एक बार एक कार्य के लिये उसका प्रयोग आरम्भ हो गया तब धीरे-२ सर्वत्र ही उसका प्रयोग होने लगा । नई शिक्षा के प्रचारकों की प्रधान भ्रान्ति यह थी कि वह देश के पूर्व इतिहास की उपेक्षा करते ये जीर्ण विदेशी शासन के अस्तित्व को मर गड़े २ दुर्गों की जड़ मानते थे हमारे पुराने सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक आन्दोलन का मूलमंत्र यह था कि हम अंगरेजी शासन को स्पष्ट और राजभक्तिपूर्वक स्वीकार करते थे क्योंकि हम जानते थे कि देश के भिन्न-२ समुदायों को धीरे-२ एक राष्ट्र में परिणत करने के लिये और भिन्न-२ क्षेत्रों में बराबर उन्नति करने के लिये जिस शान्ति और सुव्यवस्था की आवश्यकता है वह अंगरेजी शासन की बंदौलत ही मिल सकती है । पर नये पथ ने घोषणा की कि अंगरेजी शासन में विश्वास करना निरा लड़कपन है और उसके उन्न के नीचे वास्तविक उन्नति की आशा करना दुराशामान है । अपने दुर्गों और शिकायतों के विषय में अधिकारियों के पास प्रार्थनापत्र भेजने का स्वत्व इङ्गलिस्तान के निवासियों ने बड़े सप्राम के गढ़ प्राप्त किया था पर नये पथ ने इसकी कोरी भिन्नमयी बताया और इसकी घोर निन्दा की । उसने कहा कि हमें प्रायःकाट से काम लेना चाहिये, सारे देश में प्रायःकाट का प्रचार होने से हमारी सारी अभिलाषाएँ पूरी हो जायगी ।

यह शिक्षा नई थी, देश ने से सच मालूम होती थी, चित्ताकर्षक थी और स्वराज्य प्राप्त करने का सरल मार्ग बतलाने का दावा करती थी, इसलिये कुछ दिन बड़ी तेजी से इसका प्रचार हुआ । माना कि देश में अङ्गरेजी सरकार मौजूद थी पर नये पथ ने कहा कि हम इसकी पूर्ण उपेक्षा करेंगे, इस

के अस्तित्व को ओर कुछ ध्यान ही न देंगे और आशा की कि बदले में सरकार हमारी उपेक्षा करेगी, हमारे अस्तित्व की ओर ध्यान न देगी। लार्ड कर्जन के शासन के अन्तिम वर्षों में सर्वसाधारण के हृदय मडल में जो निराशा रूपी अन्धकार छा गया था उससे नई शिक्षा के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। त्यों आन्दोलन के पश्चात् भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनैतिक सुधार कराने में, कम से कम ऊपर से देखने में जो असफलता हुई थी उससे भी नई शिक्षा के फैलाने में बड़ी आसानी हुई। सर्वसाधारण में राजनैतिक बुद्धि की न्यूनता तीसरा कारण था। राजनैतिक मामलों में, और सच पूछिये तो सब ही सार्वजनिक मामलों में हमारे बहुत कम आदमी स्वयं विचार करने का कष्ट उठाते हैं। जैसे दूसरों के बनाये हुये कपड़े पहिनना आसान है वैसे ही दूसरों की स्थिर की हुई सम्मति ग्रहण करना भी आसान है। नये पथ के अधिकांश अनुयायी विद्यार्थी थे। पथ के बहुत से वयोवृद्ध अनुयायियों का तो भ्रम अब दूर हो गया है और वह अपने कार्यक्रम की असम्भवता को समझ गये हैं पर मुझे डर है कि विद्यार्थीगण के मन पर नई शिक्षा का प्रभाव पूर्ववत् बना हुआ है। इसीलिये आज मैंने इस विषय पर कुछ कहना अपना कर्तव्य समझा है।

मेरा ग्याल है कि हमारे उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने जो नये पथ से होनेवाली हानि को अच्छी तरह समझते हैं अभी तक इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की ओर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। उनकी अकार्यशीलता का कारण निस्सन्देह उनकी यह समझ है कि मामला बड़ा नाजुक है पर परिणाम उतना ही शोचनीय हुआ है जितना कि ज

धूर्त कर कर्तव्यविमुक्तता करने से होता । मेरा विचार है कि लोग हमारे विषय में चाहे कुछ भी क्यों न समझें, अब हमारा धर्म है कि सब बातें साफ २ करें । देश की ओर हमारा जो कर्तव्य है, नययुवकों की ओर हमारा जो कर्तव्य है उसका यही तफाजा है । जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूँ, नये पंथ की स्वावलम्बन विषयक शिश्ना सर्वमान्य है । पर सरकार के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिये ? इस विषय में नई शिक्षा का प्रतिपाद करना आवश्यक है । जैसा कि मेरे मित्र बाबू भूपेन्द्रनाथ चसु ने उस दिन कलकत्ते में कहा था, आप जिस प्रकार सूर्य की उपेक्षा नहीं कर सकते उसी प्रकार सरकार का उपेक्षा भी नहीं कर सकते । दूसरे, यदि आप सरकार की उपेक्षा करना चाहते हैं तो क्या सरकार भी आपकी उपेक्षा कर जायगी ? क्या वह आप से कुछ न योलेगी ? पर सब बातें तो यह है कि आपको इस तरह की बेसिर पैर की बातचीत में उत्तेजित होकर सरकार कठोर दमननीति प्रयोग करती है जिससे देश की सारी कार्यशीलता को जोर का धक्का लगता है । नये मत के कुछ नेता तो इतने आगे बढ़ गये हैं कि वह कहते हैं कि हमको पूर्ण स्वाधीनता के लिये उद्योग करना चाहिये । यदि कोई पुरुष घर पर बैठे २ स्वप्न देखना ही कर्तव्य मानले और अन्य स्वप्नों के साथ देश के लिये पूर्ण स्वाधीनता एवं सब प्रकार की पूर्णता के स्वप्न देखे तो मुझे कुछ नहीं कहना है । पर यदि वह उपदेश कि हमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्योग में लग जाना चाहिये तो दूसरी बात है । इस दशा में हमारा कर्तव्य होगा कि हम अपनी पूरी शक्ति से उसका विरोध करें । आप अपने चारों ओर जरा द्रष्टि डाल कर देखिये तो आपको स्वयं मान्य हो

जायगा कि पूर्ण स्वाधीनता का आन्दोलन हमको कैसी आपत्ति में डाल देगा । श्री २ किन्तु शान्तिपूर्वक उन्नति करने के हमारे वर्तमान अवसरों और सुमोर्तों को यह नाश कर देगा या अनिश्चित काल तक स्थगित कर देगा ।

नये पथ की शिखा से हमारे जोशीरे और भोले भाले विचारियों को ही सबसे अधिक हानि पहुची है और पहुचेंगे । यदि हमारे ये देश में कोई नवयुवकों से स्वाधीनता की बात चीत करे तो उनके मन में बहुत ऊँचे दोही विचार स्पष्टतापूर्वक उत्पन्न होंगे, एक तो यह कि विदेशियों को देश से फेंके निकालें और दूसरा यह कि कितनी जल्दी निकाल दें । इन दो महान् प्रश्नों के सामने और सब बातें अविचारणीय प्रतीत होंगी । सब जानते हैं कि ऐसे विचारों के यशीभूत हो जाने से गम्भीर जोशीली तथियत के आदमी कौसी जोखिम में जा गिरेंगे । सब से बुरी बात तो यह है कि ऐसे विचारों का आदमी जितना ही अधिक गम्भीर, जोशीला और कार्यशील होगा वह उतनी ही बड़ी आपत्ति में फसेगा । पूर्ण स्वाधीनता के पोषक कभी २ कहते हैं कि हम अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये केवल शान्तिपूर्ण उपायों का अय लम्बन करेंगे । सम्भव है कि वह यही चाहते हों पर सर कार तो अपने शासन का विध्वंस देखना नहीं चाहती और उनको शान्तिपूर्वक उद्योग न करने देगी ।

मैं आप के सामने जो विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ वह बड़े ही साधारण हैं और सब पर प्रकट हैं । ऐसी बातें लिये मानों क्षमा प्रार्थना करनी चाहिये । आज इनका याद दिवाना आवश्यक हो गया है, इससे यही

कि हमारे देश में लोगों की राजनैतिक बुद्धि कितनी जल्दी भ्रम में पड़ सकती है। हमारे नवयुवकों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अभी बहुत दिन तक हमारे देश में अङ्गरेजी शासन रहेगा और कोई शासन स्थापित नहीं हो सकता। उसको नष्ट करने की हमारी सारी चेष्टाएँ उल्टा हमें ही हानि पहुँचायेंगी। दूसरे यदि वह अपनी न्यायबुद्धि से काम लेना चाहें तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि यद्यपि इस शासन में विदेशी शासन के अवश्यभावी दोष वर्तमान हैं तथापि यह देश की उन्नति का एक बड़ा साधन सिद्ध हुआ है इसके स्थिर रहने से वह शान्ति और व्यवस्था भी स्थिर रहेगी जो देश की वर्तमान दशा में, केवल इसी पर अवलम्बित है और जो हमारे सारे हितों के साधन के लिये, हमारी मददती हुई राष्ट्रीयता के लिये, परमावश्यक है। शासक ने वचन दिया है कि हम आपके साथ समानता का वर्तमान करेंगे। हमें आशा है कि धीरे-धीरे हमको समानता का पद मिल जायगा। हमने वर्तमान शासन को स्वीकार कर लिया है और राजभक्ति का वचन दिया है। स्वीकृति और राजभक्ति के बल पर हमें कुछ अधिकार मिल गये हैं और आगे चलकर और भी अवश्यमेव मिलेंगे। स्वार्थ और सत्यता दोनों का ही तकाजा है कि हम इस शासन को नाश करने के विचारों को मन में स्थान न दें और इसकी ओर अपना व्यवहार राजभक्ति पूर्ण रखें।

राजभक्ति एक कार्यशील भाव है। इसका अर्थ केवल यही नहीं है कि हम राजा या सरकार से शत्रुता न करें किन्तु यह भी है कि जब उसपर कोई आपत्ति आवे तब उसकी सहायता

एक बात स्पष्ट है। यह यह है कि हमारा धर्म है और अवि-
कार है कि हम इसी समानता की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रहे
और किसी अन्य मार्ग का चिन्तन न कर। हम इस मार्ग के
सिरे पर, अपने वर्तमान स्थान से बहुत दूरी पर, एक भवन
की कल्पना कर सकते हैं जिसमें फरासीसी और डच लोग
(हालैंड देश के निवासी) अगरेजों के साथ बैठने हों। उस भवन
तक पहुँचने का बल हम कभी प्राप्त करेंगे या नहीं? यदि हम
वहाँ तक पहुँच भी गये तो भवन के भीतर प्रवेश करने पायेंगे
या नहीं? हमारी यात्रा किसी ओर मार्ग में तो समाप्त न हो
जायगी? इन प्रश्नों का उत्तर भविष्य ही देगा। घोर परिश्रम
के बाद अपना चित्त प्रफुल्लित करने के लिये या वहाँ तक
पहुँचने के लिये आवश्यक बल का अनुमान करने के लिये
हम चाहे समय २ पर उस भवन की ओर (समानता, स्वतंत्रता
के भवन की ओर) देख लिया करें पर "दूरवर्ती भविष्य में
हमारा भाग्य क्या होगा?" इस विषय पर अत्याधिक चिन्ता
करना न तो बुद्धिमानी है और न आवश्यक है।

मैं कह चुका हूँ कि हमको अङ्गरेजा के साथ दो प्रकार
की समानता प्राप्त करनी है—एक तो व्यक्तिगत और दूसरी
शासन सम्बन्धी। यो तो पहिले प्रकार की समानता की प्राप्ति
कठिन है पर उतनी कठिन नहीं है जितनी कठिन दूसरी प्रकार
की समानता की प्राप्ति है। इस समय भी देश में बहुत से
भारतवासी हैं जो योग्यता और चरित्रबल से अगरेजों से
किसी तरह कम नहीं हैं। पर साम्राज्य के दूसरे प्रदेशों
के समान जनसत्तात्मक स्वराज्य की प्राप्ति जनसाधारण की
आवश्यक योग्यता और चरित्रबल पर निर्भर है क्योंकि जनता

के आसत बल के आधार पर ही स्वराज्य का भवन स्थिर रह सकता है। हमें शोकपूर्वक स्वीकार करना होगा कि आज हमारे देश के जनसमूह का योग्यताबल और चरित्रबल का आसत और देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। इसलिये हमारे सामने सबसे आवश्यक काम यह है कि हम उस आसत बल को बढ़ाने का प्रयत्न कर ताकि वह फरासीसी आर डच आसतों की भांति अगरेजी आसत के बराबर हो जाय। इस क्षेत्र में जोशीले से जोशीले देशभक्त के करने के लिये काफी काम है। सच तो यह है कि जिधर देखिये उधर ही यह दृश्य दिखाई देता है कि करने के लिये काम तो बहुत है पर सच्चे कर्मवीर बहुत कम हैं। पतित जानियों को उठाकर शेष जनता के बराबर बिठाया प्रत्येक बालक-बालिका के लिये प्रारम्भिक शिक्षा, समुदाय समितियों का स्थापन, स्वेच्छी और शिष्ट की शिक्षा का प्रचार, देश की आर्थिक दशा का सुधार, उच्चशिक्षा, औद्योगिक उन्नति, देश के भिन्न भिन्न समुदायों में अधिष्ठ प्रतिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना—यह सब अन्यकार्य हमारे सामने हैं और प्रत्येक कार्य के लिये दीक्षित कर्मचारों की सेना की आवश्यकता है। क्या इस आवश्यकता की पूर्ति न की जायगी? प्रतिवर्ष जो हजारों नवयुवक हमारे विश्वविद्यालयों से निकलते हैं क्या उनमें थोड़े से भी ऐसे नहीं हैं जो उच्च आध्यात्मिक भावों से प्रेरित हैं और उन भावों के अनुसार स्वार्थहीन कर्म करें? यह हमारी मातृभूमि का कार्य है। यह सारी मनुष्य जाति का कार्य है। जिस जाग्रति की हम वातचीत किया करते हैं और जिस पर हम सब का प्रफुल्लित होना उचित ही है यदि उसके

बाद भी यह काम कार्यकर्त्ताओं के अभाव के कारण अ
 हो रह गया तो समझना होगा कि भारतमाता को ३
 पुत्रों से सच्ची सेवा का उपहार पाने के लिये अभी ३
 एक पीढ़ी तक प्रतीक्षा करनी होगी ।-

